DEVELOPMENT PLANNING OF BACKWARD ECONOMY A CASE STUDY OF SONBHADRA DISTRICT OF U. P.

पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास नियोजन : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद का एक संदर्भित अध्ययन



(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल्. उपाधि हेतु प्रस्तुत) शोध प्रवन्ध

> निर्देशक कॉ. ही. एन. सिंह, डी. फिल् प्रवस्ता, पूरोस विभाग इसाहाबाद, विश्वविद्यासय

योजकर्ता सर्वेजीर सिंह यूजोस विजान इसाहाबाद विश्वविद्यालय इसाहाबाद गौँवों का प्रादुर्भाव नगरों से पहले हुआ था। गाँव ही सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक गितिविधियों के केन्द्र हुआ करते थे। कालान्तर में नगरों का प्रादुर्भाव एवं विकास गाँवों से ही हुआ। सम्प्रित नगर आर्थिक विकास के पर्याय बन गए है। ब्रिटिश काल में गाँवों की प्रमुख भूमिका कच्चे माल के संभरण एव विनिर्मित माल के उपभोक्ता केन्द्र के रूप रही। स्वतन्त्रता के पश्चात् सभी पचवर्षीय योजनाओं मे ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी। वस्तुत सम्पूर्ण गाँवों के विकास के बिना (जहाँ देश की 75 प्रतिशत जनसख्या गाँवों में रहती हैं) देश का समन्वित-विकास नहीं हो सकता है। क्षेत्रीय असमानताओं एव विविधताओं के कारण प्रशासनिक एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म-स्तरीय विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करना तथा ग्रामीणों को जीवन स्तर को उच्च करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास पर निर्भर है। अर्थात् समन्वित क्षेत्र-विकास के लिए सूक्ष्म-स्तरीय आयोजन अपरिहार्य है।

इसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध विषय पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद का एक सदर्भित अध्ययन' का चयन किया गया वर्तमान जनपद सोनभद्र का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन कई परिकल्पनाओं एव तथ्यों की दृष्टि से किया गया है। प्रथम, 'वर्तमान समय मे उद्योग पिछड़े क्षेत्रों के विकास के माध्यम वस्तुत यह सिद्धान्त कितना कारगर है इसके अध्ययन के लिए सोनभद्र उपयुक्त क्षेत्र यहाँ का औद्योगीकरण हाल ही में प्रारम्भ हुआ है। है। उद्योगों की स्थापना से गुणात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव के अध्ययन के लिए उप्युक्त क्षेत्र है। ततीय, कुटीर उद्योगो की पर्याप्त संभावनाएं हैं किन्तु इसका स्मृचित विकास नही किया जा चतुर्थ, कृषि क्षेत्र की कमी है किन्तु जल एवं ताप विद्युत गृहों की अवस्थापना तथा बाधों एवं बंधियों के निर्माण से कृषि विकास की सम्भावना बढ़ गयी है। फसल गहनता मे वृद्धि तथा फसल प्रतिरूप में परिवर्तन की पर्याप्त सम्भावना है। प्रंचम, यहाँ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक (42.5 प्रतिशत) है। ये पिछड़ेपन के पर्याय इनके विकास की पर्याप्त आवश्यकता है। षष्ठम, रोजगार पाने के माने जाते हैं। अत ·

पर्याप्त सम्भावनाओं के बावजूद तकनीकी ज्ञान एवं अल्प वित्तीय ससाधन के अभाव मे यहाँ के लोग बेरोजगारी के शिकार हैं। सप्तम्, अध्ययन क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थित एव स्वरूप होने के कारण विकास की पर्याप्त सभाव्यता। है। अष्टम्, शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र की समस्याओं एवं आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित है(जन्म स्थली होने के कारण) तथा उसके पहुँच के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सचार एव अन्य सुविधाओं की पर्याप्त कमी है, जो विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ की भौतिक एव सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है जिसके त्वरित विकास की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र के विकास आव्यक्त का विश्लेषण संकल्पनात्मक एव व्यावहारिक दोनों ही द्रिष्टियों से किया गया है। संकल्पनात्मक विश्लेषण में यथा संभव उपलब्ध साहित्यों के अनुशीलन से प्राप्त विचारों को प्रस्तुत किया गया है। व्यावहारिक विश्लेषण आकडों एव क्षेत्रीय अनुभवों पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र के सूक्ष्म स्तरीय स्वरूप होने के कारण प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है किन्तु द्वितीयक आकड़े ही अधिक प्रयुक्त प्राथमिक आकडे जिला उद्योग केन्द्र, राबर्ट्सगंज, आद्योगिक प्रतिष्ठान केन्द्रों, जिला कृषि कार्यालय, राबर्ट्सगज, लोक निर्माण विभाग, राबर्ट्सगंज, तहसील मुख्यालय, राबर्ट्सगज एव दुद्धी, विकास खण्ड मुख्यालय, राबर्ट्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवा, चोपन, दुद्धी , म्योरपुर, व बभनी, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय; जिला स्वास्थ्य केन्द्र राबर्ट्सगज और पशु अस्पताल केन्द्र राबर्ट्सगज से प्राप्त किये गये है। द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य स्रोत जनगणना हस्त्पुस्तिका, जनपद मिर्जापुर, 1961 तथा 1971, गजेटियर, जनपद मिर्जापुर, 1988, सांख्यिकीय पत्रिका जनपद सोनभद्र, 1992; सोनभद्र जनपद के अगृणी बैंक, इलाहाबाद बैक की वार्षिक योजना, सोनभद्र 1991-92; जनपद सोनभद्र की जिला कार्य योजना, 1992-93, उद्योगों की निर्देशिका, जनपद सोनभद्र, 1991-92; भारत 1991 तथा उत्तर प्रदेश वार्षिकी, 1990-91 उपर्युक्त आंकड़ों के अतिरिक्त यथा स्थान व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं अनुभव का भी आश्रय लिया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण में दुरूह सांख्यिकीय विधियो का प्रयोग नहीं किया गया है किन्तु बस्तियों के अन्तरालन, विकास केन्द्रों के सीमांकन, शस्य गहनता, सड़क-सम्बद्धता तथा जनसंख्या प्रक्षेपण मे यथा आवश्यक सामान्य सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग विषय की स्पष्ट व्याख्या के लिए कुछ स्थानों पर आंकड़ों की पुनरावृत्ति संश्लेषित आंकड़ों को मानचित्रों एवं तालिकाओं, से विश्लेषित एवं भी की गयी है।

अधिक बोधगम्य बनाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन की सुस्पष्टता के लिए 60 तालिकाओं एवं 43 मानचित्रों आरेखों व चित्रों को सम्मिलत किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में, समय एवं संसाधनों के अभाव में, समन्वित क्षेत्र-विकास से सम्बन्धित केवल कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का विकास नियोजन प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त क्षेत्रों का विकास-नियोजन विकास-केन्द्र' उपागम के अन्तर्गत विवेचित है। विकास-केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया सर्वथा व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके लिए उपलब्ध साहित्यों के अनुशीलन तथा क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर उन्हीं बस्तियों को विकास केन्द्र/सेवा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है जो चयनित 35 आधारभूत कार्यों/सेवाओं में से जूनियर बेसिक विद्यालय, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र एवं उपकेन्द्र तथा फुटकर बाजार के अतिरिक्त किन्हीं दो कार्यों को सम्पादित कर रहे हो या उनके द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यों का मान 3.16 से कम न हों। कार्यों के मान तथा सेवा केन्द्रों के केन्द्रीयता के मापन मे एक नवीन विधि को व्यवहृत किया गया है। इस विधि से कार्यों/सेवाओ के सापेक्षिक महत्व का स्पष्टीकरण होता है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के भ्वाकृतिक स्वरूप एव कार्यात्मक रिक्तता को देखते हुए 61 नए विकास-केन्द्रों का चयन, आधार-भूत कार्यो/सेवाओ की आवश्यकता हेतु किया गया है। निर्धारित एव प्रस्तावित विकास/सेवा केन्द्रों के परिप्रेक्ष्य में ही सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का विकास-नियोजन प्रस्तुत है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को, अध्ययन क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए आठ अध्यायों में विवेचित किया गया है। अध्याय एक में शोध विषय सम्बन्धी (विकास, नियोजन एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था) समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्याय दो में अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि का विश्वद विवरण प्रस्तुत है साथ ही इसके परिप्रेक्ष्य में विकास-नियोजन प्रस्तुत है। अध्याय तीन में बस्तियों के स्थानिक-कार्यात्मक सगठन की समीक्षा तथा जनपद के विकास ध्रुवों की विवेचना प्रस्तुत है। अध्याय चार में वर्तमान कृषि प्रतिरूप के मूल्याकन के उपरान्त कृषि-विकास नीति की व्याख्या की गयी है। अध्याय पाँच में वर्तमान औद्योगिक पृष्ठभूमि का वर्णन कर स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगो के अवस्थापना एवं विकास की नीति निर्धारित की गयी है। अध्याय छ में परिवहन एवं सचार व्यवस्था के वर्तमान पिछड़े स्वरूप के संदर्भ में तीव्र विकास नियोजन का प्रस्ताव है। अध्याय सात में सामाजिक सुविधाओं

से सम्बन्धित शिक्षा एवं स्वास्थ्य के वर्तमान स्वरूप का वर्णन कर वाछित विकास हेतु नियोजन प्रस्तुत है। अध्याय आठ में समन्वित क्षेत्र-विकास से सम्बन्धित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत है। इस अध्याय मे उन पक्षों की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है जिनका समन्वित क्षेत्र-विकास में महत्वपूर्ण योगदान है किन्तु अनेक कारणों से शोध-प्रबन्ध के अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

विकास, नियोजन तथा पिछड़ेपन से सम्बन्धित साहित्य अनेक सामाजिक विज्ञानों मे उपलब्ध है, उन सभी का विवरण देना दुरूह कार्य है। यथास्थान उल्लिखित सन्दर्भों को प्रत्येक अध्याय के अन्त में संख्या - क्रम में प्रस्तुत किया गया है। शोध प्रबन्ध के अंत में दो पिरिशिष्ट दिए गए हैं। प्रथम में शब्दावली तथा द्वितीय मे प्रस्तुत शोध विषय एव क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रन्थों एव लेखों का उल्लेख किया गया है।

चिर प्रेरणा के स्रोत गुरू प्रवर डॉ० बी० एन० सिंह (प्रवक्ता, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने विषम परिस्थित में , अपने सुयोग्य निर्देशन में शोध-प्रबन्ध को यथाशीष्ट्र पूर्ण करने का सुअवसर प्रदान किया। प्रो० आर० एन० तिवारी (निवर्तमान अध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय), डॉ० आर० एन० सिंह (रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) तथा डॉ० बी०एन० मिश्र (रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनके सतत प्रोत्साहन एव विद्वतापूर्ण सुझावों से हमेशा मार्ग दर्शन मिलता रहा। डॉ० सिवन्द्र सिंह (वर्तमान अध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) तथा डॉ० आर०सी० तिवारी (रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) की प्रेरणाए न केवल प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में सहायता की वरन् जीवन की सच्चाई को समझने में आजीवन मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी, का में आभारी हूँ। डॉ० सुधाकर त्रिपाठी, डॉ० नन्द किशोर सिंह, डॉ० सुनील त्रिपाठी, डॉ० रमा शकर मौर्य, डॉ० राम दुलारे पाण्डे तथा शोध छात्र ओम प्रकाश राय एवं अशोक कुमार सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपना सुझाव एवं सहयोग प्रदान किया। में अपने समस्त परिवार जनों का, जिनके त्याग, प्रेरणा एवं स्नेह ने मुझे इस योग्य बनाया, आजीवन ऋणी रहूँगा।

अंत में, मैं टाइपिस्ट गोविन्द दास एवं राम नाथ सिंह को धन्यवाद देना चाहूगा जिन्होंने शोध-प्रबन्ध का टकण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने मे सहयोग प्रदान किया। मै उन सभी सस्थाओं,पुस्तकालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने विविध प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करके शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

इलाहाबाद 14 नवम्बर, 1993 दीपावली द्धिमेनी सिंह) (धर्मवीर सिंह) श्रोध छात्र,भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

विषय-सूची

	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	i - iv
	मानचित्रों एव आरेखों की सूची	xı - xiı
	तालिकाओं की सूची	x iii-x i v
अध्याय । :	संकल्पनात्मक विश्लेषण	1 - 44
	। । विकास, प्रगति एवं सवृद्धि की अवधारणा	
	(अ) प्रगति और विकास	
	(ब) सवृद्धि और विकास	
	(स) क्रान्ति और विकास	
	1.2 विकास की भौगोलिक अवधारणा	
	ा.3 आर्थिक विकास की अवधारणा	
	1.4 सिवकास की अवधारणा	
	1.5 विकास के निर्धारक तत्व	
	। 6 विकास के सिद्धान्त	
	।.7 नियोजन की संकल्पना	
	। . ८ नियोजन क्यों ?	
	 योजना प्रक्रिया के विभिन्न चरण 	
	। ।० नियोजन का स्वरूप	
	। ।। विकास नियोजन	
	। । । २ सूक्ष्म स्तरीय नियोजन	
	(अ) सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से लाभ	
	(ब) भारत मे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन	
	। . । 3 स्थानबद्ध नियोजन	
	। । । 4 पिछड़ी अर्थव्यवस्था की संकल्पना	
	।.।5 पिछड़ेपन का कारण	
	। । । 6 पिछड़ी अर्थव्यवस्था के मापदण्ड	
	।.।7 पिछड़े क्षेत्रों की पहचान	
अध्याय 2:	अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि	45 - 90
	2.। स्थिति एवं विस्तार	
	2.2 भौतिक विशेषता	
	(अ) प्राकृतिक विभाग	
	(।) मध्यवर्ती पठारी भाग	
	(2) सोनघाटी	
	(ब) भौतिक स्वरूप एव संरचना	
	(।) दुद्धी तहसील का भौतिक स्वरूप	
	(2) दृद्धी तहसील की भ-वैज्ञानिक संरचना	

- प्रीकैम्ब्रियन शैल
- 2. नाइस
- 3. बिजावर शैल वर्ग
- 4. फाइलाइट
- 5. क्वार्टजाइट
- 6. डोलोमाइट/चूना पत्थर
- 7. क्षारीय शैल
- 8. गोंडवाना अनुक्रम
 - (क) तालचिर फार्मेशन
 - (ख) बाराकर फार्मेशन
- (3) राबर्ट्सगंज तहसील का भौतिक स्वरूप
- (4) राबर्ट्सगंज तहसील की भू-वैज्ञानिक सरचना
 - ।. कैमूर समूह (कैमूर स्कार्य)
 - 2. सेमरी समूह
 - 3. बिजावर समूह
- (स) अपवाह प्रणाली
- (द) जलवायु
- (य) मृदा
 - (।) मृदा सरचना
 - ।. प्रीकैम्ब्रियन मणिभीय शैलों से निर्मित मुदा
 - 2. बिजावर शैल से निर्मित मुदा
 - 3. गोंडवाना अधिवर्ग की शैलों से निर्मित मुदा
 - (2) मृदा वर्गीकरण
 - ।. दुखी तहसील की मृदा
 - (क) हाथी नाला श्रेणी
 - (ख) दुद्धी संघ
 - (ग) सिंगरौली श्रेणी
 - (घ) औड़ी श्रेणी
 - (ड) कार्बनीफेरस
 - (च) गोहड़ा श्रेणी
 - 2. राबर्ट्सगंज तहसील की मृदा
 - (क) बेलन समुदाय
 - (ख) विजयगढ़ समुदाय
 - (ग) सोन समुदाय
 - (घ) परासपानी समुदाय
 - (ड) हाथी नाला समुदाय
 - (च) जुगैल समुदाय

	(र) प्राकृतिक वनस्पति एवं वन सम्पदा	
	(।) नदी तटीय सीमावर्ती वन	
	(2) श्रुष्क प्रायद्वीपीय साल	
	(3) उत्तर शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन	
	(4) शुष्क पर्णपाली वनों के क्षुद्ररोह	
	(5) सर्लई वन	
	(6) परसिद्ध वन	
	(7) शुष्क बांस	
	(ल) खनिज सम्पदा	
	(।) धात्विक खनिज	
	।. लोह अयस्क	
	2. सोना	
	(2) अधात्विक खनिज	
	3. सल्फाइड	
	4. लाइम स्टोन	
	5. मैग्नेटाइट	
	सफेद मिट्टी	
	7. मृत्तिका (क्ले)	
	8. निर्माण सामग्री	
	9. कोरण्डम	
	10 कोयला	
2.3	सास्कृतिक पृष्ठभूमि	
	(अ) लोकगीत, नृत्य एव नाट्य	
	(ब) जनसंख्या	
	(।) जनसंख्या वितरण एव घनत्व	
	(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	
	(3) साक्षरता	
	(4) व्यावसायिक संरचना	
•	(स) बस्तियों का प्रतिरूप	
	का स्थानिक-कार्यात्मक संगठन एवं नियोजन	91 - 138
	विकास-केन्द्र की संकल्पना	
	विकास-केन्द्र एव केन्द्रीय कार्य	
	केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम	
	विकास केन्द्रों का निर्धारण	
	केन्द्रीयता का निर्धारण	
	विकास केन्द्रों का पदानुक्रम	
	विकास केन्द्रों का स्थानिक वितरण	
3.8	प्रस्तावित विकास केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य	

अध्याय ३

अस्त्रामा ४	रूषि के विकास की स्वरूपणि सर्व विस्तेत्वर	139 - 172
जञ्चाय ४.	कृषि के विकास की पृष्ठभूमि एवं नियोजन	139 - 172
	4.। कृषि-सम्प्रत्यय 4.2 कृषि योग्य भूमि	
	4.2 कृति योग्य मूर्गि (अ) शुद्ध बोया गया कृषि-क्षेत्र	
	(अ) शुर्ख बाया गया फृाय-क्षत्र (ब) एक से अधिक बार बोया गया कृषि-क्षेत्र	
	4.3 फसल प्रतिरूप	
	(अ) खरीफ - फसल	
	(ब) रबी-फसल	
	(स) जायद-फसल	
	(द) औद्यानिक-फसल	
	4.4 फसल प्रतिरूप में परिवर्तन	
	4.5 फसल संयोजन	
	(अ) फसल-कोटि निर्धारण	
	(ब) फसल-संयोजन प्रदेश	
	4.6 फसल गहनता	
	4.7 सिंचाई	
	4.8 जोर्तों का आकार	
	4.9 कृषि का यन्त्रीकरण	
	4.10 पशुपालन	
	4.II कृषि-विकास नियोजन	
	(अ) भूमि सुधार	
	(ब) सिंचाई	
	(स) कृषि का वाणिज्यीकरण	
	(द) अर्सिचित भूमि में कृषि	
	(य) जायद कृषि	
अध्याय 5:	औद्योगिक पृष्ठभूमि एवं विकास-नियोजन	173 - 220
	5.1 औद्योगिक स्वरूप	
	5.2 ऐतिहासिक पर्यवेक्षण	
	5.3 उद्योगों का वर्गीकरण	
	(अ) बड़े पैमाने के उद्योग	
	(।) सीमेंट उद्योग	
	(2) अल्यूमिनियम उद्योग	
	(3) विद्युत उर्जा	
	।. जल विद्युत	
	(क) रिहन्द जल विद्युत गृह पिपरी	
	(ख) ओबरा जल विद्युत गृह	

	6.8	 (ब) जल मार्ग (स) वायु मार्ग (द) रज्जु मार्ग (य) सड़क मार्ग संचार व्यवस्था (अ) व्यक्तिगत संचार (1) डाक सेवा (2) तार सेवा (3) दूरभाष सेवा (ब) जनसचार 	
अध्याय 7		जेक सुविधाओं की प्रृष्ठभूमि एवं विकास नियोजन	256 - 298
	7.1		
		साक्षरता	
	7.3	औपचारिक शिक्षा का प्रतिरूप	
		(अ) जूनियर बेसिक विद्यालय	
		(ब) सीनियर बेसिक विद्यालय	
		(स) हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	
		(द) उच्च शिक्षा केन्द्र	
		अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम	
		शिक्षा नियोजन की प्रमुख बाधायें विद्यालयों का शैक्षिक स्तर	
	7.7	10 0 1	
	1.1	(अ) जनसंख्या प्रक्षेपण एवं छात्रों की संभाव्य संख्या	
		(ब) विद्यालय स्तर के अनुसार नियोजन	
		(।) जूनियर बेसिक विद्यालय	
		(2) सीनियर बेसिक विद्यालय	
		(3) हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	
		(4) उच्च शिक्षा केन्द्र	
		(5) तकनीकी शिक्षण संस्थान	
		(6) अनौपचारिक शिक्षा	
	7.8	स्वास्थ्य	
	7.9	स्दास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं	
		(अ) रोगों की समस्या	
		(ब) स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की समस्या	
) चिकित्सा सुविधाओं की वर्तमान स्थिति	
अध्याय 8:	7.11	। स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन वत क्षेत्र-विकास	200 - 204
AA414 0.		भरा जन-१५फात ष्टियां	299 - 306 307 - 313
	1.	७ शब्दावली	55.
	2.	Further Readings	

4.6	CROP INTENSITY 1990-91
4.7	IRRIGATION; 1990-91
4.8	LAND HOLDINGS
4.9	SPATIAL PATTERN OF BANKING FACILITIES
5.1	INDUSTRIAL UNITS; (LARGE SCALE)
5.2	TOTAL CLINKER AND CEMENT PRODUCTION
5.3	CEMENT PRODUCTION
5.4	HYDRO ELECTRICITY GENERATION
5.5	THERMAL ELECTRICITY GENERATION : PLANT WISE
	(A) OBRA (B) ANPARA
5.6	RENUSAGAR THERMAL POWER HOUSE ELECTRICITY
	GENERATION
6.1	TRANSPORT NETWORK
6.2	ROAD DENSITY PER HUNDRED KM ²
6.3	ROAD DENSITY PER LAKH POPULATION
6.4	ROAD NETWORK AND ACCESSIBILITY
6.5	FREQUENCY OF BUSES
7.1	LITERACY DISTRIBUTION ; 1991
7.2	DEVELOPMENT BLOCKWISE LITERACY OF DISTT.
	SONBHADRA; 1991
7.3	EDUCATIONAL FACILITIES
7.4	PROPOSED EDUCATIONAL FOCI ; 1991-92
7.5	SPATIAL PATTERN OF MEDICAL FACILITIES

तालिकाओं की सूची

2.1	जनपद सोनभद्र का सामान्य विवरण
2 2	वर्षा
2.3	वनों का वितरण - 1990-91
2.4	कोयले का भण्डार एव उत्पादन - 1992
2.5	जनसंख्या वितरण - 1991
2.6	जनसंख्या घनत्व
2.7	जनसंख्या वृद्धि
2.8	विकासखण्ड वार अनुसूचित जाति की जनसख्या - 1991
2.9	जनपद सोनभद्र मे साक्षरता प्रतिशत - 1991
2.10	जनसंख्या का व्यावसायिक सरचना - 1991
2.11	जनसख्या के अनुसार गाँवो का वर्गीकरण
2.12	गॉवों की सघनता एव अन्तरालन
3.1	केन्द्रीय विकास कार्य
3.2	कार्य एव कार्याधार जनसंख्या सूचकांक
3.3	कार्यों के चार पदानुक्रम
3.4	जनपद मे निर्धारित सेवा केन्द्र
3.5	विभिन्न कार्यों का महत्वानुसार मान
3.6	सेवा केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकाक
3.7	केन्द्र स्थलो का पदानुक्रमीय व्यवस्था
3.8	प्रस्तावित विकास केन्द्र
3.9	वर्तमान एवं प्रस्तावित सेवा/विकास केन्द्रों पर वर्तमान एव प्रस्तावित सुविधाए/कार्य
4. Í	भूमि उपयोग (हेक्टेयर में)- ।990-9।
4.2	विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर मे - 1991
4.3	खरीफ एव रबी फसलों के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत वितरण ।990-9।
4.4	औद्यानिक फसल 1992-93
4.5	फसल प्रतिरूप मे परिवर्तन
4.6	फसल कोटि जनपद सोनभद्र - 1990-91
4.7	फसल गहनता सूचकाक
4.8	सिचाई
4.9	जोतों की सख्या एव आकार - 1991-92
4.10	पशुओ की सख्या 1988
5. I	क्लिकर एवं सीमेंट का उत्पादन
5.2	रिहन्द जल विद्युत गृह पिपरी - उत्पादन क्षमता एव उत्पादन वर्ष
5.3	रिहन्द जल विद्युत गृह - विद्युत उत्पादन
5.4	ओबरा जल विद्युत गृह- उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन वर्ष
5.5	ओबरा जल विद्युत गृह-विद्युत उत्पादन
5.6	ओबरा ताप विद्युत गृह-उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन वर्ष
5.7	ओबरा ताप विद्युत गृह-विद्युत उत्पादन
5.8	अनपरा ताप विद्युत गृह – विद्युत उत्पादन

5.9	नेपामास जार निकास कर करा है कर कार कर
	रेणूसागर ताप विद्युत गृह इकाई एवं प्रारम्भ वर्ष
5.10	रेणूसागर ताप विद्युत गृह विद्युत उत्पादन
6·1	सडक अभिगम्यता एव घनत्व
6 2	सडको की लम्बाई
6.3	पक्की सडक से बस्तियों की दूरी
6 4	नागपुर तथा बम्बाई योजनाओं द्वारा निर्धारित सडक अभिगम्यता मानदण्ड
6.5	Metalled Road Connectivity Matrix
6.6	जनपद मुख्यालय राबर्ट्सगज से प्रमुख सेवा केन्द्रों की दूरी
6.7	जनपद सोनभद्र में उपलब्ध सचार सेवाये 1991-92
6.8	गाँवों मे उपलबध सचार सेवाएं - 1991-92
6 9	गॉवो मे उपलब्ध सचार सेवाओं का प्रतिशत - 1991-92
7 1	साक्षर व्यक्ति एवं साक्षरता प्रतिशत ।99।
7 2	शैक्षिक विवरण 1991-92
7.3	जूनियर बेसिक विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एव विद्यालयों का अनुपात-1991-92
7.4	जूनियर बेसिक विद्यालय से बस्तियो की दूरी
7.5	सीनियर बेसिक विद्यालय में छात्र छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्र छात्राओं की
	संख्या ।991-92
7.6	सीनियर बेसिक विद्यालय में छात्रों विद्यालयों तथा शिक्षकों का अनुपात
7.7	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्र छात्राओ की
	संख्या - 1991-92
7.8	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय मे छात्रों छात्राओं तथा शिक्षकों का अनुपात
7.9	प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सा सुविधा - 1991-92
7.10	विकास खण्ड वार चिकित्सा सेवा

अध्याय ।

संकल्पनात्मक विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन का शोध विषय पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास- नियोजन ≬सोनभद्र जनपद का विशेष अध्ययन≬ न केवल राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है । उप्यूक्त शोध विषय मानव समाज के लिए एक समस्या बन गयी है जिसके समाधान हेत् अनेक स्तर्शे पर अनुसंधान, प्रयोग, सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा नयी-नयी योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है । यह समस्या न केवल वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों व प्रशासकों के लिए वरन् भूगोलिवदों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है । पिछड़ी अर्थ व्यवस्था व ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को खंडों में हल नहीं किया जा सकता । इसे तो समग्र रूप मे ही सुलझाना होगा । इस शताब्दी के प्रारम्भ तक कृषि उत्पादन और उसे मिलते-जुलते क्षेत्रों , जैसे पशुपालन, डेयरी, वन, मत्स्य-पालन के विकास और मानवीय सुविधाओं जैसे पीने का पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, गाँवों को विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने को ही विकास माना जाता था । आधुनिक समय में विकास के मानदण्डों में वृद्धि होने के बावजूद उपर्युक्त आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य बरकरार है । वास्तव में विकास की अवधारणा दिग्भ्रमित हो गयी है । स्मिथ² ने विकास की समस्या को विश्व की सबसे महत्वपूर्ण समस्या माना है । विकास के तीन स्तर अविकसित , विकासशील व विकसित काफी प्रचलित हैं किन्तु इसमें कोई स्पष्ट भेद नहीं है । इस प्रादेशिक असमानता को दूर करने के लिए संतुलित नियोजन का निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है । विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेत् उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि के अनुरूप विभिन्न विकास-योजनाओं की आवश्यकता होती है । प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य ध्येय पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर उसके लिए नियोजन की एक नीतिगत व्याख्या प्रस्तुत करना है।

। । विकास, प्रगति एवं संवृद्धि की अवधारणा

विकास, प्रगति और संवृद्धि शब्दों का प्रयोग प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है । परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों शब्द समानार्थी नहीं हैं । डडले सियर्स ने करीब 20 वर्ष पूर्व सम्भवतः लैटिन अमरीकी देशों के संदर्भ में लिखा था . 'ग्रोथ विदाउट डेवलपमेण्ट' अर्थात बिना विकास के वृद्धि । आधारभूत समस्या यह है कि यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन करने की कठिनाइयों की अनदेखी कर दी जाय तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सरल मापदण्ड बन जाएगी । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तूलना करने में त्रुटियाँ आ सकती हैं , परन्तु किसी देश में यह माना जा सकता है कि इस आकलन में दोष और किमयाँ निश्चित समय में एक जैसी ही रहेंगी । इस अवधारणा के आधार पर किसी निश्चित अवधि में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की बात कही जा सकती है । विकास में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि सिम्मिलित है, जबिक सैद्धान्तिक दृष्टि से यह कई और तत्वों पर भी आधारित है । प्रगति का क्षेत्र और भी व्यापक एवं विस्तृत है । इसमें विकास के साथ-साथ अन्य सामाजिक पहलू भी समाहित है । वृद्धि का अर्थ है आकलन किए जा सकने वाले तत्वों में बढ़ोत्तरी, विकास का अर्थ है आर्थिक परिवर्तन और प्रगति से अभिप्राय है सामाजिक परिवर्तन ।3

[अ] प्रगति और विकास

प्रगति का अभिप्राय वांछनीय परिवर्तन से है जिसमें इष्ट मूल्यों की पूर्ति होती है । जब हम प्रगति की चर्चा करते हैं तो हमारा संकेत केवल दिशा से ही नहीं है बल्कि किसी अन्तिम उद्देश्य और किसी आदर्श रूप में निर्धारित गन्तव्य स्थान की दिशा की ओर होता है । यदि सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन वांछित तरीके से होता है तो उसे प्रगति समझा जाता है । प्रगति एक

सापेक्षिक धारणा है, क्योंकि इसमें वर्तमान की तुलना भूतकाल की परिस्थितियों से की जाती है । इसके साथ ही एक निश्चित सामान्य पैमाने पर परिवर्तन का मूल्यांकन भी किया जाता है । अत. प्रासंगिक तुलनाओं से ही प्रगति का सही अनुमान हो सकता है । मूल्यांकन की कसौटियाँ आर्थिक , तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक लक्षण, गुण, और मानसिक विकास है । तकनीकी प्रगति सरलतम कसौटी है । उदाहरण के लिए इसमें मुद्रा अर्थव्यवस्था और संचार व्यवस्था को सिम्मिलित किया जाता है । परन्तु प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक या सामाजिक विकास के बीच निकट का सम्बंध है । उर्जा के कुल उत्पादन और समाज के रूपान्तरण को प्रगति के मूल्यांकन का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता । ऐसे मत के अनुसार सांस्कृतिक प्रगति प्रौद्योगिक परिर्तन की तुलना में गौण मानी जाती है । वास्तव में किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन या प्रगति दूसरे क्षेत्र से सम्बन्धित है और उस पर निर्भर भी है । अतः परिवर्तन एक जटिल प्रघटना है । 4

प्रगति की अवधारणा की तरह विकास की अवधारणा में भी वांछित दिशा मे परिवर्तन की ओर संकेत है । विकास की अवधारणा एक नूतन प्रघटना है , जबिक प्रगति की अवधारणा प्रबोध और औद्योगिक क्रान्ति से जुड़ी हुई है । विकास की प्रकृति संदर्भात्मक और सापेक्षिक है । प्रगति की प्रकृति सामान्य हं और औचित्यात्मक कारकों पर आधारित है । वांछनीय दिशा में नियोजित गुणात्मक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते हैं । विकास की धारणा सामाजिक - सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा राजनैतिक और भौगोलिक परिस्थित के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न पायी जाती है ।

विकास एक समिश्र अवधारणा है । क्षेत्र के विकास में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को गिना जाता है । विकास में समाज के कमजोर वर्गों , स्त्रियों और बच्चों , बेरोजगारों , बीमार और वृद्ध लोग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण को भी सम्मिलित करते हैं । विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण और

शहरी क्षेत्रों , अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, कृषि मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण का है । अत[.] विकास एक मूल्य-भारित अवधारणा है । यह एक समाज, क्षेत्र और जनता की सामाजिक , सांस्कृतिक , आर्थिक व भौगोलिक आवश्यकताओं में सम्बद्ध है । ⁵

विकास का अभिप्राय एक प्रघटना के पूर्णतर वृद्धिरूपी उद्विकास से हैं । मनुष्य का अपने पर्यावरण पर नियंत्रण विकास का ही उदाहरण है। विकास की अवधारणा इन सामान्य मान्यताओं के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कसौटियाँ भी हैं यथा आदिम कृषि अवस्था से औद्योगिक समाज की ओर समाज का उद्विकास तथा आर्थिक परिवर्तन । ज्ञान की वृद्धि तथा मनुष्य का अपने वातावरण पर नियंत्रण इन पहलुओं में निहित है । इस अर्थ मे सामाजिक विकास सामाजिक प्रगति का पर्याय है ।

बिं संवृद्धि एवं विकास

अधिंक संवृद्धि को हम एक ऐसी वृद्धि की दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो अत्यन्त निम्न जीवन स्तर में फॉसी हुई किसी अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था को अल्पावधि में ही ऊँचे जीवन स्तर तक पहुँचा सका । ⁶ कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक संवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का कुल राष्ट्रीय उत्पाद लगातार दीर्घकाल तक बढ़ता रहता है । ⁷ आर्थिक संवृद्धि से प्रायः यह अर्थ निकाला जाता है कि उत्पादन में समय के साथ कितनी वृद्धि हुई । दूसरी तरफ आर्थिक विकास की संकल्पना में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक व सामाजिक ढाँचे में क्या परिवर्तन हुए । इस प्रकार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा क्रमशः कम होता जाता है जबिक उद्योगों, सेवाओं, व्यापार, बैंकिंग व विनिर्माण का हिस्सा बढ़ता जाता है । इस प्रक्रिया में श्रमशक्ति की व्यावसायिक संरचना में भी परिवर्तन होता है तथा उसके कार्य कुशलता व उत्पादकता में वृद्धि होती है । अतः संवृद्धि परिवर्तन के

मात्रात्मक पहलू की ओर संकेत करती है जबिक विकास में मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी प्रश्रय मिलता है ।⁸

किंडलबर्गर के अनुसार जहाँ आर्थिक संवृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होता है , वहीं अर्थिक विकास से तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन की तकनीक, संस्थागत व्यवस्था, तथा वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है । आर्थिक संवृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है । आर्थिक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करके उसकी उत्पादकता व उत्पादन बढ़ाकर आर्थिक संवृद्धि की जा सकती है किन्तु आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साधनों की संरचना में परिवर्तन लाना अनिवार्य होता है और साथ ही उसके आबंटन में परिवर्तन लाना होता है जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके । इस प्रकार जहाँ आर्थिक संवृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय पर ध्यान देना पड़ता है वहीं आर्थिक विकास का अनुमान मुख्यत सरचनात्मक परिवर्तनों के आधार पर लगाया जाता है ।

साधारणतया पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि की प्रिकृया साथ-साथ चलती है , परन्तु यह आवश्यक नहीं है । प्रायः किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होता है किन्तु अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं होता है । कुजनेत्स का मत है कि आर्थिक संवृद्धि की अवस्था में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन (या आय) में भी वृद्धि होनी चाहिए । पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है , संसाधन सीमित हैं और तकनीकी विकास की प्रक्रिया पर विकसित देशों का प्रभुत्व है , वहाँ आर्थिक संवृद्धि के द्वारा गरीबी, बेरोजगारी का न तो निवारण हो सकता है और न ही सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है । फिर भी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक संवृद्धि भले ही पर्याप्त न हो किंतु आवश्यक अवश्य है । बिना आर्थिक संवृद्धि के आर्थिक विकास कदापि नहीं हो सकता तथा बिना आर्थिक संवृद्धि के व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन भी नहीं हो सकता ।

(स) क्रान्ति और विकास

क्रान्तियाँ अनेक प्रकार की होती है यथा राजनैतिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति व धार्मिक क्रान्ति आदि । यहाँ पर क्रान्ति से तात्पर्य ' विकास - क्रान्ति' से लिया गया है । क्रान्तिकारी विकास से अप्रत्याशित विकास होता है जबिक साधारण विकास मे विकास सतत् गतिशील होता है । क्रान्ति का अर्थ परिवर्तन के चरम स्वरूप से है। ¹⁰ यदि किसी समाज या क्षेत्र में इस तीव्र परिवर्तन से सामजस्य करने की क्षमता नहीं है तो उसके नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत होते है । कहा जाता है कि 'सोना पाना और खोना दोनों अपशकुन के सूचक है', इसका प्रतीकात्मक अर्थ यहीं है कि तीव्र परिवर्तन अच्छा नही होता है। क्रान्ति से तत्कालीन व्यवस्था मे बुनियादी परिवर्तन हो जाता है । वास्तव मे क्रान्ति का अर्थ तीव्र और आमुल परिवर्तन होता है। 11 विकास से धीमे परिवर्तन का बोध होता है । विकास से सतुलित विकास का भी बोध होता है । किसी समाज या क्षेत्र मे कुछ ऐसे जड तत्व होते है, जिनमे क्रान्तिकारी विकास की आवश्यकता होती है, वास्तव मे ये विकास प्रक्रिया की कुजी होते है जिन्हे तीव्र किए बिना अन्य विकास कार्य सम्पादित हो ही नही सकते । भारत के सदर्भ मे देखा गया है कि 'हरित क्रान्ति' के बाद कृषि आधारित उद्योगों का विकास स्वत. स्फूर्त था । मानव समाज के विकास मे क्रान्तियों ने एक आवश्यक भूमिका अदा की है । क्रान्तियों के बिना एक ही प्रकार की व्यवस्था सदा चलती रहेगी, भले ही वह समय की दृष्टि से अनुपयुक्त क्यों न हो । इसके फलस्वरूप कोई प्रगति नही होगी। 12

1.2 विकास की भौगोलिक अक्प्रारणा

मनुष्य अपने चेतन व गतिशील स्वभाव के कारण सभी प्राणियों से अलग है । वह अपने वर्तमान वस्तु - स्थिति से सन्तुष्ट न रहकर उसमें मनोवांछित परिवर्तन लाकर विकसित स्वरूप देखना चाहता है । वस्तुओं एवं घटनाओं का स्वरूप परिवर्तन ही विकास होता है । 13 परिवर्तन दो तरह का होता है - एक ऋणात्मक तथा दूसरा धनात्मक, विकास का सम्बन्ध धनात्मक परिवर्तन से होता है । 14 यह परिवर्तन भूतल पर अवस्थित किसी भी वस्तु-स्थिति से हो सकता है । अतः तथ्यात्मक सदर्भ मे विकास की परिभाषाओं का स्वरूप बदलता रहता है । विकास के अन्तर्गत भूतल पर अवस्थित सम्पूर्ण तथ्यों मे धनात्मक

परिवर्तन को ही सम्मिलित किया जाता है । मनुष्य ही सभी अध्ययनो का केन्द्र - बिन्दु होता है और मानव कल्याण मे वृद्धि ही भूगोल का मूल उद्देश्य रहा है । 15 अत के क्रिया - कलापो के विकास को ही, विकास की परिधि में सिम्मलित करना चाहिए । ये क्रिया - कलाप सामाजिक, आर्थिक एव सास्कृतिक स्वरूपों से सम्बन्धित हो सकते है । इन समस्त क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं का स्थान सर्वोपरि है किन्तु विकास का यह - सम्बन्ध केवल आर्थिक क्रियाओं से ही नहीं है । इसमे वातावरण की गुणवत्ता मे वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक, प्रगति के आधारभूत कारक सरचनात्मक एवं सस्थागत परिवर्तन को भी विकास के अन्तर्गत समाहित किया जाता है । वस्तुत विकास एक व्यावहारिक सकल्पना है, जिसका अभिप्राय प्रगति, उत्थान एव वाछित परिवर्तन से है । विगत वर्षों मे विकास से तात्पर्य आर्थिक क्षेत्र मे हुई प्रगति और सुधार से समझा जाता था, किन्तु आजकल इसका आशय जीवन के विविध क्षेत्रों मे हुए वाछित गुणाल्मक एव परिमाणात्मक परिवर्तनों से लिया जाता है । 16 इन्ही ध्यान मे रखकर ब्रहुम प्रकाश एव मुनीस रजा 17 ने विकास को कार्य अथवा कार्यो की एक श्रखला या प्रक्रम माना है, जो जीवन की दशाओं में शीघ्र ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सास्कृतिक तथा वातावरणीय सुधार करता है अथवा भविष्य मे जीवन की सभावना मे वृद्धि करता है या दोनो ही कार्य इसके द्वारा किए जाते है।

गुलतुग ¹⁸ ने विकास की नयी परिभाषा देते हुए बताया कि विकास का सिद्धान्त सामाजिक विषयों का वह क्षेत्र है, जहाँ भूतकाल का अध्ययन इतिहास, वर्तमान का अध्ययन समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल आदि तथा भविष्य का अध्ययन भविष्यशास्त्र एक साथ करते हैं । आर० पी० मिश्र ¹⁹ ने विकास का विश्लेषण करते हुए कहा है कि - विकास, समाज एवं अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक विस्तार के अतिरिक्त उनमें वांछित गित से वांछित विशा में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ - साथ मानव के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण से सम्बद्ध है, जिसमें सामियक, क्षेत्रीय तथा स्थानिक पहलुओं के साथ नियोजन का समन्वय देखा जाता है । विकास के विविध पहलुओं को देखते हुए आर० एन० सिंह ²⁰ ने लिखा है कि - विकास एक आदर्शीन्मुखी संकल्पना है, जिसमें सकारात्मक, प्रयोजनात्मक एवं वांछित सतत् उर्ध्वान्मुख परिवर्तन समाहित

1.3 आर्थिक विकास की अवधारणा

अर्थिक विकास पर न केवल भूगोलिवदों ने अपितु क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने भी बहुत अधिक काम किया है । आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक सवृद्धि की आवधारणा से अधिक व्यापक है । आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सवृद्धि की पूर्व दशा का होना अनिवार्य है । बीसवीं शताब्दी के मध्य के बाद से आर्थिक विकास की सकल्पनाओं को आर्थिक सवृद्धि की संकल्पना से भिन्न माना जाने लगा । विकास की प्रमुख समस्या गरीबी, सवृद्धि होने के बावजूद बढ़ती ही गयी । पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब - उल - हक 21 का कहना है कि विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मो पर सीधा प्रहार करना है । गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए । हमें यह सिखाया गया था कि कुछ राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इससे गरीबी का निवारण होगा । अब समय आ गया है कि हम इस सम्बन्ध को बदल दें । अब आवश्यकता इस बात की है कि हम मुख्यतया गरीबी पर ध्यान केन्द्रित करें । इसके माध्यम से राष्ट्रीय उत्पाद को अपने आप महत्व मिल जाएगा । दूसरे शब्दों में अब कुल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर पर कम और उसकी संरचना पर अधिक ध्यान देना जरूरी है । '

आर्थिक विकास से सम्बन्धित दो मुख्य विचारधाराएं है --

प्रथम परम्परागत विचारधारा है - जिसमें कुल राष्ट्रीय (या घरेलू) उत्पाद में 5-7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो, उत्पादन तथा रोजगार के परिवर्तन का स्वरूप इस प्रकार हो जिसमें कृषि का हिस्सा निरन्तर कम होता जाय और तृतीयक व विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाय । इस विचारधारा के अन्तर्गत कृषि के स्थान पर उद्योग को अधिक प्रश्रय दिया जाता है । कुल राष्ट्रीय या घरेलू उत्पाद में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि होने से शेष उद्देश्यों (गरीबी निवारण, आर्थिक असमानता में कमी और रोजगार अवसरों में वृद्धि आदि) को स्वत धीरे - धीरे प्राप्त कर लिया माना जाता है ।

व्यावहारिक रूप में देखने से पता चलता है कि जनसंख्या के अधिकांश भाग को आर्थिक संवृद्धि से कोई लाभ नहीं मिला और उनकी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। इसका बहुत से विद्वानों में इस परम्परागत विचारधारा को सशोधित करके आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी असमानता और बेरोजगारी का निवारण रखा है। इसके अन्तर्गत 'पुनर्वितरण के साथ संवृद्धि' (रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ) का नारा दिया है। इस सम्बन्ध में चार्ल्स पी0 किन्डलवर्गर और बूस हैरिक ²² का कहना है 'आर्थिक विकास की परिभाषा प्राय. लोगों के भौतिक कल्याण में सुधार के रूप में की जाती है। जब किसी देश में खासकर निम्न आय वाले लोगों के भौतिक कल्याण में बढ़ोत्तरी होती है, जनसाधारण को अशिक्षा, बीमारी और छोटी उम्र में मृत्यु के साथ-साथ गरीबी से छुटकारा मिलता है, कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय न रहकर औद्योगीकरण होता है जिससे उत्पादन के लिये प्रयोग होने वाले कारकों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है और आर्थिक तथा दूसरे प्रकार के निर्णयों में लोगों की साझेदारी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता है। इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि देश विदेश में आर्थिक विकास हुआ है'।

ब्रोगर²³ ने आर्थिक विकास का अर्थ बताते हुए कहा है कि इसके अन्तर्गत सामाजिक राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के सयुक्त प्रभाव को सिम्मिलत किया जाना चाहिये । माइकेल पीठ टोडेरो²⁴ विकास के स्वरूप को सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक सरचना एव विचारों के वांछित परिवर्तन मे बताते हैं। विकास मे न केवल आर्थिक पक्ष बिल्क सामाजिक, कल्याणकारी, मनावैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पक्ष भी आते है। इसीलिये स्मिथ ²⁵ ने लिखा है कि मानव के कल्याण में बृद्धि ही विकास है। आर्थिक विकास के उपर्युक्त व्यापक उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः आर्थिक विकास को निम्न रूपों मे जाना जाता है-

- (क) आर्थिक विकास एक ऐसी प्रिकिया है जिसके फलस्वरूप किसी क्षेत्र की जनसंख्या विशेषत निर्धन जनसंख्या के लिये अधिक अर्थपूर्ण सिद्ध हो सकें।
- (ख) आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य निर्धनता समाप्त करना है।
- (ग) आर्थिक विकास का तात्पर्य वास्तिविक आप मे दीर्घकालीन वृद्धि है, न कि अल्पकालीन वृद्धि जो कि व्यापार चक्रों में वृद्धि काल में व्यक्त होता है।
- (घ) आर्थिक विकास का लक्ष्य आर्थिक असमानता में कमी लाना है।
- (इ) आर्थिक विकास के कुछ अन्य लक्ष्य, विभिन्न क्षेत्रों के विकास एव समृद्धि

मे भारी अन्तरो को कम करना तथा अर्थव्यवस्था का विशाखन एव आधुनिकीकरण करना है।

यदि इनमें से एक या दो अथवा सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने मे हम असफल रहते है तो आर्थिक विकास कहना अनुपयुक्त होगा चाहे प्रति व्यक्ति आय दुगुनी ही क्यों न हो। ²⁶

1.4 संविकास (इकोडेवलपमेन्ट) की अवधारणा

किसी भी क्षेत्र का विकास स्तर मनुष्य और उसके वातावरण के सम्बन्ध पर निर्भर करता है। प्रारम्भिक विचारधारा यह थी कि मानव क्रियाकलाप प्राकृतिक वातावरण द्वारा नियन्त्रित होता है। संसार के विभिन्न भागों में एक समान प्रकृतिक वातावरण में एक प्रकार की मानव अनुक्रिया व विकास होने की आशा की जाती थी। किन्तु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास होने से यह ज्ञात होने लगा कि प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रभावित सीमाओं को पार किया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हथियार से मानव ने विकास के अनेक द्वार खोल दिये। इस क्रान्तिकारी विकास से पारिस्थितिक तन्त्र असतुलित नजर आ रही है। पुराणों में कहा गया है कि जब देवताओ एवं असुर्शें ने तेजी से समुद्र मन्थन किया तो अमृत कुण्ड के साथ विष कलश भी निकला किन्तु दुर्भाग्य यह है कि उस विष कलश को पीने वाले आज कोई 'शंकर' नहीं है, जिसका दुष्प्रभाव अधिकांशत. गरीब जनता को भुगतना पड़ता है।

वातावरण का विनाश सिर्फ आर्थिक विकास के कारण ही नहीं वरन् अत्यधिक निर्धनता का भी प्रतिफल है। 27 भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आने वाली समस्याये गरीबी व विकास के निम्न स्तर से जुड़ी हुयी है। हमारी विशाल आबादी और उसमे हो रही निरन्तर वृद्धि तथा विकास गतिविधियों के कारण पर्यावरण को जो क्षित पहुँच रही है, वह इतनी अधिक है कि इसके लिये सीधे आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रबन्ध को अब भारत में राष्ट्रीय विकास के लिये मार्ग निर्देशक तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह पता चलने पर कि गरीबी व विकास का निम्न स्तर देश की कई पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है यह तथ किया गया कि इससे निपटने के लिये विकास दर में वृद्धि करना ही सबसे अच्छी नीति रहेगी। यह विकास ऐसा हो जिससे लोगों को विशेष रूप से गरीबों को, उनकी मूल आवश्यकताओं और बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति कर लाभ पहुँचाया जा सके। लेकिन पर्यावरण समस्याओं की एक और श्रेणी उत्पन्न हो गयी है वे समस्याों स्वयं स्वयं

विकास की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का अनचाहा परिणाम है। ये नई समस्याये है, प्राकृतिक ससाधनों का कुप्रबन्ध, वनों का बड़े स्तर पर अंधाधुंध कटाई, कूड़े-कचरे और अवांछित पदार्थों का अनियोजित ढग से फेंका जाना, विषैले रसायनों का प्रचलन, रिहायशी गतिविधि का विस्तार तथा अधाधुध निर्माण कार्य आदि। 28

उपर्युक्त विवरण से लगता है कि विकास और पर्यावरण सरक्षण एक दूसरे के विरोधी है किन्तु वास्तविक अर्थों मे ऐसा नहीं है। यू०एन०ई०पी० के महासचिव मुस्तफा कमाल तोल्वा के शब्दों में. विगत 10-15 वर्षों में वातावरण एवं विकास के अन्तर्सम्बन्ध के प्रति हमारी अवधारणा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। 1960 के दशक तक सामान्यतया यह माना जाता था कि वातावरण संरक्षण एवं विकास एक दूसरे के प्रतिलोग है। यदि विकास करना है तो वातावरण की गुणक्त्ता के ह्रास के रूप में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अर्थात बिना वातावरण को क्षति पहुँचाये आर्थिक विकास असम्भव है परन्तु अब यह महसूस किया जाने लगा है कि ये दोनों तत्व परस्पर प्रतिलोम नहीं वरन् अन्योग्नाश्रित है। बिना वातावरण सरक्षण के विकास नहीं हो सकता और बिना विकास के वातावरण सरक्षण नही हो सकता।' विकसित देशों में पर्यावरण इास का कारण विकास की देन है तथा अल्पविकसित देशों में इसका कारण गरीबी है। परन्तु विकसित राष्ट्रों में पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की क्षमता है जबकि अल्पविकसित देश ऐसा करने में अक्षम है। अतएव विकास एव वातावरण सरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू है। यही संविकाश की अवधारणा है। संविकास का सामान्य अर्थ है, बिना विनाश किए विकास, इसे संधृत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट) अथवा ठोस विकास (साउन्ड डेवलपमेन्ट) की संज्ञा दी जाती है। संघृत विकास का उद्देश्य है- मानव समाज की विद्यमान मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना भावी पीढ़ियो की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को किसी प्रकार नुकसान पहुँचाये, सुनिश्चित करना। सक्षेप मे, संविकास ऐसा विकास है, जो सामाजिक दृष्टि से वांछित, आर्थिक दृष्टि से संतोषप्रद एव परिस्थितिकी दृष्टि से पुष्ट हो। ²⁹

1.5 विकास के निर्धारक तत्व

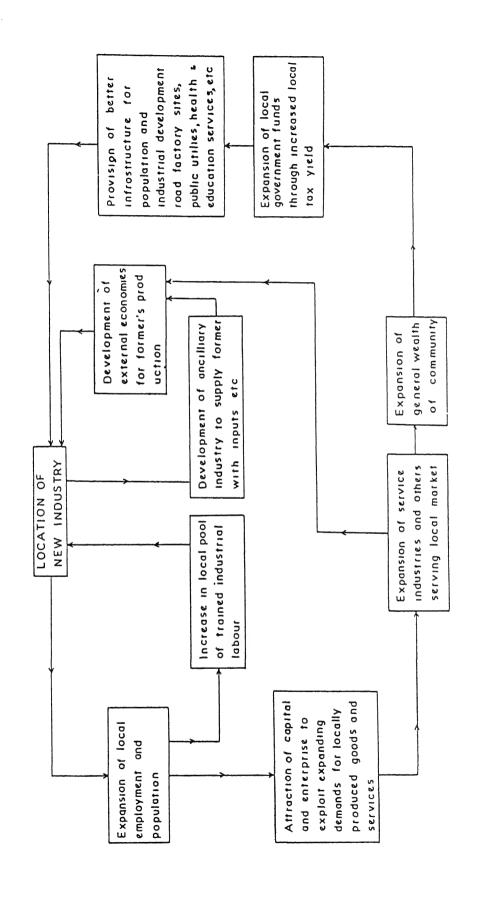
प्राकृतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थामें आर्थिक विकास के तीन आधारभूत प्राचल हैं, जिनके द्वारा विकास की दिशा तथा स्तर निर्धारित होता है। 30 किन्तु विकास की सकल्पना तथा विकास को निर्धारित करने वाले सूचको के सम्बन्ध मे मतभेद हैं । ये सूचक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समाज से दूसरे समाज तथा एक समय से दूसरे समय मे भिन्न - भिन्न हो सकते हैं । विकास स्तर के निर्धारण से सम्बन्धित एडेलमैन तथा मैरिश ³¹ ने राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों से सम्बन्धित 41 सूचकों का प्रयोग किया है । वर्तमान समय में विकास का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रस्थित में निरन्तर वृद्धि करना है । इस वृद्धि को किसी समाज की आवश्यक वस्तुओं के प्रयोग यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर से ज्ञात किया जा सकता है । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर हैगन ³² ने समाज एव व्यक्ति के कल्याण से सम्बन्धित ।। सूचकों का प्रयोग विकास के स्तर को निर्धारित करने मे किया है । सयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास शोध सस्थान ³³ (यू०एन०आर०आई०एस०डी०) ने 16 सूचकों को विकास के स्तर -निर्धारण मे उचित बताया है । बेरी ³⁴ ने 1960 मे आर्थिक विकास के विश्लेषण मे परिवहन, ऊर्जा का प्रयोग, कृषि उत्पाद, संचार, व्यापार, जनसंख्या तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्रमुख सूचकों के रूप मे प्रयुक्त किया है। इसके अतिरिक्त भी अनेद सूचक प्रयुक्त हुए है। किन्तु अधिकांश विद्वानों ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीकरण, रोजगार, संचार, परिवहन तथा जनसंख्या की संरचना, औद्योगीकरण आदि स्वकों का प्रयोग किया है।

1.6 विकास के सिद्धान्त

समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों तथा जीव विज्ञानियों ने विकास से सम्बन्धित अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । उनमें से भौगोलिक दृष्टिकोण से उपयुक्त कुछ प्रमुख सिद्धान्तों की संक्षिप्त व्याख्या निम्न है ।

मिरडल का क्यूमूलेटिव काजेश्वन मॉडल

मिरडल महोदय ³⁵ ने 1956 में विकास सम्बन्धी ' क्यूमूलेटिव काजेशन मॉडल ' प्रस्तुत किया (चित्र 1.1) जिसके माध्यम से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रादेशिक विभेदशीलता आर्थिक विकास का स्वाभाविक प्रतिफल होती है - क्योंकि एक प्रदेश बिना दूसरे को हानि पहुँचाए कभी भी विकास नहीं कर सकता है । इनके मॉडल से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास मुख्यत उन्हीं स्थानों पर केन्द्रित होता है जहाँ कच्चा माल एवं शक्ति के साधनों की



Source R J Chorly and P Haggett, Models in Geography Methuen

Fig. 1.1

उपलब्धि आसानी से होती है । उनके अनुसार किसी स्थान पर एक बार विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाने पर कार्यों के संचयी प्रभाव, केन्द्राभिमुखी शक्ति एव गुणक प्रभाव के कारण सतत् बढती जाती है । फलत. बढती हुई औद्योगिक इकाइयाँ द्वितीयक प्रकार की औद्योगिक अवस्थापना को जन्म देती है तथा केन्द्रीय प्रदेश का निर्माण होने लगता है । सामाजिक इकाइयाँ इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्वय पोषी आर्थिक वृद्धि होने लगती है । केन्द्रीय प्रदेशों की ओर अपेक्षया निर्धन क्षेत्रों से संसाधनों का आकर्षण बढ़ता जाता है जिसे मिरडल ने ' बैकवाश इफेक्ट ' कहा तथा इसके परिणाम स्वरूप अभिवर्धित केन्द्रीय प्रदेश से फैलने वाले सम्भावित विकास को ' स्प्रैड इफेक्ट ' की संज्ञा दी, जिसके माध्यम से अन्तत सम्पूर्ण प्रदेश का विकास होता है ।

इस प्रकार इन्होंने विकास की तीन अवस्थाओं का निरूपण किया । प्रथम अवस्था को प्रारम्भिक औद्योगिक स्थित कहा, जब प्रादेशिक असमानताएँ न्यूनतम होती है । द्वितीय अवस्था में सचयी कारक सर्वाधिक प्रभावित होते हैं । जिससे प्रदेश विशेष अन्य प्रदेशों की तुलना मे तीव्रगति से विकसित होता है तथा संसाधनों के वितरण मे असन्तुलन बढ़ने लगता है । तृतीय अवस्था में निस्तारण प्रभाव के कारण स्थानिक विषमताएँ कम होने लगती हैं ।

मिरडल महोदय के इस मॉडल की आलोचना इसके अत्यधिक गुणात्मकता को लेकर हुई, जिसके कारण यह मॉडल वास्तविकता से परे हो जाता है । इसके बावजूद विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के अन्तर को स्पष्ट करने मे यह मॉडल काफी सक्षम है । ³⁶

फीडमैन का केन्द्र - परिधि मॉडल

फीडमैन ने मिरडल के दो प्रदेशों की आर्थिक विषमताओं के स्थान पर स्थानिक रूप से विषमताओं का वर्णन किया है तथा विश्व को गतिशील प्रदेश, द्वुतगित से बढ़ने वाले केन्द्रीय प्रदेश तथा अल्पगित से अग्रसर होने वाले या स्थैतिक प्रदेशों में विभक्त किया है । फीडमैन के अनुसार क्षेत्रीय विस्तार में विकास के स्तर के परिप्रेक्ष्य में 4 संकेन्द्रीय कटिबन्ध देखे जा सकते हैं । 37

पहला प्रदेश - जिसकी अवस्थिति केन्द्रीय होती है - को इन्होंने केन्द्रीय प्रदेश कहा है । यह प्रदेश का वह क्षेत्र होता है जहाँ नगरीय औद्योगीकरण, उच्चस्तरीय तकनीक, विविध संसाधन तथा जटिल आर्थिक संरचना के साथ वृद्धि दर उच्च होती है । इस प्रदेश के परिधीय क्षेत्र में विस्तृत केन्द्रीय प्रदेश से प्रभावित ऊर्ध्वोन्मुख मध्यम् प्रदेश होता है जहाँ ससाधनों का अधिकाधिक उपयोग होता है, जन प्रवास बृहत् पैमाने पर होता है तथा आर्थिक वृद्धि स्थिर होती है । तत्पश्चात् परिधीय विस्तार में ससाधन युक्त सीमान्त प्रदेश होता है, जहाँ नूतन खनिजों के खोज एवं विदोहन हेतु नवीन अधिवासों का विकास होता है तथा उसकी सीमा में सवृद्धि की संभावनाएं विद्यमान होती हैं । केन्द्रीय प्रदेश से सुदूरतम् प्रदेश को उन्होंने अधोन्मुख प्रदेश कहा है, जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है तथा कृषि उत्पादन न्यूनतम होता है जो प्राथमिक संसाधनों की समाप्ति तथा औद्योगिक संस्थानों की क्षीणता के कारण सम्पन्न होता है। 'क्यूमूलेटिव काजेशन मॉडल' की ही भाँति इस मॉडल का भी प्रयोग आर्थिक एवं क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु किया जा सकता है।

रोस्टोव का आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का सिद्धान्त

यह सिद्धान्त विशेषत तकनीकी नवीनताओं को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रदेश में सामियक आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण करता है । रोस्टोव ने किसी क्षेत्र के विकास की निम्न 5 अवस्थाओं का निरूपण किया है । 38

- (क) रूढ़िवादी समाज,
- (ख) ऊपर उठने की पूर्व अवस्था,
- (ग) ऊपर उठने की अवस्था,
- (घ) चर्मोत्कर्ष प्राप्त करने की अवस्था तथा
- (ड) अधिकतम उपभोग की अवस्था ।

पहली अवस्था में इन्होंने रूढ़िवादी समाज की कल्पना किया है जिसका प्रधान व्यवसाय निर्वाहन कृषि है तथा संभाव्य संसाधनों की खोज नहीं हो पायी है । कुछ दशकों के बाद ऊपर उठने के पूर्व की अवस्था आती है जबिक अर्थिक वृद्धि तेजी से होती है और व्यापार विस्तृत होता है। वाह्य प्रभाव के कारण परम्परागत तकनीकों के प्रयोग के साथ - साथ नवीन तकनीकों का प्रयोग भी प्रारम्भ हो जाता है । तृतीय अवस्था ऊपर उठने की अवस्था आती है,

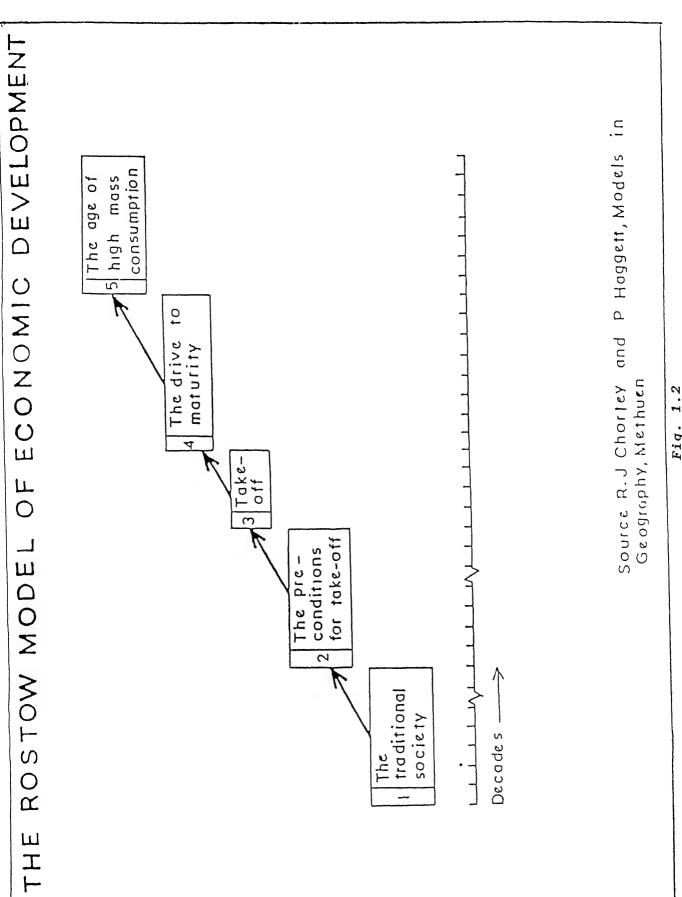


Fig. 1.2

जब प्राचीनता का प्रतिस्थापन नवीनता द्वारा हो जाता है तथा आधुनिक प्रौद्योगिकीयुक्त समाज का जन्म होता है, जिससे अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होती है, राजनीतिक एवं सामाजिक सस्थाओं में परिवर्तन होने लगता है तथा स्वय-पोषी एव स्वयं-सेवी वृद्धि आरम्भ हो जाती है। चतुर्थ अवस्था में समाज अत्यधिक सुसंगठित हो जाता है तथा पूंजी बढ़ने लगती है। कुछ पुरानी औद्योगिक इकाइयों का समापन नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण होने लगता है। वृहत् नगरीय क्षेत्र विकसित होने लगते हैं तथा यातायात- सचार व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो जाता है। चौथी अवस्था का चर्मोत्कर्ष पाचवी अवस्था है। उत्पादकता प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है। तकनीकी व्यवसाय में वृद्धि होने लगती है तथा भौतिकता में वृद्धि के साथ संसाधनों का वितरण सामाजिक कल्याण हेत् होने लगता है।

इस सिद्धान्त मे पूँजी निर्माण की विधि की व्याख्या की गयी है, किन्तु पाँच अवस्थाओं के अन्तर्सम्बन्ध को स्थापित करने वाले तन्त्र की व्याख्या नहीं की गयी है । इसके बावजूद यह साधारण तथा विकसित देशों के विश्लेषण में बहुत अधिक उपयोगी है किन्तु विकासशील देशों के विश्लेषण में यह प्रक्रिया संदिग्ध है । तृतीय विश्व के कई देश प्रथम तीन अवस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं ।

विकास-धृव सिद्धान्त

विकास ध्रुव संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1955 मे पेराउक्स ³⁹ महोदय ने किया । चूँिक पेराउक्स एक अर्थशास्त्री थे इसलिए इन्होंनें केवल आर्थिक तत्वों पर ही ध्यान केन्द्रित किया, भौगोलिक तत्वों की ओर इनका ध्यान नहीं गया । इस सिद्धान्त को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का श्रेय बोडिविले ⁴⁰ को है । विकास ध्रुवनीति के अन्तर्गत समस्या वाले क्षेत्र में एक या कई विकास ध्रुव चुन लिए जाते हैं और इन्हीं केन्द्रों पर नयी - नयी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है । इस सिद्धान्त में यह तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक व्यय अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होता है । विभिन्न सुविधाओं के पूंजीभूत होने से वहाँ स्वत स्फूर्त विकास उत्पन्न हो जाता है । केन्द्रित अर्थव्यवस्था से अवस्थापनात्मक कारक यथा सड़कें, शक्ति, जल, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का विकास हो जाता है । विकास ध्रुव सिद्धान्त में दो प्रमुख कठिनाइयाँ उत्पन्न

होती हैं । प्रथम विकास धुवों का चयन कठिन है तथा द्वितीय राजनीतिक दबाव के कारण चयन प्रिकृया और कठिन हो जाती है । बोदेविले ने इन विकास धुवों की पहचान प्रमुख केन्द्रीय बस्तियों के रूप में किया है जिनमें दूसरे बस्तियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है । उनके अनुसार उपलब्ध सुविधाओं की संख्या और क्षेत्रीय आकार में इन केन्द्रों के विभिन्न स्तर होंगे । इसमें सबसे बड़ा केन्द्र कृमश अपने छोटे केन्द्र को प्रभावित करेगा तथा अविकासत क्षेत्र इन केन्द्रों से लाभ उठा सकेगे । फलत सम्पूर्ण क्षेत्र विकास पिरिध में आ जाएगा । विकास की यह प्रक्रिया ट्रिकिल ड्राउन' तथा 'टाप डाउन' के नाम से भी जानी जाती है । विकास धुवों से विकास की ऐसी कृमबद्ध श्रृंखला बन जाती है जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में सतुलित विकास को गित मिलती है। इसके इन्हीं विशेषताओं के कारण नियोजकों में यह सिद्धान्त काफी लोकप्रिय है । विकास धुवों की अवस्थापना में, स्थान का चयन तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराने में धन की आवश्यकता, कभी - कभी इस सिद्धान्त के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं । वास्तव में विकास धुवों की उत्पत्ति का सहसम्बन्ध उस क्षेत्र के माँग व पूर्ति पर निर्भर करता है ।

1.7 नियोजन की संकल्पना

नियोजन और विकास एक दूसरे के पर्याय बन चुके है । सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए नियोजन का प्रविधि के रूप में इस्तेमाल विश्वव्यापी हो गया है । नियोजन का प्रयोग एव अर्थ विभिन्न क्षेत्रों, कालों एवं व्यक्तियों के संदर्भ में बदलता रहता है । इसीलिए फलूदी 41 ने नियोजन को बहुआयामी बताया है । उनके अनुसार नियोजन की सकल्पना व्यक्तिनिष्ठ, क्षेत्रनिष्ठ तथा तथ्यनिष्ठ है । जो व्यक्ति, क्षेत्र तथा तथ्य के संदर्भ में बदलती रहती है । फ्रीडमैन 42 के अनुसार नियोजन सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर विचार करने का भविष्य पर आधारित एक मार्ग है, जिससे समस्याओं के सामूहिक निर्णय के उद्देश्यों को नीतिगत कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । हिलहोस्ट 43 ने लिखा है कि - नियोजन निर्णय प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में व्याप्त अनेक क्रियाओं के मध्य आदर्श समन्वय स्थापित करना है । द्रोर 44 के अनुसार नियोजन ऐसे निर्णयों के निर्माण की प्रक्रिया है जिनको उपलब्ध ससाधनों द्वारा भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है । आर0 एन0 सिंह एवं अवधेश कुमार 45 के मतानुसार नियोजन से तात्पर्य किसी कार्य को सुचारू रूप

से सम्पन्न करने हेतु सुन्यवस्थित पद्धित के निर्माण करने की प्रिक्रिया से है । एम० एच० कुरैशी ⁴⁶ के अनुसार नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पहचान करना तथा ऐसी नीतियों का निर्धारण करना है जिससे उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । साध्य एवं साधनों के समन्वय द्वारा आर्थिक समस्याओं के उचित समाधान के लिए प्रयास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है ।

1.8 नियोजन क्यों ?

इस शताब्दी के आरम्भ में ही सर हारकोर्ट बटलर ने कहा था, 'अब हम सब समाजवादी हैं ।' किन्तु इस शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में यह कहना कही अधिक औचित्यपूर्ण है कि 'अब हम सब योजनाकार हैं ।' नि सन्देह अनेक व्यक्ति ऐसे होंगे जो स्वय को समाजवादी कहलाना पसन्द नहीं करेंगे किन्तु योजनाकार कहलाने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

नियोजन भारत के वैज्ञानिक युग की पद्धित - विशेष की समानार्थी हो गयी है । जब भी नियोजन शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका सामान्य अर्थ यही होता है कि नियोजन भविष्य के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था है । भविष्य के निर्णय भाग्याधीन पेरिस्थितियों के भरोसे छोड़ने के बजाय नियोजन की प्रविधि एक सुविचारित प्रयास है जिससे भविष्य का निर्माण करने वाली शिक्तयों को समझा जा सकता है और उन्हें इस प्रकार ढाला जा सकता है जिससे कि भविष्य के लिए व्यवस्था इस प्रकार की जाए जो हमारे अपने लक्ष्यो और इच्छाओं के अधिक अनुकूल हों । नियोजन से हम अपने वातावरण के प्रति असहाय आत्मसमर्पण करने की बजाय अपनी इच्छा शिक्त का प्रयोग कर सकते हैं । इस अर्थ में नियोजन विवेक की अन्धविश्वास पर, ज्ञान की अज्ञान पर और भाग्यवादी असहाय दशा पर सुव्यवस्थित पहल की सफलता की प्रतीक है । आधुनिक टेक्नालॉजी और संगठन से मनुष्य की अपने जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को समझने और उन्हे ढालने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, इसी कारण नियोजन टेक्नालॉजी और संगठन की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, इसी कारण नियोजन टेक्नालॉजी और संगठन की दासी है ।

अतः आज के प्रत्येक आधुनिक मानव या संस्थान या संगठन से यह अपेक्षा ठीक ही की जाती है कि वह अपने भविष्य के लिए नियोजन करे । इसका अर्थ यह है कि नियोजन आधुनिक समाज और अर्थ-व्यवस्था का एक विशिष्ट अंग बन गयी है । अत वर्तमान में नियोजन सुसंगठित सामाजिक कार्यों का एक अभिन्न अग बन गयी है, उसे देखते हुए समाज को आधुनिक और प्रगतिशील कहा जा सकता है । जान कैनेथ गालब्रिथ ने अपनी पुस्तक 'दी न्यू इन्डिस्ट्रियल स्टेट' में एक नए औद्योगिक समाज में नियोजन के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है । आधुनिक टेक्नालॉजी में वस्तुओं के उत्पादन में नवीनता लाने के लिए धन और साधनों की बहुल मात्रा में और लगातार आवश्यकता रहती है । केवल उत्पादन में ही नहीं बल्कि विपणन में भी, अति सतर्क और विस्तृत अनुसधान व नियोजन के बिना काम नहीं चल सकता । बौचेट के शब्दों में, 'नई आवश्यकताओं के जन्म लेने से पहले उनको पूर्य करने के साधनों पर विचार किया जाना चाहिए और इस दिशा में अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए । सभी पश्चिमी देश ऊर्जा के क्षेत्र में अपने पूर्व - अनुमान और कार्यक्रम बीस वर्ष पहले बनाते है । ऊर्जा की आपूर्ति की सामान्य दरे पन्द्रह वर्ष से भी पहले लगाई पूर्जी पर निर्भर करती है । पूर्जी निवेश के यह मानक परिमाण लोहा और स्टील उद्योग, रासायनिक उद्योग तथा अन्य तेजी से विकसित हो रही शाखाओ पर भी लागू होते हैं । इन सभी उद्योगों में उत्पादन आरम्भ होने की अनुमानित तिथि से पहले ही अधिक धन की आवश्यकता होती है ।'

अधुनिक प्रबन्धन की तकनीक - एक उद्यमी की सफलता के लिए नियोजन एक पारपत्र (पासपोर्ट) बन गया है । अधुनिक प्रबन्धन में यह एक प्रथम और महत्वपूर्ण तकनीक है । नियोजन का अभाव तैयारी का अभाव है, अत यह असफलता का मार्ग है। विकास के अन्योन्याश्रय के कारण पूर्वानुमान अर्थ-व्यवस्था के किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता है वरन् उसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है । फिर भी अर्थशास्त्री नियोजन शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं करते हैं । भविष्य के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था की, नियोजन के अर्थ में कोई विवाद नहीं है । दूसरी ओर, पहले भी और आज भी अर्थशास्त्रियों सामाजिक विचारकों और नीति - निर्धारकों द्वारा नियोजन का जो अर्थ लिया गया है, वह एक विवादास्पद विषय रहा है । उस विशेष अर्थ में नियोजन से तात्पर्य है किसी व्यक्ति या निजी संस्थान द्वारा की गयी नियोजन का स्थान राज्य द्वारा की गयी नियोजन द्वारा लिया जाना है । इस प्रकार नियोजन का तात्पर्य उस अर्थ - व्यवस्था से है जो मुक्त नीति का विकरण है।

राज्य द्वारा नियोजन का उद्देश्य है, व्यक्तियों या निजी संस्थानों, उपभोक्ताओं, उत्पादकों और कार्यकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णयों पर इस प्रकार प्रभाव डालना जिससे कि वे सब राष्ट्र के योजनाकारों द्वारा पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं या लक्ष्यों के अनुकूल हो सके। इस विशिष्ट अर्थ में नियोजन विभिन्न विचार - धाराओं, विभिन्न वादों और विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पद्धतियों के अर्थशास्त्रियों सामाजिक विचारकों और दलों के बीच, वाद -विवाद का विषय बन गया है।

मानव कल्याण हेतु मरीबी को समाप्त करना - अन्तिम रूप से विश्व के प्रगतिशील देशों में नियोजन गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने और जितना शीघ्र सम्भव हो सके, आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन लाने की एक प्रविधि है । अत नियोजन की संकल्पना और मूलाधार उस विचारधारा पर निर्भर करेगा जिस पर चर्चा की जा रही हो । नियोजन की इन विभिन्न संकल्पनाओं मे नियोजन के बारे मे सामान्य धारणा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भविष्य के लिए सुनियोजित व्यवस्था से है ।

नियोजन में यद्यपि अनेक प्रकार के व्यक्ति विश्वास रखते हैं, चाहे वह विभिन्न अर्थो में हो, फिर भी विचारकों का एक दल ऐसा भी है, जो नियोजन में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है, वे सोचते हैं कि नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन असम्भव है, व्यवहार्य नहीं है और वह निश्चित रूप से असफल रहता है । इनमें ल्यूडबिंग, बान माइसिज और फॉदर बॉन हैंक आते हैं । प्रत्येक आर्थिक प्रणाली के पास मूलभूत आर्थिक प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए । ये प्रश्न हैं - किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, किस प्रकार उत्पादन करना है, उत्पादन कब करना है, उत्पादन कहाँ और क्यों करना है, अन्तिम प्रश्न सम्भवत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंिक यह आर्थिक अभिकरण की मूलभूत समस्या से सम्बद्ध है ।

1.9 योजना प्रक्रिया के विभिन्न चरण

परम्परागत नियोजन प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण आवश्यक हैं -

वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण - इस चरण के अन्तर्गत वर्तमान
 दर्जे का आँकलन करना, उसकी समस्याओं का पता लगाना और विकास के लिए उपलब्ध अवसर्शे

का पता लगाना शामिल है । इसमें वर्तमान साधनों के परिमाण का पता लगाना भी समाहित है ।

- 2. उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारण लक्ष्यों का निर्धारण मोटे तौर पर समाज की समस्याओं और अवसर्शे पर तथा साधनों की वर्तमान एवं भावी स्थिति पर निर्भर करता है । फिर भी लक्ष्य निर्धारण का अर्थ है यह तय करना कि कौन से उद्देश्य पूरे करने है ।
- 3. नीति और नीति निर्माण इस चरण में मुख्य रूप से साधनों के विश्लेषण के परिणामों का प्रयोग होता है और इसका निर्धारण योजना के भौतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों पर निर्भर करता है । वैसे उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई नीतियाँ बनायी जा सकती है, परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की क्षमता और अवसरों की तुलना की जाए और यह आंका जाए कि क्या निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किये जा सकेंगे ।
- 4. कार्यक्रम और परियोजनाओं का पता लगाना इस चरण में उन कार्यक्रम और परियोजनाओ का पता लगाया जाता है, जो योजना के उद्देश्यो और लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
- 5. साधन आवश्यकता आंकलन इसमें चुने हुए कार्यक्रमों और योजनाओं की लागत का अनुमान लगाया जाता है और योजना में तय की गयी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन जुटाने के साधनों का पता लगाया जाता है।
- 6. चरणबद्धता और क्रियान्वयन इस चरण में परियोजना के क्रियान्वयन का कार्यक्रम तय किया जाता है तथा इसके लिए प्रशासनिक दायित्व निर्धारित किया जाता है । इसमें परियोजना क्रियान्वयन के लिए समन्वय कार्य भी बनाया जाता है । इसके लिए परियोजना से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है ।
- 7. निगरानी और आंकलन इस चरण के अन्तर्गत योजनाविध में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजना की प्रगति पर बराबर निगाह रखना शामिल है । परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है ।

मूल्यांकन या आंकलन का अर्थ है योजना के उद्देश्यो और लक्ष्यो की उपलब्धि का विश्लेषण योजना के विभिन्न चरणों में आंकलन किया जाता है, यथा मध्याविध मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन आदि । इससे क्रियान्वयन की अविध में आने वाली कठिनाइयो का पता चलता है और सफलता या असफलता के कारणों को भी जाना जा सकता है । अंतिम आंकलन में तो भावी योजनाओं के लिए दिशा निर्देश भी प्राप्त हो सकते हैं ।

1.10 नियोजन का स्वरूप

नियोजन का स्वरूप बहु-आयामी है, इसकी विशेषताओं एव उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, कई वर्गों में विभक्त किया जा सकता है । पश्चिमी देशों में बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नियोजन पद्धित प्रचिलत है, पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित नियोजन पद्धित प्रचिलत थी तथा भारत जैसे अनेक विकासशील देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नियोजन प्रणाली प्रचिलत है । प्रों0 आर0 पीं0 मिश्र 47 ने अवधि के आधार पर आर्थिक नियोजन एव विकास नियोजन, संगठनात्मक दृष्टि से आदेशात्मक एव निर्देशात्मक नियोजन, नियोजन एव विकास नियोजन, संगठनात्मक दृष्टि से आदेशात्मक एव निर्देशात्मक नियोजन, नियोजन प्रक्रिया की दृष्टि से मानकीय नियोजन एव पद्धितशील नियोजन, तत्वों के आधार पर प्रकल स्तरीय नियोजन एवं बहुस्तरीय नियोजन के रूप में विभाजित करने का प्रयास किया है । लेकिन नियोजन की प्रणालियां अन्य अनेक प्रकार से भी वर्गीकृत की गयी हैं, जैसे व्यापक नियोजन अथवा आश्रिक नियोजन, आवश्यकताजनित अथवा प्रेरित नियोजन, अधिनायकवादी अथवा लोकतांत्रिक नियोजन, क्षेत्रीय या स्थानिक योजना, भौतिक अथवा वित्तीय योजना, परिप्रेक्ष्य अथवा दीर्घावधि योजना, अल्प अवधि अथवा वार्षिक नियोजन ।

1.11 विकास नियोजन

कई पूर्व निर्धारित और सुनिश्चित सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजिनक सत्ता द्वारा सोच समझकर बनाए जाने वाले आर्थिक कार्यक्रम को ही विकास नियोजन कहते हैं । प्रो0 वाटरसन ने नियोजन की परिभाषा इस प्रकार की है - 'यह विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों के चयन का चेष्टापूर्वक और निरन्तर प्रयास है । इसमें दुर्लभ और कम उपलब्ध साधनों को कम लागत पर उपलब्ध करमा भी शामिल है । विभिन्न समाजों ने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया है । यह समाजवादी हल तक सीमित नहीं है । यह लोकतान्त्रिक और पूँजीवादी देशों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और वहाँ इस्तेमाल होता भी है ।"

नियोजन आर्थिक विकास का एक उपयुक्त साधन है । आर्थिक विकास लक्ष्य है तथा नियोजन एक मार्ग । नियोजन का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जो भविष्य मे आने वाली समस्या के समाधान के लिए की जाती है । असीमित आवश्यकताएँ और सीमित साधन, नियोजन को आवश्यक बना देती हैं । इसमे साधनों का विवेकपूर्ण आबटन प्राथमिकता के निर्धारण के आधार पर किया जाता है । व्यक्ति द्वारा नियोजन व्यष्टिवादी तथा सरकार द्वारा नियोजन समष्टिवादी होता है ।

कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था मे उपलब्ध साधनों का पूर्ण ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण उपभोग के लिए सुव्यवस्थित एवं नियन्त्रित कार्यक्रम होना चाहिए।

नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश के प्राकृतिक और जनशिक्त साधनों का उपयुक्त ढंग से उपयोग करके तेजी से आर्थिक विकास करना है । इस समय विश्व के लगभग सभी विकासशील देश तीन गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे है, वे हैं - गरीबी, असमानता और बेरोजगारी । भारत सिहत अनेक विकासशील देश इन समस्याओं से निपटने के लिए नियोजन अपना रहे हैं।

विकास नियोजन के आवश्यक पहलू निम्न है -

- विकास प्राथमिकताओं के सावधानीपूर्वक चयन द्वारा साधनों का न्यायसंगत
 आवंटन,
 - 2. अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं पर आधारित पूर्व निर्धारित लक्ष्य,
- 3. नियोजन का दायित्व और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में समन्वय के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण,
 - 4. लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त विकास नीति का चयन,
- योजना लागू करने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाना और उन्हें
 प्रयोग करना ।

- 6. पूर्ण क्रियान्वयन और
- 7. निश्चित अवधि

भारतीय योजना आयोग के अनुसार नियोजित विकास के निम्न 5 उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं : -

- ।. राष्ट्रीय आय मे अधिकतम वृद्धि
- तीव्र औद्योगीकरण एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना
- 3. रोजगार के अवसरों में अधिकतम वृद्धि,
- 4. आय की असमानताओं को कम करना, तथा
- 5. समावादी राज्य की स्थापना

इसके अतिरिक्त विभिन्न आर्थिक योजनाओं के अन्तर्गत नियोजन के भिन्नभिन्न उद्देश्य थे। सामान्यतः नियोजन को विकास का पर्याय माना जाता है। नियोजनसभी वस्तुएं सभी के लिए 48 का उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक एवं संस्थानात्मक परिवर्तन न किये जाय। विकास की प्रकृति
को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने अल्पाविध तथा प्रखण्डगत नियोजन को आर्थिक नियोजन
कहा है जबिक समाज एवं अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक एवं सस्थानात्मक परिवर्तन से सम्बन्धित
नियोजन को विकास-नियोजन कहा है। 49 आर्थिक नियोजन विकासत राष्ट्रों की ऐसी अर्थव्यवस्था
के लिये होता है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक स्थित सुदृढ़ हो चुकी है तथा उस
स्थिति को बनाए रखने की समस्या है। विकास नियोजन तृतीय विश्व के अल्पविकसित
राष्ट्रों के लिए आवश्यक है जहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं आय कम है, औद्योगिक विकास
नहीं हुआ है तथा जीवन स्तर अति निम्न है। 50

1.12 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

हाल के वर्षों में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के लिए सकल नियोजन पर जोर देने की बजाए विशेष क्षेत्रों के लिये सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर बल दिया जाने लगा है। इसे विकेन्द्रित नियोजन या एकदम निचले स्तर से नियोजन भी कहा जाता है और इसका आशय होता है जिला, विकास खण्ड और गाँव जैसे क्षेत्रों के लिए योजना बनाना। इसमें और राष्ट्रीय नियोजन में यहीं अन्तर है कि सूक्ष्म स्तर की योजना में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं

को ध्यान मे रखा जाता है जबिक राष्ट्रीय क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान मे रखकर किया जाता है । राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नियोजन के स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करने मे असफल सिद्ध हो जाने के बाद ही सूक्ष्म स्तर की योजनाए बनाना शुरू किया गया । इसमें अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र के लिये योजना बनायी जाती है जिससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नियोजन की किमयाँ नहीं रह पाती।

सूक्ष्म स्तरीय आयोजन देश के विकास प्रयासों में एक नया आयाम है और इसे निचले स्तरसे विकास की नीति भी कहा जा सकता है। इसीलिए विकास की नीति के रूप में स्थानीय स्तर के आयोजन में स्थानीय समस्याएं हल करने, स्थानीय साधन जुटाने और योजना बनाने और लागू करने की प्रक्रिया में लोगों को सम्मिलित करने के प्रयास किए जाते है। इसमे उन मानकीकृत चरणों और प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया जाता जो वृहद् स्तरीय आयोजन में अपनायी जाती है।

(अ) सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से लाभ

- 1. सूंक्ष्म स्तरीय नियोजन का एक बड़ा लाभ तो यह है कि योजनाकारों और साधारणजनों के बीच निकट का सम्पर्क स्थापित होता है। इसी कारण सूक्ष्म स्तर के नियोजन में मानवीय पहलू और जन साधारण की जरूरतों पर अधिक ध्यान रहता है। इसलिए जहाँ बृहद स्तर की योजना बनाने वालो का ध्यान शायद सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने पर रहता है, वही स्थानीय स्तर के योजनाकारों का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण आवास आदि स्थानीय समस्याओं पर होता है जो स्थानीय लोगों के लिये अधिक आवश्यक और वास्तविक होती है। राष्ट्रीय आयोजक तो जनसाधारण को प्रतिशत भर बनाकर छोड़ देते है, उसे मनुष्य समझकर नहीं चलते।
- 2. सूक्ष्म स्तर का नियोजन कुल नियोजन से अधिक प्रभावी इसलिए भी होगा क्योंकि यह अपेक्षाकृत छोटे समूह के लिए रहता है जिससे समूचे देश के सदर्भ मे विधिता बहुत कम होती है ।
- 3. सूक्ष्म स्तर का नियोजन एक समूह-क्षेत्र की ज्ञात आवश्यकताओं पर आधारित होता है, जबिक वृहद् स्तरीय नियोजन में बहुधा स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी हो जाती है। क्योंिक वहाँ राष्ट्रीय लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं।

- 4 चूंकि सूक्ष्म स्तरीय आयोजन नीचे से शुरू होता है अत इसमे लोगो को शामिल करने और क्रियान्वयन मे उनका सहयोग प्राप्त करने के अधिक अवसर रहते है।
- 5 माइक्रो स्तरीय नियोजन मे सतुलित क्षेत्रीय विकास को बढावा मिलता है जिससे आय और रोजगार के वितरण मे क्षेत्रीय असमानताए दूर करने मे मदद मिलती है।
- 6 आजकल अन्तर-क्षेत्रीय और अन्तर सामूहिक आर्थिक असमानताए समाप्त करने के उद्देश्य से स्थान-विशेष और समूह विशेष के लिए विकास कार्यक्रमों की माँग बढ रही है और इनके लिए सूक्ष्म स्तर की योजना ही सार्थक सिद्ध हो सकती है।

(ब) भारत में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

संतुलित बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के तन्त्र के रूप मे सूक्ष्म नियोजन का महत्व देश मे योजना-प्रक्रिया के आरम्भ होने के समय से ही स्वीकार कर लिया गया था। निरन्तर हर योजना मे इसे अपनाने की वकालत भी की जा रही है। पहली पचवर्षीय योजना मे भी राज्य की योजना के अन्तर्गत ही जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तरीय योजना बनाने के महत्व पर जोर दिया गया था। इसे दूसरी पचवर्षीय योजना मे भी जारी रखा गया और जिला स्तर पर चलायी जाने वाली कुछ गतिविधियो की योजना बनाई गयी। तीसरी योजना मे माइक्रो स्तरीय आयोजन के महत्व पर बल दिया गया और राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे विकास खण्ड और जिले को विकास की इकाई मानकर योजनाए बनाए।

इन सब प्रयासों के बावजूद चौथी पचवर्षीय योजना मे यह अनुभव किया गया कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन आरम्भ नहीं हो पाया है और राज्य स्तरीय योजना बनाने की परम्परागत प्रिकृया में राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों की विविध परिस्थितियों और समस्याओ पर ध्यान देना सभव नहीं हो पा रहा है।

इसलिए विभिन्न क्षेत्रो, समुदायों और परिस्थितियों की आकांक्षाओ तथा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना आवश्यक समझा गया तथा वर्तमान साधन क्षमता का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त उपायों का पता लगाया गया। अत फिर कहा गया कि जिला स्तर पर माइक्रो स्तरीय योजना बनाई जाए क्योंकि इस स्तर पर ऐसे अधिकारी उपलब्ध

हो सकते थे जो स्थानीय लोगो की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बना सकते थे, इन्हे स्थानीय पिरिस्थितियों की पूरी-पूरी जानकारी थी। परन्तु इस बात पर भी बल दिया गया की जिलों की योजनाए बनाते समय राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा जाए और जहाँ जरूरी हो वहाँ क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, खड और बाजार स्तर की योजनाए भी बनाई जाए।

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए योजना आयोग ने पहल की और दिशा निर्देश निर्धारित किए। उन योजनाओं की सूची तैयार की गयी जिन्हे जिला स्तर पर चलाया जा सकता था। इसके लिए योजना आयोग के दिशानिर्देश सुझावों के रूप में थे और राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता थी। अधिकाश राज्य इस सदर्भ में विवरण नहीं एकत्रित कर पाए और फलस्वरूप सूक्ष्म स्तरीय नियोजन लागू नहीं किया जा सका इसलिए योजनातन्त्र को, विशेषकर राज्य स्तर पर, मजबूत करना जरूरी हो गया। इसे देखते हुए योजना आयोग ने राज्यों के योजना विभागों को योग्य और कुशल तकनीकी कार्यकर्ता उपलब्ध कराया।

पाचवी पचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही गरीबी बेरोजगारी और सामाजिक असमानता की समस्याओ पर अधिक ध्यान दिया गया और ये योजना प्रक्रिया का मुख्य केन्द्र बिन्दु भी बन गई। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए योजना तन्त्र और निर्णय प्रक्रिया को इस स्तर पर लाना जरूरी समझा गया जहाँ लोगों की समस्याओं का पता लगाकर सिक्रिय सामुदायिक सहयोग से इन्हें हल करने के प्रयास किए जा सके।

स्थित की माँग को देखते हुए क्षेत्रीय विकास के कई विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए और उनके क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञ एजेंसिया गठित की गयी। इनके साथ ही गरीबी रोकने और क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों को लागू करने, बुनियादी न्यूनतम जरूरते पूरी करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रयासो के विकेन्द्रीकरण की जरूरत महसूस की गयी। इसलिए इस स्तर पर खण्ड स्तरीय आयोजन को ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज करने का माध्यम समझा गया क्योंकि इसमे रोजगार के और आय जुटाने के स्थानीय साधनो का अधिकतम उपयोग किया जा सकता था और साथ ही स्थानीय समस्याएं हल करने पर ध्यान दिया जा सकता था। यह विश्वास था कि विकासखण्ड अपने छोटे क्षेत्रीय आकार और कम जनसख्या के कारण योजनाएं और कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने में एक आदर्श इकाई बन सकता था।

इससे पहले राज्य स्तर पर नियोजन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए योजना आयोग ने एक योजना का निर्माण किया 51 किन्तु जिला सतर पर नियोजन के निर्देश इससे भी पहले 1969 में दिए जा चुके थे। 52 1978 से 1983 की अवधि में विकास खण्ड स्तर पर नियोजन का विकास किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्य-क्रम को स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा सुदृढ़ बनाना था। 53 नवम्बर 1977 को विकास खण्ड स्तर पर नियोजन' हेतु गठित 'दातावाला कमेटी' ने निम्न सुझाव दिया 54 -

- । कृषि एव सम्बन्धित क्रियाये
- 2 गौण सिचाई
- 3 मदा सरक्षण एव जल-प्रबन्ध
- 4 पशुपालन एवं मुर्गी पालन
- 5 मत्स्य पालन
- 6 वानिकी
- 7 कृषि उत्पादों का प्रक्रमण
- 8 कृषि उत्पादन में साधनों की पूर्ति
- 9 कुटीर एव लघु उद्योग
- 10 स्थानीय सुविधा आधार
- ।। सार्वजनिक सुविधाए यथा

पेय जल आपूर्ति

स्वास्थ्य तथा पोषण

शिक्षा

आवास

सफाई

स्थानीय परिवहन

जनकल्याण कार्यक्रम

12 स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण तथा स्थानीय जनसख्या के कौशल मे वृद्धि

यद्यपि खण्ड स्तरीय योजना मूलरूप से व्यापक योजना थी जिसे स्थानीय साधनों के आकलन के आधार पर बनाया जाना था फिर भी यह रोजगार जुटाने के लिए चलाई गई योजनाओं और लाभकर्ताओं तक ही सीमित रह गई सीमित खण्ड योजना बनाने का कारण था, खण्ड स्तर पर कुशल तकनीकी कार्यकर्ताओं का अभाव, माइक्रो योजनाओं के लिए योग्य एव कुशल कर्मचारियों की नितान्त कमी को देखते हुए निर्णय लिया गया कि विकास खण्ड स्तर पर योजनाए बनाने के लिए जिला - स्तर पर नियोजन एकक बनायी जाय ।

छठी पचवर्षीय योजना के शुरू मे की गई समीक्षाओं से पता चला कि सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन के लिए समताए बहुत ही कम थी। अत सही प्रक्रियाओं और उपयुक्त ढोंचे की खोज होनी चाहिए थी। इस दिशा मे जिला नियोजन सबधी कार्यदल ने 1982 मे एक धीमी पहल अपनाने की वकालत की । इसके बाद योजना आयोग ने जिला स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण लागू करने के उपाय प्रारम्भ किए । इसकी प्रतिक्रिया मे कई राज्यो ने राज्य योजनाओं के विभाज्य प्रावधानो को जिले के लिए हस्तान्तरिक कर दिया और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के उपाय लागू कर दिए । जिला स्तर पर नियोजन तन्त्र को मजबूत बनाने की केन्द्रीय योजना भी शुरू की गई और चुने हुए अधिकारियो को जिला और विकास खण्ड नियोजन का प्रशिक्षण दिया गया।

इन सबके बावजूद सातवीं पचवर्षीय योजना में नियोजन के विकेन्द्रीकरण के लिए समुचित तन्त्र उपलब्ध नहीं हो सका और प्रशासन बराबर कमजोर बना रहा जबिक ग्रामीण विकास के अनेक नए कार्यक्रम शुरू होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अन्य विभागीय कार्यक्रमों के साथ उनका सामजस्य स्थापित करना भी जरूरी हो गया था तािक जिला और विकास खण्ड स्तर के नियोजन के लिए प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण लागू हो सके। इसिलए सातवी योजना में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को बढावा देने के कई उपाय अपनाए गए। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

1.13 स्थानवद्ध नियोजन

स्थानवद्ध नियोजन की रचना, क्षेत्र विकास की धारणा पर आधारित होती है। प्राकृतिक और आर्थिक पहलू किसी क्षेत्र को लाभप्रद स्वरूप प्रदान करते है और उसी के कारण वहाँ पर आर्थिक कार्यकलाप विकसित होता है। इस प्रकार योजनाकारों ने महानगरीय क्षेत्रों, नदी-घाटी क्षेत्रों और औद्योगीकरण क्षेत्रों, भौगोलिक समूहों, उत्खनन क्षेत्रों, जल-सगृह क्षेत्रों, बाढ़ नियन्त्रण आदि क्षेत्रों को अलग-अलग बताया है। कितपय सजातीय व्यवस्थाए यथा जल मृदा-प्रकार परिवहन व्यवस्थाएं आदि ऐसे क्षेत्रों को क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक नियोजन तैयार करने

के लिए उपयुक्त इकाइया बना देती है।

यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे क्षेत्रों की सीमाए प्रशासिनक सीमाओं के अनुरूप हो, नदी क्षेत्र अथवा मिट्टी की किस्मों की कोई कृत्रिम सीमाए नहीं होती है। अत एक नयी धारणा बन रही है कि वर्तमान प्रशासिनक सीमाओं से मिले-जुले क्षेत्रों के लिए स्थानबद्ध योजनाए बनाने की अपेक्षा नियोजन के क्षेत्र निर्धारित कर दिए जांय और उनके लिए क्षेत्र योजनाए तैयार की जाय । ऐसे नियोजन क्षेत्रों की कुछ विशेषताए भी है। ये आर्थिक कार्यकलाप के प्रसार केन्द्र बन जाते है। कभी-कभी इन्हे विकास केन्द्र अथवा केन्द्रीय क्षेत्रों की भी सज्ञा दी जाती है।

क्षेत्रीय विज्ञान के अध्ययन के पता चलता है कि विकास का केवल एक ही बिन्दु नहीं होता, इसकी पूरी श्रृखला होती है। विकास बिन्दुओं की श्रुखला में सबसे नीचे एक समूह की तरह जुड़े कितपय गाँव और समुदाय होते हैं। उसके बाद दूसरे केन्द्रीय स्थानों का समूह एक ऊँचे स्तर के विकास केन्द्र के इर्द-गिर्द एक तारामण्डल का रूप ले लेता है। क्षेत्रीय योजना अथवा स्थानबद्ध योजना में किसी सम्पूर्ण क्षेत्र के आर्थिक कार्यकलापों के लक्ष्यों की चर्चा करने के अतिरिक्त उन आर्थिक गतिविधियों को व्यक्त करना चाहिए जो विकास केन्द्रों की श्रृखला और उनसे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से जुड़ी हो। इसी से नियोजन को स्थित सम्बन्धी दिशा मिलती है और उनके क्रियान्वयन में वास्तविकता की प्राप्ति होती है।

1.14 पिछड़ी अर्थव्यवस्था की संकल्पना

पिछड़ी अर्थव्यवस्था की उपयुक्त परिभाषा देना कठिन है। फिर भी इसे दरिद्रता, अज्ञानता अथवा रोग की स्थिति द्वारा, राष्ट्रीय आय के कुवितरण द्वारा, प्रशासनिक अक्षमता द्वारा तथा सामाजिक विघटन द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। ⁵⁵ पिछडे (बेकवर्ड) और दिर्द्ध (पुअर) शब्द अल्पविकसित के पर्यायवाची मानकर भी प्रयोग किए जाते है। ⁵⁶ प्रस्तुत अध्ययन मे पिछडी अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थो मे किया गया है। साधारणतया पिछड़ी अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थों में किसी क्षेत्र के मात्र आर्थिक तन्त्र के लिए किया जाता है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी भोगोलिक परिदृश्य के समष्टि या समन्वित रूप में किया गया है, जिसमें आर्थिक तत्वों के साथ-साथ भौगोलिक तथ्यों को समाहित किया गया है। मानव के सम्पूर्ण क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं का विशेष महत्व है क्योंकि अन्य

क्रियाओ पर आर्थिक क्रियाओ का प्रभाव होता है। अत प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध विषय में भौगोलिक शब्द पिछडा क्षेत्र' की जगह पिछडी अर्थव्यवस्था' शब्द का प्रयोग किया गया है।

क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय विभेदशीलता तथा पिछडापन के अर्थों मे भी पर्याप्त विभेद है । स्मरणीय है कि सामान्य तौर पर क्षेत्रीय असतुलन, क्षेत्रीय विभेदशीलता तथा पिछडेपन का प्रयोग एक ही अर्थ मे किया जाता है किन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय असतुलन तथा क्षेत्रीय विभेदशीलता का दृष्टिकोण जहां अत्यधिक व्यापक है वही दूसरी ओर पिछडेपन का प्रयोग इसके एक अश के रूप मे किया जाता है। जहां क्षेत्रीय असन्तुलन व क्षेत्रीय विभेदशीलता का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के तीनों चरणों (अविकसित - विकासशील तथा विकसित) से है, वही पिछडेपन का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के मात्र प्रथम चरण (अविकसित) से है। किन्तु कुछ सन्दर्भों मे इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था के द्वितीय चरण (विकसित) मे भी किया जा सकता है।

विकास की भांति पिछडी अर्थव्यवस्था' की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है बिल्क यह एक तुलनात्मक विचार है। सामान्यतया पिछडेपन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उस स्वरूप से, जो उस क्षेत्र में रहने वाले या उस समाज में रहने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सके। अर्थव्यवस्था के पिछडेपन की तीव्रता का अनुमान ऐसी लोगों जिनकी निम्नतम् आवश्यकताए भी पूर्ण नहीं हो पाती है - की सख्या पर निर्भर करता है। ऐसी दशा का आविर्भाव किसी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तम्भ - कृषि एवं औद्योगीकरण के पिछडेपन के कारण होती है। इस पिछडेपन का कारण भौतिक तथा सास्कृतिक संसाधनों का अविकसित होना है। भौतिक संसाधनों से तात्पर्य किसी स्थान विशेष के उच्चावच्च, खनिज, जलवायु, मृदा अपवाह, प्राकृतिक वनस्पति व जीव जन्तु से है तथा सास्कृतिक संसाधनों से तात्पर्य मानव के सम्पूर्ण क्रिया-कलापों से है। भौतिक तथा सास्कृतिक संसाधनों के पिछडेपन के आधार पर पिछडी अर्थव्यवस्था निम्न प्रकार की हो सकती है -

- । भौतिक रूप मे पिछड़ी अर्थव्यवस्था
- 2. अशत भौतिक रूप से पिछडी अर्थव्यवस्था
- 3 सांस्कृतिक रूप से पिछडी अर्थव्यवस्था
- 4 अशत सास्कृतिक रूप से पिछडी अर्थव्यवस्था
- 5 भौतिक एव सास्कृतिक रूप से पिछडी अर्थव्यवस्था
- भौतिक तथा अञ्चतः सांस्कृतिक रूप से पिछडी अर्थव्यवस्था

7 अशत भौतिक तथा सास्कृतिक रूप से पिछडी अर्थव्यवस्था

भौतिक रूप से पिछडी अर्थव्यवस्था मे उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ की जलवायु जीव जन्तुओ एव मनुष्यो के स्वास्थ्य, क्रियाकलाप एव व्यवसाय के प्रतिकृल हो, उच्चावच्च इस प्रकार हो जहाँ कृषि, बागवानी, निर्माणकार्य के प्रतिकृल हो वन-ससाधनों व खनिज ससाधनों की अल्पता हो। उपर्युक्त सभी तथ्य अर्थव्यवस्था के विकास के आधार स्तम्भ है, जिनके अभाव मे विकास प्रक्रिया सचालित नहीं हो सकती। उपर्युक्त आधारभृत तत्वों के अभाव मे यदि पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो अर्थव्यवस्था और जटिल तथा पिछड़ेपन का शिकार हो जाती है।

सास्कृतिक रूप से पिछडी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक ससाधन तो प्रचुरमात्रा में होते हैं किन्तु मानव प्रबन्धन की कमी के कारण अर्थव्यवस्था पिछडी दशा में रहती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में विकास की सभाव्यता रहती है। मानव प्रबन्धन में सुधार करके ऐसी अर्थव्यवस्था को दीर्घ अविध में विकसित किया जा सकता है।

भौतिक एव सास्कृतिक रूप से पिछडी अर्थव्यवस्था मे क्षेत्रो का भौतिक या सास्कृतिक रूप मे विकास करने की सम्भावना कम होती है।

भौतिक एव सास्कृतिक दृष्टि से अंशत पिछडी अर्थव्यवस्था मे सभी सास्कृतिक एव भौतिक ससाधनो की अशत कमी पायी जाती है ।

भौतिक तथा सास्कृतिक रूप में अश्रत पिछडी अर्थव्यवस्था में भौतिक संसाधनों का अभाव अवश्य होता है किन्तु सास्कृतिक संसाधन में अश्रत कभी पायी जाती है। इसी प्रकार कुछ अर्थव्यवस्थाओं में सास्कृतिक संसाधन का पूर्णतया अभाव पाया जाता है किन्तु भौतिक संसाधनों में अश्रत कभी पायी जाती है।

यह एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है कि किसी क्षेत्र के भौतिक एव सास्कृतिक दोनो प्रकार के पिछड़े संसाधनों में, किसमें सर्वप्रथम सुधार करना आवश्यक होता है। चूंिक सास्कृतिक संसाधनों के विकसित होने पर भौतिक संसाधनों का पिछडापन श्रीष्ठ दूर हो जाता है इसलिए सास्कृतिक ससाधन को सर्वप्रथम विकसित करने की आवश्यकता है।

1.15 पिछड़ेपन का कारण

जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति निम्न आय, कृषि की प्रधानता, तकनीकी पिछडापन, भयकर बेरोजगारी, भुगतान सतुलन की बिगडती स्थिति तथा औद्योगीकरण का प्रभाव देश के सम्मुख कुछ ऐसी चुनौतियों है जो भारत को पिछड़ेपन के धरातल पर लाकर खडा कर दिया है। वैयक्तिक आर्थिक विषमताए तथा शहरो एव गाँवों मे वितरण की असमानता पिछडेपन के अन्तर को और बढा देती है। भारत के पिछड़े क्षेत्रों का मूल कारण न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक भी है। जिनमे प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता, अकुशलता, दृढ निर्णय का अभाव तथा सामाजिक रूढिवादिता, अधविश्वास, भाग्यवादिता के अतिरिक्त बाजार की अपूर्णताए, निर्धनता का दुश्चक्र, पूँजी निर्माण की निम्न दर, आधारभूत सरचना, का अभाव, उद्यमशीलता एव प्रबन्धकीय योग्यता का अभाव, प्राकृतिक ससाधनों का अभाव, प्राकृतिक स्रोतों के उचित सर्वक्षण एव सर्वित्तम उपयोग का अभाव और दोषपूर्ण सरकारी नीतिया रहे है। 57

स्वतन्त्रता पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था के पिछडेपन का सम्बन्ध तत्कालीन राजनीतिक स्वरूप व औपनिवेशिक तन्त्र से गहन रूप से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण पिरणाम यह था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई तथा कृषि प्रधान थी। इसकी आर्थिक सरचना अपेक्षाकृत उन्नत देशों से विपरीत थी। जनसंख्या का 70% से अधिक भाग कृषि में लगा हुआ था जिसका राष्ट्रीय आय में 60% से अधिक योगदान था। कृषि में जनसंख्या के अधिकाश भाग का नियोजित होना और उसमें (कृषि में) लोगों की संख्या व प्रतिशतता में लगातार बृद्धि या उनमें (जनसंख्या) में कमी न होना पिछड़ी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। ब्रिटिश शासन के शोषक व विभेदकारी नीतियों के कारण सदियों में सुस्थापित भारतीय दस्तकारी का कुछ ही वर्षों में पतन हो गया, जिससे जनसंख्या का एक बड़ा भाग रोजी-रोटी की खोज में कृषि की ओर उन्मुख हुआ। इस प्रक्रिया के अनवरत चलते रहने के कारण कृषि व जमीन पर दबाव बढा, परिणामस्वरूप भूमि का विखण्डन हुआ, कृषि व उद्योग का सम्बन्ध टूट गया। इस प्रकार कृषि का उद्देश्य मात्र भरण-पोषण होने के कारण सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पिछडेपन का शिकार हो गयी।

गैर कृषि क्षेत्र की सरचना परिवर्तित होकर छोटी व असतुलित हो गयी। उद्योग के नाम पर कृषि उपज के परिष्करण हेतु हल्के उद्योग थे न कि आधुनिक धातुकार्मिक, इजीनियरिंग गृहिनर्माण सामग्री, रसायन व खनिज तेल उद्योग। जहाँ अन्य देशो मे औद्योगिक क्रान्ति हुई वहाँ भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश बना रहा। भारतीय ससाधनों से ब्रिटिश औद्योगीकरण को गित मिली। भारत ब्रिटेन के लिए कच्चे माल कानिर्यातकर्ता तथा विनिर्मित सामान का बाजार केन्द्र बन गया। परिणामस्वरूप भारत शेष विश्व से लगातार पिछड़ा गया। उपर्युक्त विवरण से किसी देश के पिछडेपन का ज्ञान हो जाता है किन्तु किसी देश के अन्तर्गत किसी क्षेत्र विशेष के पिछडेपनकाकारण सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पद्धित न अपनाना तथा असमान नियोजन पद्धित है।

1.16 पिछड़ी अर्थव्यवस्था के मापदण्ड

पिछडी अर्थव्यवस्था का निर्धारण अनेक कारकों को ध्यान मे रखकर किया जाता है। किन्तु सामान्यतया प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति निम्न उत्पादन, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक पिछडापन, उपभोग की अधिकतम दर, बचत व पूंजी की कमी, जनसख्या का अत्यधिक दबाव तथा वृद्धिदर, रोजगार की अल्पता तथा औद्यागिक पिछडापन इत्यादि किसी भी पिछडी अर्थव्यवस्था के प्रतिबिम्ब है। साथ ही किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के पिछडेपन का निर्धारण निम्न तथ्यों के सदर्भ में दिया जा सकता है। 58

- । प्रति व्यक्ति आय
- 2 कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एव जनजातियों का प्रतिशत
- 3 कृषि भूमि जनसख्या अनुपात
- 4 कृषि में सलग्न जनसंख्या
- 5 ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात
- 6 परिवहन सचार तथा अन्य सेवाओं की उपलब्धता
- 7 जल विद्युत तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता, तथा
- 8 साक्षरता का स्तर

पिछडी अर्थव्यवस्था के उपर्युक्त तथ्यों मे केवल सास्कृतिक पक्ष को ही समाहित किया गया है। सांस्कृतिक तथ्यों मे भी क्रियाशील जनसख्या अनुपात तथा आश्रित ज़नसख्या अनुपात जैसे अनिवार्य तथ्य को समाहित नहीं किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक तत्वों को जो किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के पिछडेपन लिए कही अधिक महत्वपूर्ण है, की अवहेलना की गयी है। अत पिछडी अर्थव्यवस्था के निर्धारण में उक्त तथ्यों के साथ क्रियाशील जनसंख्या अनुपात, आश्रित जनसंख्या अनुपात, जलवायु, उच्चावच्च, जल-संसाधन, वन व खनिज आदि संसाधनों की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पिछडी अर्थव्यवस्था के निर्धारण में दो और संमस्याए है।

पहला, पिछडेपन के निर्धारण हेतु लिए गए मानदण्डों की सीमा क्या हो ? अर्थात किसी तथ्य से सम्बन्धित वह कौन सा देहलीज (श्रीशोल्ड) या औसत (एवरेज) हो जिसके ऊपर रहने पर क्षेत्र विकसित कहा जाय तथा नीचे रहने पर पिछडा कहा जाय। मापदण्डों के लिए निर्धारित मानक सीमा राष्ट्रीय औसत हो या विश्व औसत या राज्य औसत या योजना अयोग द्वारा समय - समय पर निर्धारित मानदण्ड हो।

दूसरी समस्या, पिछडेपन के निर्धारण हेतु क्षेत्र के स्तर की सीमा से है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के निर्धारण मे तुलनात्मकता पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरणार्थ यदि किसी विकास खण्ड के पिछडेपन का निर्धारण करना है तो वह तहसील जनपद किमश्नरी, राज्य तथा राष्ट्र में से किसकी तुलना में ज्ञात किया जाय? भारत के सदर्भ में यह क्षेत्र सम्पूर्ण राष्ट्र हो सकता है या योजना आयोग द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय स्तर हो सकता है।

उपर्युक्त दोनों ही तथ्यों के निर्धारण में कोई सुविचारित क्तिनुष्ठ प्रक्रियां न होकर एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके निर्धारण के बावजूद किसी अर्थव्यवस्था के पिछडेपन की वास्तिवक तस्वीर उभर कर नहीं आती है क्योंकि इससे मात्र क्षेत्रीय विषमता ही आभाषित होती है। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम होगा, समान वातावरणीय दशाओं के विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन। अर्थात किसी क्षेत्र के सम्बन्धित क्रियाओं का कितना प्रतिशत भाग विकसित किया जा चुका है तथा कितना प्रतिशत विकसित किया जाना शेष है, ज्ञात करना। सम्बन्धित क्षेत्र की कुल सम्भाव्यता का यदि 50% से कम विकसित किया गया है तो वह क्षेत्र नितान्त पिछड़ा कहा जाएगा और यदि सम्भाव्यता का 50-75% भाग विकसित किया गया है जा उसे विकासशील तथा 75% से अधिक विकसित प्रदेश को विकसित कहा जा सकता है किन्तुउपर्युक्त आंकडों पर बहुत अधिक बल नहीं दिया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों के पिछडेपन का निर्धारण आकडो की अनुपलब्धता तथा सीमित अविध के कारण सभव नहीं है। अध्ययन क्षेत्र पर सामान्य दृष्टियात करने से ही सोनभद्र के पिछडेपन का आभास हो जाता है। सोनभद्र की अर्थव्यवस्था भौतिक रूप से अशतः तथा सास्कृतिक रूप से पूर्णत पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था है। योजना आयोग⁵⁹ तथा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक परिषद⁶⁰ द्वारा प्रयुक्त मानदण्डों के अनुसार सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश ही पिछडे क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। अत द0पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित नवीन सोनभद्र जनपद भी पिछडी अर्थव्यवस्था का एक मानक प्रतिरूप है।

1.17 पिछड़े क्षेत्रों की पहचान

पिछडे क्षेत्रों की पहचान एव उनके विकास को प्रोत्साहन देने हेतु योजना आयोग ने 1968 में दो कार्यकारी दलों की नियुक्ति की थी। प्रथम, पिछडे क्षेत्रों की पहचान के लिए श्री बींंग्डीं। पाण्डे तथा द्वितीय पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए मौद्रिक एव वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु श्री एनंग्णिंग वॉंग्च्यू की अध्यक्षता में कार्यकारी दलों का गठन किया। इन आयोगों ने पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के आधार और उनमें उद्योगों की स्थापना के लिए मौद्रिक एव वित्तीय प्रोत्साहन देने की सिफारिशों का आधार प्रस्तुत किया था। वर्तमान में 1983 की संशोधित नीति के अनुसार पिछड़े राज्यों, जिलों तथा क्षेत्रों को औद्योगिक विकास के लिए अनुदान एव आर्थिक सहायता की दृष्टि से परिभाषित किया गया है। इस नीति के अनुसार पिछडे क्षेत्रों, जिलों को विकास के स्तर के आधार पर तीन वर्गों में बाटा गया है यथा 'अ' श्रेणी, 'ब' तथा 'स' श्रेणी के जिले।

वर्तमान समय मे भारत 25 राज्यों एव 7 केन्द्रशासित प्रान्तों मे विभाजित है। भारत के 25 राज्यों को 463 जिलों तथा 7 केन्द्र शासित प्रान्तों को 20 उपजिलों एव 4 जिलों मे विभाजित किया गया है। इनमे आय एव उद्योगों की दृष्टि से 267 जिले तथा 20 उप जिले पिछडे हुए है। भारत के असम, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पजाब, तामिलनाडु, कर्नाटक तथा गुजरात विकसित एव गोवा, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालेण्ड व मणिपुर पूर्ण रूप से पिछडे हुए राज्य है, जबिक आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमांचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगाल, मिजोरम तथा राजस्थान के आधे से अधिक जिले पिछडे हुए हैं। दूसरी ओर भारत के 7 केन्द्र शासित प्रान्तों में केवल दिल्ली

प्रान्त ही विकसित है, शेष 6 प्रान्त पूर्ण रूप से पिछडे हुए है। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत के 299 जिले पिछडे हुए है, जिनमे 131 जिले श्रेणी 'अ', 55 जिले श्रेणी 'ब' तथा 113 जिले श्रेणी 'स' मे आते है, जो सम्पूर्ण जिलो का 20 26% है। अर्थात भारत के कुल क्षेत्रफल का 70% व कुल जनसंख्या का 56% भाग पिछडे क्षेत्रों में आता है। 61

पिछडेपन को दूर करने तथा क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए, संविधान की धारा 280 के अधीन, प्रति पाच वर्ष मे एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ससाधनों के अतरण के लिए आयोग द्वारा अपनाए गए जनसंख्या और अन्य मापदण्ड तथा प्रविधिया पिछडे राज्यों के पक्ष मे गई है। पिछडे क्षेत्रों मे पूँजी निवेश व औद्योगिक अवस्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह स्वीकार किया गया है कि क्षेत्रीय पिछडापन एक क्षेत्रीय समस्या है। और इसका समाधान क्षेत्र की दृष्टि से ही हो सकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए पिछडे क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाए बनायी जाती है। है

संदर्भ

- । सिंह,इकबाल भारत में ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 1986, पृष्ठ 2.
- 2 Smith, D.M.: Human Geography: A Welfare Approach,
 Arnold Heine Mann, London, 1984.
- 3 दत्त, भवतोष वृद्धि, विकास और प्रगति, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय, नई दिल्ली, 15 अगस्त 1987, पृष्ठ 6.
- 4 शर्मा, के0एल0 भारतीय समाज, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ 153
- 5 वहीं, पुष्ठ 154
- 6 मिश्र, एस0के0 एव पुरी, वी0के0 भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पिन्लिशिग हाऊस, बम्बई, 1991, पृष्ठ 4
- 7 Meir, G.M. and Balduin, R.E.. Economic Development: Theory, History and Policy, New York, 1957, p.2.

- 8. Drewnowski, J.. On Measuring and Planning the Quality of Life, Mounton, The Haque, 1974, p.95.
- 9. Kuznets, S.· 'Towards a Theory of Economic Growth', in R.Lekachman (ed), National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad, p 16.
- 10 पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 4, पृष्ठ 151
- 11. देव, अर्जुन सभ्यता की कहानी (2), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 178
- 12. वहीं, पृष्ठ 179
- 13. मिश्रा, बी०एन० विकास एक वैज्ञानिक धार्मिक सन्दर्भ, भू-सगम,
 2 (।), इलाहाबाद ज्योग्राफिकल सोसायटी, इलाहाबाद, 1984 पृष्ठ ।-16
- 14 Qureshi, M.H.. India. Resources and Regional Development, NCERT, New Delhi, 1990, P. 81.
- 15. पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 2
- 16. सिंह, आर0एन0 एव कुमार, ए० 'भारतीय नियोजन प्रणाली एव ग्रामीण विकास एक समीक्षा, भू-सगम, 2 (।), इलाहाबाद ज्योग्राफिकल सोसायटी इलाहाबाद, 1984, पृष्ठ 17-24
- 17. Prakash, B. and Raya M.: Rural Development 'Issues to Ponder', Kurukshetra, 32(4), 1984, pp 4-10.
- 18. तिवारी, आर0सी0 तथा त्रिपाठी, एस0 'समन्वित ग्रामीण विकास भौगोलिक दृष्टिकोण', ग्रामीण विकास . संकल्पना, उपागम एव मूल्याकन (स0), सिंह, पी0 एवं तिवारी, ए0, पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र इलाहाबाद, 1989, पृष्ठ 48 64.
- 19. Mishra, R.P., Sundram K.P. and Prakas Rao,
 V.L.S. Regional Development Planning in
 India: A New Stretegy, Vikas Publishing House,
 New Delhi, 1974, p.189.

- 20. Singh, R.N. and Kumar, A 'Spatial Reorganisation. Concept and Approaches', National Geographer, 18 (2), 1983, pp. 215-226.
- 21. Haq, Mahbub ul, "Employment and Income
 Distributin in the 1970s A New Perspective",
 Pakistan Economic and Social Review, June
 -December 1971, p. 6.
- 22. Kindleberger, C.P. and Herrick, B. Economic Development (New York, 1977) p. 1.
- 23. Broger, D.: 'Central Place System, Regional Planning and Development in Developing Countries: Case of India', in Transformation Habitat in India Perspective, Geographical Dimention, (ed) Singh, R.L. and Rana, P.B.S. National Geographical Society of India, B.H.U., Varanasi 1978, pp. 134-164.
- 24. Todaro, M.P. Economic Development in the Third World, New York, Longman Inc 1983, p.70.
- 25. पूर्वोक्त संदर्भ सख्या 2
- 26. Seers, Dubley: "The Meaning of Development",

 Eleventh World Conference of the Society

 for International Development (New Delhi
 1969), p.3.
- 27. सिंह, जगदीश वातावरण नियोजन एव सिवकास, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, 1988. पृष्ठ 242

- 28. भारत, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 1988 89, पृष्ठ 142
- 29. पूर्वीक्त सदर्भ सख्या 27, पृष्ठ 242-46
- ³⁰. पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 14, पृष्ठ 81
- 31. Adelmn, I. and Merris, C.T.: Society, Politics and Economic Development, Boltimore, The John Hopkins, 1967.
- 32. Hagen, E.E.: 'A Framework for Analysing Economic and Political Development', in Robert Asher, (ed) Development of Emerging Countries, Washingtion D.L., Bookings Institution, 1962, pp. 1-38.
- 33. United Nations Research Institute for Social

 Development: Contents and Measurements of

 Social Economic Development, Geneva, Report

 No. 70.10, 1970.
- 34. Berry, B.J.L.: 'An Inductive Approach to the Regionalization of Economic Development', in N.Ginsburh (ed), Essays on Geography and Economic Development, Research Paper 62, Department of Geography' University of Chicago, 1960.
- 35. Myrdal, G.: Economic Theory and Underdevelopment, London, 1957.
- 36. Keeble, D.: 'Models of Economic Development',
 in R.J. Chorley and P.Haggette, Models in
 Geography, London, Methuen, 1967.

- 37. Friedman, J. The Urban-Regional Frame for National Development', International Development Review, 1966.
- 38. Rostow W.W.: The Stage of Economic Growth,
 London, Cambridge University Press, 1962,
 p.2.
- 39. Perroux, F.: 'La Nation De Croissance', Economique Applique, Nos. 1 and 2, 1955.
- 40. Boudeville, T.R.: Problem of Regional Economic Planning, Edinburgh University Press, 1966.
- 41. Faludi, A.: Planning Theory, Pergamon Press, Oxford, 1973.
- 42. Friedman, J · 'The Concept of Planning Regions,
 The Evolution of an Idea in the United States',
 Reprinted in J. Friedman and W Alonso (ed),
 Regional Development and Planning, A Reader,
 the M.I.T. Press, 1958.
- 43. Hill Horst, J.G.M. Regional Planning A
 Systems Approach. Rotterdam University Press,
 1977.
- 44. Dror, Y.: 'The Planning Process A Facet Design', International Review of Administrative Science, 29(1), 1963.
- 45. पूर्वीक्त सदर्भ संख्या, 20
- 46 कुरैशी, एम0एच0 भारत संसाधन और प्रादेशिक विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1990 पृष्ठ 118

- 47. पूर्वीक्त संख्या 19
- 48 Gillingwater, D.: Regional Planning and Social Change, A Responsive Approach, Saxon House, 1975, p.1.
- 49. पूर्वीक्त संख्या 19
- 50. पूर्वीक्त संख्या 35
- 51. Singh, A.K.: Planning of the State Level in India, Commerce Pomphlet 25, 1970, p.29.
- 52. Planning Commission,: Guidelines for the Formulation of District Plans, 1969, pp. 1.2, (U.P.Government edition).
- 53. Vaishnav, P.H. and Sundram, K.V.: Integrating

 Development Administration at the Area Level,

 in Planning Commission, Report of the Working

 Group on Block Level Planning, 1978, p 2.
- 54. वही
- 55. Keenleyside, H.L.: 'Obstacles and Means in

 Internation Development' in Dynamics of

 Development, (ed) G. Hambridge, P.8.
- 56. The United Nations Experts on Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries Wrote. 'An Adequate Synonymn for Underdeveloped Countries would be poor countries' p.3.
- 57. योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना एव प्रसारण मत्रालय, नई दिल्ली,

- 58. Chand, M. and Puri V.K. Regional Planning in India, Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1983, p.331.
- 59. Government of India, Planning Commission.

 Report of the Working Group on Identification of Backward Area, New Delhi, 1969
- 60. National Council of Applied Economic Pesearch

 Techno-Economic Survey of Uttar Pradesh,

 New Delhi, 1965.
- 61. पूर्वोक्त संदर्भ संख्या, 54
- 62. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, जून 1985, पृष्ठ 53

अध्याय 2

अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि

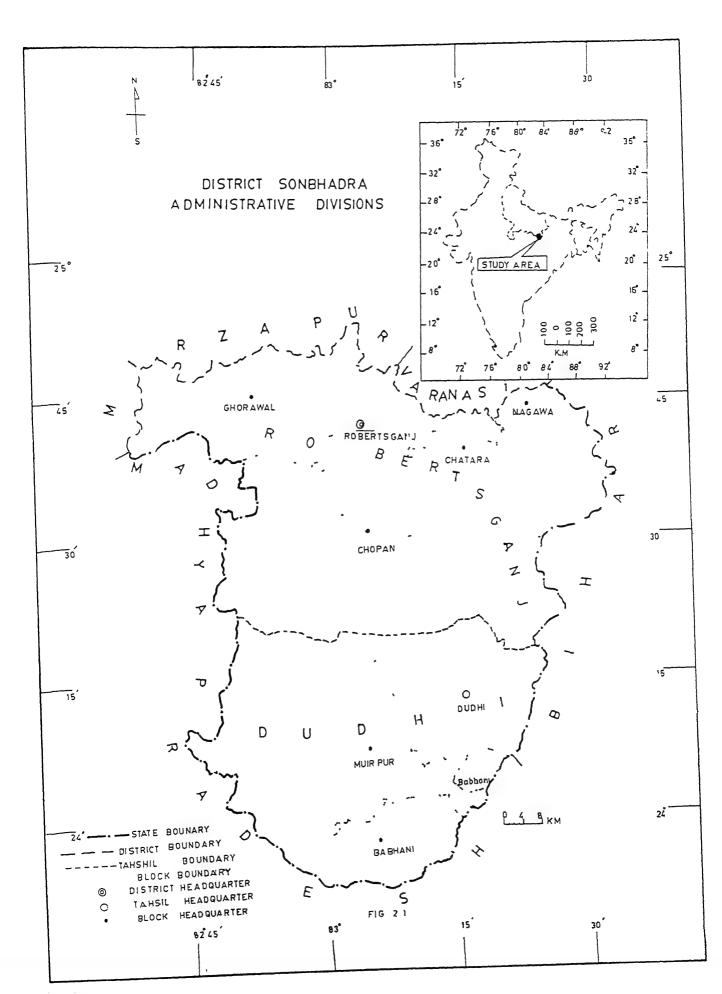
प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं से युक्त होता है । किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट प्राकृतिक तथा सास्कृतिक भू-दृश्य वहाँ के प्राकृतिक एव जैविक अन्तर्क्रिया के परिणाम होते हैं । विकास योजनाएं भौगोलिक तथ्यों एव विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही बनायी जाती हैं, किन्तु विकास नियोजन में मानव कल्याण एवं पर्यावरण सतुलन केन्द्रीय तत्व होते हैं । अस्तु प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के प्राकृतिक एवं सास्कृतिक स्वरूप का वर्णन एव विश्लेषण करना है ।

2.। स्थिति एवं विस्तार

अध्ययन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिण - पूर्व में स्थित जनपद सोनभद्र है, जिसका सृजन 4 मार्च 1989 को हुआ । वर्तमान सोनभद्र जनपद में पूर्व मीरजापुर जनपद के राबर्ट्सगंज एवं दुद्धी तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है । राबर्ट्सगंज को अस्थाई जनपद मुख्यालय बनाने के अतिरिक्त पूर्व के प्रशासनिक भागों एव क्षेत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है । जनपद का 'सोनभद्र' नामकरण अग्निपुराण में उल्लिखित सोन नदी के नाम पर किया गया है ।

'नमस्ते ब्रह्मपुत्राय शोण भद्राय ते नम । मेकलोदभवाय वृहते सर्व पाप हरायव ।।'

प्राकृतिक रूप से दक्षिण में दक्कन के पठार व उत्तर में गगाघाटी तथा राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार के सगम पर स्थित, सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र पठारी क्षेत्र है । सोनभद्र के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में बघेलखण्ड तथा रीवा का पठार, उत्तर में गंगाघाटी तथा दक्षिण मे बघेलखण्ड का पठार है । सम्पूर्ण जनपद दक्कन पठार का ही एक भाग है । सोनभद्र के पूर्व मे जनपद गढ़वा व भभुवा (बिहार राज्य), पश्चिम मे सीधी (मध्य प्रदेश), दक्षिण में सरगुजा (मध्य प्रदेश) तथा उत्तर में मिर्जापुर व वाराणसी (उत्तर प्रदेश) राजनीतिक सीमा बनाते है । अध्ययन प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23052 उत्तरी अक्षांश से 24053 उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा देशान्तरीय विस्तार 82038 पूर्वी देशान्तर के मध्य है।



अध्ययन क्षेत्र का आकार आयताकार है, जिसका उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रसरण है । इसकी उत्तर - दक्षिण अधिकतम लम्बाई ।।। कि0मी0 तथा पूर्व - पश्चिम अधिकतम चौड़ाई 95 कि0मी0 है ।³

प्रशासिनिक दृष्टि से सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र को 2 तहसीलों - राबर्ट्सगज एवं दुद्धी तथा 8 विकास खण्डों - घोरावल, राबर्ट्सगज, चतरा, नगवां, चोपन, म्योरपुर, दुद्धी व बभनी मे विभक्त किया गया है । तहसील राबर्ट्सगज में 5 विकासखण्ड (घोरावल, राबर्ट्सगज, चतरा, नगवा व चोपन) तथा दुद्धी मे 3 विकासखण्ड (म्योरपुर, दुद्धी व बभनी) हैं । सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र को 66 न्याय पंचायत, 586 ग्राम सभा, 1346 आबाद ग्राम (इसमे 4 वन ग्राम सिम्मिलित है) तथा 80 गैर आबाद ग्राम में विभक्त किया गया है । जनपद के सभी विकासखण्डों का विवरण तालिका 2.1 में प्रदर्शित है । कुल 8 नगरीय क्षेत्रों में । नगरपालिका (राबर्ट्सगंज), 2 टाउन एरिया (घोरावल व दुद्धी) तथा 5 नोटीफाइड एरिया (चुर्क - गुरमा, चोपन, ओबरा, रेनूकूट व पिपरी) है । अध्ययन क्षेत्र का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 6819.28 वर्ग कि0 मी0 है, जिसमें नगरीय क्षेत्र 20.48 वर्ग कि0मी0 तथा ग्रामीण क्षेत्र 6798 80 वर्ग कि0 मी0 है । क्षेत्रफल की दृष्टि से विकासखण्ड चोपन सबसे बड़ा (1712.97 वर्ग कि0 मी0) तथा चतरा सबसे छोटा (254.85 वर्ग कि0 मी0) है । क्षेत्रफल के अनुसार अवनत क्रम में विकासखण्डों की स्थिति क्रमशः इस प्रकार है - चोपन, म्योरपुर, नगवां, घोरावल, दुद्धी, बभनी, राबर्ट्सगज तथा चतरा (तालिका 2.1) । जनपद मुख्यालय से विकासखण्ड मुख्यालय की दूरी तालिका 2.1 में प्रदर्शित है । दुरस्थ विकासखण्ड बभनी (142 कि0 मी0) है ।

2.2 भौतिक विशेषता

अध्ययन क्षेत्र के भौतिक विशेषता के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । किसी भी क्षेत्र के विकास में भौतिक स्वरूपों एव प्राकृतिक ससाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है । अध्ययन क्षेत्र का प्राकृतिक विभाग, भौतिक स्वरूप, संरचना (भौमिकी), अपवाह, जलवायु, वनस्पति, मृदा एव खनिज संसाधनो का वर्णन किया गया है ।

(अ) प्राकृतिक विभाग

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, जो बघेलखण्ड पठार, छोटा नागपुर पठार

तालिका 2.।

1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		, 1		, !
1	1426	1346	586	66	100.00	6819.28	योग जनपद	
					00.30	20.48	योग नगरीय	1 1 1 1 1 1 1 1
	1426	1346	586	66	99.70	6798.80	योग ग्रामीण	
142	72	5 71 4 वनग्राम	35	, c	8.91	608.26	8. बभनो	1 1 1 1 1 1 1 1
79	102	98	46	œ	10.37	707.45	7. दुब्दी	
104	124	120	55	∞	19.61	1337.89	6. म्योरपुर	2 दुही
27	93	91	60	9	25.20	1712.97	5 चोपन	
3	143	128	62	7	13.43	916.20	4. नगवां	
19	190	168	63	Ćτ	3.73	254.85	3. चतरा	
Ćτ	340	3,29	117	10	6.48	442.45	2 राबर्ट्सगंज	
24	354	337	148	14	12.00	818.73	। . घोरावल	। राबर्ट्सगंज
9	0	7	6	: : : : : : :	4	: : : : : : :	2	1 - 1
की दूरी	1 1 1 1 1 1		t t t t					
से वि०खं0मु०						(वर्ग कि0मी0में)		
राजस्व ग्राम जनपद मुख्यालय	राजस्व ग्राम	आबाद ग्राम	ग्राम सभा	न्याय भचायत	क्षेत्रफल प्रतिशत में	क्षेत्रफल	विकसस्खण्ड	तहसील
				챞	जनपद - सोनभद्र			

स्त्रीत

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 16, 25, 29 व 113 एवं उससे संगणित 1

(रोहतास पठार) तथा गंगा घाटी से परिवृत्त है । प्राकृतिक स्वरूप तथा भूमि की बनावट की दृष्टि से इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, ⁴ जिसका विवरण इस प्रकार है ।

(।) मध्यवर्ती पठारी भाग

इस भाग के अन्तर्गत तहसील राबर्ट्सगंज का विकासखण्ड घोरावल, राबर्ट्सगंज, चतरा व नगवा का सम्पूर्ण भाग सिम्मिलित है, जो सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का लगभग 35% है । यह उप-सम्भाग विन्ध्य पर्वत के अन्तर्गत पठारी हिस्से से होता हुआ कैमूर पर्वत श्रृंखला की अंतिम सीमा सोन नदी तक स्थित है । यह संभाग गंगा की घाटी से 400 से लेकर 1100 तक की ऊँचाई पर स्थिति है । इस क्षेत्र के अनेक पहाड़ी नाले कर्मनाशा, चन्द्रप्रभा, बेलन तथा सोननदी में मिलते हैं । घोरावल से वैनी तक लगभग 60 कि0 मी0 लम्बा तथा 15 कि0 मी0 चौड़ा समतल मैदानी भाग परिलक्षित होता है ।

(2) सोनघाटी

यह उप-संभाग सोन के दक्षिण में स्थित है, जिसके अन्तर्गत विकासखण्ड चोपन, म्योरपुर, दुद्धी तथा बभनी आते हैं । यद्यपि यह संभाग पहाड़ियों तथा जंगलों से आच्छादित है, फिर भी सिगरौली, सोनघाटी एवं दुद्धी घाटी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपजाऊ है । इस क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है, जिसमें कनहर व रिहन्द नदी मिलती है ।

(ब) भौतिक स्वरूप एवं संरचना

जनपद सोनभद्र के दोनों तहसीलों (राबर्ट्सगंज व दुद्धी) के भौतिक स्वरूप एवं संरचना का विवरण पृथक - पृथक प्रस्तुत किया जा रहा है । इसे मानचित्र 2.2, 2.3 व 2.4 मे प्रदर्शित किया गया है ।

(।) दुद्धी तहसील का भौतिक स्वरूप

यह क्षेत्र अधिकांश रूप में पहाड़ी है । इसके उत्तर में पहाडियों एव पठारों की एक सतत् श्रृंखला है जिसकी लम्बाई लगभग 75 कि0 मी0 तथा चौडाई 6 से 12 कि0 मी0 है । इसमें छोटी - छोटी पहाड़ियाँ तथा कूट (रिजेज) इघर - उधर दिखायी पड़ती है, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर 4 कि0 मी0 चौड़ी एक और सतत् कूट (रिज) है । पश्चिम में अवस्थित एक लम्बी श्रृंखला जिसमें चिल्काटाँड़, खड़िया एवं बाँसी वन खण्ड सम्मिलित हैं,

का भी विन्यास पहाड़ी है । सामान्यतया इन पहाड़ियों एवं कूटों (रिजेज) की प्रवणता (ग्रेडियेण्ट) सामान्य से अधिक की ओर है लेकिन इनमें से कुछ पहाडियों जैसे गोंडा मुर्गारानी पहाडी, चैनपुर पहाड़ी, झंडी पहाड़ी (बहेराडोलखण्ड), बॉसी खण्ड की पहाडियों तथा चिल्काटॉड पहाडी बहुत ही खड़ी ढाल की है तथा अविक्षप्त है । यह क्षेत्र उत्तर एव दक्षिण मे मुख्य पहाडियों के बीच मे एक उतार - चढ़ाव दार मैदान है जो कि अनेक छोटे-छोटे नालो आदि से कटा-पिटा है । केन्द्रीय मैदानी ढाल दक्षिण की ओर समुद्र की सतह से लगभग 400 मीटर तथा उत्तर की ओर लगभग 215 मीटर की ऊँचाई पर है, जबिक पहाडियों मैदान की सतह से और भी ऊँची है । इस क्षेत्र की सबसे ऊँची चोटी समुद्र की सतह से 65। मीटर ऊँची है, जो कि दक्षिण पूर्व मे चैनपुर पहाडी (रानी कोठी पहाड़) में है ।

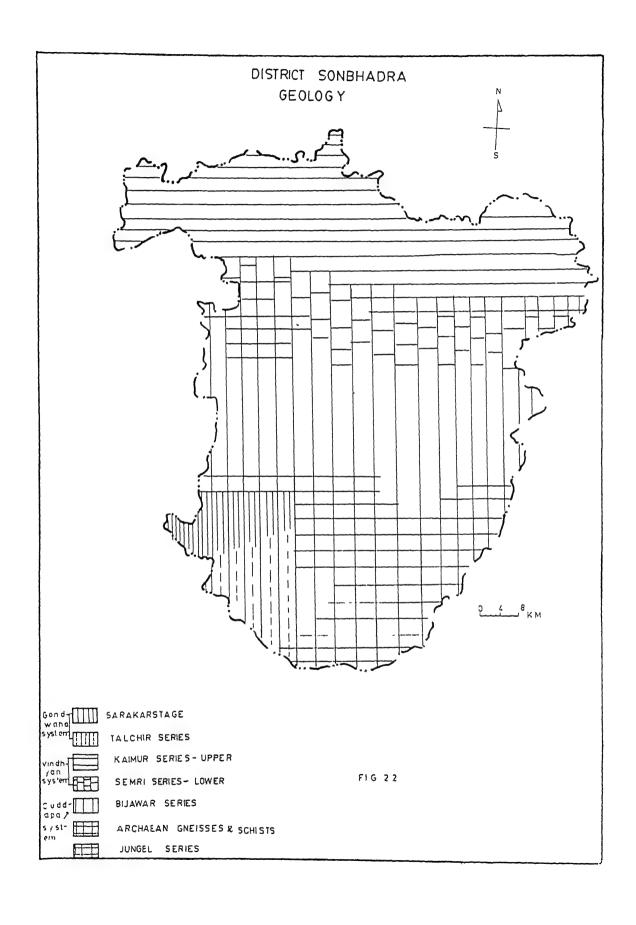
निचली चट्टानी पहाड़ियाँ एवं उनकी शाखाएँ जो कि अधिवासों के पास हैं, को छोड़कर पूर्णतया जगलों से ढकी है । अधिवासों के पास की पहाड़ियाँ अत्यधिक चारागाह के रूप में प्रयुक्त होने के कारण उजड़ सी गयी है तथा इन्ही कारणों से अपक्षरण का भी शिकार हुई हैं । इसके बीच का चपटा मैदानी क्षेत्र जगह - जगह पर छोटे - छोटे ग्रामों से भरा हुआ है, जहाँ की आबादी कृषि कार्य मे सलग्न है । इस क्षेत्र का अधिकाश भाग वनाच्छदित है तथा अत्यधिक पथरीला होने के कारण कृषि कार्य हेतु लगभग अनुपयुक्त है । यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक सरचना के कारण मध्य भारत से काफी मिलता जुलता है ।

(2) दुद्धी तहसील की भूवैज्ञानिक संरचना

भारतीय स्तर शैलक्रम के अनुसार इस क्षेत्र की शैलें प्रीकैम्ब्रियन एवं पुराकल्पीय है जिनमे प्रीकैम्ब्रियन शैलों का बाहुल्य स्पष्ट है विविध शैल वर्गो का क्रमबद्ध विवरण निम्नवत् है।

।. प्रीकैम्ब्रियन शैल

दुद्धी तहसील में विगोपित (इक्स्पोज्ड) प्रीकैम्ब्रियन शैलें मणिभीय एवं बिजावर शैल वर्गों में वर्गीकृत की जा सकती हैं । मणिभीय शैलें म्योरपुर, बभनी व दुद्धी क्षेत्र (दुद्धी - विण्डमगंज सार्वजनिक निर्माण मार्ग के दक्षिण में) तथा बिजावर शैलें सम्पूर्ण पिपरी क्षेत्र, अविशिष्ट दुद्धी क्षेत्र एवं अनपरा क्षेत्र के मार्गों में विगोपित है ।



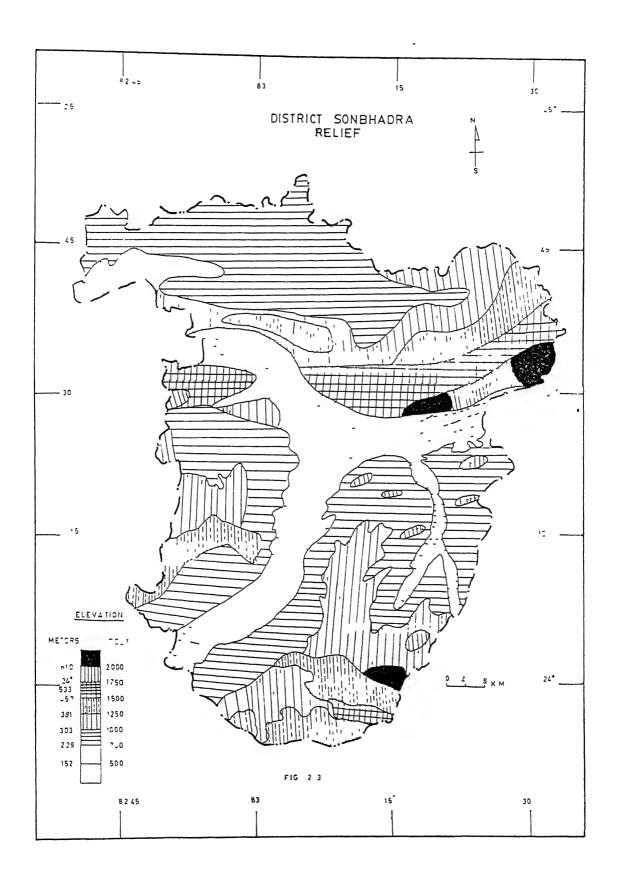
प्रीकैम्ब्रियन मणिभीय शैलों में अधिकांशत नाइस तथा उनके साथ सम्बद्ध शैलें (जैसे मेटा - अवसादीय शैलों, मेटा अवसादीय एवं धारीय अंतरावेश) परतें (बेन्ड्स) क्वार्ट्स पिंक फेल्डस्पारएपिडोट शैल मालाऍ (रीफ्स) क्वार्ट्ज शिरा आदि है । बिजावर शैलों मे मुख्यत मृदास्मिक (पेलिटिक) एव सिकताश्मिक (सेमिटिक) शैलों के स्थानान्तरित समरूप मेटामार्फिक इक्विवेलेन्ट्स जैसे कि गुलाबी भूरी हरीतिमा युक्त स्लेट, फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट तथा अल्पमात्रा मे क्षारीय शैलों के (बेसिक एक्स) स्थानान्तरित समरूप हैं।

मणिभीय एवं बिजावर शैलों का सम्पर्क भ्रिशित है । यह तथ्य उत्तर में डुमरा से प्रारम्भ होकर रनटोला, बैरपान से होते हुए औड़ी तक परिलक्षित सिलीशियम ब्रेशिआ कूट (रिज) की उपस्थिति से सत्यापित होता है । परन्तु क्षेत्र में मणिभीय एव बिजावर शैलों का क्षैतिज स्थानान्तरण दृष्टिगत नहीं होता । यह सम्भवत भ्रश की प्रक्रिया स्ट्राइक के अनुरूप होने के कारण हो सकता है ।

दुढ़ी तहसील के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व हिस्सों मे कई स्थानों पर मेटा सेडिमेन्टरी/ इग्नीयस इनक्लेट्स/बैन्ड की परलें अन्तरावेश नाईसों के बीच दिखाई पड़ते है । इस वर्ग मे क्वार्ट्जाइट, मणिभीय चूना पत्थर, केल्किसिलिकेट ग्रेन्यूलाइट, हार्नब्लेंड, शिस्ट, एम्फीबोलाइट आदि अन्तर्भूत हैं । इसके अतिरिक्त बिजावर शैल समूह के मुख्य फाइलाइट प्रक्षेत्र और नाइसों के बीच एक और प्रक्षेत्र है, जिसमें स्थूलकणीय बायोटाइट शिस्ट तथा फाइलाइट परतें है ।

- 2. नाइस बिण्ढमगंज के उत्तर से दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा तक के क्षेत्र में नाइस शैलों का बाहुल्य है । सामान्यतया उपलब्ध नाइसें निम्न हैं -
 - (क) गुलाबी बायोटाइट नाइस
 - (ख) सूक्ष्म कणीय बायोटाइट नाइस
 - (ग) पॉर्फाइराइटीक बायोटाइट नाइस
 - (घ) परतदार नाइस तथा मिश्राश्म
 - (ड) चाक्षुष नाइस

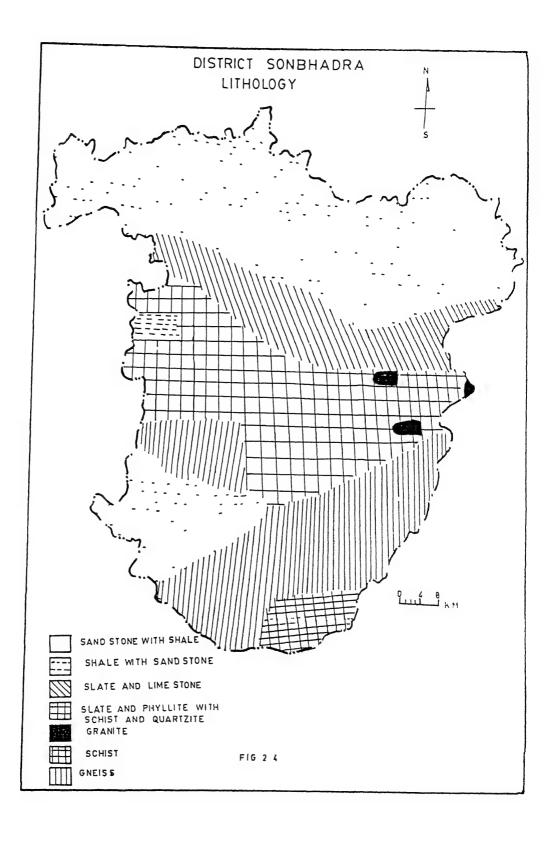
खाटाबरन खण्ड मुख्य रूप से गुलाबी बायोटाइट नाइसों पर अवस्थित है जो कि स्थूल कणीय एवं भुरभुरी सी है । यह मुख्यतया क्वार्ट्ज गुलाबीफेल्डस्पार, बायोटाइट नाइसें रासपहरी,



परनी तथा गड़िया और बराइटाँड़ के बीच में देखी जा सकती है । पॉर्फाराइट, अप्रार्थिइट पूर्क विण्डमगंज, दुढ़ी के अधिकतर भागों मे अवस्थित है । यह मुख्यतया गुलाबी एक सफेट फेल्प्स्पार, क्वार्ट्ज बायोटाइट से बनी है । परतदार नाइसों एवं मैनिटाइटस जो कि हार्नब्लेड शिस्ट तथा बायोटाइ नाइसों के एकान्तरित परतों के रूप में होने के कारण बनें है, करिहया और सिसवा के बीच तथा आरंगपानी, बरवाटोला, जामपानी, विश्रामपुर, बोमपकरी, हुमेलदोहर और सागोबाँध खण्डो मे दिखायी देते हैं । नाइसें बहुत ही सूक्ष्म कणीय तथा अति केल्डस्पेशिक (जिनमें सफेद, गुलाबी फेल्डस्पार है) शैलें है । फेल्डस्पार सामान्यतया फेल्डस्पार के पुजित समूहों (जिनमे सामान्यतया माइक्रोक्लाइन और सफेद फेल्डस्पार दिखाई पड़ते हैं) से निर्मित है । यह नाइसें झिली, महुआ, नवाटोला तथा चेरी और गौसकाटा के बीच मे दिखायी देती हैं ।

- 3. बिजावर श्रेल वर्ग बिजावर शैलवर्ग की शैलों दक्षिण में दुद्धी वर्ग की मणिभीय शैलों एव उत्तर में कजरहट के निम्न विन्ध्य (लोअर विन्ध्यन)जो कि अगोरी विजयगढ़ वर्नों में है । शैल वर्गों के बीच के मध्य प्रक्षेत्र में स्थित है । इस वर्ग का मणिभीय शैलों के साथ सम्पर्क भृशित तथा निम्न विन्ध्य शैलों के साथ सम्पर्क भृशित अथवा विसगत है । बिजावर वर्ग की मोटाई 24 से 40 कि0 मी0 है जिसका 5-12 कि0 मी0 दुद्धी तहसील में पड़ता है। बिजावर वर्ग में निम्नलिखित क्रम परिलक्षित होता है।
- (क) राख के रंग की एवं हल्के रंग की क्लोराइट सेरिसाइट फाइलाइट तथा अभ्रकीय बालू पत्थर की वीप्ताकार संस्तर,
- (ख) ब्रेक्शिएटेड क्वार्ट्जाइट, हीमेटाइट क्वार्ट्जाइट, पतली वीप्ताकार (लेन्टिकुलर), स्तरकीय (लैमिनेटेड), फाइलाइट तथा बालूकीय कार्बोनेट तथा
 - (ग) डोलोमाइट, मणिभीय चूना पत्थर और सिडेराइट वाले कार्बोनेट ।

इस सम्पूर्ण वर्गक्रम के साथ इस्त रंग के क्षारीय शैले अल्प मात्रा मे पाये जाते हैं तथा इस वर्ग की शैलों के पर्णन (फीलिएशन) के सिदश (पैरलल) एव पर्णन को काटती हुई क्वार्ट्ज कैलसाइट की पतली परतें पायी जाती है। ऊपर दिए हुए सम्पूर्ण क्रम मे संस्तरो का एक दूसरे से मिल जाना एक सामान्य दृश्य है।



4. फाइलाइट - यह सामान्यतया राख के रगवाली, सूक्ष्म कणीय तथा हल्के सस्तरवाली सेरिसाइट एवं क्लोराइट फाइलाइट है । यह शैल सदैव ही अत्यधिक भाजित (क्लीण्ड) होती है । कभी-कभी भाजन और संस्तरीकरण में अन्तर करना कठिन होता है । कहीं - कहीं परतदार हीमेटाइट का केन्द्रीकरण भी पाया जाता है । पुन. स्फटित (रीक्रिस्टेलाइज्ड) क्वार्ट्जाइट के 5 मि0 मी0 से 2 से0 मी0 मोटाई वाले संस्तर एकान्तरित रूप से फाइलाइट से मिलते है । इसके अतिरिक्त स्थूल कणीय अभूकीय बालू पत्थर भी प्राप्त हैं । ये पत्थर फाइलाइट के साथ उनकी स्ट्राइक के अनुरूप सामान्य सूक्ष्म कणीय फाइलाइट्स में मिल जाते है ।

30 कि0 मी0 क्षेत्र जो कि 24⁰15' से 24⁰18' उत्तरी अक्षांश एवं 83⁰17' - 83⁰24' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित हैं, में उपस्थित फाइलाइट्स में एन्डाल्यूसाइट उपस्थित है । एण्डाल्यूसाइट पूर्ण विकसित त्रिपार्श्वीय मिणयों (प्रिज्मैटिक क्रिस्टल्स) के रूप में पाया जाता है जो कि स्लेटी रंग के हैं तथा सामान्यतया लम्बाई में । से0 मी0 से 1.5 से0 मी0 तक के होते हैं । ये विशेषरूप से विण्ढमगंज के उत्तर - पूर्व में स्थित सुखड़ा नाले में, हरनाकछार के उत्तर पश्चिम में एवं गड़िया के उत्तर - पूर्व में स्थित बिजुल झरिया नाले में दिखायी पड़ते हैं ।

- 5. क्वार्ट्जाइट फाइलाइट क्रम के ऊपर निम्न क्वार्ट्जाइट उपलब्ध है ।
 - (क) बेक्शियेटेड क्वार्ट्जाइट
 - (ख) क्वार्ट्जाइट ब्रेक्शिया
 - (ग) बैण्डेड हीमेटाइट क्वार्ट्जाइट

इनमें से प्रथम दो लोहित या लोहा रहित हो सकते हैं । ये शेष सामान्यतया पुन स्फटित हैं, हॉलािक अविशष्ट (रिलक्ट) संस्तरीकरण भी कभी-कभी दिखायी देता है । सस्तरों की मोटाई 2 से0 मी0 से 15 से0 मी0 के बीच में है ।

6. डोलोमाइट/चूना पत्थर - डोलोमाइट/चूना पत्थर एव पुन स्फटित चूना पत्थर के छोटे- छोटे विगोपन (इक्पोजर्स) कहीं - कहीं दिखाई देते हैं । इनमें हथवानी - म्योरपुर सडक के किनारे, मुर्घवा - 9 पर एवं सिंधवा ग्राम के दक्षिण में विगोपित शैल उल्लेखनीय है।

7- **क्षारीय शैल -** ये मुख्तया हल्के या गहरे हरे रंग के सूक्ष्मकणीय कहीं - कहीं पर्णित शैल हैं । इनमें अल्प मात्रा में सल्फाइट, चालकोपायराइट, आरूतेनोपायराइट आदि खिनज कहीं - कहीं पाये जाते हैं । सामान्यतया परतों की मोटाई पाँच से पच्चीस मीटर तथा लम्बाई आधा से चार कि0 मी0 होती है ।

क्वार्ट्ज शिराएं एन क्वार्ट्ज फेल्डस्पार शैल मालाए (क्वार्ट्स बेन्ड एण्ड क्वार्ट्स फेल्डस्पैथिक रीफ्स) बिजावर एन प्रीकैम्ब्रियन मिणभीय शैलों को काटती हुई क्वार्ट्ज शिराएँ इस क्षेत्र के अधिकतम हिस्सों मे दिखाई देती है । ये सामान्यतया दुग्धवत् श्वेत (मिल्की ह्वाइट) तथा कभी - कभी धूमल एवं हल्की पीली (जहाँ क्वार्ट्ज के साथ आरसेजिक हो) रंग की अपखिण्डत (फेंग्मेन्ट्री) या बेक्शिएटेड होती है । इनकी मोटाई कुछ मि० मी० से 3 मीटर तक तथा लम्बाई कुछ मीटर से 1/2 कि० मी० तक हो सकती है ।

गुलाबी फेल्डस्पार क्वार्ट्ज शैल मालाएँ अधिकतर रेखीय विगोपनों के (लिनीयर आउटक्राप) रूप में दिखाई देती हैं । ये विशेषतया लभरी, कुण्डाभाती, सोनवानी, पिपरी आदि क्षेत्रों में दृष्टिगत है । यह शैल सामान्यतया निम्नलिखित रूप मे उपलब्ध है -

- (क) 0.5 से 3.0 मी0 मोटी परतों के रूप में नाइसों एव बिजावर मेटा अवसादीय शैल क्रम के पर्णभ के सदिश ।
- (ख) अनेक कोणीय खण्डों के रूप में जो कि अपक्षरण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है।

क्षारीय नितुन्न शैलें (बेसिक इन्द्रूसिव रॉक्स) साधारणतया नाइसों एव बिजावर अनुक्रम में रालिभित्ती (डाइक) एवं राल पट्ट (सिल) के रूप में मिलती है । क्षारीय शैलें मेटाडोलेराइट, माइक्रोग्रैबो, जोराइट, डोलेराइट आदि है । जोगिया पहाड़ मे विगोपित ओलिबीन ग्रैबो शैल हरे रग की मॉटल्ड दृष्टिगत होती है जिसमें अपक्षरण के बाद गड्ढे पड़ जाते हैं । ये शैल दुद्धी क्षेत्र में काफी अधिक मात्रा में पायी जाती है ।

8. **मोंडवाना अनुक्रम -** निम्न गोंडवाना वर्ग की तालचिर एवं बाराकर रचित (फार्मिशन) की शैल क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में दृष्टिगत होती है जो उत्तर प्रदेश की

सीमा पर स्थित सिगरौली कोयला क्षेत्र मे उपस्थित शैल क्रम का प्रतिनिधित्व करती है । सिगरौली क्षेत्र का लगभग 52 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र कोटा ग्राम के निकट अवस्थित है । सिंगरौली कोयला क्षेत्र में निम्निलिखित क्रम उपस्थित हैं।

निम्न गोंडवाना वर्ग (क) तालिचर फार्मेशन (ख) बाराकर फार्मेशन

- (क) तालिचर फार्मेश्वन यह पहाड़ी क्षेत्र की तलहिट्यों एवं समतल मैदानी क्षेत्र में अवस्थित हैं । तालिचर बाराकर का मिलन स्थल खड़ी काट में नहीं दिखाई देता है । औड़ी (24⁰12'15"30 अक्षांश एवं 82⁰ 46' 30" पूर्वी देशान्तर) के दक्षिण पिश्चम में देवहर नदी में यह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । इनमें कैल्केरियस बालू पत्थर तथा मृदा पत्थर तथा गादीय शैल सिम्मिलित हैं । इस क्षेत्र के कुछ कुओं की काट में महीन दानेदार क्लास्टिक चूना पत्थर का भी पता लगा है । कैल्साइट चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में है एवं इसके अतिरिक्त गारनेट, अभ्रक, एपीडोट तथा स्टाइल आदि हैं ।
- (ख) बाराकर फार्मिशन बाराकर संरचनाओं के इस सम्पूर्ण समूह का 95% बालू पत्थर है जबिक शेष भाग में बर्फ और ग्रेशेल्स, मृत्तिका बैण्ड तथा कोयला के स्तर है । बालू पत्थर जो पिक मध्यम से मोटे दानेदार तथा कहीं कहीं पेब्ली व ग्रिटी भी हैं, इसमें घुसे हुए पेबुल्स ब्यास में 1-5 से0 मी0 तक है । बालू पत्थर सफेद रंग के हैं , लेकिन उनमे सामान्यतया एक हल्की गुलाबी झलक दिखाई देती है, जो कि पोटाश फेल्सपार के अधिक अनुपात में होने के कारण है । किसी किसी स्थान पर यह बालू पत्थर फेरयुजिनस भी है । अपक्षरण के समय दानेदार फेरयुजिनस कांक्रीशंस छोड़ने की इसकी प्रकृति है । कोटा के उत्तर में छोडी हुई कोयला खान के पास उपलब्ध बालू पत्थर अत्यधिक फेरयुजिनस है और हीमेटाइट अपक्षरित सतह पर मोटेल्ड रूप में दिखाई देता है । इस बालू पत्थर में बांसी के पास कोल सीम से निकट रूप में सम्बद्ध, सिडेराइट के सेन्ट्रीजन्स भी पाये जाते हैं । यह सम्भवत कोयले में सीमिश्रत पाइराइट के भंग होने के कारण बनते हैं । फेल्सपैयीय बालू पत्थर, मृत्तिका से सम्पर्क स्थल पर बदल कर केओलिनाइट बन जाता है । बांसी क्षेत्र में कार्बोनिशियस शैल का एक महत्वपूर्ण एक्सपोजर दिखाई देता है, इसमें कुछ पौधों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं । इन शैलों में एक लगातार लेंस के रूप में एक पतला कोयले का स्तर भी प्राप्त हुआ है ।

(3) राबर्ट्सगंज तहसील का भौतिक स्वरूप

इस भूखण्ड के भौतिक स्वरूप में बहुत अधिक विषमता दृष्टिगेचर होती है, उच्चावच्च में भी विषमता है । उत्तरी भाग में बेलन बेसिन समप्राय अवस्था में है । अत यहाँ पर निरंपेक्ष उच्चावच्च तथा आपेक्षिक उच्चावच्च दोनों अत्यन्त कम हैं । ⁵ घोरावल से वैनी तक लगभग 60 कि0 मी0 लम्बी तथा 15 कि0 मी0 चौड़ी समतल पेटी में अच्छी कृषि की जाती है । सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु यही सबसे बड़ा 'कृषि क्षेत्र' है । इस पेटी के दक्षिण में तथा सोन नदी घाटी से सलग्न पूर्व से पश्चिम दिशा में कैमूर पर्वतमाला फेली हुई है । केमूर पर्वतमाला तहसील के सम्पूर्ण मध्यवर्ती व पूर्वी क्षेत्र में फैली हुई है । इसकी चोटी का भाग प्राय समतल है । कैमूर के कगार से दक्षिण में सोन नदी तक कुछ छोटी - छोटी पहाड़ियाँ है जो प्राय पूर्व - पश्चिम दिशा में अधिस्थापित हैं और कटी हुई हैं । कैमूर श्रेणी की सामान्य ऊँचाई 200 से 450 मीटर तक है । सोन नदी के बाएं तट पर, कैमूर का दक्षिणी ढाल काफी तीव्र है । इसमें बड़ी नदियों का अभाव है । कैमूर के दक्षिणी ढाल से वर्षा के दिनों में तीव्र वेग से बहने वाले नाले सोन नदी में मिलते हैं । तीव्र अपरदन के कारण दिक्षणी ढाल लगभग खड़ा हो गया है, जो देखने में दीवार जैसा लगता है । सोन के तटीय भागों में जलोढ़ मुदा पायी जाती है, जिसमें अच्छी खेती होती है । विकासखण्ड घोरावल के दिक्षणी व पूर्वी भाग में अनेक पहाड़ियाँ हैं जो 150 - 400 मीटर तंक ऊँची है ।

सोन नदी का दक्षिणी भाग अनेक छोटे - छोटे नालों से कटा - फटा है , ये नाले सोन नदी में सीधे या सहायक नदियों के माध्यम से मिल जाते हैं । छोटे - छोटे नालों में बन्धे बनाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए समतल बनाया जाता है । इस प्रकार चोपन क्षेत्र के वन पहाड़ी, ऊर्ची - नीची भूमि और नालों या गहरी घाटियों के किनारों में ही अवस्थित है । कैमूर पर्वत माला के भू-खण्ड में स्थित भाग का समुद्र की सतह से अधिकतम ऊँचाई 628.5 मीटर गुरूर - गड़ाव खण्डों की सीमा के निकट तरिया क्षेत्र में है । इस क्षेत्र में सोन नदी के तल की समुद्र की सतह से ऊँचाई लगभग 153.0 मीटर से 173.4 मीटर तक है ।

(4) राबर्ट्सगंज तहसील की भू-वैज्ञानिक संरचना

कैमूर पर्वत माला के उत्तरी भाग बेलन - बेसिन में मुख्यत महीन तथा मध्यम कणों वाले क्वार्ट्ज युक्त बालुका प्रस्तर पाये जाते हैं, जो कि ऊपरी विन्ध्यन के 'कैमूर-क्रम'

विसंगतियां (अन-कॅनफॉरिमटी)

-----<u>l</u>

बिजावर समूह

- बीनक्वार्ट्ज
- फैरूजिनस सैण्डस्टोन व लाइमस्टोन
- शैलयुक्त बेन्डेड हेमाटाइट जसपार
- बेसिपेटेड क्वार्ट्जाइट
- काल्क क्लोराइट शिस्ट
- रेड शेल
- परसोई फिलाइट व शेल

1. केमूर समूह (केमूर स्कार्प) - केमूर स्कार्प इस भूखण्ड के मध्य व पूर्वी भाग मे हैं, यहाँ से सोन नदी तक अनेक अवसादी शैल विगोपित है । सोन नदी के दक्षिण में प्रमुख शैल कागलोमरेट सैण्डस्टोन पोरसेलेनाइट तथा लाइमस्टोन है । सोन नदी से उत्तर की ओर जाने में सबसे प्रमुख शैल रचना रोहतास लाइमस्टोन की है । इसका रंग साधारण तथा धूसर ग्रें है । यह प्रथकम्भाजी (फ्लेगी) तथा पतले तलों से एकान्तरित (अल्टरनेट) है । आधार (दक्षिण मे) की ओर सिलीसियस व शैलयुक्त नाइसस्टोन पाया जाता है परन्तु उत्तर की ओर अच्छी प्रकार के लाइमस्टोन की मोटी पर्त है । यह गहरे भूरे रग की है तथा इसमे शैल का अन्तर्वशन (इन्टरकैलेशन) बहुत कम है । यहीं लाइमस्टोन चुर्क फैक्ट्री में सीमेण्ट बनाने के प्रयोग मे लाया जाता है ।

रोहतास लाइमस्टोन के उत्तर में क्वार्ट्जाइट प्रकार की शैल श्रृंखला है । आधार (दक्षिण) की ओर पृथक - पृथक कगार (स्कार्प) बनाती हुई क्वार्ट्जाइट की दो पिट्टियों दृष्टिगोचर होती हैं । निचले कगार की मोटाई लगभग 25 मी0 है । यह सपुन्जिव (मैसिव). बालूकणीय (ग्रिटी) तथा श्वेत धूसर रंग का है । इसका ऊपरी भाग शैल युक्त है । निचले और क्वार्ट्जाइट के बीच लगभग 15 मी0 मोटी, सैकजायित (सिलिसिफाईड) शैल, प्रकार की शैलों की पर्त है। ऊपरी कगार की मोटाई लगभग 30 मी0 है। यह महीन कण्युक्त तथा सफेद रंग की है।

क्वार्ट्जाइट श्रृंखला के उत्तर मे विजयगढ शैल प्रकार की श्रृंखला मे, शैल भली भांति विगोपित (एक्सपोज) नहीं हुए हैं । इसमें पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के शैल प्रागारमय (कार्बोनिसियस) काला, शैल सीदमय (सिल्टी) सैण्डस्टोन, माइकायुक्त सैण्डस्टोन तथा लौह पत्थर है । इस श्रृंखला की मोटाई लगभग 80 मीटर है ।

विजयगढ़ शैल के उत्तर में महीन कणयुक्त तथा पृथकम्भाजी (फ्लेगी) सैन्डस्टोन हरे व भूरे रंग की माइकायुक्त, बालूमय शैल प्रकार के शैल है । इनके ऊपर महीन कणयुक्त हरे रंग के सैण्डस्टोन की शैले है तथा इसके उपरान्त भूरे रंग के सैण्डस्टोन तथा हल्के बैंगनी रंग के बालूमय (रेतीले) प्रकार की शैलें हैं । यहीं शैलें मुख्य कैमूर पर्वतमाला को बनाती हैं। इनकी मोटाई लगभग 200 मी0 है ।

कैमूर पर्वतमाला की चोटी की ओर (उत्तर में) बढ़ने पर शैलों का स्वरूप अधिक शुद्ध रूप से क्वार्ट्जाइट प्रकार हो जाता है । इसका रंग सफेद है तथा इसमे बैंगनी व लाल कण (धब्बे) दिखलाई पड़ते हैं । इन्हें धन्धरौल क्वार्ट्जाइट कहा जाता है ।

- 2. सेमरी समूह सोन नदी के दक्षिणी भाग में लगभग कजरहट डाला ओबरा तक आदि विन्ध्य की सेमरी माला की शैलों पाई जाती है । भू-खण्ड के पिश्चमी भाग में नेवाड़ी तथा बरगवां के निकट सोन नदी के दक्षिण किनारे में ग्लोकेनाइटिक सैण्डस्टोन विद्यमान है । नेवाड़ी गाँव के निकट ओलिव शेल, विगोपित हैं । रिहन्द नदी के पूर्व में तथा अरंगी गाँव की दक्षिणवर्ती पहाड़ियां कजरहट लाइमस्टोन तथा शेल युक्त है । बिल्ली -बाड़ी तथा कजरहट क्षेत्रों में लाईम स्टोन सीमेण्ट तथा लौह कारखानों के लिए कच्चे माल के रूप में खनन किया जाता है । जुगैल (रिहन्द नदी के पश्चिम में) के पास एक विशिष्ट प्रकार की शेल श्रृंखला है, जिसको जुगैल सीरीज कहते हैं और पश्चिम में सीधी जिले (म0प्र0) की ओर चली जाती है । इसमें कांग्लोमरेट व सैण्डस्टोन प्रकार की शैले पाई जाती है । कनहर नदी के पूर्व में झिरगाडाण्डी के पास कुछ क्षेत्र में ग्रेनाइट प्रकार की शैलें भी विगोपित (एक्सपोज) हुई हैं।
- 3. बिजावर समूह सोन नदी के दक्षिण में स्थित भू-खण्ड के अधिकाश भाग में बिजावर समूह की श्रेलें पाई जाती हैं । बिजावर माला उत्तर में सेमरी माला (आदि विन्ध्य)

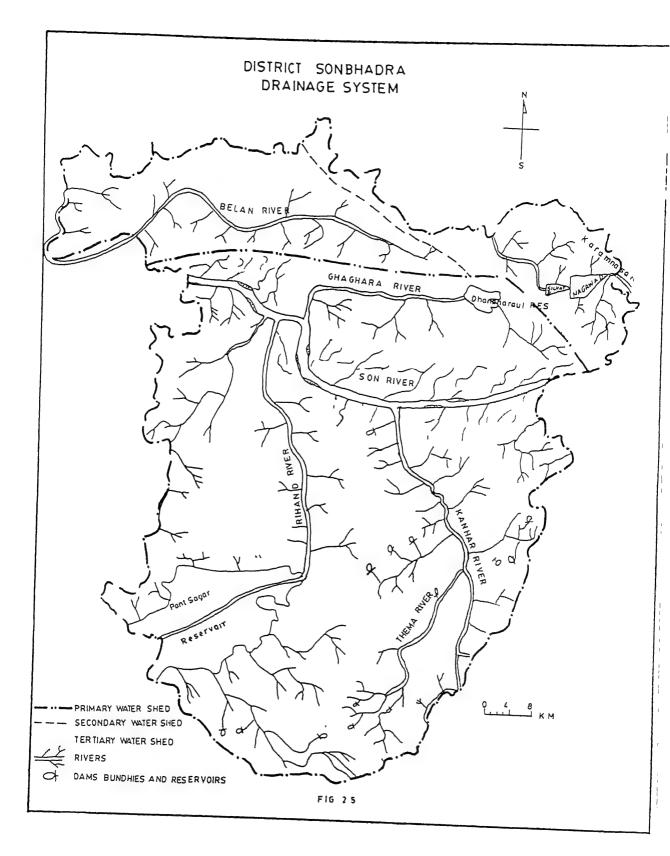
से बरगवां व द्वारी के मध्य स्थित एक विभीगत कटिबन्ध (फाल्ट जोन) से अलग होती है। इस कटिबन्ध में मुख्यतया ब्रेसिपेटेड व फेरूजिनस प्रकार की शैल विद्यमान है।

रिहन्द नदी के पश्चिम में परसोई - गरदा (दक्षिण सीमा) तथा बिजौरा - भरहरी (उत्तरी सीमा) के मध्य मे स्थित भू-भाग में बिजवाड़ माला के शेल प्रकार जैसे रेड शेल, ब्रेसिएटेड क्वार्ट्जाइट, काल्क क्लोराईट, शिस्ट बैन्डेड हेमाटाइट जसपार फैरूजिनस सैण्डस्टोन व लाइमस्टोन पाये जाते हैं । इस श्रृंखला के अधिक कठोर प्रकार के शैल (क्वार्ट्जाइट, बैन्डेड हेमाटाईट, क्वार्ट्जाइट जसपार, सैण्डस्टोन) प्राय पूर्व - पश्चिम दिशा मे अधिस्थापित पहाड़ियों में, जिनकी समुद्र सतह से ऊँचाई लगभग 300 से 480 मीटर तक है, पाये जाते हैं । इन पहाडियों की घाटी में बिजवाड़माला के शेल व सिस्टोज प्रकार के शैल विद्यमान है ।

(स) अपवाह प्रणाली

अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है । सोन के अतिरिक्त कर्मनाशा, बेलन, घाघर, गोटन, बिजुल, रिहन्द तथा कनहर आदि निदयां हैं । सोनपार की प्रवाह प्रणाली दक्षिण से उत्तर की तरफ है । सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकटक से निकलकर जनपद सोनभद्र के विकासखण्ड चोपन की उत्तरी सीमा बनाती हुई, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई पटना (बिहार) के पास गंगा नदी मे मिल जाती है । सोन नदी का उत्तरी ढाल काफी तीव्र है । घाघर के अतिरिक्त कोई प्रमुख नदी उत्तर दिशा से आकर नहीं मिलती है । उत्तरी ढाल से आने वाले अधिकांशत बरसाती नाले हैं, जो प्रपात का रूप भी धारण कर लेते हैं । सोन के दक्षिण से आकर मिलने वाली निदयों में विजुल, रिहन्द तथा कनहर है । सोन के दक्षिण में आयताकार प्रवाह - प्रणाली दृष्टिगत होता है । कनहर व बिजुल निदयां ग्रीष्म ऋतु मे लगभग जल रहित हो जाती है। बिजुल की सहायक नदी गोटन है । रिहन्द व कनहर की प्रमुख सहायक नदी पॉगन, थेया, बीछी तथा अझीर हैं । रिहन्द के ऊपरी भाग में रिहन्द जलाशय के निर्माण तथा पिपरी व ओबरा मे जलविद्युत गृह निर्माण से , प्रवाह प्रणाली नियन्त्रित हो गयी है । इन निदर्यों को तरूणावस्था में देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इनका प्रतिस्थापन अत्यन्त प्राचीन सरचना पर हाल ही मे हुआ है । सोन तथा इसकी सहायक नदियां भौतिक बाधाओं को काटकर प्रवाहित होती है जिससे स्पष्ट होता है कि निचली संरचना पर उनका अध्यारोपण हो गया है ।

सोन नदी के उत्तर में बेलन, कर्मनाशा व घाघर तीन प्रमुख नदियां हैं । घाघर नदी पर विकासखण्ड चतरा में धंधरौल जलाश्रय का निर्माण किया गया है । यह नदी दक्षिण



दिशा में प्रवाहित होती हुई सोन नदी में मिलती है । कर्मनाशा नदी शाहाबाद, रोहतास से प्रवाहित होती हुई जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड नगवां में प्रवेश करती है, जो स्वय गंगा नदी की सहायक नदी है । कर्मनाशा पर 1918 में सिलहट तथा 1948 में नगवा बाध का निर्माण किया गया । कर्मनाशा में पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले अनेक नाले आकर मिलते है । बेलन नदी, विकास खण्ड चतरा के करद - ऐलाई गाँव से निकलकर विकास खण्ड राबर्ट्सगंज व घोरावल से होकर मिर्जापुर, रीवा तथा इलाहाबाद जनपद में प्रवाहित होती हुई टोंस नदी में, जो स्वयं गंगा नदी की सहायक है, मिल जाती है । बेलन प्रवाह बेसिन अण्डाकार रूप मे है । बेलन तथा उसकी सहायक नदियों ने आयताकार प्रवाह - क्रम का निर्माण किया है ।

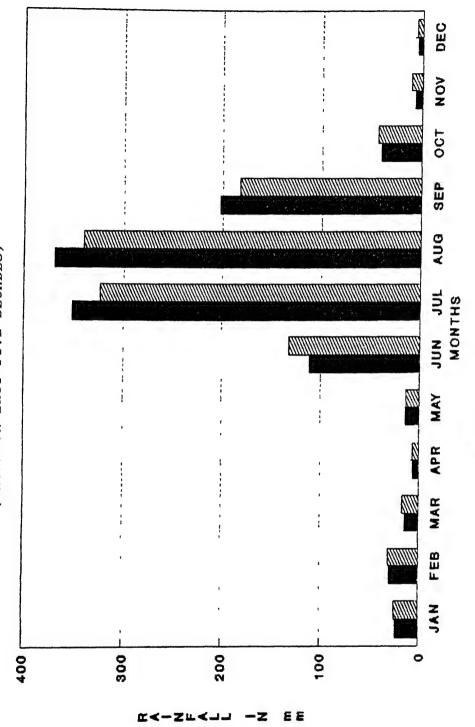
(द) जलवायु

जनपद सोनभद्र की जलवायु उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जनपदों से सर्वथा भिन्न तथा मध्य प्रदेश के अधिक समान है । इसकी मुख्य विशेषता दीर्घ और प्रचण्ड ग्रीष्म, साधारण जलवृष्टि और अल्पकालिक एवं मृद्ध शिशिर है । ग्रीष्म ऋतु सामान्यत मध्य मार्च से जून के अन्त तक रहती है, जब प्राय मानसूनी वर्षा प्रारम्भ हो जाती है । अप्रैल से भीषण गर्मी प्रारम्भ हो जाती और 'लू' चलने लगती है । धूल भरी आँधी का प्रकोप सामान्यतया कम रहता है । ग्रीष्म ऋतु में 400 सेन्टीग्रेट तापमान सामान्य तौर पर रहता है किन्तु कभी-कभी तापमान 460 सेन्टीग्रेट तक पहुँच जाता है । यद्यपि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में दिन का अधिकतम तापमान राज्य के अन्य स्थानों की तुलना में सबसे अधिक नहीं है तो भी ऐसा समझा जाता है कि यहाँ दिन के समय बेचैनी और भीषण गर्मी का प्रकोप अन्य स्थानों से कहीं अधिक है । इसके मुख्य कारण वायुमण्डल की अधिक स्वच्छता, पारदर्शिता, नग्न शैलों द्वारा सूर्य के किरणों का परावर्तन तथा भयंकर 'लू' समझे जाते हैं । ताप विद्युत केन्द्रों व उसके आसपास के क्षेत्रों में, जनपद के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है । दिन की अपेक्षा रातें कम कष्टप्रद होती है ।

यहाँ शीत ऋतु अल्पकालिक होती है । यह लगभग मध्य नवम्बर से फरवरी के अन्त तक रहती है । कठोर जाड़े की अवधि प्राय नगण्य होती है । तुषारापात साधारण और कम होता है और प्रायः घाटियों एवं निचली तलहटियों तक ही सीमित रहता है । प्रात काल सोन व रिहन्द नदी तथा धन्धरौल, नमवा व सिलहट जलाश्रय के तटवर्ती भागों मे प्राय कुहरा छा जाता है । सामान्यतया ग्रीष्म तथा श्रीतकाल स्वास्थ्यवर्धक है ।

NORMAL RAINFALL OF ROBERTSGANJ AND DUDHI

(BASED ON LAST FIVE DECADES)



Fin 2 6

ROBERTSGANJ DUDHI

वर्षा जून के अन्त या जुलाई से प्रारम्भ होती है । अधिकतम वृष्टि जुलाई, अगस्त एव सितम्बर में होती है । वृष्टि अक्टूबर के मध्य तक होती है । शीतकालीन जल वृष्टि प्राय जनवरी और फरवरी में होती है । यहाँ प्रदेश के अन्य भागों की अपेक्षा शीतकालीन 🕒 वृष्टि अधिक सुनिश्चित है । कुछ वर्षो मे शीतकालीन जल वृष्टि लगभग शून्य हो जाती है साथ ही मानसून वृष्टि भी लगभग नगण्य होती है । ऐसी असामान्य परिस्थिति में क्षेत्र सूखा ग्रस्त हो जाता है । यहाँ बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों तरफ से आने वाली मानसून हवाओं से वर्षा होती है । जनपद सोनभद्र की औसत वार्षिक वर्षा । 15 से0 मी0 है । 90% से अधिक वर्षा वर्ष के चार माह (जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर) मे हो जाती है । 50 वर्षी के वर्षा के वार्षिक औसत आंकड़ों का प्रदर्शन तालिका 2.2 में किया गया है । जिसके देखने से स्पष्ट होता है कि राबर्ट्सगंज में औसत वार्षिक वर्षा 117.63 से0 मी0 तथा दुद्धी में 113 37 से0 मी0 होती है इन दोनों तहसीलों के वार्षिक वर्षा में लगभग 5 से0 मी0 का अन्तर है । इससे स्पष्ट होता है कि वर्षा सभी भागों में एक समान होती है । एक दिन में यदि 2.5 मि0 मी0 वर्षा होती है, तो उसे वर्षा का दिन मानकर 50 वर्षों के वर्षा के दिन का प्रदर्शन भी तालिका 2.2 में किया गया है । तालिका 2.2 में वर्षा के दिन के प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि जनपद सोनभद्र में लगभग 60-6। दिन वर्षा के होते हैं । मानसून के समय आर्द्रता अधिक रहती है, जो 70% से अधिक हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर दोपहर मे सापेक्षिक आर्द्रता बहुत कम हो जाती है।

तालिका 2.2 वर्षा

राबर्ट्सगंज			दुद्धी		
माह	औसत वर्षा (मि0मी0 में.)	वर्षा का औसत दिन(प्रतिदिन 2.5 मि0मी0 या इससे अधिक)	औसत वर्षा (मि0मी0 मे)	वर्षा का ओसत दिन (प्रतिदिन 2 5 मि0मी0 या इससे अधिव	
	2	3	4	5	
जनवरी फरवरी	23.9 29.7	1.9 2.1	25.7 31.0	1.9	
मार्च अप्रैल	14.0 6.6	1.4 0.6	17.0 6.9	l · 6 0 · 7	

1	2	3	4	5
मई	14.5	1.2	13.5	1 5
जून	111.8	6 3	132 3	7.3
जुलाई	351.5	16.3	323.9	16.0
अगस्त	369.5	16.8	340.1	16.7
सितम्बर	202.4	9.6	182 4	9.1
अक्टूबर	40.4	2.4	43 9	3.1
नवम्बर	7 6	0 6	11.2	0 8
दिसम्बर	4 8	0.5	5 8	0.4
	~~~~~~~~			
योग	1176.3	60.0	1133.7	61.5

स्त्रोत Uttar Pradesh District Gazetteers, Mirzapur, 1988, p.16.

# (य) मृदा

# (।) मृदा संरचना

इस क्षेत्र की मृदा मूल रूप में अधिकाशत अविशष्ट प्रकार की है । ¹⁰ मृदा की प्रकृति मूल शैल (पैरेण्ट रॉक) के अनुसार भिन्न - भिन्न होती है जो निम्निलिखित है ।

1. प्रीकैम्ब्रियन मिणभीय शैलों से निर्मित मृदा - प्रीकैम्ब्रियन मिणभीय शैलें (जैसे नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट, क्षारीय अंतरावेश आदि) लाल रंग वाली बलुई दोमट मिट्टी को जन्म देती हैं । मिट्टी का यह रंग लोहांश अधिक होने के कारण न होकर विस्तृत विसरण के कारण होता हैं । यह निम्न कोटि (ऊँची पहाड़ियों पर हल्की, बजरीदार तथा हल्के रंग वाली) से उच्च कोटि (मैदानों और घाटियों में अधिक उर्वर, गहरी काली) की होती है । यह मिट्टी सामान्यतया थोड़ी सी कैल्केरियस होती है तथा इसमे नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है । इसमे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा हल्के से थोड़ी अधिक तथा क्षार की मात्रा अच्छी होती है ।

कुछ प्रदेशों में मिट्टी मे तुलनात्मक रूप से पोटाश (जहाँ मूल शैलों में पोटाश फेल्डस्पार एवं मस्कोवाइट की मात्रा अधिक हो जहाँ मुख्यतया बायोटाइट एवं हानैब्लैंड वाली शैल हो ) तथा चूना एवं मैग्नेशिया (जहाँ एम्फीबोलाइट अल्पबेसिक रॉक आदि क्षारीय शैलों का

बाहु ल्य हो) की मात्रा अधिक होती है । क्वार्ट्जाइट शैल से बनी मृदा अत्यन्त उर्वरक, बलुई हल्के कोटि की तथा पत्थर मिश्रित पोषक तत्वों से रहित होती है । इसकी जलधारण क्षमता भी बहुत कम होती है ।

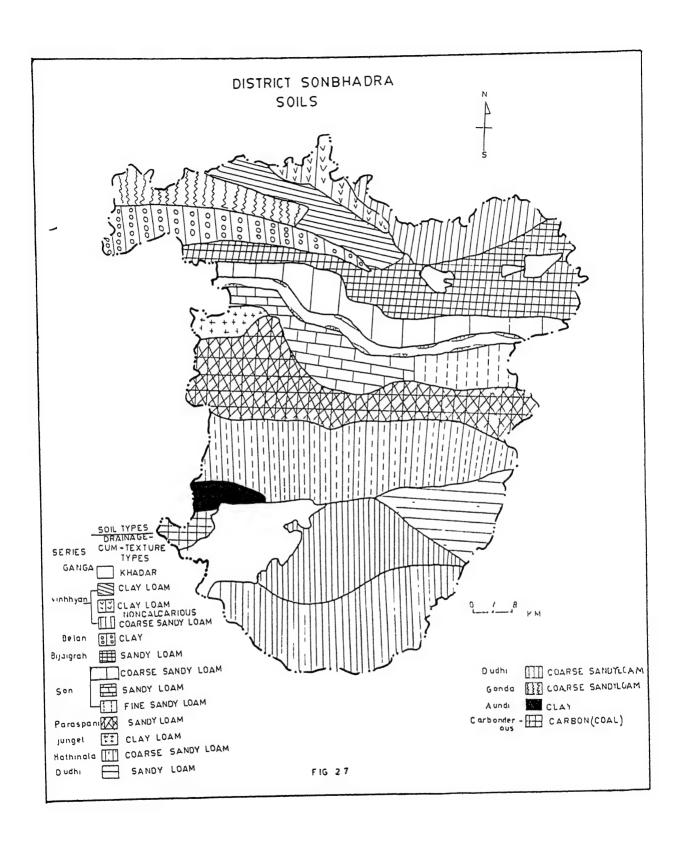
- 2. बिजावर शैल से निर्मित मृदा बिजावर वर्ग की शैलें विघटित होने पर मुख्यत मृत्तिकामय मिट्टी बनती है । एक प्राचीन संरचना होने के कारण इसके ऊपर की मिट्टी अत्यधिक परिपक्व होती है और यह क्रिया सतत गौण परिवर्तनों से सम्पन्न होती है। यह मिट्टी कैलकेरियस तथा क्षारीय होती है । इसमें कार्बोनिक पदार्थ नहीं के बराबर होते है। इस मृदा की प्रकृति स्थान पर, उसमें उपस्थित अशुद्धियों की मात्रा पर वह जिन शैलों के अपक्षरण से बनी है, उन शैलों के प्रकार पर (जैसे मृदािशमक, सिकतािसक, क्षारीय कार्बोनेट आदि) निर्भर करती है ।
- 3. गोंडवाना अधिवर्ग की शैलों से निर्मित मृदा गोंडवाना अधिवर्ग की शैले विघटन के उपरान्त अपेक्षाकृत निम्न कोटि एवं उर्वरता की मिट्टी को जन्म देती है । सामान्तया मिट्टी बलुई होती है । इसमें ह्यूम्स की मात्रा कम तथा रासायनिक प्रक्रिया उदासीन होती है।

# (2) मृदा का वर्गीकरण

अध्ययन क्षेत्र का मृदा वर्गीकरण प्रत्येक तहसील का अलग - अलग प्रस्तुत किया गया है।

### ।. दुद्धी तहसील की मुदा -

- (क) हाथीनाला श्रेणी यह श्रेणी लगभग समस्त उसी क्षेत्र में उपलब्ध है, जिस क्षेत्र में बिजावर समूह की शैलें है । शैलें अत्यधिक विघटित रूप में है और परिष्कृत एवं स्पष्ट परिच्छेदिका सुलभ नहीं है । पहाड़ियां निम्न कोटि के वनों से आच्छादित है यहाँ पर अल्पकृषि कार्य सम्भव है । उत्पन्न फसल का स्तर भी बहुत निम्न श्रेणी का है । मिट्टी का रंग पीले भूरे से पीला लाल तक है और अधिकांशतया उसमें अभ्रक मिला हुआ है । मिट्टी की सतह अधिकांशतया पतली है ।
- (ख) दुद्धी संघ बिजावर समूह की शैलों के दक्षिण में मृदाओं का एक समूह पाया जाता है । जिसके विभिन्न संगठनों का संतुलन एवं मोटाई जो कि त्रिभुजाकार रूप में है



और जिसका शीर्ष विण्ढमगंज के निकट है । दक्षिण की ओर इसका विस्तार है और म्योरपुर क्षेत्र को आच्छादित करने के पश्चात् यह गोविन्द बल्लभपन्त सागर (रिहन्द जलाशय) में मिल जाता है । साधारणतया घाटी में पायी जाने वाली मिट्टी भी निम्न कोटि की है और क्षेत्र मे पहाडियों के बाहुल्य के कारण मृदा बजरीयुक्त है । यद्यपि निम्न क्षेत्रों मे मृदा उर्वर एव गहरी है । यह मिट्टी काले रंग की है, जबकि ऊँचे स्थानों की मिट्टी लाल है ।

- (ग) सिंगरौली श्रेणी इस प्रकार की मिट्टी रिहन्द नदी और उसकी सहायक नदी देवहर नाला के बीच वाले क्षेत्र में पाई जाती है । परन्तु अब इस प्रकार का अधिकाश भाग रिहन्द जलाशय में डूब गया है । खडिया, बांसी और औड़ी के कुछ क्षेत्र ही इस श्रेणी में आते हैं । स्थानीय भाषा में यह मिट्टी 'केवल मिट्टी' के नाम से पुकारी जाती है । यह अत्यधिक उर्वर है । यह काले रंग की मटियार दोमट मिट्टी है जो कि सम्भवत वार्बोनीफेरस पदार्थों से ही उत्पन्न हुई है । यह प्रतिक्रिया में हल्की क्षारीय है तथा इसमें कार्बोनिक पदार्थों का सीमश्रण मध्यम श्रेणी का है ।
- (घ) ओड़ी श्रेणी गोंडवाना एवं नाइस समूह की शैलों के बीच में यह क्षेत्र अवस्थित हैं और हाथीनाला समूह के नीचे भूमि की एक पतली तिकोनी पट्टी के रूप में मिलता है । त्रिकोण का शीर्ष औड़ी के पास है और आधार के दोनों सिरे बेलवादह और पहाड़ी (अव जलाशय में) पाये जाते हैं । इस क्षेत्र की मिट्टी लाली लिए हुए मृत्तिकामय है । इस श्रेणी का एक मुख्य भाग अब रिहन्द जलाशय में समाविष्ट है । बैरपान, लोझरा और औड़ी क्षेत्रों के कुछ भाग इस श्रेणी में सम्मिलित हैं ।
- (ड.) कार्बनी फेरस यह श्रेणी भी उसी क्षेत्र में उपलब्ध है, जिस क्षेत्र में गोंडवाना समूह की शैलें फैली हुई हैं । बांसी, खड़िया और चिल्काटांड इस श्रेणी में ही स्थित है ।
- (च) गोहड़ा श्रेणी इस श्रेणी की मिट्टी इस मण्डल में ठीक दक्षिण में बभनी श्रृंखला तथा गोहड़ा क्षेत्र में गोंडा मिर्गारानी और जोराही खण्डों के पास पाई जाती है । यह मिट्टी बलुई दोमट होते हुए भी ठोस और कड़ी है, और उसमें मोरम के रूप में ग्रेंबल तथा अर्घ विषटित शैलों का बाहुल्य है । निम्न क्षितिजों में इनका अनुपात अधिक है । मिट्टी का रंग गहरे लाल से भूरे लाल तक बदलता है । रंग में लाली की मात्रा निचले स्तरों में बढ़ती जाती है ।

- 2- रार्क्सगंज तहसील की मृदा इस भूखण्ड की मृदा पठारी सरचना की है तथा इनकी निम्न विशेषताएं हैं -
- मृदा कम गहरी, मोरम, कंकड़युक्त तथा कही कही लौह पट्ट लिए हुए है । मटियार का अनुपात औसत सामान्यत अच्छा तथा नाइट्रोजन व फास्फेट तत्वों की कमी है ।
- जलधारण क्षमता सामान्य है परन्तु कम गहराई के कारण शीघ्र सूख जाता है।
- मटियार या लौह पट्ट वाली मृदा में जल बहाव अवरूद्ध होता है जिससे दल - दल हो जाता है ।

विन्ध्य क्षेत्र मे अवशिष्ट मूल (रेजुडूअल ओरिजिन) की मृदा पायी जाती है। विन्ध्य श्रेणी के शैलों के अपक्षयन (वेदिरग) से यह मृदा विकसित हुई है । इस भू-खण्ड मे उत्तर मे दक्षिण के क्रम मे विन्ध्य वर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित समुदाय की मृदा पाई जाती है।

बेलन - मटियार दोमट (क्ले)

विजयगढ़ - बलुई दोमट

सोन - बलुई दोमट (सैन्डी लोम)

- दोमट (लोम)
- बारीक बलुई दोमट (फाईनसैन्डी लोम)

परासपानी - बलुई दोमट (सैन्डी लोम)

हाथीनाला - मोटी रेत (कोर्स सैन्ड)

जुगैल - दुद्धी मिट्टी बरगवां, देवखर आदि के दक्षिण में सफेद मिट्टी पर्याप्त रूप से पायी जाती है ।

(क) बेलन समुदाय - इस भू-खण्ड के थोड़े से क्षेत्र मे जो कैमूर पर्वतमाला चोटी के मैदानी भाग में स्थित है, इस समुदाय की मृदा पायी जाती है । मृदा कैल्केरियस प्रकार की है । इसके नीचे कंकर ग्रन्थाएं (कंकर नाड्यूल) हैं ।

- (ख) विजयमढ़ समुदाय इस समुदाय की मृदा कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में पायी जाती हैं । यह सैण्डस्टोन व स्लेट प्रकार की शैलों के अपक्षयन से विकसित हुई है । यह भू भाग पहाड़ी व कटा- फटा है । मृदा का रंग पीला व लाल है । इसकी रचना बलुई दोमट (सैन्डीलोम) प्रकार की है । यह थोड़ी सी अम्लीय अचूर्णिय (नान कैल्केरिअस) तथा मोटी बजरी वाली (कोर्स ग्रेवली) है ।
- (ग) सोन समुदाय इस समुदाय की मृदा सोन नदी के दोनों किनारो मे स्थित भू-भाग मे पायी जाती है । यह मृदा समुदाय आदि विन्ध्य प्रकार की शैल माला के अपक्षयन से विकसित हुई है जिसके चार मुख्य भाग है । मृदा की सरचना बलुई दोमट, दोमट तथा बारीक बलुई दोमट प्रकार की है ।
- (घ) परासपानी समुदाय सोनघाटी के दक्षिण में शैलों का विन्यास अलग प्रकार (विजयवाड माला) का हो जाता है । अतएव यहाँ की मृदा में भी पर्याप्त भिन्नता आ जाती है । भू-भाग पहाड़ी है । मृदा का रंग अधिकतर लाल है । वास्तव में मृदा का रंग जारण अवस्था (आक्सीडेशन स्टेज) पर निर्भर करता है । यह गहरे धूसर से तेज लाल हो जाता है।
- (ड) हाथीनाला समुदाय इस समुदाय की मृदा भू-खण्ड के दक्षिणी भाग (दुन्ही क्षेत्र की सीमा) में पायी जाती है । मृदा के गुण लगभग परासपानी समुदाय की तरह ही है । इसका रंग पीला भूरा या पीला लाल होता है तथा इसमें चमकते हुए अभूक (माइका) के दुकडे दृष्टिगोचर होते हैं ।
- (च) जु**गैल समुदाय भू-ख**ण्ड के उत्तरी पश्चिमी भाग में इस समुदाय की मुदा पायी जाती है । यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की श्रैल श्लेखला विद्यमान है ।

# (र) प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन

प्राकृतिक संसाधनों में वनस्पित एवं वन संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपों में प्राकृतिक वनस्पित मानव - जीवन को प्रभावित करती है। । वन वास्तव में नवीकरण योग्य संसाधन हैं तथा ये उत्पादी और संरक्षी दोनो प्रकार के कार्य करते हैं। ¹² पर्यावरण को शुद्ध रखने, भूमि के कटाव को रोकने, मृदा में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने तथा जलवायु को मृदु बनाने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ¹³ वनस्पित प्रकारों के अध्ययन से सम्बन्ध मुख्यतः प्रमुख जातियों, उनकी दिखावट (वाह्य रूप), अनुकूलन स्वरूप, पारस्परिक

साहचर्य सम्बन्ध तथा जलवायिवक क्रमोत्कर्ष पर पहुँचने के लिए आवश्यक विकास की अवस्थाओं से होता है, अर्थात एक समुदाय के रूप में उनका पूर्ण विकास जिनके बाद उनमे बृद्धि नहीं होती बल्कि वे संतुलित रहते हैं। 14 प्राकृतिक वन से आशय किसी भी भू-भाग पर उन पेड़, पौधों, झाड़ी, जड़ी - बूटियों व घासपातों तथा काई से है जो स्वत उगने, बढ़ने और नष्ट होने के लिए स्वच्छन्द हैं। 15 मृदा की विभिन्नता, उच्चावच्च की विषमता तथा अपवाह प्रणाली के अनुसार स्थानिक रूप मे वनों मे विभेद पाया जाता है। केवल थोड़े से उष्ण नदी तटीय सीमावर्ती (रिपेरियन फिन्जिंग फारेस्ट) वनों को छोड़कर जो नदियों और नालों के किनारों की पट्टियों पर स्थित है, इस भूखण्ड के लगभग सभी वन उत्तरी शुष्क पर्णपाती वर्ग के है। विकासखण्ड चोपन के उत्तर - पूर्व तथा नगवां के दक्षिणी भाग में भरूही (क्लारोक्जाइलौन स्वीटीनिया) प्रमुर मात्रा मे विद्यमान है, इसकी उपस्थिति उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती उपवर्ग में कही जा सकती है। कर्मनाशा नदी तट में पाए जाने वाले साल के बहुत थोड़े से वन को छोड़कर इस जनपद मे सभी वन उत्तरी शुष्क पर्णपाती वर्ग के है। चैन्पियन तथा सेठ के वर्गीकरण के अनुसार इस जनपद में निम्नलिखित वर्ग के वन जाये जाते है। 16

क्रम संख्या	वर्गीकरण	प्रकार
1	2	3
		माइस्ख ट्रापिकल फारेस्ट
1.	4 ई/आर एस ।	उष्ण नदी तटीय सीमावर्ती वन
		ड्राई ट्रापिकल फारेस्ट
2.	5बी/सी - । सी	शुष्क प्रायद्वीपीय साल
3.	5बी/सी 2	उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन
		विकृत अवस्था
4	5/डी एस ।	शुष्क पर्णपाती के क्षुद्ररोह
		मृदीय प्रकार
5.	5 <b>/</b> \\$ 2	सलई वन
6.	5 /ई 4	परसिद्ध वन
7.	5 / <del>\$</del> 9	शुष्क बांस ब्रेक
8.		रोपवन
9.		नदी तट

# (।) नदी तटीय सीमावर्ती वन

इस प्रकार के वन निदयों तथा बड़े नालों के किनारों पर सकरी पिट्टयों मे पाए जाते हैं । वृक्षों की प्रजातियों में कहुआ, जामुन, कठजामुन, करज, आजन, गुटेल तथा गुरही मुख्य है । अन्य वृक्ष प्रजातियों में चिलबिल, तेन्दू, असना, धौ, भुरकुल, खाजा, साल व करम उल्लेखनीय है । अधोवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

### (2) शुष्क प्रायद्वीपीय साल

अध्ययन क्षेत्र के समस्त साल इसी प्रकार के अन्तर्गत आते है । साल न्यूनाधिक अनुपात में लगभग समस्त भू-खण्ड में पाया जाता है । परन्तु इसकी अवस्थिति छोटी निदयों एव बड़े नालों की घाटियों में अधिक है । साथ ही, अपेक्षाकृत ठण्डी उत्तरी ढालों में भी साल का अनुपात बढ जाता है । सोन नदी के उत्तरी भाग में लगभग सभी नालो के किनारे साल न्यूनाधिक अनुपात में पाया जाता है । कैमूर की ढालों मे इसका अनुपात घट जाता है । परन्तु कैमूर पर्वतमाला की चोटी के समतल टुकड़ों में कहीं - कही साल का अनुपात पर्याप्त रूप में बढ़ जाता है । साल वृक्ष शुद्ध रूप में विद्यमान न होकर मिश्रित रूप मे पाया जाता है । साल के प्रमुख मिश्रण वृक्ष तेन्द्र, धौ, सिद्धा, पियार, असना, बहेड़ा, ऑवला आदि उल्लेखनीय है । घासों मे प्रमुख है - बगई, चुराँठ, चिकनिआ तथा भूसभूसिया ।

# (3) उत्तरी मिश्रित पर्णपाती वन

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश वन इसी प्रकार के अन्तर्गत आते हैं । यह वन पहाडियों की चोटियों के समतल भागों, पहाड़ी ढालों, उच्च स्थिलयों व कूटो में विद्यमान है । वृक्ष प्राय क्षीण आकृति व छोटे प्रस्तम्भों वाले हैं । प्राय सभी प्रजातियों के वृक्ष ग्रीष्मकाल में पूर्णतया पर्ण विहीन हो जाते हैं । इनमें वर्षा ऋतु में पुनः नई पित्तयों आ जाती है । इस भाग के प्रमुख वृक्ष तेन्दू, धौ, झींगन, खैर, ककोर, कटैला विरल अवस्था में पाए जाते हैं । इनके अतिरिक्त सर्लई, कुर्लु, धुसुर, आंवला, गलगल आदि भी उपलब्ध है । अधिक समतल भागों व उच्च स्थिलयों में जहाँ मृदा की गहराई अपेक्षाकृत अच्छी है, अनेक प्रजातियों के वृक्ष मिश्रण में पाये जाते हैं ।

# (4) शुष्क पर्णपाती वनों के शुद्ररोह

इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में है, जहाँ विगत कुछ वर्षो मे भारी अनियमित

पातन हुए हैं । ऐसे क्षेत्र अधिकतर गाँवों के पास हैं । इनमे घरेलू जानवरो के चारण, अनियमित पातन, स्कन्धकर्तन (पोलाई) तथा शाखाकर्तन आदि का अत्यधिक जोर है । इन वनों मे पायी जाने वाली झाड़ियों में मुख्य कुलधनई, झरबेरी, भैक्सी, करोंदा, खैर, बेर, कटैला, सेहुड व कोराया है ।

# (5) सलई वन

सर्लई वन लगभग समस्त भू-खण्ड में व्याप्त है । पहाड़ियों के समतल चोटियों, कूटों व बाहुकूटों (स्पर) तथा उच्च स्थिलयों में जहाँ जल का निकास अच्छा हो, सर्लई अधिक पाई जाती है । यह उल्लेखनीय है कि सर्लई प्राय पथरीली व चट्टानी स्थानों में भी जहाँ मृदा कम हो , पाई जाती है । इन वनों में सर्लई उच्च वितान की मुख्य प्रजाति हो जाती है । इसके वृक्ष 10-15 मीटर ऊँचे तथा औसतन 30 से0 मी0 व्यास के है । पहाडियों के चोटियों में कही - कहीं विशुद्ध रूप में भी सर्लई विद्यमान है । सर्लई के वृक्ष की विशेष उपयोगिता मालूम न होने के कारण पिछले वर्षों में कटान से बच गए थे।

# (6) परसिद्ध वन

परिसद्ध वन विस्तृत क्षेत्र में एक साथ नहीं पाया जाता । इसकी अवस्थिति अपेक्षाकृत छोटे व कम विस्तृत क्षेत्रों में देखी जाती हैं । यह लगभग सदाबहार प्रजाति हैं । अतएव शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों में इसकी अलग से पहचान करना सरल होता है । वृक्ष अधिकतर तरूण हैं । कहीं - कहीं प्रौढ़ या अति प्रौढ़ वृक्ष भी दिखाई पड़ते हैं । प्राकृतिक पुनर्जनन सन्तोषप्रद है । जैविक कारणों द्वारा परिसद्ध वनों को बहुत क्षति पहुँचायी गयी है।

# (7) शुष्क बॉस

इस भू-खण्ड में बाँस की केवल एक प्रजाति पाई जाती है । सोन नदी के उत्तर में समस्त तिरया व गुर्मा राजियो में बाँस उपलब्ध है । यह नालो के किनारों तथा समस्त पहाड़ी ढालों में अधिकतर पाया जाता है । परन्तु कहीं - कहीं तो यह चट्टानी व विप्रपाती कूटों (रिज) में भी विद्यमान है । सबसे अच्छे बाँस युक्त क्षेत्र पकरी व कन्धौरा, पश्चिमी ससनई, पूर्वी ससनई, झिरया, गड़ाव, मोहना व भीतरी खण्डों में स्थित हैं । बाँस युक्त सभी क्षेत्रों में उच्च वितान बहुत घनी अवस्था में नहीं है ।

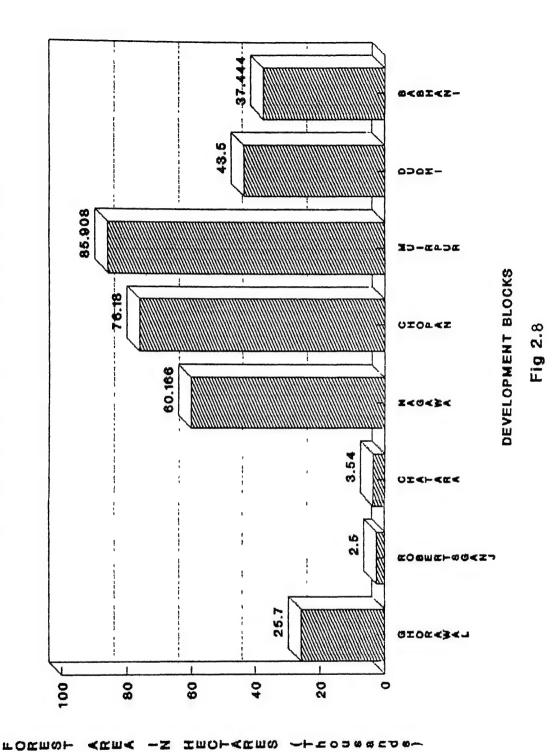
तालिका 2.3 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के 49 11% (334918 है0) क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है । वनो का सर्वाधिक क्षेत्रफल विकासखण्ड म्योरपुर मे है । वनों के क्षेत्रफल के अनुसार अवनत क्रम मे विकासखण्डों की स्थित क्रमश इस प्रकार है - म्योरपुर (25 65%), चोपन (22 74%), नगवा (17 96%), दुद्धी (12 99%), बभनी (11.18%), घोरावल (7.67%), चतरा (1 06%) तथा राबर्ट्सगज (0.75) (तालिका 2.3) । अध्ययन क्षेत्र मे वनों का अनुपात देश व प्रदेश की तुलना में अधिक है । वन ससाधन की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र समृद्ध है । जंगलों में रहने वाले अनेक जंगली जानवरों, पशुओं व पक्षियों की सुरक्षा के लिए 'कैमूर वन अभ्यारण्य' का निर्माण किया गया है । प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण वनों को 4 वन प्रभागों (डिवीजन) तथा 18 राजियों (रेज) में विभक्त किया गया है ।

तालिका 2.3 वर्नों का वितरण 1990 -91

विकासखण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल हे0 मे	वन क्षेत्रफल हेक्टेयर में	क्षेत्रफल का प्रतिशत	कुल वनों का % प्रतिशत
1	2	3	4	5
घोरावल	81873	25700	31 39	7.67
राबर्ट्सगंज	44245	2500	5.65	0.75
चतरा	25485	3540	13.89	1.06
नगवां	91620	60166	65.66	17.96
चोपन	171297	76180	44 46	22 74
म्योरपुर	133789	85908	64 21	25 65
दुद्धी	70745	43500	61 49	12.99
बभनी	60826	37444	61 56	11 18
ग्रामीण योग	679880	334918	49.11	100-00
नगरीय योग	2048			
जनपद योग	681928	334918	49.11	100-00

स्त्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 43 एवं संगणित ।

DEVELOPMENT BLOCKWISE FOREST OF DISTRICT SONBHADRA: 1990 - 91



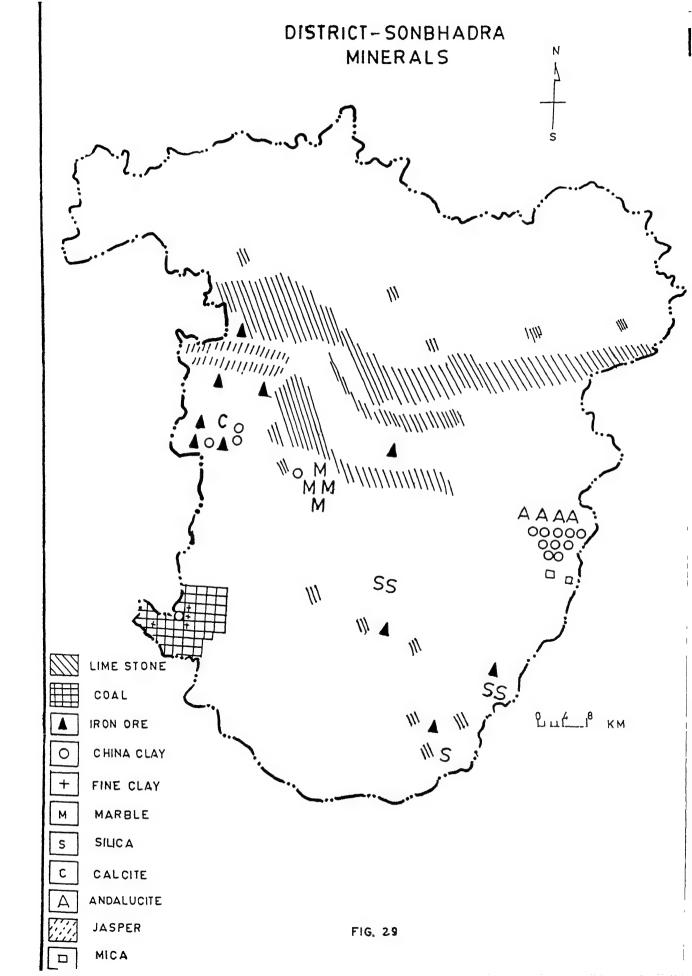
# (ल) खनिज सम्पदा

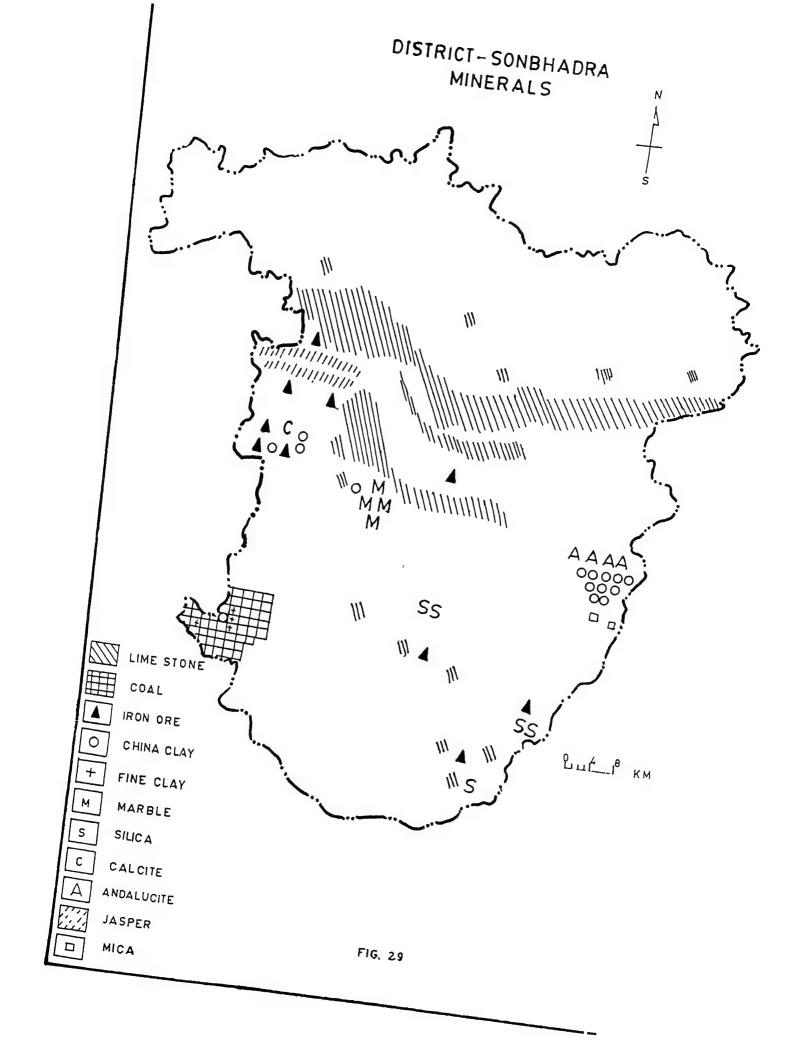
खनिज ससाधनों की विविधता एवं मात्रा की दृष्टि से जनपद सोनभद्र का अद्वितीय स्थान है । रत्नगर्भा के रूप में जहाँ 'काला हीरा' और अभ्रक का भण्डार है, वहीं पर सफेद संगमरमर भी इसी क्षेत्र को प्राप्त है । यहाँ के पत्थरों मे मैगनीज, लोहा, डोलोमाइट आदि के अयस्क प्रचुर मात्रा में पाये जाते है, जिसके कारण सोननदी एवं मारकुण्डी पहाड़ी के मध्य स्थित सलखन एवं पदाध में चूना उद्योग बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं । इतना ही नहीं लौह अयस्क के पत्थर की आपूर्ति बिहार प्रदेश वे बोकारों स्टील प्लांट को भी होता है ।

जनपद मे स्थित खनिजों के आधार पर आसपास के क्षेत्रों में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है । सिंगरौली कोयला क्षेत्र पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र, चूनापत्थर पर आधारित सीमेण्ट कारखाना एवं चूना उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं । जनपद सोनभद्र के प्रमुख खनिजों को निम्न दो वर्गों मे बाटा जा सकता है -

- (।) धात्विक खनिज लौह अयस्क, सोना
- (2) अधात्विक खनिज फेल्सपार, अभ्रक, सल्फाइड, लाइमस्टोन, हीरा, मैग्नेटाइट, भवन व सड़क निर्माण मे काम आने वाले पत्थर ।
- ा. लौह अयस्क लोहे को राष्ट्रीय समृद्धि का प्रतीक माना गया है । मानव सभ्यता के विकास में लोहा एवं उससे निर्मित विविध वस्तुओ का महत्वपूर्ण योगदान है । वर्तमान समय में भी किसी देश की शक्ति का आंकलन लोहे के उत्पादन एवं उसके उपयोग से निर्धारित होता है ।

जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील में बिजावर श्रेणी की शैलों मे लौह अयस्क के कई निक्षेपों का पता लगा है । यह अयस्क बेण्डेड, हीमेटाइट -क्वार्ट्जाइट से बने हुए एवं उससे सम्बद्ध है । प्राचीनकाल में एक स्थानीय जाति 'आगरिया' द्वारा छोटे पैमाने पर कई स्थानों पर इस अयस्क से लोहा निकाला जाता था । ये लोग इससे कृषि आदि कार्यो में उपयुक्त यन्त्र बनाया करते थे । चोपन ब्लाक के बरगवां के लगभग 2 कि0 मी0 दक्षिण - पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित पहाड़ी में, जो पश्चिम से भरहरी तक चली गई है, बेण्डेड हेमेटाईट पाया जाता है । इनमें से कोई भी निक्षेप आर्थिक रूप से मूल्यावान नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में लौह उत्खनन को छोड़ दिया गया है ।





- 2- सोना भारत ही नहीं बल्कि विश्व के आर्थिक गतिनिधियों में सोने का अति महत्वपूर्ण स्थान है । सोने की प्राप्ति या तो शिला संरचनाओं की पट्टिकाओं से अथवा नवीन या प्राचीन निदयों द्वारा अवसादित एल्यूवियम मिट्टी से की जाती है ।
- 3. सल्फाइड बिजावर एवं प्रीकैम्ब्रियन मणिभीय शैलों को काटने वाली क्वार्ट्ज शिराओं में सल्फाइड के खनिज (जैसे पायराइट, चालकों पायराइट आदि) अल्पमात्रा में पाये जाते हैं । कही - कहीं इन खनिजों का प्रमाण तुलनात्मक दृष्टि से अधिक भी हो जाता है ।
- 4- लाइमस्टोन उत्तम कोटि का व अधिक मात्रा में लाइमस्टोन सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है । सोन के ठीक दक्षिण में बरगवा, घटीसा, ओबरा, डाला आदि के आस-पास भी लाइम स्टोन पाया जाता है । यह इस भूखण्ड की सबसे महत्वपूर्ण खनिज सम्पत्ति है । कजरहट चूना पत्थर खान, जिसके नाम पर चुनार में कजरहट सीमेण्ट कारखाना स्थापित किया गया है, इस खान का चूना पत्थर अधिकतर डाला सीमेण्ट के कारखाने में प्रयुक्त होता है । दूसरी महत्वपूर्ण खान गुरमा चूनापत्थर खान है, जिससे पटवध व सलखन में चूना निर्माण उद्योग तथा चुर्क में सीमेण्ट कारखाना स्थापित है । बसुहारी में चूना पत्थर का विशाल क्षेत्र पाया जाता है । इस क्षेत्र को सरकार अपने नियंत्रण में लेकर नया सीमेण्ट कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ।
- 5- **मेग्नेटाइट -** परसोई के पूर्व में बहुत कम गात्रा में क्वार्ट्जाइट के साथ पाया जाता है ।
- 6. **सफेद मिट्टी -** सफेद मिट्टी बरगवां, देवखर आदि के दक्षिण में पर्याप्त रूप से पाई जाती है । स्थानीय निवासी इसे घरेलू उपयोग में लाते है ।
- 7. मृत्तिका (क्ले) सूक्ष्म विभाजित एव अतिसूक्ष्म कर्णो वाली मृत्तिका के निक्षेप बाराकर स्टेज में बांसी, मिश्रा और मकड़ीखोह में उलबब्ध है । निक्षेपो की सम्भावित क्षमता लगभग तीन मिलियन टन ऑकी गयी है, जिसमें से लगभग 2.2 मिलियन टन अग्निरोधक उद्योग द्वारा अग्निरोधक ईटों के निर्माण के लिए उपयुक्त है ।
- 8. निर्माण सामग्री इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नीस, डोलेराइट, क्वार्ट्जाइट सैण्डस्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर आदि भवन, सड़क एवं अन्य उपयोगी सामान बनाने के लिए

उत्कृष्ट स्त्रोत है । बरगवा की दक्षिणी पहाड़ियों में तथा ओबरा के दक्षिण में निम्न कोटि का सगमरमर पाया जाता है । करौंती के ठीक उत्तर में संगमरमर की पट्टी पायी जाती है । इसका रग सफेद है तथा निर्माण सामग्री के लिए उपयुक्त है । महदिया से 2 कि0 मी0 उत्तर पूर्व में नीलिमा लिए हुए चमकीले सगमरमर के बारे में जानकारी मिली है । इसी तरह का एक निक्षेप गीधर के पास पाया जाता है ।

डोलोमाइट के निक्षेप बरगांव और कजरहट में है । ओबरा के पास भलुवा डोलोमाइट खान तथा डाला से 3 कि0 मी0 दूर चोपन रोड पर बारी डोलोमाइट खान सर्वाधिक प्रसिद्ध है ।

सजावटी पत्थर के रूप में काम आने वाले जास्पर, एपिडोट शेल आदि कहीं-कहीं प्रचुरता में पाया जाता है । अनेक स्थानों में कंकड़ उपलब्ध है । हेमेटाइट (लौहयुक्त) तथा जास्पर, जुगैल व पनिसला के दक्षिण-पूर्व में पाये जाते हैं ।

- 9. कोरण्डम मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सीमा से लगे हुए दीप्रा और कडोयनी गाँव के बीच तथा रिहन्द नदी के एक कि0 मी0 पूर्व में पाया जाता है।
- 10. कोयला (सिंगरौली कोल फील्ड लिमिटेड) सिंगरौली एक इलाका है इस नाम का न कोई गाँव है न ही शहर । बताया जाता है कि सिंगरौली एक राज्य था जो मध्य प्रदेश के सीधी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विभक्त हो गया । इस राज्य का महल रिहन्द जलाशय मे जलमग्न है । सिंगरौली कोल फील्ड के अन्तर्गत' खानों में से केवल तीन खान (बीना, ककरी व खड़िया) है । किन्तु अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सम्पूर्ण कोयला क्षेत्र का वर्णन किया गया है । इंडियन ब्यूरो ऑफ महन्स' ने 1961 मे कुछ निश्चित स्थानों पर विस्तृत अध्ययन कराए, जिससे सिंगरौली क्षेत्र भारत के कोयला मानचित्र पर उभर आया । 1963 मे एन० सी० डी० सी० के अन्तर्गत सिंगरौली -। खदान का विधिवत प्रारम्भ हुआ । लेकिन उसे बीच में रोककर 1965 में पहली खदान झिगुरदा परियोजना प्रारम्भ हुई जो कि अपने कोयले की मोटाई (162 मी०) की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है । 18

सिंगरौली क्षेत्र से लगा हुआ पलामू में भी कोयले का विस्तृत भण्डार है । बिहार के हजारी बाग और रॉची क्षेत्र जहाँ 'नेशनल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन' बाद में 'सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड' का मुख्यालय रहा, वहीं से इस क्षेत्र को जिसे सिंगरौली क्षेत्र' कहा जाता था, कोयले के उत्खनन् की देख-रेख लगभग 20 वर्षों तक चली । ऐसे समय में ही रूसी वैज्ञानिक की

तालिका 2.4

1 1 1 1	परियोजना	कुल कोयला क0टन में	खदान क्षेत्र वर्ग किमी0 टन	الما	बुदान की उत्पादन क्षमता सम्पूर्ण क0 अनुमोदित प्रतिवर्ष क0टन/वर्ष	उत्पादन आरम्भ वर्ष	असतन स्ट्रीपिन अनुपात	कुल उत्पादन क0धनमी0	अनुमंदित राशि करोड़ रूपया
-	गोरबी	2 44	1.4	0 -	0.1	1972	1 47	5	7.52
2.	झिगुरदा	12 10	- 5	0.3	0.3	1965	1.15	21.5	24.87
ယ	बीना	10.83	4.0	0.45	0.45	1976	2.2	30.6	168 64
4	जयन्त	34.90	10.1	1.0	1.0	1976	2.6	112.5	378 04
Çī	ककरी	7.19	2.3	0.25	0.25	1980	2.25	20.9	137.80
6	अमलोरी	31.93	9.51	1.0	0.4	1984	4.40	157.3	527.11
7.	दुर्छीचुआ	34.50	8 68	1.0	0.5	1983	3.29	134 9	289.68
$\infty$	खडिया	29.92	7.93	1.0	0 4	1	4.23	145.2	400.00
9	निगाही	49 18	15.54	1.40	0.42	1	3.76	215.3	588.75
0.	मोहेर	37.6	8.8	1.0	1	ı	3.30	147.5	I
=	. गोरबी बी0	छोटी परियोजना	है। दो वर्ष प	पहले प्रारम्भ हुई	हर्द ।				•
12	मरक	प्रस्तावित							3
X	परियोजना क्रम संख्या 3, 5, 8 सोनभद्र में तथा श्रेष सोनभद्र की सीमा पर मध्य प्रदेश में है।	। ३, ५, ८ सोनभद्र	में तथा श्रेष सो	नभद्र की सी	मा पर मध्य प्रदेश	<b>平 8</b>	; ; ; ;	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l		1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

एन0सी0लि0 की गृहपालिका बसुन्धरा जून-जुलाई 1992 पृ0 30.

<del>설</del> ·

देखरेख मे यहाँ के कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं (गोरबी, झिंगुरदा, बीना, जयन्त, ककरी, अमलोरी, दुद्धीचुआ, खड़िया, निगाही, गोरबी बी., मरक तथा मोहेर) को सन् 1974 में सी0 एम0 पी0 डी0 आई0 एल0 ने विभक्त किया । इसमें झिंगुरदा सीम (162 मी0) रानीगज की और अन्य सभी बराकर श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । इस समय 220 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र में लगभग 900 करोड़ टन कोयले का भण्डार छिपा है जो कि प्रमुखत तापीय ऊर्जा के लिए ही उपयुक्त है।

सिंगरौली के दक्षिण में लगभग 200 कि0 मी0 पर मध्य प्रदेश का ही एक प्रमुख कोयला क्षेत्र चिरिमरी' शुरू हो जाता है जो कि वर्तमान मे 'साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड' के अन्तर्गत आता है और यहाँ का भी कोयला 'पावर हाउस' के लिए उपयोग किया जा रहा है। सिगरौली में कोयले की तीन परत है -

- (क) पुरेवा टाप (12 मीटर),
- (ख) पुरेवा बाटम (९ मीटर) और
- (ग) तुर्रा (20 मीटर)।

ये खानें अन्य स्थानों के विपरीत पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर नीचे है जिन्हें आसानी से खुली खदान (ओपन कास्ट) विधि से ऊपरी सतह को हटाकर कोयले को खोद लिया जाता है । इस कार्य के लिए आजकल उच्च तकनीक ने 'डम्पर', 'शावेल', 'ड्रेगलाइन' आदि अनेक उत्खनन यन्त्र उपलब्ध हैं । दुधीचुआ परियोजना को विश्वबैंक से जयन्त, खडिया, निगाही परियोजनाओं को भूतपूर्व सो एसघ से, अमलोरी को ब्रिटेन से सहायता मिली हैं । मशीनों को चलाने के लिए उच्च स्तर के तकनीकी और कुशल कारीगर 'नार्दर्न कोल फील्ड्स लि0' में लगभग सभी मिलकार 15 हजार से अधिक कार्यरत है । यहाँ का प्रति मजदूर 6.67 घ०मी० कोयला उत्पादन करता है जबिक कोल इण्डिया में औसतन एक घ० मी० से नीचे, मजदूर निकाल पाते हैं । इस क्षेत्र में नार्दर्न कोल फील्ड्स लि0 जो कि कोल इण्डिया लि0 की एक सहायक कम्पनी है और जिसका 1985 में गठन किया गया था, विगत कई वर्षों में कोयला उत्पादन से करोड़ों रूपयों का लाभ प्राप्त कर रही है ।

# 2.3 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

सोनभद्र और मीरजापुर उत्तर प्रदेश का एक हृदय क्षेत्र है । यह जनपद अनादिकाल से वन्य - सभ्यता के कारण लिलत कलाओं का केन्द्र तो रहा ही है जनजातीय संस्कृति का भी केन्द्र रहा है। 19 विन्ध्य शैल समूह तथा कैमूर क्षेत्र के मध्य मे स्थित यह जनपद पवर्तों की कठोरतम् चट्टानों तथा तरल लावा के शीतल होने से बनी प्राचीनतम् जलज चट्टानों से बना है। इस भू - भाग को आदि मानव की क्रीड़ा - स्थली होने का श्रेय प्राप्त है। मिले प्रमाणों के अनुसार निश्चय ही इस अचल की गोद मे पृथ्वी के, पहले मानव ने क्रीड़ाए की होंगी। उसके अस्तित्व एवं मानव विकास की लम्बी यात्रा के प्रमाण इस क्षेत्र मे यत्र - तत्र बिखरे रूपों में पाये जाते हैं, जो कई अपरदन सतहों में मिलते हैं। 20

यहाँ आदिम प्रजातियाँ नदी के किनारे या पर्वतों की गुफाओं मे निवास करती थी । शिकार इनकी आजीविका थी, जो नुकीले पत्थर और हड्डी के हथियार से किया जाता था । पंचमुखी के शैलाश्रित गुहाचित्र जिसके प्रमाण है । आज भी ओबरा पानी की टकी के नीचे की गुफा मे लावा के गिरने से बने स्तम्भ तथा डमडम पहाडी की गुफा में जलज चट्टानों द्वारा बने नुकीले तेज पत्थर देखे जा सकते हैं । इन शैल चित्रों मे पशु - पक्षियों के शिकार नृत्य, सगीत तथा पारम्परिक जीवन के विविध दृश्य समाहित है जिनको कुछ विदेशी इतिहासकारों ने ईसा पूर्व 400 वर्ष बताया । डाँ० हसमुख सांकलिया ने इस सभ्यता को ईसा से एक से पाँच लाख वर्ष पूर्व स्वीकार किया है । सोढ़रीगढ़ के अवशेष, पचमुखी की खुदाई से मिले सामान, सिक्के तथा वर्तन के टुकड़े व मूर्तियाँ पाषाणकाल की सभ्यता के बारे में जानकारी देते है । ऐसा अनुमान है कि इस समय तक आदमी गुफा से निकल कर मकान आदि बनाने तथा श्रृंगार आदि करने लगा होगा । पशु पूजा, वृक्ष पूजा तथा मातृ पूजा आदि शुरू हो गयी होगी ।

रामायण व महाभारत काल के सास्कृतिक चिह्न यहाँ प्राप्त हुए हैं । सुनसुमार गिरि यहीं था । कहा जाता है कि महाभारत युद्ध मे जरासंध ने अनेक नरेशों को यहीं बंदी बनाकर रखा था । किन्तु प्राचीन काल में कभी आर्य यहाँ तक पहुँच पाये होंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता । पौराणिक कथाओं तथा यहाँ पर मिले शिवलिंग व प्रतिमाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि शैव मतावलिम्बयों ने इस भू-भाग पर शासन अवश्य किया होगा और शिव मन्दिर तथा शिवलिंग की स्थापना की होगी । शिवद्वार स्थित शिव - पार्वती की सृजन प्रतिमा शायद इसी काल की है ।

तृतीय शताब्दी में कान्तित (कान्तिपुरी) नाग वंशीय वाकाटक राजवंश के राजाओं की राजधानी रही तथा नवीं शताब्दी तक उन्नत रही । ऐसा उल्लेख मिलता है कि ग्यारहवीं से तेरहवी शताब्दी के मध्य यह क्षेत्र द्वितीय काशी के रूप में विख्यात रहा । कहीं - कहीं पर ऐसा वर्णन भी मिलता है कि पाँचवी शताब्दी में विजयगढ़ किले पर कोल राजाओ का आधिपत्य रहा और तेरहवी शताब्दी में आभीर वंश के प्रतापी राजा राज्य किया करते थे । आभीर जाति को हर्ष तथा दण्डी के समय तक मान्यता प्राप्त थी । किवदन्ती है कि राजश्री इन्ही वनों मे शरण ली थी । अगोरी दुर्ग पर गदनशाह, विजयगढ़ पर काशी नरेश राजा चेत सिंह, सोढ़रीगढ़ पर गहड़वाल राजाओं का अन्तिम आधिपत्य था । मजरी कथा व चनवा की कथा लोरिक से सम्बन्धित है, जो इसी स्थान पर घटी घटनाए है । लोरिक पत्थर मारकुण्डी पर आज भी शौर्य एवं सुहाग के प्रतीक के रूप में विख्यात है ।

### (अ) लोकगीत, नृत्य एवं नाट्य

कृषि क्षेत्रों के विस्तार तथा औद्योगिक सभ्यता के प्रसार के फलस्वरूप आदिवासी जातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं , किन्तु उनकी संस्कृति विद्यमान है । अध्ययन क्षेत्र की लोक संस्कृति बहुत ही प्रभावशाली है । वीर लोरिक की वीरता एव प्रेम की कहानी को इस क्षेत्र में आज भी 'लोरिकायन' के रूप में श्रद्धा के साथ गाया और सुना जाता है । लोरिकायन में वर्णित करीब - करीब सभी स्थल सोनभद्र में ही हैं, जिसके प्रमाण यहाँ मिलते हें । लोरिकायन को लिपबद्ध नहीं किया गया था । फिर भी इस क्षेत्र की जनता के कंठ में आज भी 'लोरिकी' 'चनैनी' के रूप में विद्यमान है । बीसवीं शताब्दी का मध्य 'कजली' का स्वर्ण युग कहा जाता है । राबर्ट्सगज 'कक्ली' के अखाड़ों के लिए प्रसिद्ध था । इस शताब्दी के प्रारम्भ में जहांगीर खलीफा ने 'कजली' की शुरूआत की थी । 1940 -41 में चिकया, 1943 - 44 में अहरौरा एव 1942 में मिर्जपुर में कजली की प्रतियोगिता हुई । पंडित रामिनहोर ने राबर्ट्सगंज में एक अखाड़ा बनाया । इसके बाद से सोनभद्र कजली का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया । विजयगढ़, अगोरी व कण्डाकोट दुर्ग, पंजमुखी, मुखादरी, सीतामुण्ड आदि की गुफाओं की बनावट तथा वहां बने विचित्र चित्र आज भी कोतुहल व तिलस्म - बोध करते हैं, जिसका रोचक वर्णन देवकी नन्दन खत्री के लोकप्रिय उपन्यास 'चन्द्रकांता' व 'चन्द्रकाता संस्तित' में देखने को मिलता है।

अध्ययन क्षेत्र में अनेक नृत्य होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं - करमा, कोलदहकी, धरकहरी, अगरही, डोमकच, सैलानृत्य, गोदनही, करगही, ललहीछठ, उधवा, झूमर तथा मोखाजा। जनपद सोनभद्र की इस विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के सौष्ठव और विविधता मे वृद्धि करने की आवश्यकता है । इन परम्पराओं को संकलित, संगृहित तथा सरिक्षत कर भारत महोत्सव के माध्यम से देश - विदेश मे प्रचारित व प्रसारित करने की आवश्यकता है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब औद्योगिक सभ्यता इसका समूल विनाश कर देगी ।

# (ब) जनसंख्या

### (।) जनसंख्या वितरण एवं घनत्व

प्रादेशिक अध्ययन के विषय - वस्तु का केन्द्र बिन्दु मानव है । मानव एक उत्पादक, सेवाओं का सृजन-कर्ता, उपभोक्ता तथा स्वय एक ससाधन है । इसमे प्रकृति को प्रभावित करने एव उससे अनुकूलन की अपार क्षमता होने के बावजूद अनेक भौतिक तथा सास्कृतिक कारकों ने जनसख्या वितरण को प्रभावित किया है । भौतिक कारकों मे अभिगम्यता, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी तथा जल की उपलब्धि आदि मुख्य कारक है । सास्कृतिक कारकों मे सास्कृतिक समूहों का विस्थापन, उत्प्रवास तथा राजनैतिक कारणों द्वारा विस्थापन आदि सम्मिलित है । अध्ययन क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को उपर्युक्त कारकों ने अत्यधिक प्रभावित किया है । जिन विकासखण्डों में अपेक्षाकृत अच्छी कृषि होती है (घोरावल, राबर्ट्सगज एवं चतरा), वहाँ जन-घनत्व सबसे अधिक है तथा जिन विकासखण्डों रेग वटे उद्योगों का विकास हुआ है , वहाँ भी अन्य विकासखण्डों की अपेक्षा अधिक जन-घनत्व है । नगवा व बभनी विकासखण्ड मे न तो उल्लेखनीय कृषि होती है और न ही उद्योग पाए जाते हैं फलत जन-घनत्व सबसे कम पाया जाता है । अवनत क्रम में विकासखण्डवार प्रति वर्ग कि0 मी0 जन-घनत्व इस प्रकार है - राबर्ट्सगंज (312), चतरा (265), घोरावल (191), म्योरपुर (144), दुद्धी (137), चोपन (97), बभनी (94) तथा नगवा (60) (तालिका 2-6) ।

तालिका 2.5 जनसंख्या वितरण 1991

विकासखण्ड	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	गत दशक से वृद्धि प्रतिशत
	2	3	4	5
। . घोरावल	155963	82359	73604	35.77
2. राबर्ट्सगंज	137889	72784	65105	<b>26</b> .60
3.चतरा	67441	35404	32037	27.71
4.नगवां	54518	28637	25881	29-21

	2	3	4	5
5 चोपन	166693	88609	78084	26.43
<ol> <li>म्योरपुर</li> </ol>	192719	105623	87096	77.63
7 दुद्धी	96533	50826	45707	34.28
८. बभनी	57618	30102	27516	26 06
वन ग्राम	1584	855	<b>72</b> 9	-
गामीण योग	930958 (86.6%)	495199	435759	36.25
नगरीय योग	144083 (13.4%)	82204	61879	-
जनपद योग	1075041	577403	497638	38.75

स्त्रोत - सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 28 एवं संगणित ।

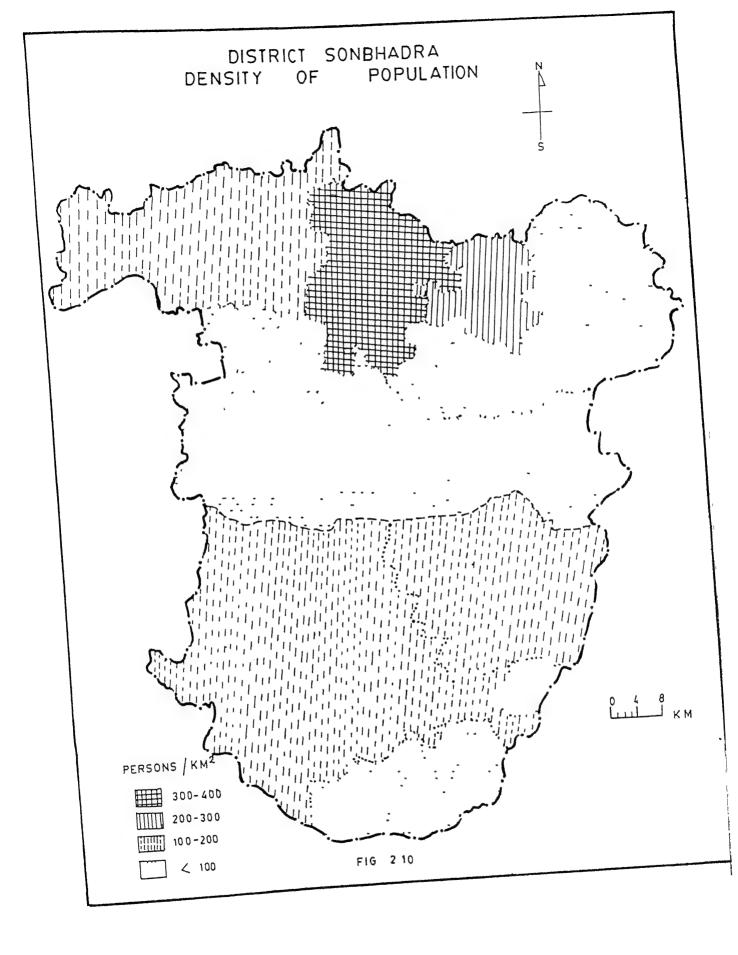
यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में प्रति दशाब्दी जन-घनत्व मे वृद्धि हो रही किन्तु उत्तर प्रदेश व भारत की तुलना में जन-घनत्व अभी भी बहुत कम है (तालिका -2 6)। 1951 में अध्ययन क्षेत्र का प्रति वर्ग कि0 मी0 जन - घनत्व 49 था। 1961, 1971, 1981 तथा 1991 में क्रमश 63, 83, 114 तथा 158 हो गया । 1991 में उत्तर प्रदेश का जन घनत्व 47। तथा भारत का 267 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 था।

तालिका 2.5 से स्पष्ट है कि विकास खण्ड चोपन में जनसंख्या, क्षेत्रफल की तुलना में (लगभग 25%) कम (लगभग 18%) है । कृषि प्रधान विकासखण्ड घोरावल, राबर्ट्सगज तथा चतरा में 'क्षेत्रफल प्रतिश्रत' की तुलना में 'जनसंख्या प्रतिश्रत' अधिक है । उद्योग प्रधान विकासखण्ड म्योरपुर व दुद्धी के क्षेत्रफल व जनसंख्या प्रतिश्रत के अनुपात में बहुत अधिक समानता है, जबिक उद्योग विहीन एवं अल्प कृषि क्षेत्र युक्त विकासखण्ड नगवां व बभनी में क्षेत्रफल की तुलना में

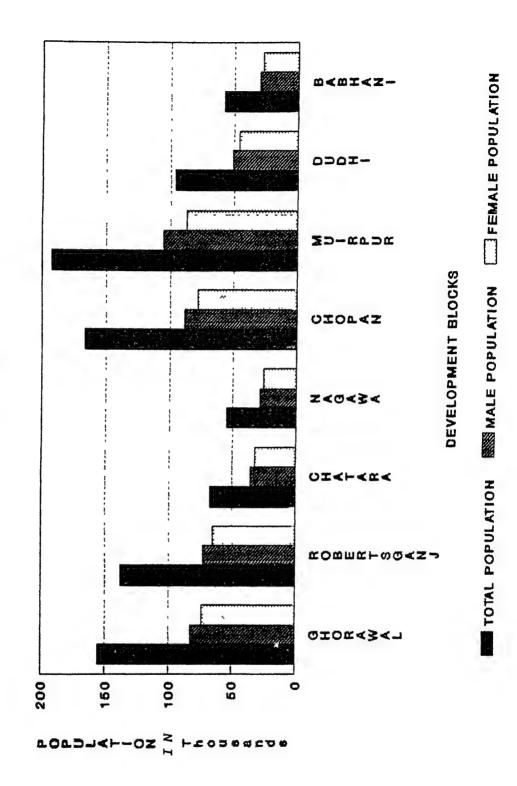
# तालिका 2.6

# जनसंख्या घनत्व

वष 	ि। विकास खाण्ड	घनत्व प्रति वर्ग किमी0
195	51	49
196	51	63
197	71	83
198	31	114
199	) [	158
विक	स खण्ड १९९१	
1.	घोरावल	191
2	राबर्ट्सगज	312
3	चतरा	265
4	नगवा	60
5.	चोपन	97
6	म्योरपुर	144
7	<b>दु</b> न्ही	137
8	बभनी	94
- <b>-</b> .		
	ग्रामीण	137
	नगरीय	7035
	सम्पूर्ण जनपद	158
उत्त	र प्रदेश	471
भारत	<b>T</b>	267



# DEVELOPMENT BLOCKWISE POPULATION OF DISTRICT SONBHADRA: 1991



जनसंख्या बहुत ही कम है (तालिका 2 । व 2 5) । इससे स्पष्ट है कि कृषि तथा उद्योग जनसंख्या वितरण को प्रभावित किए है। उल्लेखनीय है कि उद्योग प्रधान विकास खण्ड म्योरपुर में जनसंख्या वृद्धि गत कुछ वर्षों में ही हुआ है। 1981-91 मे म्योरपुर में 77 63% जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसका प्रत्यक्ष कारण उद्योग एव खनन है।

अध्ययन क्षेत्र की 1951 में जनसंख्या 331170 थी जो 1991 में बढ़कर 1075041 हो गयी। प्रतिदशक जनसंख्या वृद्धि 1961, 1971, 1981, व 1991 में क्रमश 30.40, 30 59, 37.39 तथा 38.75% हुई (तालिका - 2.7) । अध्ययन प्रदेश में कुल 8 नगरीय क्षेत्र (घोरावल, राबर्ट्सगज, चुर्क - गुरमा, ओबरा, पिपरी, रेजूकूट, चोपन व दुद्धी) है, जिनसे 13 4% लोग रहते हैं। 86.6% जनसंख्या ग्रामीण है (तालिका - 2 5)।

तालिका 2.7 जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	जनसंख्या	गत दशक से वृद्धि	गत दशक से वृद्धि प्रतिशत में
1951	331 170		
1961	431841	100671	30 40
1971	563954	132113	30.59
1981	774804	210850	37.39
1991	1075041	300237	38 75

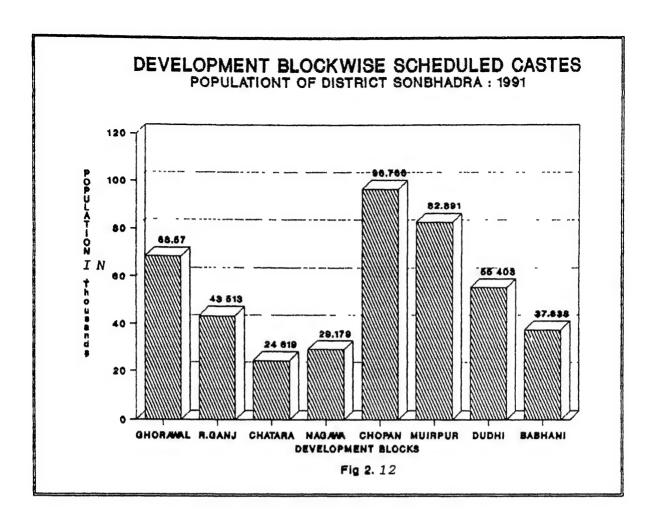
# (2.) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

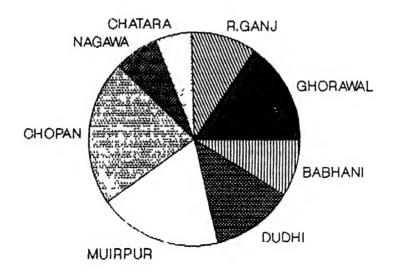
अध्ययन क्षेत्र' में अनुसूचित जातियों की बहुलता है। सरकारी आकड़ों में 1981 तक एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं थी। ऐसा लगता है उन्हें अनुसूचित जाति मे सम्मिलित कर लिया गया था। किन्तु 1991 में 139 अनुसूचित जनजाति के लोगों की पहचान की गयी है। इसमें 94 पुरूष तथा 45 महिलाएं हैं। ²¹ अध्ययन क्षेत्र में कुल 456872 लोग अनुसूचित जाति के हैं जो कुल जनसंख्या के 42.5% है। 96.24% अनुसूचित जाित के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 3.76% नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। अवनतक्रम में इनकी जनसंख्या प्रत्येक विकास खण्ड में इस प्रकार हैं - चोपन - 21.18%, म्योरपुर - 18 14%, घोरावल - 15%, दुद्धी - 12.13%, राबर्टसगंज - 9.52%, बभनी - 8.24%, नगवां - 6.39% तथा चतरा 5 39% (तािलका 2.8) । विकास खण्ड चोपन, म्योरपुर, घोरावल व दुद्धी में सिम्मिलित रूप से लगभग 65% अनुसूचित जाितयां रहती हैं। भारत में अनुसूचित जाित के 15.8% तथा उत्तर प्रदेश में 23 3% लोग हैं। अत तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन प्रदेश में इनकी संख्या अधिक है। तािलका 2.8

अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1991

क्रम सं0	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या	प्रतिशत	
t	घोरावल	68570	15 00	
2.	राबर्टसगंज	43513	9.52	
3	चतरा	24619	5.39	
4.	नगवा	29179	6.39	
5	चोपन	96766	21.18	
6.	म्योरपुर	82891	18.14	
7	दुखी	55403	12 13	
8.	बभनी	37638	8.24	
वन ग्राम		1109	0 24	
ग्रामीण		439688	96.24	
नगरीय योग		17184	3.74	
सम्पूर्ण जनप		456872	100.00	

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र 1992, पृष्ठ 30 एवं पृष्ठ 31 से सगणित 1





# (3.) साक्षरता

अध्ययन क्षेत्र में 1971 में 20 60%, 1981 में 27.50% तथा 1991 में 34 40% लोग साक्षर थे। 1991 में पुरूषों की साक्षरता 47 56% तथा स्त्रियों की 18 56% थी। भारत में 52.11% लोग साक्षर है जिनमें पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत कृमश 63.86 तथा 39 42 है। भारत की तुलना में अध्ययन प्रदेश में बहुत कम लोग साक्षर हैं। विकास खण्ड म्योरपुर, चतरा, राबर्ट्सगज, घोरावल, दुन्धी, चोपन, बभनी व नगवा में साक्षरता प्रतिशत कृमश 41 29, 31 04, 30.32, 25.42, 22 94, 20 73, 19 28 व 18.27 है। सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 27.92% लोग साक्षर हैं, जबिक नगरीय क्षेत्र म 74.08% लोग साक्षर हैं (तालिका 2.9)।

तालिका 2.9 जनपद सोनभद्र में साक्षरता प्रतिशत

कुल	पुरूष	स्त्री
2	3	4
20.60	29.10	10 90
27.50	38.00	15 10
34.40	47.56	18 56
25.42 30.32 31.04 18.27 20.73 41.29 22.94	38.69 45.40 47.91 29.55 31.47 54.07 36.05 31.66	10.28 13.09 12.08 5.56 8.07 25.01 8.02 5.42
	2 20.60 27.50 34.40 25.42 30.32 31.04 18.27 20.73 41.29	2 3 20.60 29.10 27.50 38.00 34.40 47.56 25.42 38.69 30.32 45.40 31.04 47.91 18.27 29.55 20.73 31.47 41.29 54.07 22.94 36.05

1	2	3	4	
वनग्राम	29 34	46 04	9.68	
ग्रामीण योग	27.92	41.12	12 49	
नगरीय योग	74.08	84.08	60.20	
सम्पूर्ण जनपद	34.40	47.56	18.56	

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ - 41 ।

## (4.) व्याक्सायिक संरचना

तालिका 2.10 को देखने से स्पष्ट हो होता है कि 43.21% लोग कृषक है, तथा 26.90% लोग कृषि मजदूर है। सम्पूर्ण कृषि कृषि से सम्बन्धित कार्यों में लगे लोगों की संख्या कुल कर्मकरों की 70.87% है। निर्माण कार्य मे 1.27%, यातायात एव संचार मे 1.12% तथा खनन कार्यों में 0.98% जनसंख्या लगी है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ बड़े उद्योगों की आवस्थापना के बावजूद अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान है।

जनपद के कुल कार्यशील जनसंख्या को ।। व्यवसाय वर्ग में विभक्त किया गया है। प्रत्येक कार्य में लगे लोगो की संख्या व प्रतिशत तालिका - 2 10 में प्रदर्शित है।

## (स) बस्तियों का प्रतिरूप

बस्तियों का प्रतिरूप कोई आकस्मिक कारकों अथवा घटना का परिणाम नहीं होता। उसका सीधा सम्बन्ध जिस स्थान पर बस्ती की उत्पत्ति हुई है उससे तथा उसकी नाभि के विन्यास से होता है। हैगेट (1979) के अनुसार धरातल पर बस्तियों मानव व्यवसाय की अभिव्यक्ति है तथा सांस्कृतिक भू-दृश्य के रूप में विकसित मानव की

तालिका - 2.10 जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना - 1991

क्रमसंख्या	व्यक्साय		कुल संख्या का प्रतिशत
1		3	
1.	कृषक	194849	43 21
2.	कृषक मजदूर	121310	26 90
3.	पशुपालन, जंगल लगाना		
	व वृक्षारोपण	3423	0 76
<ul><li>4.</li><li>5.</li><li>6.</li><li>7.</li></ul>	खान खोदना प्रारिवारिक उद्योग गैर पारिवारिक उद्योग निर्माण कार्य	4425 5213 23918 5741	0 98 l 16 5 30 l 27
8.	व्यवसाय एवं वाणिज्य	13009	2 89
9.	यातायात एवं संचार	5072	1.12
10.	अन्य कर्मकर	33776	7.49
11.	कुल मुख्यकर्मकर	410636	91.07
12	सीमान्त कर्मकर	40265	8.93
13.	कुल कर्मकर	450901	

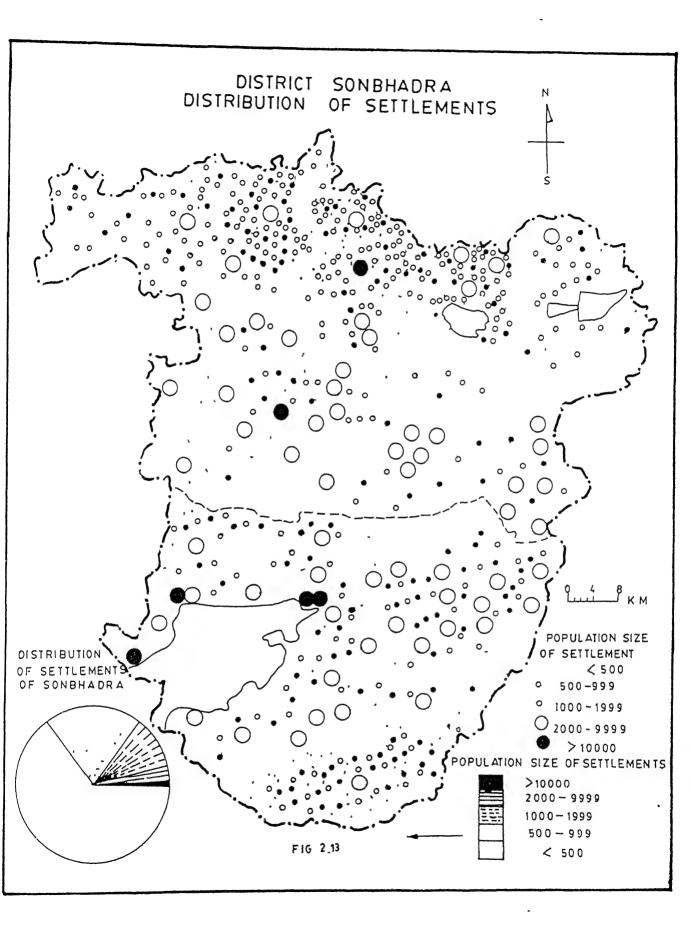
स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ - 32, 33, 34 एवं इसके आधार पर सगणित ।

प्रथम रचनायें हैं, प्रत्येक बस्ती की अपनी मौलिक विशेषता होती है। कुछ सामान्य विशेषताओं यथा आकार, अन्तरालन, बसाव प्रतिरूप तथा गहनता आदि के परिप्रेक्ष्य में बस्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। आकारकीय एवं कार्यात्मकता के

तालिका - 2.।। जनसंख्या के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण जनसंख्या का आकार

क्रम सं0	वि <b>कासख</b> ण्ड	200 से कम	200-499	500-999	1000-1999	2000-4999	5000 से अधिक	योग
5 I		2	ω	4	5	6	7	8
	घोरावल	121	119	80	<u>ట</u>	ယ	i i	354
	राबर्ट्सगंज	122	135	60	18	σ		340
	चतरा	87	61	26	13	ယ	ı	190
	नगवां	53	53	28	8	-	ŧ	143
	चोपन	14	17	20	17	19	6	93
	म्योरपुर	14	33	28	30	<b>=</b>	00	124
	ુ તું	16	29	21	24	12	t	102
	बभनी	7	24	8	22	ı	~	72
1	वनग्राम	6	-	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	- !	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	© 1
	ग्रामीण योग	440	472	281	164	54	15	1426
	जनपद योग	440 (30.86%)	472 (33.10%)	281 (19.71%)	164	54 (3.76%)	15 (1.05%)	1426

म्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ - 42

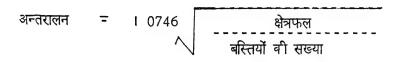


आधार पर बस्तियों को ग्रामीण एवं नगरीय दो वर्गों में विभक्त किया जाता है ।

जनपद सोनभद्र में 8 नगरीय बस्तियों तथा 1346 ग्रामीण बस्तियों है। यद्यपि सम्पूर्ण ग्रामों की संख्या 1426 है। ग्रामीण क्षेत्रों मे कुल 86.6% तथा नगरीय क्षेत्रों मे 13 4% जनसंख्या निवास करती है। सम्पूर्ण अध्ययन प्रदेश में 200 से कम जनसंख्या वाले गावों की संख्या 440, (30.86%) 200 से 499 जनसंख्या वाले गावों की संख्या 472 (33 10%), 500 से 999 जनसंख्या वाले गांवों की संख्या 281 (19.71%), 1000 से 1999 जनसंख्या वाले गांवों की संख्या 164 (11.50%), 200 से 4999 जनसंख्या वाले गांवों की संख्या 54 (3 29%) तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की संख्या 15 (1.05%) है (तालिका 2.11) ।

अध्ययन क्षेत्र में बड़ी बस्तियों की अवस्थित दूर-दूर है। बस्तियों की जनसंख्या के अनुसार आकार में कमी के साथ-साथ उनके बीच की दूरी में कमी पायी जाती है। सामान्यतया बस्तियों का आकार परिवहन मार्गों के अभिगम्यता से प्रभावित होती है। बस्तियों का स्वरूप कृषि प्रधान क्षेत्रों में संहत है किन्तु अधिकाम्न बस्तियां विकीर्ण है। बस्तियों का अवस्थापनात्मक वितरण बस्तियों की सघनता और अन्तरालन के द्वारा समझा जा सकता है। बस्तियों की सघनता से तात्पर्य प्रति 100 वर्ग किमीं। क्षेत्र में बस्तियों की सख्या से है। जनपद में बस्तियों की सघनता 21 बस्ती प्रति 100 वर्ग किमीं। है, जो काफी न्यून है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्षेत्रीय वितरण और अधिक असमान है। प्रति 100 वर्ग किमीं। में सबसे अधिक बस्तियां कृषि प्रधान विकास खण्डों राबर्ट्सगज, चतरा तथा घोरावल में क्रमश 77, 75 तथा 43 है। शेष विकास खण्डों नगवां, दुद्धी, बभनी, म्योरपुर तथा चोपन मे क्रमश 16, 14, 12, 9 तथा 5 है। विकास खण्ड चोपन में प्रति 100 वर्ग किमीं। बस्तियों की सख्या 5 अत्यधिक कम है।

बस्तियों की सघनता तथा अन्तरालन में विलोम सम्बन्ध है। सघनता कम होने पर अन्तरालन बढ़ता है। तथा सघनता बढ़ने पर अन्तरालन कम होने लगता है, उपर्युक्त तथ्य तालिका - 2.12 से स्पष्ट है। बस्तियों के अन्तरालन की गणना माथेर (1944) द्वारा प्रयुक्त सूत्र द्वारा की गयी है, जो निम्नलिखित है -



तालिका 2.12 गाँवों की सघनता और अन्तरालन

क्रम सं <b>0</b>	विकासखण्ड	सघनता प्रति ।00 वर्ग किमी0	अ <b>न्तरालन</b> किमी0 में	-
1.	घोरावल	43	1 63	
2	राबर्ट्सगज	77	1 23	
3	चतरा	75	1 25	
4	नगवां	16	2 72	
5	चोपन	5	4-61	
6	म्योरपुर	9	3 54	
7	दुद्धी	14	2 83	
8	बभनी	12	3 12	
	जनपद योगः	21		

अध्ययन प्रदेश के बस्तियों की सघनता और अन्तरालन के विश्लेषणोपरान्त कहा जा सकता है कि बस्तियों का वितरण प्रतिरूप असमान है। बस्तियों का असमान वितरण प्रतिरूप भ्वाकृतिक विशेषताओं तथा कृषि से प्रभावित है। भौतिक तथ्यों का बस्तियों के वितरण प्रतिरूप पर सबसे अधिक प्रभाव है। अध्ययन क्षेत्र की अधिकाश बस्तियां मिट्टी, लकड़ी व घास-फूस से निर्मित हैं।

जनपद में नगरीय बस्तियों की संख्या बहुत कम है। कुल 8 नगरीय क्षेत्र (घोरावल, राबर्ट्सगंज, चुर्क-गुरमा, ओबरा, चोपन, दुर्द्धी, रेनूकूट तथा पिपरी) है। नगरीय जनसंख्या 13.4% है। अध्ययन क्षेत्र के अनेक औद्योगिक केन्द्रों जैसे - रिहन्द नगर, शिक्तिनगर, अनपरा, रेणूसागर, डाला आदि को नगरीय क्षेत्र की मान्यता शीघ्र मिलने की सम्भावना है। अध्ययन क्षेत्र मे नगरीकरण बहुत धीमी गित से हो रहा है। यहाँ ग्रामीण बस्तियों व ग्रामीण संस्कृति का ही बाहुल्य है।

किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक पृष्ठभूमि के वर्णन मे कृषि, उद्योग तथा परिवहन एव सचार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अध्याय - 4 मे कृषि, अध्याय - 5 में उद्योग तथा अध्याय - 6 में परिवहन एव सचार का विस्तृत वर्णन एव विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसलिए तथ्यो के पुनरावृत्ति न होने देने की दृष्टि से इस अध्याय मे उपर्युक्त तथ्यों को वर्णित नहीं किया गया है।

### सन्दर्भ

- केशरी, अर्जुनदास 'सोनभद्र एक नयी संस्कृति को जन्म देगा', स्वतन्त्र भारत, लखनऊ,6 मार्च 1989.
- 2. Gazetteer of India, Uttar Pradesh, District Mirzapur, 1988,p.1
  - 3. वही, मानचित्र सख्या 2.1 से सगणित
  - 4 एकीकृत जिला योजना, जनपद सोनभद्र, 1992-93, पुष्ठ 5.
- 5. सिंह, सविन्द्र[.] 'भू आकृति विज्ञान', बसुन्धरा प्रकाशन, दाउदपुर, गोरखपुर, 1982, पृष्ठ 652-53.
  - 6 वही, प्रष्ठ 652
  - 7. वही, प्रष्ठ 654.
  - 8 वही पृष्ठ 652.
  - 9. पूर्वोक्त संदर्भ संख्या 2, प्रष्ठ 16.
- 10. ओबरा वन प्रभाग, उत्तर प्रदेश की प्रबन्ध योजना 1992-93,2001-2, कार्य योजना कृत प्रथम.
- ।।. सिंह, जगदीश, राव, बच्चा प्रसाद व सिंह, रामबली तीन दक्षिणी महाद्वीप (तुलनात्मक प्रादेशिक अध्ययन), तारा पन्लिकेशन, वाराणसी, 1980, पृष्ठ 59.

- 12. कुरैशी, एम0एच0 'भारत, ससाधन और आर्थिक विकास' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1990, पृष्ठ ।।
- 13. कुरैशी, एम0एच0 'भूगोल के सिद्धान्त', भाग 11, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1989, पृष्ठ 6.
- 14. रजा, मुनीम व एजाज, अहमद,: भारत का सामान्य भूगोल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1978, पृष्ठ 74.
- 15 चेतन, सुदर्शन कुमार 'हमारे वन' , प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1981, पृष्ठ ।.
  - 16. पूर्वोक्त सदर्भ संख्या 10, पृष्ठ 37.
  - 17. नवभारत टाइम्स, लखनऊ, ४ मार्च 1992, पृष्ठ ४.
  - 18. एन0सी0एल0 की गृहपालिका, 'बसुन्धरा, 1992,पृष्ठ 11-12.
- 19. केशरी, अर्जुनदास संस्कार भारती, ओबरा (शोणभद्र) की स्मारिका,4 अप्रैल 1992, पृष्ठ 31.
- 20. सोनभद्र, इतिहास और संस्कृति, संस्कार भारती, ओबरा (सोणभद्र) की स्मारिका, अप्रैल 1992, पृष्ठ 27
  - 21. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 31

### बस्तियों का स्थानिक - कार्यात्मक संगठन एवं नियोजन

प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जिसका निर्माण न केवल वहाँ प्राप्त संसाधनों द्वारा अपित वहाँ निवास करने वाले लोगों के द्वारा भी होता है । ससाधनों तथा आर्थिक क्रियाओं के असमानता के कारण ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न स्तरीय सेवा केन्द्रों का अभ्युदय तथा विकास होता है । इन सेवा केन्द्रों का अधिवास प्रतिरूपों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । अन्य देशों की भौति भारत मे भी विभिन्न भौगोलिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सुसहत एवं व्यासत दोनों ही प्रकार के अधिवास प्रतिरूपों का विकास हुआ है । इन दो प्रतिरूपों के अतिरिक्त दोनों के मध्य अनेक प्रतिरूपों जैसे विसारित पल्लियों आदि का भी विकास स्थान विशेष की विशिष्ट सामाजिक एव आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मिलता है । 2 कृषि आधारित बडे पैमाने पर संहत भारतीय बस्ती प्रतिरूप की मुख्य विशेषता है । 3 अध्ययन क्षेत्र मे अधिकाशत पायी जाती हैं । अहमद ⁴ ने उत्तरी सोनभद्र मे विसारित प्रकार का अधिवास तथा दक्षिणी सोनभद्र में व्यासृत अधिवास का प्रतिरूप बताया है । व्यासृत बस्तियाँ ऐसे बस्तियों के प्रतिरूप हैं जिनमें आवासगृह परस्पर दूरी पर स्थित होते हैं और सम्पूर्ण बस्ती बिखरी एव फैली हुई होती है । उत्तरी सोनभद्र के विकासखण्ड घोरावल, राबर्ट्सगंज एवं चतरा के बेलन घाटी कृषि क्षेत्र में नाभिक बस्तियाँ पायी जाती है । ये ऐसे बस्तियों के प्रतिरूप है जिसमें आवासगृह सुसंहत होते **हैं । माइत्सेन** ⁵ ने सुसंहत ग्रामीण अधिवास को सामुदायिक कृषि व्यवस्था से और व्यासत आवासगृहों को व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था से सम्बन्धित बताया है ।

नगरों का विकास गाँवों से होता है और नगरवासी निरन्तर ग्रामवासियों के परिश्रम पर ही पनपते हैं । 6 सामाजिक - आर्थिक अधःसंरचना की दृष्टि से ये ग्रामीण बस्तियाँ नगरी बस्तियों की अपेक्षा पर्याप्त रूप से पिछड़ी हैं । इनके पिछडेपन के कारण ही बड़े पैमाने पर कार्यशील जनसंख्या का स्थानान्तरण गाँवों से नगरों की ओर हो रहा है, जो भारतीय जनसंख्या की प्रमुख समस्या है । गाँवों से नगरोन्मुखी स्थानान्तरण की समस्या का समाधान, ग्रामीण बस्तियों की सामाजिक - आर्थिक अधःसंरचना के विकास मे निहित है । 7 इस समस्या का समाधान क्षेत्र के विकास द्वारा ही सम्भव है और उस क्षेत्र का विकास ऐसे अनेक बस्तियों के माध्यम से किया जा सकता है जहाँ लगभग सभी आधारभूत सामाजिक-

आर्थिक सुविधाओं का केन्द्रीकरण हो । यदि ये बस्तियाँ आवागमन एवं सचार माध्यमों से आपस में सुसम्बद्ध हो जाय तो विकास की गित और तेज हो सकती है । प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र 'पिछड़ी अर्थव्यवस्था' का प्रतिरूप है । अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत बस्तियों को पहचनाने का प्रयास किया गया है जो संख्या मे अल्प हैं । साथ ही सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए, विकेन्द्रीकरण के माध्यम से, ऐसे नवीन केन्द्रों का चयन तथा विकास केन्द्रों के रूप में संवर्धन के लिए नियोजन प्रस्तुत किया गया है ।

### 3.1 विकास - केन्द्र की संकल्पना

जिन बस्तियों में किसी भी मात्रा या गुण के सामाजिक एवं आर्थिक क़ियाओं का संकेन्द्रण हो जाता है, विकास - केन्द्र के रूप मे अभिहित किया जाता है । विकास-केन्द्रों को अनेक नामों से जाना जाता है जैसे - सेवा केन्द्र, विकास - ध्रुव, केन्द्र-स्थल व विकास बिन्दु आदि । कार्यों की तीव्रता के आधार पर विकास केन्द्रों को तीन वर्गों - (1) विकास ध्रुव, (2) विकास केन्द्र, और (3) विकास बिन्दु, में रखा गया है । प्रो0 आर0 पी0 मिश्र 8 (1975) ने विभिन्न प्रकार के कार्यों की संरचना के आधार विकास केन्द्रों को निम्न 6 वर्गों में विभक्त किया है -

- ।. विकास ध्रुव
- 2. विकास केन्द्र
- 3. विकास बिन्दु
- 4. सेवा केन्द्र
- 5. बाजार केन्द्र
- 6. गाँव केन्द्र

प्रस्तुत अध्ययन में इन सभी प्रकार के विकास जनक केन्द्रों को विकास केन्द्र कहा गया है कुछ बस्तियों की विशिष्ट स्थिति एवं कार्यों के केन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप विकास केन्द्रों के रूप में अभिनिर्धारण हो जाता है । ऐसी बस्तियों ही सम्बन्धित कार्यों द्वारा अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवा प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें सेवा केन्द्र के रूप में अभिहित किया जाता है । ⁹ इस प्रकार की बस्तियों की पहचान सर्वप्रथम मार्क जेफरसन ¹⁰ ने केन्द्र स्थल (सेन्ट्रल प्लेस) के रूप में किया था । इसी आधार पर क्रिस्टालर ¹¹ ने 'केन्द्र स्थल सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया । सेवा केन्द्रों का आधार छोटे गाँव से लेकर वृहद् नगरों तक होता है । ये कन्द्र विकास तथा नवाचार के जनक होते है । इन सेवा केन्द्रों के आधार पर पेराउक्स ¹² महोदय ने, जो एक अर्थशास्त्री थे, विकास धृव सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। बोडेविले ¹³ ने इस सिद्धान्त को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में नया आयाम दिया ।

### 3.2 विकास केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

कोई भी विकास केन्द्र चाहे जिस आकार प्रकार का हो वह सामाजिक - आर्थिक कार्यों का संग्रह केन्द्र होता है तथा समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है । बड़े विकास केन्द्रों में विकास कार्यों की सख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है । किसी भी विकास केन्द्र की स्थापना एव स्थायित्व उन सामाजिक - आर्थिक कार्यों पर निर्भर करता है, जिसके द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा प्रदान करता है । अतः ये केन्द्र परिधीय क्षेत्र से इष्टतम रूप में जुड़े होते है । इन केन्द्रों के सेवाओं का लाभ प्रत्येक जन तक पहुँचे, इसके लिए सम्पूर्ण क्षेत्र में विभिन्न स्तर के सेवा केन्द्रों का जाल होना चाहिए । वास्तव में ये केन्द्र सामाजिक - आर्थिक कार्यों के क्रीड़ा स्थल के रूप मे होते हैं । इन सेवा केन्द्रों का स्वरूप स्थानीय इकाई के समान होता है, जिनके द्वारा अधिकांश सुविधाएँ एवं सेवाएं प्रमुखत निश्चित क्षेत्र के लोगों को दिए जाते हैं ।

सेवा केन्द्रों या केन्द्र स्थलों पर अनेक कार्यों का सकेन्द्रण होता है किन्तु इनमें से कुछ कार्य केन्द्र स्थल की जनसंख्या के लिए तथा कुछ कार्य समीपवर्ती क्षेत्र (सेवित क्षेत्र) की जनसंख्या के लिए होते हैं । स्वयं केन्द्र स्थल की जनसंख्या को सेवा प्रदान करने वाले कार्यों को सामान्य कार्य (नान बेसिक फंक्सन) तथा समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने वाले कार्यों को आधारभूत कार्य (बेसिक फंक्सन) कहा जाता है, जिस पर ही उनकी अवस्थित होती है । सामान्यतः सामान्य कार्य सभी बस्तियों द्वारा किये जाते है किन्तु आधारभूत कार्य कुछ विशिष्ट बस्तियों द्वारा ही सम्पादित होते हैं । क्रिस्टालर 14 ने इन

आधारभूत कार्यों को केन्द्रीयकार्य (सेन्ट्रल फक्सन) कहा है । भट्ट 15 ने तकनीकी, सस्थागत कारणों से असर्वगत (नान यूबीक्यूट्स) तथा कुछ निश्चित क्षेत्रों की सेवा के लिए निश्चित स्थानों पर अवस्थित सेवाओं को 'केन्द्रीय कार्य' के रूप मे माना है । राजकुमार के अनुसार जिन कार्यो से लोगो का स्थानान्तरण संभव होता है उसे 'केन्द्रीय कार्य' कहते है। यह स्थानान्तरण दैनिक, मासिक, वार्षिक, स्थायी, अस्थायी आदि अनेक रूपों मे हो सकता है। किन्तु किसी भी कार्य का केन्द्रीय कार्य होना इस बात पर निर्भर है कि उसका उस क्षेत्र में क्या महत्व है ? किसी विकास केन्द्र के केन्द्रीय कार्यों का महत्व, स्वय उस केन्द्र एव सम्बन्धित क्षेत्र के विकास में योगदान से है । सम्बन्धित केन्द्र एव क्षेत्र का विकास केन्द्रीय कार्यों का प्रतिफल होता है । इन विकास केन्द्रों का विकास, परिधीय क्षेत्रों के योगदान का भी परिणाम है । वास्तव मे केन्द्रीय कार्यों का सम्बन्ध सम्बन्धित विकास केन्द्र एवं क्षेत्र का विकास करने है । अत ऐसे कार्यों को 'केन्द्रीय विकास कार्य' (सेन्ट्रल ग्रोथ फक्सन) कहना अधिक उपयुक्त है । प्रस्तुत अध्ययन में प्रशासनिक, कृषि एवं पशुपालन, शिक्षा एव मनोरंजन, परिवहन एवं संचार, चिकित्सा, वित्तीय तथा व्यापार एवं वाणिज्य से सम्बन्धित 35 कार्यों को केन्द्रीय विकास कार्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है । सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे व्याप्त इन कार्यों को प्रवेशी जनसंख्या (इन्ट्री प्वाइट पापुलेशन), संतृप्त जनसंख्या (सेचुरेशन प्वाइट पॉपुलेशन) और कार्याधार जनसंख्या (थ्रीशोल्ड पॉपुलेशन) के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका 3.। केन्द्रीय विकास कार्य

	ध्ययन क्षेत्र में ल संख्या	प्रवेशी जनसंख्या	सपृक्त जनसंख्या	कार्याधार जनसंख्या
1	2	3	4	5
(क) प्रशासनिक कार्य				
। जिला मुख्यालय	t	20669	20669	20669
2 तहसील मुख्यालय	2	8960	20669	14815.5
3. विकासखण्ड केन्द्र	8	1078	20669	10873.5
4 . न्याय पंचायत केन्द्र	66	438	11413	5925.5
5. थाना	12	334	43325	21839.5
6. पुलिस चौकी	7	996	35247	18121.5

~~~~~~~~				
1	2	3	4	5
(ख) कृषि एवं पशुपाल	ग न			
7. शीत भण्डार	ı	20669	20669	20669
8 बीज, कीटनाशक ए	वं			
उर्वरक केन्द्र	78	264	1544	904
9. पशु अस्पताल	16	667	43345	22006
10 पशु सेवा केन्द्र	20	362	1863	1112 5
(ग) श्रिक्षा एवं मनोरंज	न			
।। महाविद्यालय	2	8960	43345	26152 5
 हायर सेकेन्ड्री वि 	30	508	6250	3379
13. सीनियर बेसिक वि	96	317	6263	3275
। ४ जूनियर बेसिक वि(715	122	658	390
। ५ छविगृह	5	9837	35247	22542
(घ) परिवहन एवं संच	गर			
।6 रेलवे स्टेशन हाल्ट सहित	26	539	12190	6364 5
17. बस स्टेशन	18	810	8901	4855 5
18. बस स्टाप	42	240	4381	2310.5
19. फेरी घाट	10	310	33383	16846.5
20 डाकघर	136	160	1851	1005.5
21. दूरभाष एवं तारघर	16	2250	6350	4300
(ड) चिकित्सा				
22. अस्पताल	5	8960	43345	26152.5
23. प्रा0 स्वा0 केन्द्र	29	456	6260	3353
 अायुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा 	तय 17	448	35247	1883.5
25. होम्योपैथिक चिकित्सालय	20	320	43345	21832.5

	2	3	4	5
26 मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्रः एवं उपकेन्द्र	118	110	815	462.5
27. पंजीकृत व्यक्ति- गत क्लिनिक	106	285	6250	3267 5
28 पजीकृत औषधालय	36	860	6250	√ 3555
(च) वित्तीय कार्य				
29 राष्ट्रीय बैंक	50	250	6250	3250
30 भूमि विकास बैंक	2	8960	20669	14815.5
3। जिला सहकारी बैंव	F 10	1300	35247	18273.5
32. सयुक्त ग्रामीण बैंक	10	1248	35247	18247.5
(छ) व्यापार एवं वाणि	च			
33. फुटकर बाजार	46.	48	863	455 5
34 थोक बाजार	8	2250	20669	13280
35. साप्ताहिक बाजार	36	242	24310	12276

3.3 केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम

जो कार्य जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है उसका स्तर भी उतना ही ऊँचा होता है । कार्यों के महत्व से केन्द्र की केन्द्रीयता प्रभावित होती है । अतः किसी निश्चित स्तर के कार्यों से युक्त केन्द्र का महत्व और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वह केन्द्र अधिक जनसंख्या की सेवा करता है । परन्तु उतनी ही मात्रा में उससे उच्च स्तर के कार्यों को सम्पादित करने वाले वेन्द्र का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि वह और अधिक जनसंख्या की सेवा करता है । इसलिए केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम निर्धारण, नितान्त आवश्यक

है । प्रत्येक केन्द्रीय कार्यों के निर्धारण में उनका तुलनात्मक महत्व निर्धारित होता है । 'कार्यों की प्रवेशी जनसंख्या' के आधार पर मिरयालगुड़ा तालुका के अध्ययन में, एल0 के0 सेन 17 ने कार्यों का पदानुक्रम निर्धारित किया है । किन्तु ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से प्रवेशी जनसंख्या प्रभावित होती रहती है जो कार्यों के पदानुक्रम के निर्धारण में सर्वथा सक्षम नही होता है । अत प्रस्तुत अध्ययन में कार्याधार जनसंख्या सूचकांक को पदानुक्रम निर्धारण मे आधार बनाया गया है । 'कार्याधार जनसंख्या' किसी भी प्रदेश मे किसी भी कार्य को उपयुक्त ढग से सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, जो प्रदेश से सम्बन्धित कार्य की प्रवेशी और सपृक्त जनसंख्या के बीच की स्थित होती है ।

प्रवेशी जनसंख्या से तात्पर्य किसी कार्य को सम्पादित करने से सम्बन्धित उस निम्नतम जनसंख्या से है जिस पर किसी बस्ती में किसी कार्य की अवस्थापना हो । प्रस्तुत अध्ययन मे प्रवेशी जनसंख्या की गणना सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के बस्तियों मे से की गयी है । जनसंख्या वह जनसंख्या आकार है जिसके ऊपर किसी प्रदेश मे कोई कार्य (यूबीक्वीटस) हो जाता है । 18 किन्तु, प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में इस नियम का दृढता से पालन करना संभव नहीं है । उदाहरण स्वरूप जनपद मुख्यालय की जनसख्या 20669 है । इसे सपुक्त जनसंख्या मानने में कठिनाई यह है कि इससे अधिक जनसंख्या वाले अध्ययन क्षेत्र में 4 केन्द्र (ओबरा - 43345, रेनुकूट - 25247, शक्तिनगर - 33383 तथा अनपरा - 24310) हैं किन्तु जनपद मुख्यालय तो एक ही हो सकता है । ऐसे कई कार्यों के संपृक्त जनसंख्या निर्धारण में, सम्बन्धित कार्य को करने वाले सबसे बड़े केन्द्र की जनसंख्या को संपृक्त जनसंख्या मान लिया गया है । कार्याधार जनसंख्या की गणना रीड मुञ्च 19 विधि द्वारा इसके बाद सबसे कम कार्याधार जनसंख्या वाले कार्य की जनसंख्या से सभी कार्यों की कार्याधार जनसंख्या में भाग देकर कार्याधार जनसंख्या सुचकांक की गणना की गयी है । पुन कार्याधार जनसंख्या सुचकांक के निरीक्षण के बाद कार्यों के 4 पदानुक्रम निर्धारित किए गए हैं । तालिका 3.2 में कार्य, उनकी कार्याधार जनसंख्या तथा उनका सूचकांक तथा तालिका 3.3 में कार्यी का पदानुक्रम का विवरण दिया गया है।

तालिका 3.2 कार्य एवं कार्याधार जनसंख्या सूचकांक

क्रम सं0	केन्द्रीय कार्य		कार्याधार
		जनसंख्या 	जनसंख्या सूचकाक
1	2	3	4
1	महाविद्यालय	26153	67 05
2	अस्पताल	26153	67 05
3	छविगृह	22542	57.80
4	पशु अस्पताल	22006	56 43
5	थाना	21840	56.00
6.	होम्योपैथिक चिकित्सालय	21832	55.98
7	जिला मुख्यालय	20669	52.99
8.	शीत भण्डार	20669	52.99
9	जिला सहकारी बैंक	18274	46.86
10.	संयुक्त ग्रामीण बैंक	18248	46.79
11	पुलिस चौकी	18122	46.47
12	फेरी घाट	16847	43.20
13.	तहसील मुख्यालय	14816	38.00
14.	भूमि विकास बैंक	14816	38.00
15.	थोक बाजार	13280	34 05
16.	साप्ताहिक बाजार	12276	31.48
17.	विकास खण्ड केन्द्र	10874	27.88
18.	रेलवे स्टेशन	6365	16.22
19.	न्याय पंचायत	5926	15 19
20.	बस स्टेशन	4856	12.45
21.	टेलीफोन एवं तारघर	4300	11.03
22.	पंजीकृत औषधालय	3555	9.12

	2	3	4
23	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	3379	8 66
24.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3353	8.59
25	सीनियर बेसिक विद्यालय	3275	8.40
26.	पंजीकृत व्यक्तिगत क्लिनिक	3268	8 38
27	राष्ट्रीय बैंक	3250	8 33
28.	बस स्टाप	2311	5.93
29.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय	1884	4 83
30	पशु सेवा केन्द्र	1113	2.85
31	डाकघर	1006	2.58
32.	बीज,कीटनाशक एवं उर्वरक केन्द्र	904	2 32
33.	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	463	1.19
34.	फुटकर बाजार	456	1.16
35	जूनियर बेसिक विद्यालय	390	1 00

तालिका 3.3 कार्यों के चार पदानुक्रम

पदानुक्रम	कार्याधार जनसंख्या सूचकांक	कार्यो की सख्या
1	2	3
I	67.05 से अधिक	2
II	43.20 से 57.80	
III	27.88 से 38.00	5
IV	1.00 से 16.22	18

3.4 विकास केन्द्रों का निर्धारण

भारत में वर्तमान विकास केन्द्रों का प्रतिरूप ऐतिहासिक- सांस्कृतिक शक्तियों तथा एवं राजनैतिक आवश्यकताओं का परिणाम है।²⁰ विकास केन्द्रो के निर्धारण से तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र में अवस्थित बस्तियों में से उन बस्तियों का चयन करना जो वितरित बस्तियो का सेवा-केन्द्र के रूप में सेवा कर रहा हो। सेवा केन्द्रों के निर्धारण की प्रक्रिया सिद्धान्त रूप मे जितनी आसान लगती है व्यावहारिक रूप में उतनी ही जटिल प्रक्रिया है। अध्ययन प्रदेश के विपुल बस्तियों में से किन-किन बस्तियों को किस मात्रा में तथा किस आधार पर सेवा-केन्द्र का अभिनिर्धारण किया जाय? वांछित आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण परिमाणात्मक मानदण्डो का उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। फलत वास्तविक विकास केन्द्रों का सुनिश्चयन नहीं हो पाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजित एवं परिभाषित बस्तियों कभी-कभी समस्या खड़ी कर देती हैं। कुछ गाँवों में कई पुरवे अनेक केन्द्रक के रूप में कार्य करते हैं तथा कभी-कभी राजस्व गाँव वास्तविक बस्ती की इकाइयों से मेल कभी-कभी एक ही सातत्यकीबस्ती कई राजस्व गाँवों में बटी होती है। कभी-कभी कुछ चौराहे, मोड़ या मुख्य सड़क की अवस्थितियाँ इतनी महत्वपूर्ण होती है कि मात्र एक या दो कार्यों के सम्पादन के बावजूद व्यावहारिक रूप में कई बड़े सेवा केन्द्रों से महत्वपूर्ण प्राय यह भी देखने को मिलता है कि केन्द्रीय कार्यों की अवस्थिति सरकारी आंकड़ों में वस्तुत प्रदर्शित नहीं होता है। अत सेवा केन्द्र के केन्द्रीय कार्यों की गणना में प्राय कठिनाई होती है। घोरावल विकास खण्ड का मुख्यालय घोरावल मे न होकर खुरूवाव में है। नगवां विकास खण्ड का मुख्यालय वैनी में है। चतरा विकास खण्ड का मुख्यालय रामगढ़ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि चतरा, राबर्ट्सगंज विकास खण्ड की बस्ती है जबिक रामगढ़ उक्त विकाखण्ड में नहीं आता है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो विकास केन्द्रों के निर्धारण में समस्या उत्पन्न करती हैं।

सामान्यतः सेवा केन्द्रों का निर्धारण केन्द्रीय सेवाओं की उपस्थिति, केन्द्रीयता तथा केन्द्रीयता सूचकांक, जनसंख्या आकार, कार्यशील व कुल जनसंख्या के अनुपात, केन्द्रीय कार्यों के कार्याधार जनसंख्या तथा बस्तियों के सेवा क्षेत्र के आधार पर या उपर्युक्त आधारों में एकाधिक आधारों पर किया जा सकता है। विगत कुछ वर्षों में भारत में सेवा केन्द्रों

के निर्धारण में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। सुधीर वनमाली 2 ।, सेन 22 , नित्यानन्द 23 , कुमार एव शर्मा 24 , एसoबीo सिंह 25 तथा खान 26 आदि विद्वानों ने कार्यों के सकेन्द्रण के आधार पर सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया है जिसमें कार्यों के औसत कार्याधार जनसंख्या को भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त दत्ता 27 ने परिवहन सूचकांक के आधार पर आलम 28 ने जनसंख्या के आधार पर, जीoकेo मिश्र 29 ने प्राथमिक कार्याधार जनसंख्या के आधार पर, जगदीश सिंह 30 जनसंख्या के आकार और कार्यों की उपस्थित के आधार पर तथा भट्ट 31 एवं पाठक 32 आदि विद्वानों ने बस्तियों की केन्द्रीयता को सेवा केन्द्रों के निर्धारण में आधार माना है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सेवा केन्द्रों के निर्धारण की अनेक प्रक्रियाए है। सभी प्रक्रियाए व्यक्तिनिष्ठ है क्योंकि सेवा केन्द्रो का चयन, केन्द्रीय कार्यों का चयन तथा सतप्त जनसंख्या बिन्दु का चयन जिसके ऊपर ही सम्पूर्ण विश्लेषण सभव है, अध्ययनकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। प्रस्तुत अध्ययन में कार्यों की औसत कार्याधार जनसंख्या, परिवहन द्वारा बस्तियों की सम्बद्धता तथा केन्द्रीय कार्यों की अवस्थित के माध्यम से सेवा केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया गया है। सर्वप्रथम केन्द्रीय कार्यों को सम्पादित करने वाली बस्तियो मे उन्ही का चयन करने का प्रयास किया गया है जिनकी जनसंख्या सम्बन्धित कर्यों की कार्याधार जनसंख्या से ऊपर तत्पश्चात् किन्ही दो केन्द्रीय विकास कार्यों को सम्पादित करने वाली बस्तियों का चयन किया गया है जिनका मान 3.16 से अधिक है। चयनित सेवा केन्द्रों में से अधिकाश केन्द्रों पर जुनियर बेसिक विद्यालय, मातु एव शिशु कल्याण केन्द्र एवं उपकेन्द्र तथा फुटकर बाजार पाए जाते है। अत सेवा केन्द्रों के कार्यात्मक अक की गणना मे उपर्युक्त कार्यों के मान को नहीं जोड़ा गया है। यद्यपि फुटकर बाजार के मान (2 17) से राष्ट्रीय बैंक (2), पजीकृत व्यक्तिगत क्लिनिक (0 94), डाकघर (0.74) सीनियर बेसिक विद्यालय (। 04) तथा न्याय (1 52) का मान कम है किन्तु इन कार्यों की कुछ सेवा केन्द्रों पर ही उपस्थिति के कारण इनके मान को जोडा गया है, उक्त मानदण्डो के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में कुल 63 सेवा केन्द्रों को मान्यता प्रदान की गयी है। इन 63 सेवा केन्द्रों का जनसंख्या तथा सम्पादित होने वाले कार्यों की संख्या तालिका 3.4 में प्रदर्शित है। इन सेवा केन्द्रों द्वारा सम्पादित कार्यों का नाम तालिका 3.1 मे तथा इनकी स्थानिक अवस्थितिया मानचित्र 3 1 मे प्रदर्शित है ।

तालिका 3.4 जनपद में निर्धारित सेवा केन्द्र

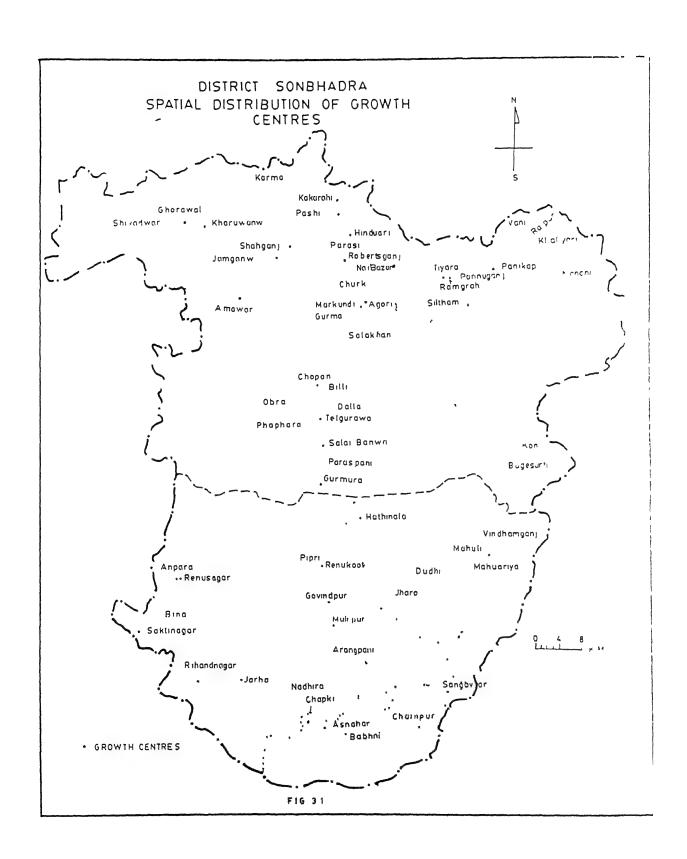
क्रम स्तंख्या	सेवा केन्द्रों का नाम		सम्पादित होने वाले केन्द्रीय
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1991	कार्यों की संख्या
1	2	3	4
1	राबर्ट्सगंज	20669	25
2	दुर्खी	8960	24
3	घोरावल	4361	16
4	रामगढ	2250	17
5	बैनी	1300	12
6	चोपन	8901	17
7	म्योरपुर	2747	15
8	बभनी	4326	15
9	चुर्क	6250	14
10	ओबरा	43350	20
11	डाला	4370	11
12	सलखन	978	9
13	गुरमा	4040	8
14	रेनूकूट	35247	17
15	पिपरी	12190	15
16	अनपरा	24310	18
17.	रेणूसागर	6350	7
18.	बीना	3710	11
19.	शक्तिनगर	33383	14
20.	रिहन्द नगर	9837	15
21.	खलियारी	1351	10

I	2	3	4
22	माची	996	6
23	पनिकप	663	3
24	पन्नूगज	334	3
25	तियरा	435	2
26	सिलथम	508	7
27	नई बाजार	710	6
28	ककराही	836	7
29	परासी दूबे	991	7
30	मारकुण्डी	1214	5
31	तेलगुडवा	810	4
32	कोन	1850	12
33	हाथीनाला	963	6
34	गुरमुरा	1660	6
35	सलई बनवा	854	4
36	बिल्ली	1488	6
37	परासपानी	1675	6
38	फफरा	693	5
39	बागेसुर्ती	761	4
40	खरूवाव	1078	4
41	शाहगज	1863	11
42	शिवद्वारा	1460	5
43	जमगाव	883	3
44.	करमा	980	7
45	पसही	883	6
46	गोविन्दपुर	638	6
47	जरहा	6233	7

1	2	3	4
48	सागोवार	1851	8
49	निधरा	4381	5
50	विण्ढमगज	1248	12
51	महुली	1438	8
52	अमवार	463	7
53	चपकी	1549	6
	चेनपुर	1163	7
54	-	807	7
55	असनहर महुअरिया	539	7
56	नहुआर्या झारो	1661	9
57			4
58	हिन्दुआरी 	461	3
59	लिलासी	662	
60	आरगपानी	4347	4
61	रायपुर	973	4
62	चकरिया	739	2
63	अगोरी	944	3
64	कि र् विल	3355	2
65	सण्डी	523	2
66.	नाकों -	317	l

3.5 केन्द्रीयता का निर्धारण

केन्द्रीयता सेवा केन्द्रों के निर्धारण का अभिन्न अंग है। केन्द्रीयता से सेवाकेन्द्रों के महत्व का आंकलन तथा सापेक्षिक महत्व का पता चलता है। सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारण भी केन्द्रीयता के आधार पर किया जा सकता है। किसी केन्द्र की केन्द्रीयता उसके द्वारा सम्पादित कार्यों के गुण और उनकी मात्रा का द्योतक है। ³³ भट्ट³⁴ ने कार्यों की मात्रा



एव गुण के साथ-साथ कार्यों की सभाव्यता को केन्द्रीयता कहा है। किसी भी केन्द्र की केन्द्रीयता का उसके जनसंख्या आकार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है परन्तु यह अनिवार्य नहीं है। कभी-कभी जनसंख्या आकार तथा केन्द्रीयता मे ऋणात्मक सम्बन्ध भी दृष्टिगत होता है।

केन्द्रीयता का निर्धारण एक जटिल एव व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। इसका निर्धारण एक या एक से अधिक आधारों पर किया जा सकता है। क्रिटालर (1933)³⁵ ने दक्षिणी जर्मनी में टेलीफोन कनेक्सन के आधार पर केन्द्रीयता का निर्धारण किया। डनकन³⁶, ब्रश्न³⁷, स्मेल्स³⁸, कार्टर³⁹, उल्मेन⁴⁰, हार्टले एव स्मेल्स⁴¹ तथा कार⁴² आदि विद्वानों ने किसी केन्द्र पर पाए जाने वाले सभी चयनित कार्यों के आधार पर केन्द्रीयता का निर्धारण किया। ब्रेसी⁴³ ने केन्द्रों के आकर्षण शिवत के आधार पर तथा ग्रीन⁴⁴, केस्थर्स⁴⁵ ने आकर्षण शिवत के साथ-साथ केन्द्रों की विभिन्न केन्द्रों से परिवहन सम्बद्धता को भी ध्यान में रखा है। सिद्दाल ने फुटकर और थोक व्यापार अनुपात तथा एबियोदन⁴⁷ ने 1967 में 'बहु-विचर विश्लेषण' (मल्टी वेरीएट एनालिसिस) के द्वारा केन्द्रीयता का निर्धारण किया। 1971 में प्रेस्टन⁴⁸ ने फुटकर व्यापार तथा औसत पारिवारिक आय के आधार पर केन्द्रीयता मॉडल प्रस्तुत किया किन्तु आकडो पर अत्यधिक निर्भरता, इसके व्यावहारिक प्रयोग को सीमित कर देती है। वाश्चिगटन के स्नोहिमश काउन्टी के अध्ययन में बेरी और गैरिशन⁴⁹ ने 1958 में केन्द्रों के केन्द्रीयता निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों व उसकी कार्याधार जनसख्या और पदानुक्रम का उपयोग किया।

भारतीय विद्वानों ने भी केन्द्रीय स्थलों की केन्द्रीयता का निर्धारण अधिकांशत केन्द्रीय कार्यों के सख्या के आधार पर किया है। कार्यों के आधार पर विश्वनाथ $(1967)^{50}$ ओ०पी० सिंह (1971), 51 प्रकाशाराव $(1974)^{52}$, जगदीश सिंह $(1976)^{53}$ आदि विद्वानों ने सराहनीय कार्य किया है। कार्यों की परस्पर यातायात सम्बद्धता के आधार बहुत कम कार्य हुआ है, फिर भी जैन $(1971)^{54}$ तथा ओ०पी० सिंह $(1971)^{55}$ ने उल्लेखनीय कार्य किया है। केन्द्रीयता का निर्धारण सर्वाधिक प्रचलित केन्द्रीय कार्यों के आधार पर किया जाता है। विभिन्न कार्यों को महत्व प्रदान किया जाना स्विववेक पर आधारित है। जगदीश सिंह $(1977)^{56}$

ने शैक्षिक सेवाओं के लिए निम्न प्रकार से मान निर्धारित किया -

प्राइमरी स्कूल ।

जूनियर हाई स्कूल 2

हायर सेकेन्ड्री/इण्टर कालेज 3

डिग्री कालेज 4

विश्वविद्यालय/उच्च तकनीकी सस्थान 5

इस विधि से विभिन्न कार्यों के महत्व को आकना सर्वथा उपयुक्त नहीं होता है। उपर्युक्त विवरण मे विश्वविद्यालय के महत्व को प्राहमरी स्कूल से मात्र 5 गुना अधिक बताया गया है, जो उचित नहीं है। अस्तु प्रस्तुत अध्ययन मे उक्त दोषों से बचने के लिए कार्यों के महत्व के अनुसार मान निर्धारण की एक नवीन प्रक्रिया अपनायी गयी है। इस विधि मे सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे चुने गए 35 केन्द्रीय कार्यों में से सभी कार्य को बराबर महत्व प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य को 100 मान दिया गया है। इन कार्यों के प्रति इकाई महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक केन्द्रीय कार्य की कुल सख्या से 100 को विभाजित किया गया है। इससे कार्यों के सांपक्षिक महत्व का निर्धारण होता है। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत अध्ययन मे जूनियर बेसिक विद्यालय का मान इस विधि से 0 14 इकाई है तो महाविद्यालय का महत्व 50 इकाई है। विभिन्न कार्यों का मान निर्धारण तालिका 3 5 मे प्रदर्शित है।

तालिका 3.5 विभिन्न कार्यों का महत्वानुसार मान

क्रम संख्या	केन्द्रीय कार्य	क्षेत्र में उनकी संख्या	क्षेत्र में उनका कुल महत्व	
(ক)	प्रशासनिक कार्य			
1	जिला मुख्यालय	1	100	100 00
2.	तहसील मुख्यालय	2	100	50.00

l 	2	3	4	5
3	विकास खण्ड केन्द्र	8	100	12 50
4	न्याय पचायत केन्द्र	66	100	1 52
5	थाना	12	100	8 33
6	पुलिस चौकी	7	100	14 29
(ख)	कृषि एवं पशुपालन			
7	शीत भण्डार	t	100	100 00
8	बीज, कीटनाशक एव उर्वरक केन्द्र	78	100	1 28
9	पशु अस्पताल	16	100	6 25
10	पशु सेवा केन्द्र	20	100	5 00
(ग)	श्विक्षा एवं मनोरंजन			
11	महाविद्यालय	2	100	50 00
12	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	30	100	3 33
13	सीनियर बेसिक विद्यालय	96	100	1 04
14	जूनियर बेसिक विद्यालय	715	100	0 14
15	छिय गृह	5	100	20 00
(됨)	परिवहन एवं संचार			
16	रेलवे स्टेशन हाल्ट सहित	26	100	3 85
17	बस स्टेशन	18	100	5 56
18	बस स्टाप	42	100	2 38
19	फेरी घाट	10	100	10 00
20	डाकघर	136	100	0 74
21	टेलीफोन एवं तारघर	16	100	6 25
(ॾ)	चिकित्सा			
22	अस्पताल	5	100	20 00
23.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	29	100	3 45
24	आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय	17	100	5.88

1	2	3	4	5
25	होम्योपैथिक चिकित्सालय	20	100	5 00
26	मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र	118	100	0 85
27	पजीकृत व्यक्तिगत क्लिनिक एव उपकेन्द्र	106	100	0 94
28	पजीकृत औषधालय	36	100	2.78
(च)	वित्तीय वर्ष			
29	राष्ट्रीय बैंक	50	100	2 00
30	भूमि विकास बैक	2	100	50 00
31	जिला सहकारी बैंक	10	100	10 00
32	सयुक्त ग्रामीण बैक	10	100	10 00
(छ)	व्यापार एवं वाणिज्य			
33	फुटकर बाजार	46	100	2 17
34	थोक बाजार	8	100	12 50
35	साप्ताहिक बाजार	36	100	2 78

पूर्व के अध्ययनों में कार्यों के महत्व के अनुसार ही केन्द्रों के सांपेक्षिक महत्व को आकने का प्रयास किया जाता रहा है किन्तु उनके द्वारा सेवित जनसंख्या से भी केन्द्रों के सांपेक्षित महत्व का ज्ञान होता है। सामान्यतया उच्च स्तरीय कार्यों और केन्द्रों द्वारा सेवित क्षेत्र एव जनसंख्या का आकार बड़ा होता है किन्तु यह आवश्यक नहीं है। ⁵⁶ छोटे-छोटे प्रशासनिक सेवा केन्द्रों का सेवा क्षेत्र एव सेवित जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि सम्बन्धित प्रशासनिक सेवा केन्द्र के सम्पूर्ण जनसंख्या को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस सेवा केन्द्र का ही आश्रय लेना पड़ता है, भले अन्य सेवा केन्द्र की अपेक्षा वह दूर ही अवस्थित हो। कार्यों के महत्व की तीव्रता का अनुमान किसी केन्द्र द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यों के महत्व को जोड़कर किया गया है तथा इसे 'कार्यात्मक अंक' (फंक्शनल स्कोर) की सज्ञा प्रदान की गयी है। कार्यों के महत्व की तीव्रता क्षेत्र में व्याप्त उनकी संख्या पर निर्भर है जिनका मान तालिका 3 5 में प्रदर्शित

है। अध्ययन क्षेत्र मे निर्धारित केन्द्र स्थलो मे से सबसे कम कार्यात्मक अक से सभी केन्द्र स्थलो के कार्यात्मक अकों को भाग देकर कार्यात्मक सूचकाक (फक्शनल इंडेक्स) प्राप्त किया गया है। प्रत्येक केन्द्र का कार्यात्मक अक एव सूचकाक तालिका 3 6 मे प्रदर्शित है। प्रत्येक केन्द्र की कुल सेवित जनसख्या को न्यूनतम जनसख्या वाले केन्द्र की जनसख्या से विभाजित करके सेवित जनसख्या सूचकाक प्राप्त किया गया है। कार्यात्मक सूचकाक की ही भांति सेवित जनसख्या सूचकांक भी सापेक्षित महत्व को उपयुक्त ढग से व्यक्त करता है। प्रत्येक केन्द्र के कार्यात्मक सूचकांक और सेवित जनसख्या सूचकांक को जोडकर उनके केन्द्रीयता अक निर्धारित किए गए है। इस केन्द्रीयता अक से उपयुक्त विधि द्वारा केन्द्रीयता सूचकांक परिकलित की गयी है। केन्द्रीयता अक की अपेक्षा केन्द्रीयता सूचकांक केन्द्रीयता सूचकांक परिकलित की गयी है। केन्द्रीयता अक की अपेक्षा केन्द्रीयता सूचकांक केन्द्री की सापेक्षिक केन्द्रीयता को व्यक्त करने मे अधिक समर्थ है। तालिका 3 6 मे विभिन्न केन्द्रों के केन्द्रीयता सूचकांक प्रदर्शित है।

तालिका 3.6 सेवा केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक

क्रम संख्या	विकास केन्द्र	कार्यात्मक अंक	कार्यात्मक सूचकांक	सेवित जनसंख्या	सेवित जनसंख्या सूचकांक	केन्द्रीयता अंक	केन्द्रीयता अंक सूवकांक
.1	2	3	4	_5	6	7	8
I	राबर्ट्सगज	443 85	83 12	1075041	874 01	957 13	478 57
2	दुद्धी	261.49	48.99	404079	328.52	377 51	178 76
3.	घोरावल	79.45	14.88	8947	7.27	22.15	11 08
4	रामगढ	82 84	15 51	67441	54 83	70 34	35.17
5	बैनी	57.88	10.84	54518	44 32	55 16	27.58
6	चोपन	83.30	15.60	166693	135.52	151 12	75 56
7	म्योरपुर	68 - 49	12.83	192719	156.68	169 51	84.76
8	बभनी	67.95	12.72	57618	46 84	59 56	29.78
9	चुर्क	53.28	9.98	10394	8 45	18 43	9 22
10	ओबरा	163.96	30.70	85930	69 62	100 32	50.16
11	डाला	33.22	6.22	7856	6.93	12 61	6.31
12	सलखन	20.78	3.60	8330	6 77	10.37	5.19

1	2	3	4	5	6	7	8
13	गुरमा	19.82	3 71	6312	5 13	8 84	4 42
14	रेनूकूट	96.61	18 09	68972	56 07	74 16	37 06
15	पिपरी	77 83	14 57	15403	12 52	27 09	13 55
16	अनपरा	111.08	20 80	44350	36 06	56 86	28 43
17	रेणूसागर	17.20	3.22	8380	6 81	10 03	5 02
18	बीना	31 22	5 85	7736	6.29	12 14	6 07
19	शक्तिनगर	62 05	11 62	62382	50 71	62 33	31 17
20	रिहन्द नगर	77 83	14 57	29542	24 02	38 59	19 29
21	ख लियारी	22 01	4 12	5233	4 25	8 34	4 17
22	माची	30.34	5 68	8342	6.78	12 46	6 23
23	पनिकप	6 92	1.30	1840	1.50	2 8	1 4
24	पन्तूगज	11 45	2 14	67441	54 83	59 77	29 89
25	तियरा	5 83	1 09	2226	1.81	2 9	1 5
26	सिलथम	13.89	2.60	3832	3 12	5 72	2 86
27	नई बाजार	11 09	2 08	2638	2.14	4 22	2 11
28	ककराही	16.06	3 00	6763	5.50	8 50	4 25
29.	परासी	18.37	3 44	8988	7.30	11 74	5 87
30	मारकु ण्डी	7 64	1 43	1962	1 60	3 03	1 52
31	तेलगुड़वा	10.02	1.88	2150	1.75	3 63	1 32
32	कोन	42 04	7.87	7430	6 04	13 91	6 96
33	हाथीनाला	16 30	3 05	2316	1.88	4.93	2.47
34	गुरमुरा	11 97	2.24	3640	2 96	5.2	2.60
35.	सलई बनवा	9 95	15.29	3177	2.55	17 84	8 92
36.	बिल्ली	11.73	2.20	4780	3.86	6, 06	3.03
37.	परासपानी	15.69	2.94	5360	4-36	7.30	3 65
38.	फफरा	9.95	1.86	4070	3.31	5.17	2.09

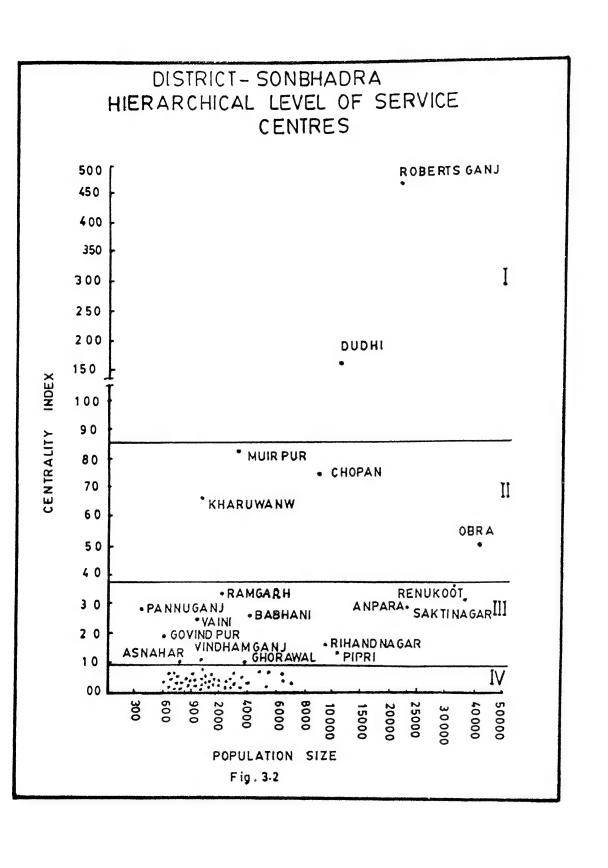
1	2	3	4	5	6	7	8
39	बागे सुर्ती	6 84	I 28	3843	3 12	4 40	2 20
40	खस्बाव	16.90	3 16	160324	130 34	133 50	66 75
41	<u>খাह गज</u>	35 52	6 65	6311	5 13	11 78	5 89
42	शिवद्वार	10 34	1 95	5411	4 40	6 35	3 18
43	जमगाव	5 84	1 09	2612	2 12	3 21	1.61
44	करमा	24 81	4 65	8613	7 0	11 65	5 83
45	पसही	10 23	1 92	9663	7 86	9 78	4 89
46	गोविन्दपुर	16 23	30 04	6678	5 43	35 47	17 74
47	जरहा	15 62	2 93	14312	11 64	14 57	7 29
48	सागोवार	19 44	3 64	13478	10 14	13 78	6 89
49	नधिरा	13 06	2 45	9908	8 06	10 51	5 26
50	विण्ढमगज	54 55	10 22	15680	12 74	22 96	11 48
51	महुली	20 64	3 86	10072	8 18	12 04	6 02
52	अमवार	24 14	4 52	8020	6 52	11 04	5 54
53	चपकी	21 05	3 94	11342	9 22	13 16	6.58
54	चैनपुर	14 74	2 76	14342	11 66	14 42	7 21
55	असनहर	16.67	3.12	6204	5 04	22 59	11 30
56	महुअरिया	16 73	3.13	5441	4 42	7.55	3 78
57	झारो	23.33	4.37	13463	10 95	15.32	7 66
58	हिन्दुआरी	5 34	1 00	1230	1 00	2 00	1 00
59	लिलासी	8-82	1 65	6370	5 18	6 83	3 42
60	आरगपानी	6.08	1.14	11307	9.19	10 33	5 17
61	रायपुर	18.69	3.50	3050	2.48	5 98	4 99
62	चकरिया	6 28	1.17	4310	3.50	4-67	2 34
63.	अगोरी	16.23	3.04	3380	2 74	5.78	2.89

3.6 विकास-केन्द्रों का पदानुक्रम

केन्द्र-स्थलों का पदानुक्रमीय व्यवस्था केन्द्र स्थल सिद्धान्त का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण केन्द्र स्थलो मे परस्पर सम्बद्धता तथा कार्यात्मक संशिलष्टता पायी जाती है। कार्यात्मक संश्लिष्टता के परिणामस्वरूप केन्द्र स्थलों मे कार्यात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, फलत उनमे पदानुक्रमीय भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। क्रिस्टालर⁵⁷ के अनुसार वस्तुओं एव सेवाओं का प्रवाह उच्च स्तरीय केन्द्र से निम्न स्तरीय केन्द्र की ओर होता है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय केन्द्र निम्न स्तरीय केन्द्रों के कार्यों के सम्पादन के साथ कुछ विशिष्ट कार्यो को भी सम्पादित करते है, जो निम्न स्तरीय मे नहीं पाए जाते है। व्यावहारिक दृष्टि सै प्रत्येक केन्द्र स्थल मे कुछ कार्यात्मक विशिष्टीकरण पाया जाता है। अत निम्न स्तरीय केन्द्र भी उच्च स्तरीय केन्द्र को सेवा प्रदान करते है। केन्द्र स्थल सिद्धान्त के अनुसार कि पदानुक्रम के किसी भी स्तर से सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रो की केन्द्रीयता समान होगी, एक आदर्शवादी परिकल्पना है। व्यावहारिक रूप में ऐसा सभव नहीं है। अत प्रस्तुत अध्ययन मे केन्द्रीयता की असमानता को ध्यान मे रखकर केन्द्रो का पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। केन्द्र स्थलो के पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के निर्धारण के लिए उनके केन्द्रीयता सूचकाक के सातत्य को भग करने वाले अलगाव बिन्दुओं को सीमा माना गया है। तालिका 3 6 तथा चित्र 3 2से स्पष्टत तीन अलगाव बिन्दु दृष्टिगत होते है जिनके आधार पर अध्ययन क्षेत्र के केन्द्र स्थलों के चार पदानक्रमीण व्यवस्था बनायी गयी है। चारों स्तरों से सम्बन्धित केन्द्रीयता सूचकाक वर्ग तथा उनके अन्तर्गत सम्मिलित केन्द्रो की सख्या तालिका 3.7 मे प्रदर्शित है ।

तालिका 3.7 केन्द्र स्थलों की पदानुक्रमीय व्यक्स्था

पदानुक्रमीय स्तर	केन्द्रीयता सूचकांक वर्ग	केन्द्रों की संख्या
I	।78.76 से अधिक	2
II	50.16 से 84.76	4
III	।1.08 से 37.08	13
IV	। से 9.22	44



अध्ययन क्षेत्र मे प्रथम स्तर के 2 केन्द्र, द्वितीय स्तर के 4 केन्द्र, तृतीय स्तर के 13 केन्द्र तथा चतुर्थ स्तर के 44 केन्द्र विद्यमान हैं, जिनका प्रदर्शन मानचित्र 3 2 में किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में कार्यों तथा स्थलों के पदानुक्रमीय व्यवस्था में, साम्यता है दोनों का निर्धारण 'अलगाव बिन्दु' से किया गया है तथा दोनों के पदानुक्रमों में चार स्तर निर्धारित हुए है।

3.7 विकास केन्द्रों का स्थानिक वितरण

अध्ययन क्षेत्र मे विकास केन्द्रों का स्थानिक वितरण असमान है (मानचित्र 3 ।)। आर0 सी0 शर्मा केअनुसार विकासकेन्द्रोंके वितरण पर जनसख्या और बस्तियों के घनत्व का प्रभाव पड़ता है। विकास केन्द्रों का असमान वितरण प्रतिरूप अध्ययन क्षेत्र के किसी एक भाग में नहीं है वरन् सम्पूर्ण भाग में है। बेलन घाटी में विकास केन्द्रों की सख्या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। बेलन घाटी कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए विकास केन्द्रों की सख्या अधिक है। रिहन्द जलाशय के चतुर्दिक विकास केन्द्रों की स्थित औद्योगीकरण से प्रभावित है। शेष विकास केन्द्रों की स्थिति परिवहन मार्गों से प्रभावित है। हिन्दुआरी, तेलगुडवा व हाथीनाला का विकास केन्द्रों के रूप में विकास सडक जक्शन के कारण ही है। विकास केन्द्र फफरा, बिल्ली, गुरमुरा, झारो, ककराही आदि रेलवे स्टेशन के कारण विकासत हुए। विकास खण्ड म्योरपुर के लगभग सभी विकास केन्द्र (रिहन्द नगर, शक्तिनगर, म्योरपुर, रेनृकृट, पिपरी, अनपरा, रेणूसागर, बीना आदि) औद्योगिक केन्द्र होने के कारण बेलन घाटी के विकास केन्द्रों की अपेक्षा उच्च स्तरीय है। वनों, पठारों तथा पहाडियों वाले क्षेत्रों में विकास केन्द्र बहुत कम है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के विकास केन्द्रों के अन्तरालन को नियन्त्रित करने वाले प्रमुख कारक निम्न है :

- । धरातलीय स्वरूप
- 2 कृषि योग्य भूमि तथा जल की उपलब्धता
- 3 परिवहन एव संचार माध्यम
- 4 औद्योगीकरण

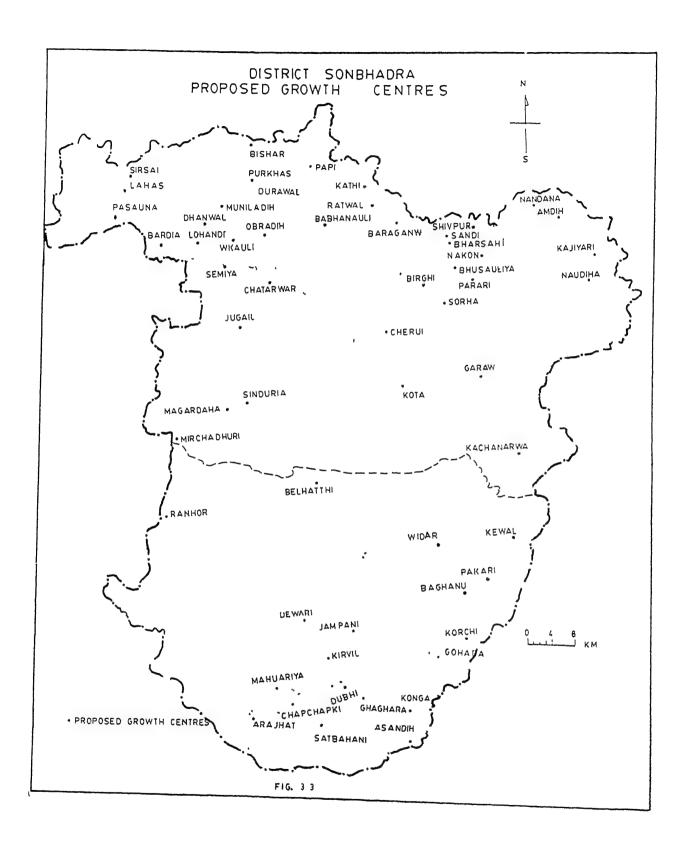
जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुए हैं, अन्य कारकों के विपरीत होने के बावजूद धीरे-धीरे विकास केन्द्रो का स्वतः विकास हो गया है। विकास खण्ड नगवा से दुद्धी के बीच (उत्तर दक्षिण में) बहुत बड़े क्षेत्र में एक भी विकास केन्द्र नहीं है। विकास खण्ड चोपन में औबरा, डाला, चोपन व तेलगुडवा तथा कुछ रेलवे स्टेशन युक्त विकास केन्द्रो को छोडकर पूर्व से पश्चिम मे बहुत बडे क्षेत्र पर एक भी विकास केन्द्र नहीं है ।

3.8 प्रस्तावित विकास केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

किसी भी क्षेत्र का विकास सामाजिक आर्थिक सुविधाओं के त्वरित उपलब्धता पर निर्भर करता है। उक्त सुविधाओं के त्वरित उपलब्धता का सुनिश्चयन विकसित सेवा केन्द्रों/विकास केन्द्रों की मात्रा एव सुविधाजनक अवस्थिति पर निर्भर करता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में विकास केन्द्रों का वितरण उचित एव पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में कार्यात्मक रिक्तता विद्यमान है। जूनियर बेसिक विद्यालय, डाकघर तथा मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र जैसी सुविधा भी प्रत्येक बस्ती को नहीं है। अत जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एव सचार, कृषि, उद्योग एव व्यापार आदि सुविधाओं की सुलभता के लिए कुछ नए सेवा केन्द्रों/विकास केन्द्रों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान सेवा केन्द्रों को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। वर्तमान सेवा केन्द्रों एव प्रस्तावित सेवा केन्द्रों पर प्रस्तावित कार्यों को तालिका 3 8 में दर्शाया गया है। प्रस्तावित विकास केन्द्रों की अवस्थिति निर्धारित करने में निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा गया है।

1

t	धरातलीय स्थिति
2	बस्तियो की जनसंख्या
3	कार्यात्मकता रिक्तता
4	विकास केन्द्रों की गम्यता सीमा
5	सड़कों की स्थिति एव स्तर
5	परिवहन साधन तथा
7	विकास केन्द्र होने की सभाव्यता



तालिका 3.8 प्रस्तादित विकास केन्द्र

क्रम संख्या	विकास केन्द्र	जनसंख्या
1	ओबराडीह	836
2	बिसहार	752
3	मुडिलाडीह	698
4	वर्दिया	730
5	दुरावल	905
6	वकौली	511
7	सिरसाई	389
8	मोरसिम	763
9	धनावल	848
10	लोहाड़ी	972
11	परसोना	761
12	लहास	653
13	पुरखास	1011
14	रतवल	412
15	बभनौली	930
16	पापी	878
17	केथी	1113
18	बडागांव	1530
19	सण्डी	523
20	भरसही	605
21	सोढ़ा	663
22	नाकों	317
23	शिवपुर	252

1	2	3
24	भुसौलिया	802
25	बिधी	530
26	पडरी	478
27	नन्दना	992
28	कजियारी	775
29	गड़ाव	683
30	नौडीहा	478
31	चेर्ल्ड	1182
32	आमडीह	699
33	आसनडीह	472
34	<u>ह</u> भा	648
35	गोहडा	1286
36	घघरा	1278
37	चप-चपकी	1210
38.	सतबहनी	950
39	कोंगा	1496
40	अरझट	868
41	कोरची	1815
42	वीडर	1113
43	केवाल	1315
44	पकरी	908
45	बघाडू	1400
46.	महु अरिया	1350
47	किरविल	3355
48	रणहोर	1747
49	देवरी	1260

1	2	3
50	बेलाही	850
51	जामपानी	1130
52	जोगोडीह	2350
53	वेलहत्थी	898
54	सिन्दुरिया	1138
55	सेमिया	690
56	जुगैल	963
57	मगरदहा	1560
58	मिर्चाधुरी	1890
59	चतरवार	1342
60	कचनरवा	2250
61	कोटा	1740

तालिका 3 8 व 3 9 से स्पष्ट है कि अधिकाश प्रस्तावित केन्द्रों पर निम्न स्तरीय केन्द्रीय कार्यों का ही सम्पादन होता है। चूिक केन्द्रीय कार्यों मे औद्योगिक कार्यों को सिम्मिलित नहीं किया गया है इसिलए इन कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया गया है। जूनियर बेसिक विद्यालय, डाकघर, फुटकर बाजार, बीज एव उर्वरक केन्द्र तथा मातृ एव शिशु कल्याण कार्य की उपस्थित अधिकांश प्रस्तावित सेवा केन्द्रों पर है। इन सेवा केन्द्रों को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ मध्यम स्तर के कार्यों को सम्पादित करने का प्रस्ताव है। अध्ययन क्षेत्र मे तीन तहसील (रामगढ़, ओबरा व रेनूकूट) बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पाच विकास खण्ड (रिहन्द नगर, अनपरा, पिपरी, श्राहगंज तथा ओबरा) तथा 25 न्याय पचायत बनाने का प्रस्ताव है। शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि एवं पशुपालन आदि सुविधाओं की वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है।

प्रस्तावित 6। विकास केन्द्रों पर केन्द्रीय कार्यो की उपस्थित को दो चरणों मे पूरा कराना चाहिए प्रथम चरण 1995 तक तथा द्वितीय चरण 2000 तक होना चाहिए । इसके बाद प्रस्तावित केन्द्रीय कार्यो के नियोजन की पुन आवश्यकता होगी । इस नियोजन को पूरा करने मे सरकार के विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी । प्रस्तावित विकास केन्द्रों की अवस्थितियाँ मानचित्र 3 3 मे तथा इन पर प्रस्तावित कार्य तालिका 3 9 मे देखी जा सकती है ।

तालिका 3.9 वर्तमान एवं प्रस्तावित सेवा/विकास केन्द्रों पर वर्तमान एवं प्रस्तावित सुविधाएं/कार्य

क्रम स0	कन्द	व र्तमान सेवाएँ,/कार्य	प्रस्तावित सुविधाएँ,/कार्य
		3	

(अ) वर्तमान सेवा केन्द्र

राबर्ट्सगंज

जि.मु.,त.मु.,वि.मु., था., शी.भ., बी.के., पु.चौ, पसे के., म.वि, त.शि.स., उके, प.अ., कृ.गर्भा., हा.से., सी बे.वि., औप स, बस्टा., सू.विके, भे विके. जू.बे.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., म वि.के., दू.भा., अस्पा., प्रा स्वा.के., आ यू.चि., हो.चि, मा शि.के., प.व्य.क्लि., पं.औ., सा.स्वा.के., उ.स्वा.के., प.नि.के, रा.बें., भू.वि.बें, जि.स.बें., सं ग्रा.बें., ग्रा.बें., थो.बा, फु.बा, कु विके.,

थो.बा., फु.बा.,

2. दुखी

त मु ,वि मु ,था., बी के , उ के , प अ., कृ.गर्भा., पु.चौ , शी भ , प से.के , त शि स , म वि., हा.से.वि., सी.बे.वि., जू बे.वि., रे स्टे., सिने , आ यु चि , सा.स्वा के ,उ.स्वा ब स्टे., फे.घा., डा.घ., ता.घ., दू भा., अस्प , के., कु.पा के , सू वि.के , भे वि के., प्राःस्वा.के., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., प नि म वि के , के , रा.बैं., भू.वि.बैं., जि.स.बैं., सं.ग्रा.बैं ,ग्रा बैं.,

			119
- -	2	3	4
3.	घोरावल	था., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से.,सी.बे.वि., जू.बे.वि , ब.स्टे., डा.घ., ता.घ., दू.भा., प्रा. स्वा.के., हो.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं. औ , रा.वें., जि.स.बें., सं.ग्रा.बें., थो.बा., फु. बा.,	शी.भं., म.वि , सिने. , अस्प., आ.यु.चि., कु.वि.के., सू.वि.के.,भे.वि के ,म.वि के., सा.स्वा के.,
4.	रामगढ	वि मु., न्या.के., बी.के., उ.के., प.अ., हा. से., सी.बे.वि., जू.बे.वि., डा.घ., ता.घ., आ. यू.चि , मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., रा.बैं., जि.स.बैं., सं.ग्रा.बैं., फु,बा., थो.बा.,	त.मु., पुचौ., शी भं., म.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., दूभा., अस्प., प्रास्वा के., हो.चि.,भू.वि.बैं., सा.स्वा.के.,
5.	वैनी	वि.मु, न्या के., बी.के., उ.के., प.अ., जू.बे वि., ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के, हो चि., मा. के., पं औ, जिस.बैं.,स.ग्रा.बैं, फु.बा., ग्रा.बैं,	था ,शी.भं., म.वि , हा से., सी.बे.वि , ब.स्टे., रे स्टे., ता.घ , दू भा., अस्प , आयु.चि., पं व्य क्लि., भू वि.बैं, थो बा भे.वि.के., कु.वि.के.,
6.	चोपन	वि.मु., था., बी.के., उ.के., प अ., हा.से.,सी बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., ता. 'घ., दू.भा., प्रा.स्वा.के., हो.चि., मा.शि.के., पं.च्य.क्लि., पं.औ., जि.स.बैं., सं.ग्रा.बैं., फु. बा.,	शी भे., म.वि., सिने, फे घा., अस्प., आ.यू.चि., भू वि वैं, थो बा, कृ गृर्भा., म.वि के., भे.वि.के., कु.वि.के., ग्रा बैं. सा.स्वा.के.,
7.	म्योरपुर	वि.मु., न्या.के., बी.के., उ.के., प.अ., सी. बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., रा.बै., फु.बा., सा.बा., कु.वि.के,	पु.चौ., शी.भं., हा.से., दू.भा., ता.घ., अस्प., आ.यू.चि, हो.चि., भू.वि.बैं., सं ग्रा.बैं., थो.बा., भे.वि.के., सू.वि.के.
8.	बभनी	वि.मु., न्या.के., पु.चौ., बी.के., उ.के., प. अ., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टे., डा.य.,ता. घ., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., रा.बैं.,सं.ग्रा.बैं.,	था., शी भं., हा.से., दू.भा., अस्प., हो चि , आ.यू.चि., प.व्य.क्लि., भू.वि.बै. थो.बा., कु.पा.के., भे.वि.के.,

फ़ु.बा.,

1	2	3	4
9.	चुर्क	न्या.के., पु. चौ., बी.के., उ.के., हा.से.,	सिने., दू.भा., जि.स.बैं, स.ग्रा.बैं.
		सी बे.वी., जू.बे.वि., डा.घ., ता.घ., प्रा.स्वा.	थो.बा., कु.वि.के., सा.स्वा.के,
		के., आ.यू.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि.,	
		पं. औ., रा.बॅं., फु.बा.,	
10.	ओबरा	था., बी.के., उ.के., प.अ., म.वि., हा.से.,	त.मु., वि.मु., शी भं., फे.घा.,
		सी.बे.वी., जू.बे.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे.,	जि.स. बॅं., स.ग्रा.बें., कुवि.के.,
		डा.घ., ता.घ., दू.भा., अस्प., प्रा.स्वा.के.,	सू.वि.के., म.वि.के., ग्रा.बैं.,
		आ.यू.चि., हो.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि.,	कृ0गर्भा.
		पं.औ., रा.बॅं., फु.बा., थो.बा.,	
11	डाला	बी.के., उ.के., हा.से., सी.बे.वि., जू.बे.वि.,	प.अ., दू.भा., हो.चि , जि.स.बैं.
		ब.स्टे., डा.घ., ता.घ., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि.,	स.ग्रा.बॅं., कु.वि.के., सा.स्वा.के.,
		मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., प.औ., रा.बैं., फु.ब.,	कृ0 गर्भा ,
12.	सलखन	न्या.के., बी.के., उ.के., प.स.के., सी.बे.वि.,	पु.चौ., हा.से.वि., रे.स्टे., ता घ.,
		जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., आ.यू.चि., मा.शि.	प्रा.स्वा.के., प.औ., ग्रा.बॅॅं.,
		के., पं.व्य.क्लि., रा.बॅं., फु.बा.,	जि.स.बॅं., कु.वि.के., सू.वि.के.,
13.	गुरमा	बी.के., उ.के., हा.से.वि., सी.बे.वि., जू.बे.वि.,	कृ.गर्भा., आ.यू.चि., प.औ., ग्रा.
		रे.स्टे., ब.स्टा., हो.चि., मा.शि.के., पं.व्य.	बैं., भे.वि.के., कु.वि.के.,
		क्लि., रा.बॅं., फु.ब.,	प्रा. स्वा. के.,
14.	रेनूकूट	उ.च., बी.के., उ.के., हा.से.वि., सी.बे.वि.,	जि.मु.था., वि.मु., शी.भं, प
		जू.बे.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे.,डा.घ., ता.घ.,	अस्प., म.वि., फे.घा., अस्प,
		दू.भा., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., मा.शि.के.,	हो.चि., भू.वि.बॅं., कु.वि.के,
		पं.च्य.क्लि., पं.औ., रा.बैं., जि.स.बैं., फु.बा.,	के., ग्रा. बैं
		थो. बा., भे.वि.के.	
15.	पिपरी	था., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से.वि., सी.वे.	वि.मु., म.वि., अस्प., जि.स.बैं.,
		वि., जू.वे.वि., ब.स्टे., फे.घा., डा.घ., ता.	थो.बा, कु.वि.के., म.विके., ग्रा.

I	2	3	4
		घ., दू.भा., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., मा.शि.के., पं.च्य.क्लि., पं.औ., फु.बा.	बैं., औ.पु.स.
16	अनपरा	था., वी.के., उ.के., प.अ., हा.से., सी.बी.वि., जू.बे.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., ता.घ.,	
		दू.भा., अस्प., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., पं.व्य.	सं.ग्रा.बैं., कु.वि.के., म.वि.के.,
		क्लि., प.औ., रा.बैं., कु.बा., थो.बा.	सू.वि.के., औ प्र.सं., त.शि.सं.
17.	रेणूसागर	सी बे.वि., जू.वे.वि., डा.घ., प्रा.स्वा.के.,	उ.चौ., प.से.के., हा.से.वि.,
		ता.घ., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., रा.बें.,	सा.स्वा.के., दू.भा., आ.यू.चि.,
		फु. बा.	हो.चि., जि.स.बैं., थो बा,
			कु.वि.के, मवि.के, मवि.,
			वी.के , उ.के , ब.स्टा.
18.	बीना	वी.के., उ.के., हा.से.वि., सी.बे.वि., जू बे.	पु.चौ, पसे के., सिने., दूभा.,
		वि., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., ता.घ., प्रा.स्वा.के.	अस्प., आ.यू.चि., ग्रा.बॅॅं., थो.बा.,
		मा शि के ., पं व्य क्लि , पं औ., रा बैं , फु बा ,	भे.वि.के., कु.वि.के.
19.	शक्ति नगर	था., बी.के., उ.के., हा.से.वि., सी.बे.वि.,	विमु., शी.भं., म.वि., पअ.,
		जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., फे.घा., डा.घ.,	कृ गर्भा., सिने , दू.भा., अस्प.,
		ता.घ., प्र.स्वा.के., मा.शि.के., प.व्य.क्लि.,	आ.यू.चि., भू.वि.बैं., जि.स.बैं.,
		पं.औ., रा.बैं., थो.बा., फु.बा.	सं.ग्रा.बैं., कु.वि.के., म.वि के.,
			भे.वि.के., औ.प्र.सं.
20.	रिहन्द नगर	था., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से.वि., सी.बे.	वि.मु., म वि., रे.स्टे., अस्प.,
		वि., जू.बे.वि., सिने., ब.स्टे., फे.घा., डा.घ.,	हो.चि., भू.वि.बैं., जि.स.बैं.,
		ता.घ., दू.भा., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., मा.शि.	सं.गा.बैं., कृ.वि.के., म.वि.के.,
		के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., रा.बैं., फु.बा.	भे.वि.के., थो.बा.
21.	खलियारी	न्या.के. , बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि.,	
		ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., मा.शि. के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., रा.बैं,, फु,बा.	सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., ता.घ., अस्प., हो.चि., ग्रा.बैं., जि.स.बैं.,

l	2	3	4
		. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	कु.वि.के., भे.वि.के, थो बा.,
22.	माची	पु.चौ., बी.के., उ.के., प.से के., डा.घ.,	कृ0गर्भाः हा.से.वि , सी.बे.वि , ब स्टा ,
22.	11 41		
		मा.शि.के., फु.बा., सा.बा.	ताघ., प्रास्वा.के., आयू.चि., भेविके
23	पनिकप	मीने किल ने किला मिली	
23	नानकम	सी बे.वि., जू.वे.वि., आ.यू.चि.,मा.शि के.	फु.बा, कृगर्भा, ग्रा.बैं.,कु.वि.के,
0.4			न्या के
24	पन्नूगज	था , ब स्टा., डा घ ,म.शि के	ताघ, दूभा, प्रस्वाके, पव्य
			क्लि, रा.बै, जिस बैं, फु.बा,
٥	C		पसके., पनिके.
25.	सिलथम	हा.से.वि., न्या.के., वी.के., उ.के., प.से.के.,	पु.चौ, सीबे.वि, जूबेवि,
		डा.घ., मा.शि.के., रा.बै., फु.बा.	ग्रा बैं, कु वि.के., भे वि के
			ताघ, प्रास्वा.के.
26.	नई बाजार	बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा.,	कृ.गर्भा, हासे.वि., डा.घ.,
		प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., पं.च्य.क्लि., रा.बें.,	ता.घ., पं.औ., ग्रा.बैं., कु.वि के.,
		फु.बा.	पु.चौ., न्या.के.
27.	ककराही	प.से के., सी.बे.वि., जू बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा.	न्या.के., वी के., उ.के., हा.से.
		प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., रा.बैं.,	वि., डा घ., सा.स्वा.के., पं.औ.,
		फु. बा.	ग्रा. बैं., कु.वि. के
28.	परासी	न्या.के., बी.के., उ.के., हा.से., जू.बे.वि.,	कृ.गर्भा., सी.बे.वि., प्रा.स्वा.के.,
		ब.स्टा., डा.घ., हो.चि., पं.व्य.क्लि., फु.बा.	पं.औ., कुवि.के., प.निके.,
			ग्रा बैं., रा बैं.
29.	मारकुण्डी	बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा.,	न्या.के., ब.स्टे , डा.घ., सा.स्वा.
		फु.बा.	के., प.नि.के , भे.वि.के., ग्रा.बैं.
			म.वि.के.

l	2	3	4
30.	तेलगुड़वा	जू.बे.वि., ब.स्टे., डा घ., मा.शि.के., पं.व्य.	बी.के, उ.के, प.से.के., प्र.औ.,
		क्लि., फु.बा., सा.बा.	कु.वि.के., ग्रा.बैं., रा.बैं.
31.	कोन	न्या.के., था., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से.,	म.वि , रा.बैं , ग्रा.बैं., सा.स्वा.के.,
		सी.बे.वि., जू.बे.वि., डा.घ., फे.घ., ब.स्टा.,	भे.वि.के, कु.वि.के., सू.वि.के.,
		प्रा.स्वा.के , म.सि.के., पं.च्य.क्लि., पु.बा.,	म.वि.के., थो.बा.
		सा. बा.	
32.	हाथी नाला	बी.के., उ.के., प.से.के., जू.बे.वि., ब.स्टे.,	न्या.के., पु चौ., सी.बे.वि., हा.के.,
		डा घ., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., फु.बा., सा.बा.	ता.घ, दूभा., थो.बा., उ.स्वा.के.,
			रा बैं., सं.ग्रा.बैं.
33.	गुरमुरा	बी.के., उ.के., प.अ., जू.बे.वि., रे.स्टे.,	न्या.के., हा.से.वि., सी.बे.वि., ता.घ.
		ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के , पं.व्य.क्लि., फु.बा.,	सा.स्वा.के., पनिके., रा.वैं, कु.वि
		सा. बा	के., भे.वि के., सूवि.के.
34.	सलई बनवा	जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., म.शि.के., प.व्य.	रा.बैं., जि.स.बैं., कृ.गर्भा, हो.चि.,
		क्लि., फु.बा., सा.बा.	प.नि.के., भे.वि.के., बी.के., उ के.
35.	बिल्ली	सी.बे.वि., जू वे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ.,	प.से.के., बी.के., उ.के., ता घ, सा.
		मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., फु.बा., थो.बा.	स्वा.के., हो चि., सा ग्रा.बैं.,
			भे.वि.के., न्या. के.
36.	परासपानी	जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., हो.चि., मा.	सी.बे.वि., बी.के., उ.के., कृ.गर्भा.,
		शि.के., पं.व्य.क्लि., फु.बा., सा.बा	प नि.के., उ.स्वा के., भे.वि.के.,
			पं औ.
37	फफरा	जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के.	सी.बे.वि., न्या.के., बी.के., उ.के.,
		पं.व्य.क्लि., फु.बा.सा.व.	प.से.के., प औ., सं.ग्रा.बैं., जि स.बैं.
			भे.वि.के.
38.	बागेसुर्ती	जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के.,पं.व्य.क्लि.,	बी.के., उ.के., न्या.के., सी.बे.वि.,
		फु.बा., सा.बा.	भे.वि के., जि.स.बैं.

1	2	3	4
39	खुरूवाव	वि.मु , बी.के , उ.के., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ. मा.शि.के., फु.बा.	हो चि , कु.वि.के., भे वि.के., प नि.
40.	शाह गंज	न्या के , पु.चौ., बी.के , उ.के , हा से वि , सी.बे.वि , जू.बे.वि , ब स्टा , डा घ , प्रा स्वा के .	के., रा.बैं., जि.स बैं. वि मु, प औ., प अ., कृ गर्भा ,ता घ सा.स्वा के., म.वि.के, भे.वि.के,
41.	शिवद्वार	मा शि के., पं.व्य.क्लि., रा बैं., स.ग्रा.बैं., फु.बा. बी.के., उ.के., प.से.के, जू.बे.वि., मा शि.के, पंव्य.क्लि., फु.बा.	कु.वि.के., थो.बा न्या.के., सी बे वि , सा.स्वा.के., प नि.के., कृ गर्भा , रा.वें., ग्रा बैं ,
42.	जमगांव	न्या.के., बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., मा.शि.के., फु.बा.	भे.वि.के., प औ. ग्रा बैं., कृ.गर्भा., कु.वि.के., प नि के डा.घ
43.	करमा	था., बी.के., उ.के., सी.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के., पं.च्य.क्लि.	न्या.के., रा.बैं., उस्वा.के., आ.यू.चि., कु.वि.के., पनिके., पसे.के.
44	पसही	बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब स्टा., डा.घ., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि, फु.बा.	कु. वि. क., कु. गर्भा., उस्वा. के., कु.वि. के., रार्वे, ग्रार्वे
45.	गोविन्दपुर	डा.घ., हा.से.बि., जू.बे.वि., मा.शि.के., ब.स्टा., रा.बैं., फु.बा., सा.बा.	बी.के., उ.के., ता घ., सी.बे.वि., ब.स्टे., ग्रा बैं, भे.बि.के., सू.वि.के.,
46.	जरहा	न्या.के., बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., आ.यू.चि., मा.शि.के., फु.बा.	न्या.के. कृ.गर्भा., प.नि.के., प.से.के., ग्रा.बें., उ.स्वा.के., भे.वि.के, हा.से
47.	सांगोवार	सा.बा. न्या.के., बी.के., उ.के., प.अ., सी.बे.वि., जू बे. वि., ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., फु.बा., सा.बा.	पु.चौ., हो.चि., प.नि.के., भे.वि.के. ग्रा.बैं.

1	2	3	4
48	निधरा	बी के., उ.के., जू बे.वि., ब.स्टा , डा.घ., आ. यू.चि., फु.बा., सा.बा.	न्या.के., सी.बे.वि., उ.स्वा.के., प.नि. के., प.आ, ग्रा.बें., कु.वि.के., भे.वि.के.
49.	विण्ढमगंज	पु.चौ., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से., सी.बे.वि., जू बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., रा बैं., सं.ग्रा.बैं., फु.बा., सा.बा.	था., न्या.प., कृ.गर्भा., सिने., ता घ., हो.चि., सू.बि.के., भे वि के., कु.वि के., म वि.के
50	महुली	न्या.के., प.से.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि , ब.स्टा., आ यू.चि., मा.शि.के., रा.बैं., फु.बा., सा.बा.	बी.के., उके., उस्वाके., हो.चि., भे.वि.के., प.अ.
51.	अमवार	प.से.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., आ.यू. चि., मा.शि.के., रा.बैं., फु.बा., सा.बा फे.घा.	न्या.के., बी.के , उ.के., कु.पा के., उ.स्वा.के
52.	चपकी	हा.से., जू.बे वि., ब.स्टा., डा.घ., आ.यू.चि., हो.चि., मा.शि.के., फु.बा., सा.बा.	सी.वे., बी.के., उके., कृ.गर्भा, ग्रा.
53.	चैनपुर	न्या.के., बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., डा.घ., हो.चि., मा.शि.के., फु.बा., सा.बा.	हा.से., रा.बें., गा बें., उ.स्वा.के., प.नि.के, कृ गर्भा., भे.वि.के., पं और
54.	असनहर	बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.फ., प्रा.स्वा.के., हो.चि., मा.शि.के., फु.बा.	न्या के., प.अस्प., सा.स्वा के., प.औ. भे.वि के., ग्रा.बैं.
55.	महुअरिया	सा.बा. सी.बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., हो. चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., फु.बा., सा.बा.	. रा.बैं., बी.के., उके., प.से.के, उ.स्वा.के., आयूचि., भे.वि.के.
56.	झारो	न्या.के, बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., हो.चि., मा.शि.के., रा.बैं., फु.बा., सा.बा.	प्रा.स्वा.के., हा.से., ता.घ., आ.यू.चि. कृ.गर्भा., ग्रा.बैं., कु.वि.के., भे.वि.के, सू.वि.के.
57.	हिन्दुआरी	बी.के., उ.के., पं.व्याक्ति., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के., कु.बा.	सी.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., रा.बैं., उ.स्वा.के., सूवि.के., कु.वि.के., ग्रा.बैं.

		2	3
58.	लिलासी	हो.चि., सी.बे.वि., मा.शि.के., सा.बा.,जू.बे.वि.,	प.नि.के , उ.स्वा.के., ग्रा बैं , बी.के., उ.के., कृ.गर्भा , कु.वि.के., डा घ , फु.बा.
59.	आरगपानी	डा.घ., सी.बे.वि., न्या.के., सा.बा., मा.शि.के., जू.बे.वि.	बी.के., उ.के., प.से.के, हो.चि, सा.स्वा.के., प.औ, ब.स्टा.
60	रायपुर	बी.के., उ.के., पु.चौ., मा.शि.के., डा.घ., ब. स्टा., जू.बे.वि.	सी.बे.वि., न्या.के., कृ.गर्भा , हो.चि. प.नि.के., ग्रा.बैं
61.	चकरिया	हो.चि., उ.के., जू.बे.वि., मा.शि.के.	बी.के., डा.घ, कृ.गर्भा, प नि.के., आ.यू.चि, ग्रा.बें., भे वि.के., सी.बे.वि., प.औ.
62.	अगोरी	रे.स्टे., ब.स्टा., फे घा., जू.बे.वि.	सी.बे वि., पनि के., आ.यू.चि., पं.औ., ग्रा बैं., कु.वि.के., ता.घ, उ.स्वा.के., भे.वि.के.
63	तियरा	प्रास्वाके, पव्यक्ति, जूबेवि	प सुके, माशिके, म विके, कुविके, डाघ

ब. प्रस्तावित केन्द्र

1.	ओबराडीह	न्या.के., जू.बे.वि., डा.घ.	उ.के., बी	ा.के., फु.बा.,	कु.वि.के.,
			सी.बे.वि ,	हा से , ग्रा-बैं.,	आ.यू.चि.,
			प.से.के.		
2.	बिसहार	जू.बे.वि., उ.के., मा.शि.के.	सी.बे.वि.,	न्या.के.,	प.नि.के.,

कृ.गर्भा.,कु.बी.के., डाघ., फु.बा. हो.चि.

l 	2	3 	4
3.	मुङ़िलाडीह	जू.बे.वि., आय.यू.चि.	पं.औ., सी.बे.वि., डा.घ., मा.शि.के, बी.के.,
			उ.के., प.नि.के., प.से.के., भे.वि.के., ग्रा.कैं.,
			रा.बैं.
4.	बर्दिया	जू.बे.वि., ब स्टा., उ.के.	बी.के., आ.यू.चि , हासे., उ.स्वा.के., ग्रा.बैं.,
			मा.शि.के., डा घ.
5	दुरावल	जू.बे.वि., मा.शि.के.	बी.के., उ.के., डा.घ, कृ.गर्भा, हो चि.,
			कु.वि.के., फु बा., ग्रा बैं., सी बे वि
6.	बकौली	न्या के , मा.शि.के.	जू.बे.वि., सी.बे.वि., डाघ., ग्राबैं, फुबा.,
			बी के., उ.के., प्रा.स्वा.के., कु वि के.
7.	सिरसाई	बी के. मा.शि.के.	जू.बे.वि., सी.बे.वि., डाघ., कृगर्भा, पनिके.,
			सू.वि.के., फु.बा
8	मोरसिम	जू.बे.वि., उ.के., फु.बा.	मा.शि.के., डा.घ., बी के., प.नि.के, सी.बे वि.,
			उन्स्वा के , पं.औ , प.से के , कु.वि.के , न्या के
9.	धनावल	जू.बे.वि., मा.श.के., फु.बा.	सी.बे.वि., हा.से., ग्रा.बैं., पऔ, कुविके.,
			म.वि.के., प.से के. डा घ.
10.	लोहाड़ी	सी.बे.वि., जू.बे.वि.,	उ.के., बी.के., हा.से., प अस्प., आ.यू चि., प.औ.
			प.नि.के., सू वि.के., डा घ., रा.बैं.
11.	परसौना	डा.घ., जू.बे.वि.	प्रा.स्वा.के., सी.बे.वि., प से.के., रा बैं., उ.के.,
			बी.के., भे.वि.के., न्या.के
12.	लहास	मा.शि.के., उ.के., बी.के., जू.बे.	सी.बे.वि., उ.स्वा.के., प.स.के., ग्रा.बैं., प.औ.,
		वि.	डा.घ.
13.	पुरखास	उ.के., बी.के., जू.बे.वि., डा.घ.	आ.यू.चि., हो.चि., सी.बे.वि., ग्रा.बैं., कु.वि.के.,
			मा.शि.के.
14.	रतवल	जू.बे.वि., न्या.पं.	सी.बे.वि., डा.घ., उ.स्वा.के., मा.शि.के., फु.बा.,
			बी.के., उ.के.

1	2	3	4
15.	बभनौली	उ.के., बी.के., डा.घ., जू.बे.वि.	फु.बा., सी.बे.वि., मा.शि.के., प.से के.,
			आ.यू.चि., पं.औ., ग्रा.बॅं.
16.	पापी	जू.बे.वि., डा.घ.	बी.के., उ.के., मा.शि.के, हो.चि., कृ.गर्भा.,
			फु.बा., सी.बे.वी.
17.	कैथी	जू.बे.वि.	डा.घ., सी.बे.वि., आ.यू.चि , कृ.गर्भा., ब.स्टा.,
			ग्रा.बॅं., फु.बा., प.नि के., उ.के., बी.के.
18.	बड़ागाव	जू.बे.वि., सी बे.वि.	डा.घ., बी.के., उके., मा.शि.के., प.नि.के.,
			हो.चि., कु वि.के , ग्रा.बैं
19	सण्डी	सी.बे.वि., डा.घ., मा.शि.के.	जू.बे.वि., बी.के., उ.के., प.नि.के., प.अस्प.,
			आ.यू.चि., ग्रा.बैं., हा.से. फु.बा
200	भरसही	सी.बे.वि.	जू.बे.वि., डा.घ, उ.के, बी.के., मा.शि.के.,
			कु.या.के., फ.बा.
21	सोढ़ा	सी.बे.वि , जू.बे.वि.	बी.के., उके., आयूचि., कुबा, प्रा.स्वा.के.
			प.औ., प.से.के., मा.सि के , कु वि के., रा.बै.
22	नाकों	सी.बे.वि., मा.शि.के.	जू.बे.वि , बी.के., उ.के., उ.स्वा.के., रा.बैं.
			मा.शि.के., हा.से., प.से.के
23.	शिवपुर	जू.बे.वि	उ.के., बी.के., मा शि के., कृ.गर्भा., फु.बा.
24.	भुसौलिया	मा.शि.के., जू.बे.वि.	सी बे.वि., बी के , उ.के., फु.बा , हो.चि.
			कृ.गर्भा., ग्रा.बॅं., डा घ
25.	वीधी	सी बे.वि , जू.बे.वि.	हा.से., बीके., उ.के., माशि.के, पसे.के.
			उ.स्वा.के., फु.बा , डा.घ., प.औ
26.	पडरी	सी बे.वि., जू.बे.वि.	डा.घ., हा.से., मा.शि.के., आ यू.चि., कु वि के.
			कृ.गर्भा., न्या.प.
27.	नन्दना	जू.बे.वि., मा.िश के. उ.के.	बी.के., डा.घ., सी.बेवि, पनिके., आ.यूचि.
			फु.बा., कु.वि.के., ग्रा.बैं.
28.	क्जियारी	मा.शि.के., उ.के.	सी.बे.वि., जू.बे.वि., बीके., प.अ., डा.घ.

1	2	3	4
29	गडाव	न्या.प., जू.बे.वि.	कु.बा., ग्रा.बैं., भे.वि के., न्या प. सी.बे.वि., हा से.वि, उके., बी के., फुबा., ग्रा.बैं.,उ.स्वा के., प.से के, मा शि.के., भे वि के.,
30	नौडीहा	न्या.पं., मा.शिके, जूबे.वि.	मि.वि.के.,सूवि के सी.बे.वि., बी के., उके, फुबा., कृ.गर्भा, प.नि.के., हो.चि, डा.घ
31.	चेरूई	जू बे.वि.	सी.बे.वि., उ.स्वा के., प.से के, बी.के., उके,
32	आमडीह	जू.बे वि., ब.स्टा., मा.शि.के., न्या.प	फु.बा,म सि के, डाघ सी.बे.वि., हा से.वि., बी.के., उ.के., प्रा.स्वा के., रा.बैं., ग्रा बैं., फुबा, कुवि के., सूवि के, डा.घ.
33	आसनडीह	मा शि के., जू.बे.वि.	सी.बे.वि., कृ.गर्भा, डाघ, उ.स्वाके, प.निके,
34	डूभा	हो चि., जू.बे.वि.,	फु बा सी.बे.वि, प से.के., प नि के, मा शि.के, डा घ., ता घ., कु.वि के, भे वि.के, उ के., बी के
35	गोहड़ा	मा शि.के., जू.बे.वि., डा.घ.	सी.बे.वि., आ.यूचि, उ.के, बी.के, प.निके.,
36	घघरा	फु.बा., डा.घ., जू.बे.वि.	कृ गर्भाः, पं.औः उ.केः, बी केः, होःचि, पः अस्पः, पंऔः, कुःवि.केः,सी.बे.विः, सूवि.के, ग्राबैंः, न्या प
37.	चप-चपकी	जू.बे.वि., उ.के., फु.बा., मा.शि.के.	बी.के, न्या.पं., उ.स्वा के., प.नि के., प से.के.,
38.	सतबहनी	डा.घ., जू.बे.वि.	डा.घ., ग्रा.बैं. बी.के., उ.के., ब.स्टा , आ.रू चि., उ.स्वा.के., प.औ., प.से.के., ग्रा.बैं., मा.शि के
39.	कोगा	सी.बे.वि., जू.बे.वि., डा.घ.	उ.के., बी.के., हा से.वि., पंऔ., हो.चि., प्रा.स्वा.के.,फु.बा, भे.विके., ब.स्टे.

l	2	3	4
40.	अरझट	मा शि.के., जू.बे.वि., फु.बा.	सी.बे.वि., डा.घ., आ.यूचि., हो.चि., बी.के.,
41	कोरची	जू.बे.वि., डा.घ., मा.शि.के.	उ.के.,कृ.गर्भा., कुवि.के. उ.के., बीके., सी.बे.वि., फु.बा., भे.विके.,
42	वीडर	सी बे.वि., जू.बे वि., फु.बा.	सू वि.के.,म.वि.के , कृ.गर्भा., उ.स्वा.के., ग्रा बैं डा.घ., मा.शि.के., आ यू चि., हो चि., प.नि.के., भे.वि.के., प.से.के.
43	केवाल	जू.बे.वि., मा.सि.के. डा.घ.	उ.के., बी.के., उ.स्वा के., हो.चि., फु.बा., ग्रा.बैं., सी.बे.वि., प.से.के.
44	पकरी	उ के., बी.के , जू.बे.वि.	सी.बे.वि., प.नि.के., डा.घ., आ यू.चि., प.औ., प.से.के, कु.विके, सू.वि.के
45.	बघाडू	सी बे.वि., जूबे.वि., मा.शिके.,	डा.घ., हा.से., बी.के., उके, पसेके., पऔ,
46	महु अरिया	फु बा. रे.स्टे., जू.बे वि., फु.बा.	उ.स्वा.के, बस्टा, भे.विके. सी.बेवि, उ.के., बीके., प.से.के, उस्वाके,
47.	कि रविल	डा.घ., सी.बे वि., न्या.पं., जू बे.वि.	प.नि.के., ग्रा.बैं., कु वि के , भे वि के., न्य.प. हा.से., पु.चौं., उ.के., बी के., प्रास्वा.के., प अ., रा.बैं., ग्रा.बैं., बस्टा, सू.वि.के., कु वि के ,
48	रणहोर	सी.वे बि , जू.बे.वि., मा.सि.के.	भे वि.के., मा शि.के डा.घ., उ.के, बी के., प से.के., उ स्वा के. आ.यू चि.,पं.औ., प नि.के
49.	देवरी	उ.के., बी.के., जू.बे.वि., मा.शि.के.	सी.बे.वि., डा.घ., कृ.गर्भा, आ.यू.चि., हो चि. पं.औ., फु बा
50.	बेलाही	जू.बे.वि., फु.बा.	सी.बे.वि., उ.के., बी के , कृ.गर्भा , उ.स्वा.के. पं.औ.,कु.वि.के., भे.वि के , डा.घ., मा शि के
51	जामपानी	जू.बे.वि., उ.के., बी.के., मा.शि.के.	सी.बे.वि, डा.घ., उ.स्वा.के., प.नि.के., प से.के. पु.बा., कु.वि.के.

1	2	3	4
	->00		
52	जोगीडीह	जू.बे वि., रे.स्टे., सी.बे.वि.,	डा.घ., बीके., उके, पसेके, उस्वाके,
		फु बा.	मा शि.के., ग्रा बैं., न्या.प
53	बेलत्थी	जू.बे.वि.	सी.बे.वि, उ.के., बी.के, माशि.के., कृगर्भा,
			उस्वा.के., भे.वि के , डा.घ , न्या.पं.
54	सिन्दुरिया	न्या प., जू बे.वि	मा शि के., सीबेवि, हासे, उके, बीके.,
			भे.वि.के., प्रास्वाके,पऔ., ग्रा.बैं., डाघ,
			प.से.के., फु.बा
55	सेमिया	जू.बे वि., मा.शि.के.,उ के.,बी.के.	सी.बे.वि., प.नि.के , उस्वा.के , पसे के., फुबा
			कु.वि.के, भे.वि के.
56	जुगैल	जू.बे वि., मा.शि.के.,फु.बा	सी.बे.वी., उके., बीके, पनिके, होचि.
			उ.स्वा.के., कु.वि के., कृ.गर्भा, डा घ
57.	मगरदहा	जू.बे वि., रे.स्टे., फु.बा.	बी.के., उ.के., सी बे.वि., प्रा.स्वा के., आ.यू चि
			प.से.के., ग्रा.बें, मा शि के., पं औ., डा.घ
58.	मिर्चाधुरी	जू बे.वि., रे.स्टे., मा शि.के.,बी.के.	उ.के., सी बे.वि., उ.स्वा.के, प.अ., प.नि के
			कु वि.के, भे.वि के, डा.घ, न्या.प.
59.	चतरवार	जू.बे.वि., सी बे.वि., बी.के.,उ.के.	डा.घ., मा शि.के., आ यू.चि., हो.चि., कृ गर्भा.
			न्या के , सु.वि.के., डा.घ , प.औ.
60.	कचनरवा	जू.बे.वि., डा.घ., मा.शि.के.	उ.के., बी के., सी.बे.वि., पसे.के., उ.स्वा.के.
			प.औ., प.नि.के., कृ.गर्भा, ग्रा.बैं., भे.वि.के.
			हा.से.
61.	कोटा	जू बे.वि., मा.शि.के., बी.के.,	सी.बे.वि., प्रा.स्वा.के., हो.चि., प अ., डा.घ.
		उ.के.	भे.वि.के.,ग्रा.बैं., पं औ., हा.से
शब्द सं	क्षेप		

जि मु

त मु.

जिला मुख्यालय

तहसील मुख्यालय

शब्द-संक्षेप

वि मु.	विकास खण्ड मुख्यालय	पं.च्य.क्लि	पजीकृत व्यक्तिगत क्लिनिक
न्या पं के	न्याय पचायत केन्द्र	पं.औ.	पजीकृत औषधालय
था	थाना	सा स्वा के	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
पु.चौ.	पुलिस चौकी	उ.स्वा.के.	उप स्वास्थ्य केन्द्र
शी भं.	शीत भण्डार	प.नि.के.	परिवार नियोजन केन्द्र
बी.के	बीज वितरण केन्द्र	रा.बॅं.	राष्ट्रीय बैंक
उ.के.	उर्वरक वितरण केन्द्र	भू.वि.बैं	भूमि विकास बैंक
प.अ	पशु अस्पताल	जि.स.बैं.	जिला सहकारी बैंक
प.से.के	पशु सेवा केन्द्रं	सं. ग्रा. बैं.	स्युक्त ग्रामीण बैंक
कृ. गर्भा.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	ग्रा.बैं.	ग्रामीण बैक
म.वि.	महाविद्यालय	थो. बा.	थोक बाजार
हा.से.	हायर सेकेण्ड्री विद्यालय	फु.बा.	फुटकर बाजार
सी.बे वि.	सीनियर बेसिक विद्यालय	सा.बा.	साप्ताहिक बाजार
त शि.सं.	तकनीकी शिक्षण संस्थान	कु.वि.के.	कुक्कुट पालन विकास केन्द्र
औ.प्रसं.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	सू.वि.के.	सुअर पालन विकास केन्द्र
सिने.	छविगृह	भे.वि.के.	भेड़ पालन विकास केन्द्र
रे.स्टे.	रेलवे स्टेशन	म.वि.के.	मत्स्य पालन विकास केन्द्र
ब.स्टे.	बस स्टेशन	जू.बे.वि.	जूनियर बेसिक विद्यालय
ब स्टाः	बस स्टाप		
डा.घ.	डाक घर		
ता.घ.	तार घर		
दू.भा.	दूरभाष		
अस्प.	अस्पताल		
प्रा.स्वा.के.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
आ यू.चि.	आयूर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय		
हो.चि.	होम्योपैथिक चिकित्सालय		
मा शि के	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र		

संदर्भ

- पद्मनाभन्, अन्नत 'मनुष्य व वातावरण', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एवं
 प्रिशक्षण परिषद्, नई दिल्ली, पृष्ठ 79.
- 2. शर्मा, लक्ष्मी नारायण 'अधिवास भूगोल', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1983 पृष्ठ 70.
- 3. Thaha, A: 'Indentification of Hierarchical Growth centres and Delineating of their Hinterlands', 10th cources of IRD, NICD, Hyderabad, Sept.-Oct. 1977, p.1 (Cyclostyled paper).
- 4. Ahmad, E.. Rural settlement types in Uttar Pradesh, A.A.A.G., vol.42 1952, pp. 223-46.
- 5. Meitzen, R.: Siedlung and Agrawesen der westgermanen und obstgermanen, der Kelten, Romer, Finner and slaven (3 vols. and atlas) (Berlin : W. Herty, 1895).
- 6. सिंह, इकबाल भारत मे ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, 1986, प्रष्ठ 1.
 - 7. Pathak, R.K.: Environmental Planning Resources and Development, Chugh Publication, Allahabad, 1990, p. 54.
 - 8. Mishra, R.P., Sundram, K.P. and Prakasa
 Rao, V.L.S.: Regional Development Planning in India:
 New Strategy, Vikas Publishing House, New Delhi, 1974.
 - 9. Babu, R.: Micro-Level Planning: A Case study of Chhibramau Tahsil (Farrukhabad District, U.P.),

Unpublished Thesis, Geography Department, Allahabad University, 1981.

- 10. Jefferson, M.: 'The Distrubution of World's City Folks', Geographical Review, Vol. XXI, p. 453.
- 11. Christaller, W. Die Zentralen orte in Suddent Schland, Jena, G. Fisher, 1933, Tramspated by C.W. Basikin, Englewood Cliffes, N.J., 1966.
- 12. Perroux, F. : 'La Nation de Crossance', Economique Applique, Nos. 1 and 2, 1955.
- 13. Boudeville, T.R.: Problem of Regional Economic Planning, Edinburgh University Press, 1966.

14. op. cit., fn. 11.

15. Bhat, L.S. Micro - Level Planning - A Case study of Karanal Area, Haryana, India, Vikas, New Delhi, 1976, p. 45.

16. op. cit. fn.7. p.55.

17. Sen, L.K.: 'Planning of Rural Growth Centres for Integrated Area Development - A Study in Miryalguda Taluka', NICD, Hyderabad., 1971, p.92.

18. op. cit. fn.7, p.61.

- 19. Haggett, P. etal.: 'Determination of Population Threshold for Settlement Functions by Read Muench Method', Professional Geographer, Vol 16, 1964, pp. 6-9.
- 20. Roy, P. and Patil, B.R. (eds): Manual for Block Level Planning, Mackmillan, New Delhi, 1977, p. 25.

- 21. Wanmali, S.: 'Regional Planning for social Facilities A Case Study of Eastern Maharastra', NICD, Hyderabad, 1970, p.45.
 - 22. op. cit., fn. 17, p.92.
- 23. Nityanand, P. and Bose, S.: 'An Integrated Tribal Development Plan for Keonjhar District Orissa', NICD, Hyderabad, 1976.
- 24. Kumar, A. and Sharma, N.: Rural Centres of Services', Geographical Review of India, Vol. 39, No. 1, 1977, pp. 19-29.
- 25. Singh, S.B.: 'Spatial Orgnisation of Settlement Systems', National Geographer, Vol. XI No.2, 1976, pp. 1930-140.
- 26. Khan, W. etal.: 'Plan for Integrated Development in Pauri Garhwal,' NICD, Hyderabad, 1976, pp. 15-21.
- 27. Dutta, A.K.: 'Transportation Index in West Bengal A Means to Determine Central Place Hiearchy', National Geographical Journal of India, Vo. 16. No. 3 and 4, 1970, pp. 199 207.
- 28. Alam, S.M., Gopi, K.N. and Khan, W.A.:
 'Planning for Metropolitan Region of Hyderabad A
 Case Study', in S.P. Chatterjee, et al. (ed), Proceedings
 of Symposium on Regional Planning, National Committee
 of Georgaphy, Calcutta, 1971.
- 29. Mishra, G.K.: 'A Methodology for Indentifying Service Centres in Rural Area', Behavioural

Sciences and Community Development, Vo. 6, No. 1, 1972, pp. 48 - 63.

30. Singh, J.: Central Place and spatial Organisation in a Backward Economy - Gorakhpur Region - A Case Study Integrated Regional Development, Uttar Bharat Bhoogol Parishad, Gorakhpur, 1979.

31. op. cit., fn. 15.

32. op. cit., fn. 7, p. 45.

33. Prakasha Rao, V.L.S. · 'Problems of Micro - Level Planning', Behavioural Sciences and Community Development, Vol. 6, No. 1, 1972, p. 151.

34. op. cit., fn. 7, p. 45.

35. op. cit., fn. 11.

36. Duncun, J.S. . 'New - Zealand Towns as Service Centres', N.Z.G., Vol. 11, 1955, pp. 119-38.

37. Brush, J.E.: 'The Hierarchy of Central Places in South - Western Wiscoosin', Geographical Review, Vol. X LIII, No. 3, 1953, pp. 380 - 402.

38. Smailes, A.E.: 'The Urban Hierarchy in England and Wales', Geography, 1944, Vol. 29.

39. Carter, H.: 'Urban Grades and Spheres of Influence in South - West Wales', Scot Geography Mag., Vol. 71, 1955, pp. 43 - 58.

40. Ullman, E.L.: 'Trade Centres and Tributary Areas of Phillippines', Georgaphical Review, Vol. 50, 1960, pp. 203 - 218.

- 41. Hartley, G. and A.E. Smailes: 'Shopping Centres in Greater London Areas', Trans. Inst. Br. Geog., 29, 1961, pp. 201 213.
- 42. Kar, N.R.: 'Urban Hierarchy and Central Functions Around the City of Calcutta and its Significance', in L. Norgery (ed.), proceedings of the I.G. II. Symposium in Urban Geography, Lund, 1962.
- 43. Bracey, H.E.: 'Town as Rural Services Centres', Trans, Inst. Br. Geog., 19, 1962, pp. 95-105.
- 44. Green, F.H.W.: 'Motor Bus Centres in South West England Considered in Relation to Population and Shopping Facilities', Trans. Inst. Br. Geo. Vo. 14, 1948, pp. 57 69.
- 45. Carruthers, W.I. 'A Classification of Services Centres in England and Wales', Geographical Journal, Vo. 123, 1957, pp. 371 85.
- 46. Siddal, W.R.: 'Wholesale Retail Trade Ratios as Indices of Urban Centrality', Economic Geography, Vol. 37, 1961.
- 47. Ablodeen, J.O.: 'Urban Hierachy in a Developing Country', Economic Geography, Vol. 43 (4), 1967, pp. 347 367.
- 48. Preston, R.E.: 'The Structure of Central Place Systems, Economic Geography', Vol. 47 (2), 1971, pp. 136 55.

- 49. Berry, B.J.L. and Garrison, W.L.: 'The Functional Bases of the Central Places Hierarchy', Economic Geography, Vo. 34 (2), 1958, pp. 145 54.
- 50. Vishwanath, M.S.: A Geographical Analysis of Rural Markets and Urban Centres in Mysore, Ph.D. Thesis, B.H.U. Varanasi.
- 51. Singh, O.P.: 'Towards Determining Hierarchy of Service Centres A Methodology for Central Place Studies', N.G.J.I. Vol. XVII (4), 1971, pp. 165 177.
- 52. Rao, V.L.S.P.: 'Planning for An Agricultural Region, in New Strategy, Vikas, New Delhi, 1974.
- 53. Singh, J. . 'Nodal Accessibility and Central Place Hierarchy A Case Study in Gorakhpur Region', pp. 101 112.
- 54. Jain, N.G.: 'Urban Hierarchy and Telephone Services in Vadarbh (Maharashtra)', N.G.J.I., Vo. XVII (2 and 3), 1971, pp. 134 37.

55. op. cit., fn. 51.

56. op. cit., fn. 30.

op. cit., fn. 11.

XXXXXXXXX

अध्याय 4

कृषि के विकास की पृष्ठभूगि एवं नियोजन

अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कुल कार्यशील जनसख्या का 70.88%भाग कृषि तथा उससे सम्बद्ध कार्यों में लगा हुआ है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 26.45% भाग पर कृषि होती है। जबिक देश के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। कृषि क्षेत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं कहा जा सकता किन्तु कृषि कार्य में लगी कार्यशील जनसंख्या के आधार पर नि संदेह अध्ययन क्षेत्र को कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जा सकता है। आधुनिक वृहद् उद्योगों का विकास भी कृषि के महत्व एवं उस पर निर्भरता को सकुचित नहीं कर पा रही है। वास्तविक रूप में अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक क्रियाकलामों एव संस्कृति का आधार कृषि ही है। कृषि, यहाँ के लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन नहीं वरन् जीवन शैली है।

4.। कृषि-सम्प्रत्यय

कृषि का प्रारम्भ, नव पाषण युग में हुआ, वेदों तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों मे भी कृषि का उल्लेख है। वास्तव में यह एक ऐसा आर्थिक कार्य है जिसका विकास लेखन-कला के पूर्व हुआ था। अनेक प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक विकास के बावजूद कृषि का महत्व अक्षुणण है। कृषि उत्पादन की विफलता से सम्पूर्ण आर्थिक तन्त्र अव्यवस्थित हो जाती है। कृषि सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है।

मिट्टी को जोतने-गोड़ने तथा फसल उगाने एवं पशु-पालन करने की कार्य प्रणाली, कला एवं विज्ञान को कृषि कहते हैं। बुकानन (1959)² ने कृषि शब्द को मिश्र-शब्द कहा है जिसका बड़ा व्यापक अर्थ है और इसके अन्तर्गत मानव प्रयोग के लिए खाद्य पदार्थ अथवा कच्चे माल उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का उपयोग करने वाली अत्यन्त साधारण से लेकर विषम विधियां आती हैं। इसी तथ्य को मेकार्टी (1966)³ ने सोदेश्य फसलोत्पादन एवं पशुपालन कहा है। कृषि के इस व्यापक अर्थ को अंग्रेजी का एग्रीकल्चर' शब्द अंशिक रूप में ही व्यक्त करता है, जिसका अर्थ भूमि को जोतकर फसल पैदा करना है। परन्तु कृषि

के अन्तर्गत फसल उत्पन्न करने के साथ-साथ पशुपालन तथा सिचाई आदि क्रियाए भी सिम्मिलित की जाती है। कृषि ने मानव के घुमक्कड़ प्रवृत्ति को स्थायित्व प्रदान किया। मानव बिस्त्यों के प्रतिरूप एवं कृषि में घनिष्ठ सह-सम्बन्ध है। जिम्मरमेन के अनुसार कृषि मानव के उन उत्पादक प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा वह भूमि पर बस कर उसके उपयोग की किशिश करता है और यथासंभव पौधों एवं पशुओं के प्राकृतिक प्रजनन एव वृद्धि की प्रिकृया को तीव्र एवं विकसित करता है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य मानव के लिए आवश्यक या उसके द्वारा वांछित वानस्पतिक एवं पशु उपजें उत्पन्न करना है। जसवीर सिंह (1974)⁵ ने कृषि की सिवस्तार व्याख्या की हैं, उनके अनुसार, कृषि फसलोत्पादन से अधिक व्यापक है। यह मानव द्वारा ग्रामीण पर्यावरण का रूपान्तरण है जिससे कितपय उपयोगी फसलों एवं पशुओं के लिए सम्भव अनुकूल दशाए सुनिश्चित की जा सके। इनकी (फसलो एव पशुओं की) उपयोगिता सतर्क चयन से बढ़ायी जाती है। इनमे उन सभी पद्वितयों को सिम्मिलित किया जाता है , जिनका प्रयोग कृषक कृषि के विभिन्न तत्वो को विवेकपूर्ण ढग से संगठित करने और अनुकूलतम उपयोग से करता है।

मानवीय आर्थिक क्रियाओं मे कृषि सबसे अधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण है। ⁶ मेक मास्टर⁷ द्वारा प्रतिपादित कृषि के भौगोलिक अध्ययन के तीन उपागमों - पारिस्थितिकी भूमि उपयोग तथा सांख्यिकीय में भूमि उपयोग उपागम को अपनाया गया है। आंकर्ड़ों एवं सूचकाओं की अनुपलब्धता के कारण अन्य दो उपागमों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

4.2 कुषि योग्य भूमि

अध्ययन क्षेत्र की 86.61% जनसंख्या गाँवों में रहती है जहाँ उत्पादन का मुख्य स्त्रोत भूमि है। भूमि पर अधिकार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर को व्यक्त करता है। स्वतन्त्रता के बाद भूमि सुधार के लिए किए गए पुनर्वितरण ने सार्वजिनक पद्वित में विशेष स्थान ले लिया है जैसे ग्रामीण उत्पादन पद्वित कृषि पर ही केन्द्रित थी, भूमि सुधार भी कृषि से ही सम्बन्धित था। भूमि पर कृषि-कार्य किया जाना भूमि उपयोग का एक माध्यम है। फाक्स ने भूमि उपयोग के प्रारम्भिक अवस्था को 'भूमि प्रयोग' (लैण्ड यूज) तथा द्वितीय सोदेश्य उपयोग को 'भूमि उपयोग' (लैण्ड यूटीलाइजेशन) बताया। चौहान के वैनजेटी तथा

भूमि का अपना कोई महत्व नहीं है, इसका मूल्याकन मानवीय प्रयासों से आका जाता है - भूमि का उपजाऊ और बंजर रूप में वर्गीकरण उसके सम्भावित सामाजिक उपयोग से है। प्रारम्परिक रूप में कृषि ही भूमि का सबसे उपयुक्त उपयोग है। इसलिए कृषि-उत्पादकता ही भूमि वर्गीकरण का आधार रहा है। भूमि की उपयोगिता की धारणा स्थिर न होकर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। पारम्परिक रूप में कृषि ही भूमि का सबसे उपयोगी प्रयोग रहा है। फिर भी अध्ययन क्षेत्र में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का एक बड़ा हिस्सा है जिसके समुचित उपयोग की आवश्यकता है।

कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत शुद्ध बोये गए क्षेत्रफल के अतिरिक्त कृषि योग्य बजर भूमि, वर्तमान परती भूमि तथा अन्य परती भूमि को सिम्मिलत किया गया है। इसके अन्तर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (681928 हेक्टेयर) के 38.61 प्रतिशत भाग समाहित हैं। शेष का 49.11% वन, 8.87% ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि, 6.12% कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग मे लायी गयी भूमि, 0.04%, चारागाह तथा 1.24% भाग पर उद्यान वृक्षों का प्रसार है (तालिका 4.1)। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता विकास खण्ड राबर्ट्सगज, चतरा तथा घोरावल में कृमश 75.66%, 65.24%, तथा 60.38% है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता विकास खण्ड राबर्ट्सगज, चतरा तथा घोरावल में कृमश 75.66%, 65.24%, तथा 60.38% है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता विकास खण्ड नगवां, म्योरपुर, दुन्दी, चोपन तथा बभनी में कृमश 20.60%, 29.60%, 33.38%, 33.74% तथा 35.39% है (तालिका - 4.1)।

(अ) शुद्ध बोया गया कृषि-क्षेत्र

शुद्ध बोये गए क्षेत्र के अन्तर्गत केवल वास्तविक कृषित क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 180354 हेक्टेयर है जो सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का26.45% है तथा कुल कृषि योग्य भूमि का 68 42% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र0 का शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र सबसे अधिक विकास खण्ड रावर्ट्सगंज में 64.28% तथा सबसे कम विकास खण्ड नगवां में 13.23% है। किन्तु कृषि योग्य भूमि का शुद्ध बोया कृषि क्षेत्र सबसे अधिक तथा न्यून क्रमश विकास खण्ड चतरा में 92.20% तथा म्योरपुर मे

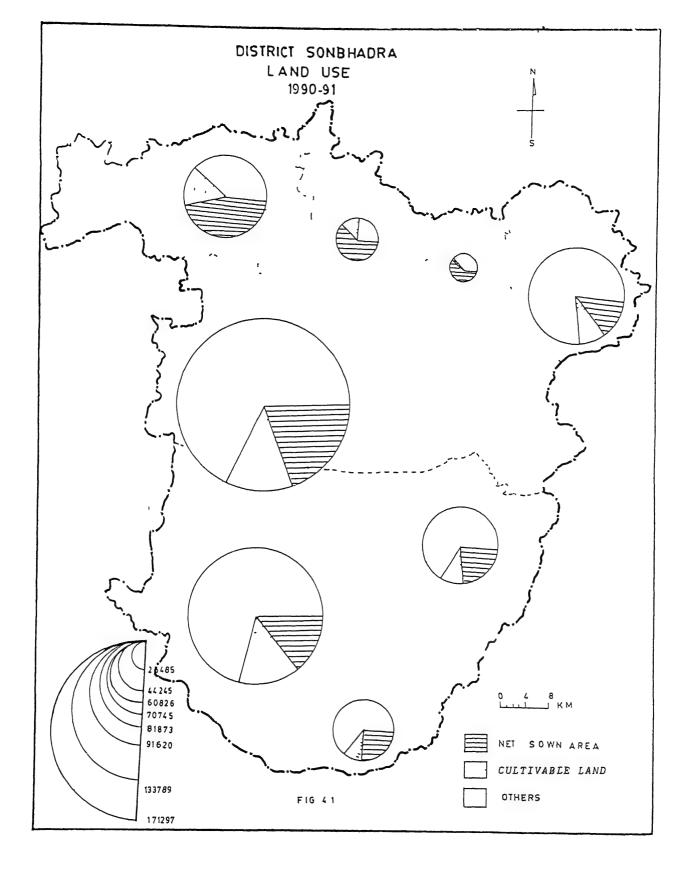
49.22% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र अवनत क्रम में क्रयश राबर्ट्सगंज (64.28%), चतरा (60.15%), घोरावल (48.20%), बभनी (25.14%), दुन्धी (22.76%), चोपन (19.78%), म्योरपुर (14.57%), तथा नगवा (13.23%) है। इसी प्रकार कुल कृषि योग्य भूमि का शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र अवनत क्रम मे क्रमश विकास खण्ड चतरा (92.20%), राबर्ट्सगंज (84.96%), घोरावल (79.83%), बभनी (71.05%), दुन्धी (68.19%), नगवा (59.11%), चोपन (58.62%), तथा म्योरपुर (49.22%) है। स्पष्ट है कि विकास खण्ड वार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कृषि योग्य भूमि एव शुद्ध बोया कृषि क्षेत्र तथा कृषि योग्य भूमि का शुद्ध बोये गए कृषि क्षेत्र का क्रम समान नहीं है। इसका प्रमुख कारण धरातलीय स्वरूप है। अपेक्षाकृत मैदानी भागों में कृषि योग्य भूमि के अधिकतम भाग पर कृषि कार्य होता है।

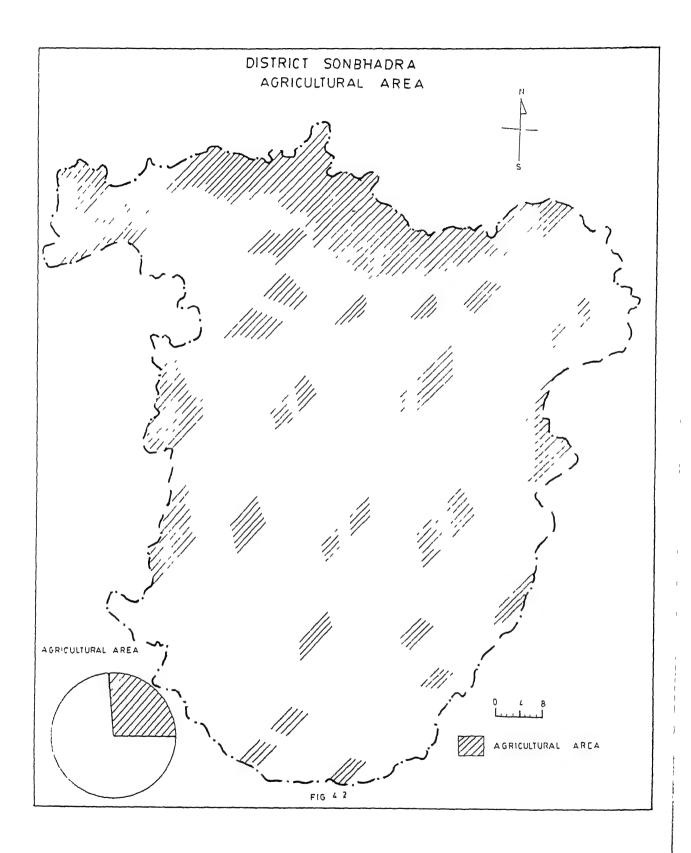
(ब) एक से अधिक बार बोया गया कृषि-क्षेत्र

कुछ कृषि क्षेत्रों में विभिन्न समयों मे एक से अधिक फसल उगायी जाती है। विभिन्न सगयों में एक ही कृषि क्षेत्र मे एक से अधिक बार बोये गए क्षेत्र को इसके अन्तर्गत सिम्मिलित करते है। एक से अधिक बार बोया गया कृषि क्षेत्र बहुफसली क्षेत्र से स्पष्टत भिन्न है । बहुफसली कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत एक ही समय में एक साथ एक से अधिक फसलों को बोया जाता है जबकि एक से अधिक बार बोये गये कृषि-क्षेत्र के अन्तर्गत फसलों को एक वर्ष मे एक से अधिक बार बोया जाता है। किसी क्षेत्र में एक से अधिक बार फसलों का बोया जाना सिंचाई सुविधा, मृदा की उर्वरा शक्ति, नयी टेक्नालजी आदि कृषि निवेश (इन्पुट) पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त लघु जोतों के आकार वाले भागो मे वृहद् जोतों के की अपेक्षा एक से अधिक बार कृषि क्षेत्र के बोये जाने की सम्भाव्यता आकार वाले भागों अधिक पायी जाती है। इसी प्रकार शिक्षित युवकों द्वारा कृषि कार्य करने पर कृषि क्षेत्र के एक से अधिक बार बोए जाने की सम्भावना बढ़ जाती है। अध्ययन क्षेत्र के कुल शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के 41.56% (74966 हेक्टेयर) भाग पर एक से अधिक बार कृषि कार्य होता है। विकास खण्ड राबर्ट्सगंज में सबसे अधिक 64.22% भाग पर एक से अधिक बार कृषि कार्य होता है । इसके बाद क्रमशः घोरावल (59.22%), नगवां (48.03%), चतरा (43 25%), चोपन (37.72%), दुन्ही (18.82%), बभनी (15.93%) तथा म्योरपुर (13.18%) स्थान आता है।

तालिका 4.। भूमि उपयोग (हेक्टेयर मे) 1990 - 91

					•								
विकसखण्ड	भौगोलिक क्षेत्रफल	कुल कृषि योग्य भूमि हेक्टेयर भें	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि प्रति0	भुद्ध बोया गया क्षेत्र0	कुल भौगो0 क्षेत्र0 का प्रतिशत	भूति भूति वा मान्य भूति भूति वा मान्य	द्भिषयोग्य बजर भूमि	भूमे वर्तमान	भूति	*#####################################	सूबि अतिरिक्त अन्य अन्य अपयोग अपयोग भूमि वायोग भूमि	चारागाह	उद्यान वृक्षों का क्षेत्रफल
- !	2	ω ! !	4	5	6	7	8	9	10	=	12	13	14
घोरावल	81873	49433	60 38	39464	48 20	79 83	3290	2481	2481 4198	1381	4057		1191
राबर्दसगज	44245	33477	75 66	28442	64 28	84 96	1254	1760	1760 2021 3251		4555	26	436
चतरा	25485	16627	65 24	15330	60.15	92 20	593	240	494	478	4197	ယ	610
नगवा	91620	20500	22.60	12118	13.23	59.11	4287	1900	2195 1352		5060	2	4540
चोपन	171297	57798	33.74	33885	19.78	58.62	11850	2323	9740 23381 12285	23381		130	1543
म्योरपुर	133789	39614	29.60	19499	14.57	49.22	7704	5584	6827 2048		6114	1	105
હિલ્લી	70745	23617	33.38	16104	22.76	68.19	2028	1360	4125 1001		2616	1	Ξ
बभनी	60826	21524	35.39	15293	25.14	71.05	2428	670	3133		1528	4	· ∞
योग	679880	262620	38.63	180135	26-50	68.59	33434	16318 3		33210		276	8444
नगरीय योग	2048	642	31.35	219	10.69	34.11	<u> </u>	169	223	52	1354		
जनपद योग	681928	263262	38.61	180354	26.45	68.42	33465	16487	32956	33262	16487 32956 33262 41766	276	8444
1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1		1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1





4.3 फसल प्रतिरूप

फसल प्रतिरूप के अन्तर्गत फसलों के स्थानिक एव कालिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। अनेक फसलों के स्थानिक और कालिक वितरण से बने स्वरूप को फसल प्रतिरूप वहते है। 12 फसल प्रतिरूप पर भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तथा सस्थागत कारकों का प्रभाव पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के फसल प्रतिरूप वितरण के लिए कालिक पक्ष को अपनाया गया है क्योंिक इसमें स्थानिक प्रतिरूप का स्वत समावेश हो जाता है। अध्ययन क्षेत्र में खरीफ एव रबी दो मुख्य फसलें हैं। जायद फसल की खेती नहीं के बराबर होती है। जायद फसल कुछ सब्जियो एव फलों तक ही सीमित है। अध्ययन क्षेत्र के खरीफ, रबी एव जायद फसलों के अन्तर्गत समाहित कृषि क्षेत्र को तालिका 4 2 में प्रदर्शित किया गया है।

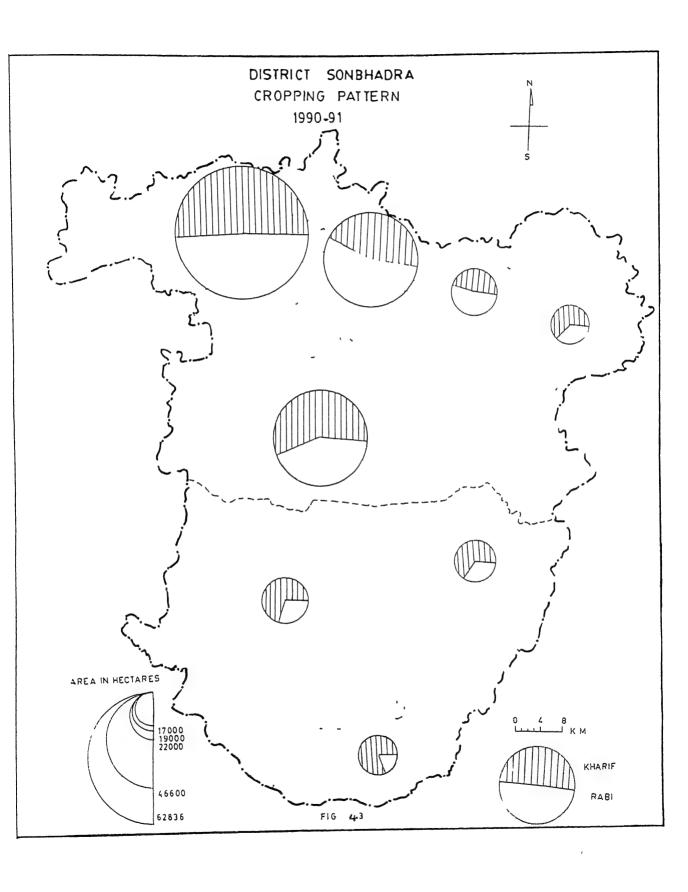
(अ) खरीफ - फसल

जून-जुलाई मे मानसून आगमन के समय बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूगफली, तिल, तम्बाकू, मूग, अरहर, उड़द तथा मोठ आदि खरीफ की फसलें हैं। अध्ययन क्षेत्र मे 146153 हेक्टेयर क्षेत्र पर खरीफ की खेती की जाती है जो सकल बोये गए क्षेत्र का 57.24% तथा कृषि योग्य भूमि का 55.52% है। सकल बोये गए कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक 80 76% भाग पर विकास खण्ड बभनी मे कृषि होती है। खरीफ फसलों का क्षेत्रफल, सकल बोए गए क्षेत्र का अवनत क्रम में विकासखण्ड बभनी, म्योरपुर, दुन्ही, नगवां, चोपन, घोरावल, चतरा तथा राबर्ट्सगज मे ग्रमश 80.76%, 73.29%, 66.07%, 64.73%, 57.50%, 51.24%, 48 40%, तथा 46.40% है। पहाड़ी विकास खण्डों में उच्च प्रतिशत होने का कारण रबी फसल, के लिए आवश्यक सिंचाई व्यवस्था का अत्यन्त अभाव तथा मुदा संरचना है। इन विकास खण्डों में खरीफ फसलों में मक्के का प्रतिशत सबसे अधिक है। जबिक विकास खण्ड चतरा, राबर्ट्सगंज तथा घोरावल (जो अपेक्षाकृत समतल है) में धान की अच्छी खेती होती है। गन्ना, खरीफ एवं रबी दोनो फसल मौसम में होता है, इसलिए इसका विवरण अलग से प्रस्तुत किया गया है। सकल बोए गए कृषि क्षेत्र में धान का प्रतिशत 22.69, ज्वार का प्रतिशत 1.31, मक्का का प्रतिशत 5.34, तथा बाजरा का प्रतिशत0.19 है (तालिका 4.3)।

तालिका 4 2 विभिन्न परालों के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टेगर में 1991

विकासहरू । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	र्भ भूग	एकत नोपा इत्रेफत है0 मे 2 2 2 26707 21961 17939 46666 22069	प्रतिश्रत 3 24 61 18 29 8 60 7 03 18 27 8 64 7 50	खरीफ फसल मे बोग क्या होत्रफल 32200 21594 10630 11612 26833 16175	प्रतिश्वत 51.24 46 23 48.40 64 73 57.50 73.29 66.07	रूनी पसल में नीया नया शेनफल 6 29955 24968 11331 6327 19809 5890	प्रतेश्वत 7 47 67 53 46 51 60 35.27 42.00 26.69 33 91	अवद्य प्रस्तुत अवद्य वृद्य होत्रपत्त 23 23	9 0.10 0.05 - - - - 0.02	02 G G G G G	स्त क्ला फरत का क्षेत्रफल 10 617 5 122
	चतरा नगवा चौपन	21961 17939 46666	8 60 7 03 18 27	10630 11612 26833	48.40 64 73 57.50	6327 19809	51 60 35.27 42.00	1 1 1			
7 6	_{पुर} पुर	22069 19134	8 64 7 50	16175	73.29 66.07	5 990 6489	26.69 33 91	ω Δ		0.02	0.02 -
८ वभनी गामीच योग	वभनी	17729	6 95	14318	80 76	3411	19 24	2 '		,	
3	समस्त नगरीय योग	•	- 3	149	53.41	130	46.45	' '		,	
जनपद योग	끸	255320	100.00	146153	57.24	108310	42.42	94		0.04	0.04 763

स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 45-46 एवं संगीणत ।



तालिका 4.3 खरीफ एवं रबी फसलों के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का प्रतिश्रत वितरण 1990-91

फसल	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सकल बोये गए 255320 हेक्टेयर का प्रतिशत
कुल खाद्यान्न	218016	85 39
कुल धान्य	189722	74.30
कुल दलहन	28294	11 08
कुल तिलहन	20234	7.92
धान	70469	27.69
गेहूँ	47803	18.72
া	22223	8.70
ज्वार	3351	1.31
मक्का	13630	5.34
बाजरा	496	0 19
ग्ना	763	0 30
आलू	522	0.20

स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992 से संगणित ।

(ब) रबी-फसल

रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर से दिसम्बर माह तक होती है। इन फसलों की कटाई मार्च-अप्रैल माह में होती है। इन फसलों की उत्पादकता सिचाई पर निर्भर करती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, अलसी तथा बरसीम आदि मुख्य रबी की फसलों हैं। अध्ययन क्षेत्र में खरीफ फसलों की तुलना में रबी के फसलो का कम विकास हुआ है। रबी फसलों के अन्तर्गत 108310 हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है जो सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि का 41.14%, तथा सकल बोए गए कृषि क्षेत्र का 42.42% है। सकल बोए गए क्षेत्र का विकास खण्डवार रबी फसलों बोए गए क्षेत्र, अवनत क्रम में इस प्रकार हैं -

40-4-0 DISTRICT SONBHADRA AREA UNDER DIFFERENT CROPS: 1990 - 91 Fig 4.4 CROPS O-10mmD0 中レーの目 250 50

राबर्ट्सगज (53.46%), चतरा (51.60%), घोरावल (47.67%), चोपन (42.00%), नगवां (35.27%), दुद्धी (33.91%), म्योरपुर (26.69%), तथा बभनी (19.24%) (तालिका 4.2)।

रबी की मुख्य फसल गेहूं है जो सकत बोए गए क्षेत्र के 18 72% भाग पर बोई जाती है। जौ की बुवाई 8.70% भाग पर होती है (तालिका 4.3)। गेहूं का कृषि क्षेत्र अवनत क्रम में क्रमश विकास खण्ड घोरावल, राबर्ट्सगज, चतरा, चोपन, नगवां, दुद्धी, म्योर्पुर तथा बभनी में हैं।

तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि खरीफ एव रबी फसलों के अन्तर्गत सम्पूर्ण खाद्यान्नों, धान्यों, दलहनों तथा तिलहनों की बुवाई क्रमश 218016, 189722, 28294 तथा 20234 हेक्टेयर पर की जाती है। सकल बोये गए कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों का प्रतिशत 85.39% है जबिक धान्यों, दलहनों एवं तिलहनों की बुवाई क्रमश 74.30%, 11.08%, तथा 7.92% भाग पर होती है। गन्ने की बुवाई सकल बोये गए क्षेत्र के 0.30% भाग पर होती है। सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्र का 80.87% विकास खण्ड घोरावल में, 15.99% राबर्ट्सगज में तथा 3.15% चोपन में पाया जाता है। आलू का कृषि क्षेत्र भी अति न्यून (522 हेक्टेयर) है।

(स) जायद - फसल

खरीफ तथा रबी के ग्रीष्मकालीन सक्रमण काल मे जायद की कृषि की जाती है, जिसमें उड़द, मूंग, खरबूज, तरबूज, ककड़ी तथा सिब्जियों का उत्पादन किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे जायद फसल के अन्तर्गत केवल सिब्जियों का उत्पादन होता है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल अत्यधिक न्यून, 94 हेक्टेयर है, जो सकल बोए गए कृषि क्षेत्र का 0.04% है। सिंचाई सुविधा की कमी इस फसल को निरूसाहित करती है। कुछ नगरीय क्षेत्रों के आस-पास क्षेत्रों में जायद फसलों का उत्पादन होता है।

(द) औद्यानिक - फसल

औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत उन फसलों को सिम्मिलित किया गया है जिनका

उत्पादन उद्यानों के रूप में किया जाता है । खरीफ, रबी तथा जायद फसलो की तरह इसका कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इन्हे 'बारहमासा' (वर्ष भर) बना दिया है। इसके अन्तर्गत फलों, सिब्जियों, मशालों तथा फूलों को सिम्मिलित किया गया है। यद्यिप इनमे से कुछ को खरीफ, रबी एव जायद फसलों के अन्तर्गत सिम्मिलित किया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तालिका 4.4 में उल्लिखित फसलों को औद्यानिक फसल की सज्ञा दी गयी है।

तालिका 4.4 औद्यानिक फसल 1992-93

		उत्पादन	उत्पादकता
मशाला तथा फूल	हेक्टेयर मे	विवंटल में	क्विंटल / हेक्टेयर
			44
।. फल			
आम	1303	7516.00	57 67
अमरूद	2115	11575-00	54 72
केला	10	40.00	40 00
नीबू प्रजाति	37	172.72	46.48
ऑवला देशी	727	3565.37	49 05
बेर	925	4916.37	53 15
अन्य	3327	13717-22	41.23
योग	8444	41502.25	49 15
2. सब्जियौं			
आलू	529	6880-00	130.00
टमाटर	517	4924-42	95.25
बेंगन	435	3967 - 20	91 20
मिर्च	365	2110-68	57 20

	2	3	4
गोभी प्रजाति	210	1745.10	83.10
कद्दू प्रजाति	874	5943.20	68.00
मटर	403	3304 60	82 00
भिण्डी	517	2505.00	50.00
अन्य	993	8172.39	80.30
योग	4847	39632 59	81.76
3. मशाला			
हल्दी	25	336.84	120 30
मिर्च	217	193.13	8.90
धनिया	435	506.92	11 6
मेथी	315	318 00	12 0
सौंफ	18	20.16	11 2
प्याज	503	6840.80	136.0
लहसुन	85	425.00	50.0
अन्य	103	640.66	62.20
योग	1706	9341.51	54 76
4. फूल			
गुलाब	3	2 46	8.20
गेंदा	4	4.04	10 10
रजनी गंधा	1	0.35	3 50
अन्य	2	1.44	7.20
योग	10	8.29	8.29

तालिका 4.4 से स्पष्ट है कि औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बहुत कम है । अमरूद के बाग आम के बाग से अधिक हैं । केला का क्षेत्रफल मात्र 10 हेक्टेयर है। आलू और टमाटर का कृषि क्षेत्र लगभग समान है किन्तु उत्पादन तथा उत्पादकता में महत्वपूर्ण अन्तर है । मशालों में धनिया की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है । अध्ययन क्षेत्र के 10 हेक्टेयर भूमि पर फूल उगाए जाते हैं, जिनमें गुलाब तथा गेंदा प्रमुख है । तालिका 4.4 में विस्तृत विवरण उल्लिखित है ।

4.4 फसल प्रतिरूप में परिवर्तन

तालिका 4.5 में 1960-61 तथा 1990-91 का फसल प्रतिरूप प्रदर्शित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि इन वर्षों के अन्तराल में फसल प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । इस परिवर्तन के प्रमुख कारण शुद्ध बोये गए क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि तथा अन्य कृषि निष्टियों (इनपुट्स) एवं विधियों के विकास तथा कृषकों द्वारा उन्हें अपनाए जाने के जागरूकता के कारण संभव हो सका । सर्विधिक परिवर्तन खाद्यान्नों में हुआ । अध्ययन क्षेत्र की चावल हमेशा प्रमुख फसल रही है । वर्ष 1990 - 91 में भी एक चौथाई से अधिक (27.69%) भाग पर बोई जाती है । सबसे अधिक गुणात्मक परिवर्तन चावल की फसल में

तालिका 4.5 फसल प्रतिरूप में परिवर्तन

फसल	सकल बोये गए क्षेत्र का प्रतिशत		परिवर्तन		
	1960-61	1990-91			
चावल	17.31	27.69	+ 10-38		
गेहूँ	11.68	18.72	+ 7.04		
जौं	16.27	8.70	- 7.57		
ज्वार	4.70	1.31	- 3.39		
मक्का	11.60	5.34	- 6.26		
बाजरा	2.60	0.19	- 2.41		
गन्ना		0.30	+ 0.30		

किसी इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलों के समूह को फसल - सयोजन कहते है जो वहाँ की प्राकृतिक - आर्थिक दशाओं तथा कृषक की सामाजिक एव वैयक्तिक गुणों के अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है । 14

(अ) फसल - कोटि निर्धारण

फसल- कोटि निर्धारण के अन्तर्गत फसलों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित किया जाता है जो सकल बोए गए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात किया जाता है । प्रस्तुत अध्ययन में सकल बोये गए क्षेत्र से सभी फसलों के बोए गये क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात किया गया है । इसके पश्चात उसे अवनत क्रम में रखकर प्रत्येक विकासखण्ड की फसल - कोटि निर्धारित की गयी है । कोटि निर्धारित करते समय अध्ययन क्षेत्र के सकल बोए गए क्षेत्र का सम्बन्धित फसल का क्षेत्रफल यदि ।.00% से कम है तो छोड़ दिया गया है । यदि सम्बन्धित बोए गए फसल का क्षेत्रफल विकासखण्ड स्तर पर ।.00% से कम है तो उसे कोटि - निर्धारण में सम्मिलित किया गया है ।

उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर कोटि - निर्धारण के लिए कुल 10 फसलों (चावल, गेहूँ, मक्का, चना, जौ, मसूर, तिल, अरहर, अलसी तथा ज्वार) का चयन किया गया है । यद्यपि जनपद स्तर पर प्रथम कोटि चावल (27.69%) का, द्वितीय कोटि गेहूँ (18 72%) का, तृतीय कोटि जौ (8.70%) का चतुर्थ कोटि चना (6.05%) का तथा पंचम कोटि मक्का (5.34%) का है । किन्तु विकासखण्ड स्तर पर इसमें काफी विभिन्नता है । सामान्यतौर पर चावल प्रथम कोटि की फसल है । किन्तु विकासखण्ड राबर्ट्सगंज -चोपन तथा म्योरपुर में इसकी द्वितीय कोटि है । एक विकासखण्ड (राबर्ट्सगंज) में गेहूँ की प्रथम कोटि तथा तीन विकासखण्डों (घोरावल - चतरा तथा नगवां) में द्वितीय कोटि है । विकासखण्ड म्योरपुर व दुद्धी में इसकी षष्ट्म कोटि है । विकासखण्ड म्योरपुर में जौ प्रथम कोटि की फसल है । विकासखण्ड दुद्धी व बभनी में मक्का द्वितीय कोटि की फसल है । अलसी को विकासखण्ड घोरावल, राबर्ट्सगंज, चतरा तथा नगवां में क्रमज्ञ तृतीय, चतुर्थ, तृतीय तथा तृतीय कोटि प्राप्त है, जबिक शेष विकासखण्डों मेमहत्वपूर्ण कोटि नहीं प्राप्त है । तिल, ज्वार, मसूर तथा अरहर को सामान्यत निम्न कोटि प्राप्त है । उल्लेखनीय है कि मोटे अनाजों को अपेक्षाकृत उच्च कोटि प्राप्त है (तालिका - 4.6)।

तालिका 4.6

फसल कोटि, जनपद सोनभद्र वर्ष, 1990-91 फसलों की कोटियां एवं उनका एकल बोये गए क्षेत्र से प्रतिशत

म्यू० म्यूर	H 0	गे	चा0	म्रोतः स	· ·	7.	6.	57	4.	္	2.	.	विकसस्यण्ड
मन्ना		<i>ज्</i> त्रों.	चावल	साहिंयकीय पत्रिव	बभनी	લુદ્ધી	म्योरपुर	चोपन	नगवां	चतरा	राबर्ट्सगंज	घोरावल	विकस्सखण्ड ।
				पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 43-55 से सगणित ।	चा0 19.69	বাত 20.85	जौ 29.15	च0 23.81	चा0 37.70	বা 0 46.88	गे0 45.41	चा0 38 14	
				, 1992, पृष्ठ ४३	म0 16.67	म0 16 50	चा0 13.49	चा0 18.92	गे0 12.92	गे० ३०.।।	चा032.41	गे० 28.52	2 3 4 5 6
				43-55 से सग	जौ 14.71 ति0 8 30 गै0 7.45 अर0 4.08 च0 1.65	जौ0 15.45	म0 10.81	म0 15.05	अ0 7.06	अ0 8.08	च0 5.29	अ0 5.87	ယ
નો ગો ં	নি		अर0	णित -	ति० 8 30	च0 9.11 ति0 4.17 गे0 3.80	ति0 6.58 ज्वा0 4.44 गे0 3.97	गे0 14.29	जौ 6.48	च0 2.78	अ0 5.22	ਚ0 5.04	4
			र0 अरहर		गे0 7.45	ति0 4.17	ত্ৰা0 4.4	ज्वा0 3 6	H 0 5.00	जौ. 2.60	म्सू० 2 72	जौं। 2.98	5
- 10 A	- A	21	1		अर0 4.08	गे0 3.80		6 अस्य 3.65	म0 5.00 अर0 1.91 च0 1.78	मसू0 2.41	मसू0 2 72 जौ । 80	जौं। 2.98 म0 2.76	6
						अर0 2.73 अ0 1.60	च0 1.72	ज्वा0 3 66 अंस0 3.65 अ0 3.32	च0 1.78	मसू0 2.41 म0 0.90	म0 0.92	मसू० । 79	7
					अ0 1.20	अ0 1.60	अर0 ।.26	ति0 2.45	ति० ।.30	अर0 0.82	ज्वा० 0.76	अर0 0.92	&
					ত্ৰা0 0.76	和 0.62	अ0 0.98	जौ 1.82	म्यूः।।।	अर0 0.82 ज्वा0 0.24	ज्वा० 0.76 अस० 0.60	अर0 0.92 ज्वा0 0.62	9 10
					मसू० 0.14	ज्वा० 0.37	मसू० 0.23	मसू० 0.72	ত্ৰা0 0.66	ति0 0.23	ति० 0.13	ति0 0.46	10

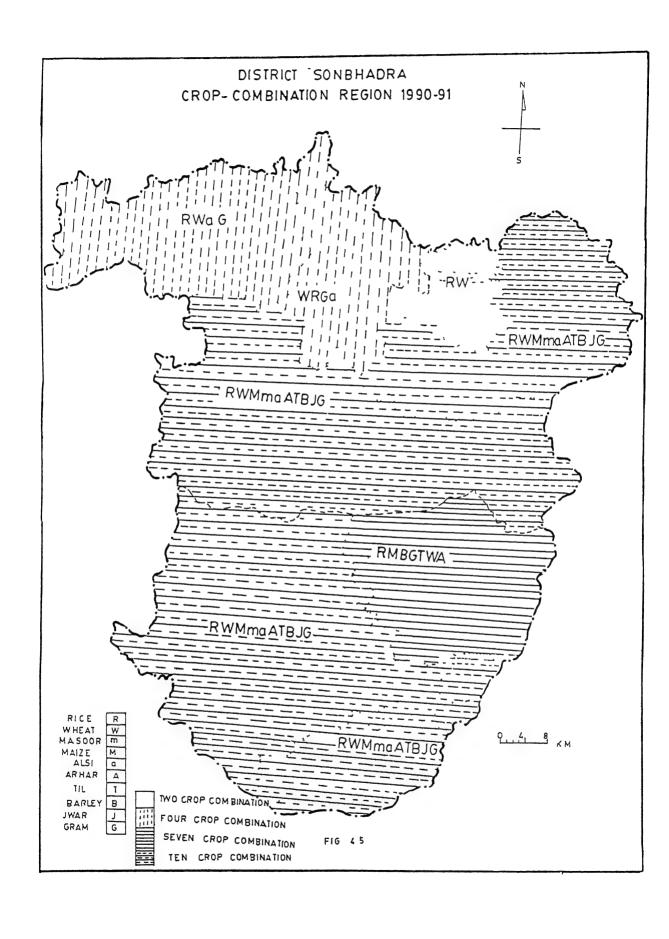
(ब) फसल - संयोजन प्रदेश

फसल - संयोजन प्रदेश का निर्धारण सांख्यिकीय विधियों पर आधारित है । जानसन 15 , थामस, 16 वीवर 17 तथा अय्यर 18 आदि विद्वानों द्वारा निर्धारित सांख्यिकीय विधियों महत्वपूर्ण है । इसके अतिरिक्त औद्योगिक सरचना के विश्लेषण में दोई 19 द्वारा अपनायी गयी विधि तथा नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण में नेल्सन 20 द्वारा अपनायी गयी सांख्यिकीय विधि भी काफी महत्वपूर्ण है । इनमें वीवर तथा दोई द्वारा अपनायी गयी सांख्यिकीय विधिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तथा कुछ सुधारों के साथ अनेक विद्वानों द्वारा अपनायी जा रही हैं । किन्तु प्रस्तुत अध्ययन में इन विद्वानों द्वारा प्रतिपादित विधियों को नहीं अपनाया गया है, क्योंकि इनकी विधियों वही प्रयोज्य हो सकती है जहाँ सकल बोए गए क्षेत्र के 50% क्षेत्र के अन्तर्गत ही दो या दो से अधिक फसलों का प्रतिनिधित्व हो ।

अत अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट और उचित फसल - संयोजन में विभक्त करने के लिए अलग विधि को अपनाया गया है । यदि किसी विकासखण्ड मे उसके सकल बोये गए भाग के 50 प्रतिशत से अधिक भार पर किसी फसल का अकेला भाग है या अकेला आधिपत्य है तो उसे एक फसली साहचर्य प्रदेश के अन्तर्गत रखा गया है । इसके साथ ही विकासखण्डों के फसल - संयोजन में उतनी ही फसलों को सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा बोए गए क्षेत्रों का योग 75% तक है । उक्त विधि के परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन क्षेत्र में द्विफसली से लेकर 10 फसली तक चार प्रकार के फसल - संयोजन प्रदेश निर्धारित हुए हैं।मानचित्र 4 5 से स्पष्ट है कि एक फसली संयोजन किसी भी विकास खण्ड में नहीं है । विकासखण्ड चतरा में द्विफसली सयोजन है तथा घोरावल एवं राबर्ट्सगज में चार फसली सयोजन है । विकासखण्ड दुद्धी में सात फसली संयोजन तथा म्योरपुर, चोपन एवं बभनी में दस फसली संयोजन है ।

4.6 फसल - गहनता

कृषि उपज को बढ़ाने के लिए फसल - गहनता बढ़ाना अनिवार्य है । बढ़ती आबादी के भरण - पोषण एवं सीमित कृषि - क्षेत्र की समस्या क। समाधान फसल गहनता से ही सम्भव है । फसल - गहनता का अर्थ है - एक ही खेत पर एक वर्ष मे अधिक - से - अधिक बार फसलों को उगाना । फसल - गहनता से भूमि उपयोग की तीव्रता का ज्ञान होता



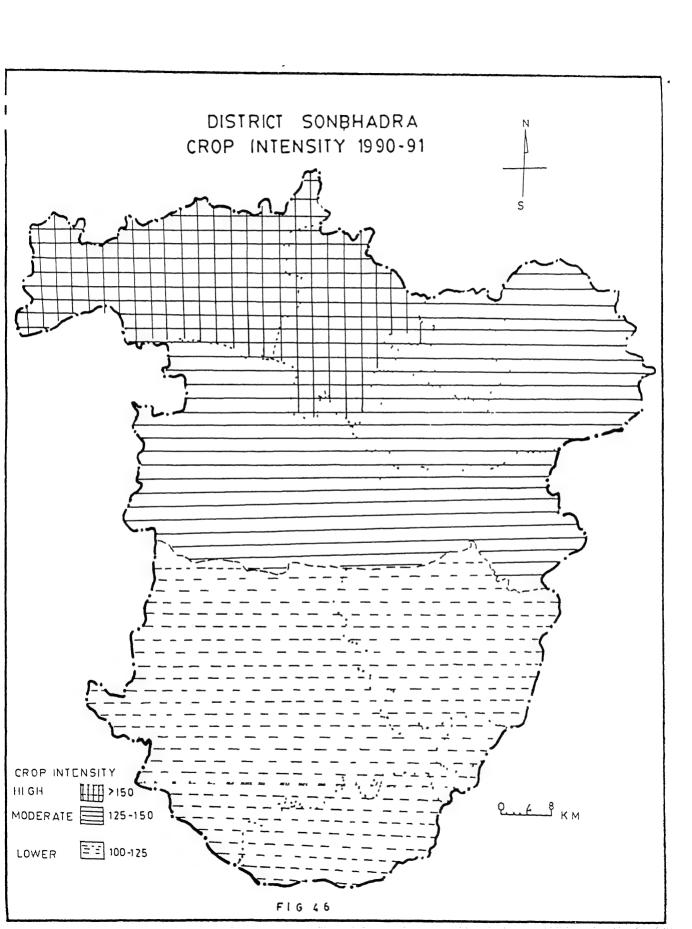
है। किसी भी क्षेत्र में फसल गहनता को हरित क्रान्ति से बढायी जा सकती है। प्रस्तुत अध्ययन मे फसल गहनता सूचकाको की गणना निम्न सूत्र के माध्यम से की गयी है -

> फसल - गहनता सूचकाक = कुल बोया गया क्षेत्र ------ × 100 श्रुद्ध बोया गया क्षेत्र

तालिका 4.7 फसल - गहनता सुचकांक

विकास खण्ड	सकल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र		
घोरावल	62836	39464	159 22	
राबर्ट्सगज	46707	28442	164 22	
चतरा	21961	15330	143 25	
नगवा	17939	12118	148 04	
चोपन	46666	33885	137 72	
म्योरपुर	22069	19499	113 18	
दुद्धी	19134	16104	118 82	
बभनी	17729	15293	115 93	
ग्रामीण योग	255041	180135	141 58	
नगरीय योग	279	219	127 39	
जनपद योग		180354		

स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992 से सगणित ।



अध्ययन क्षेत्र मे औसत फसल-गहनता सूचकाक 141 56 है। किन्तु विकासखण्ड स्तर पर इसमे भिन्नता है। विकासखण्ड राबर्ट्सगज मे फसल गहनता 164 22 तथा घोरावल मे 159 22 है अर्थात 150 से अधिक फसल गहनता वाले केवल दो विकासखण्ड नगवा, चतरा तथा चोपन है। 100 से 125 फसल-गहनता के अन्तर्गत भी तीन विकास खण्ड दुद्धी (118 82), बभनी (115 93) तथा म्योरपुर (113 18) है (मानचित्र 4 6)।

4.7 सिचाई

कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम साधनों द्वारा होती है। सिचाई का प्राकृतिक साधन वर्षा है। वर्षा के अभाव तथा अनिश्चितता के कारण कृत्रिम साधनों द्वारा जल उपलब्ध कराना ही सिचाई कहलाता है। मानसूनी वर्षा वी अनिश्चितता, अनियमितता, असामयिकता तथा विषमता सिचाई की आवश्यकता को अनिवार्य बना देती है।

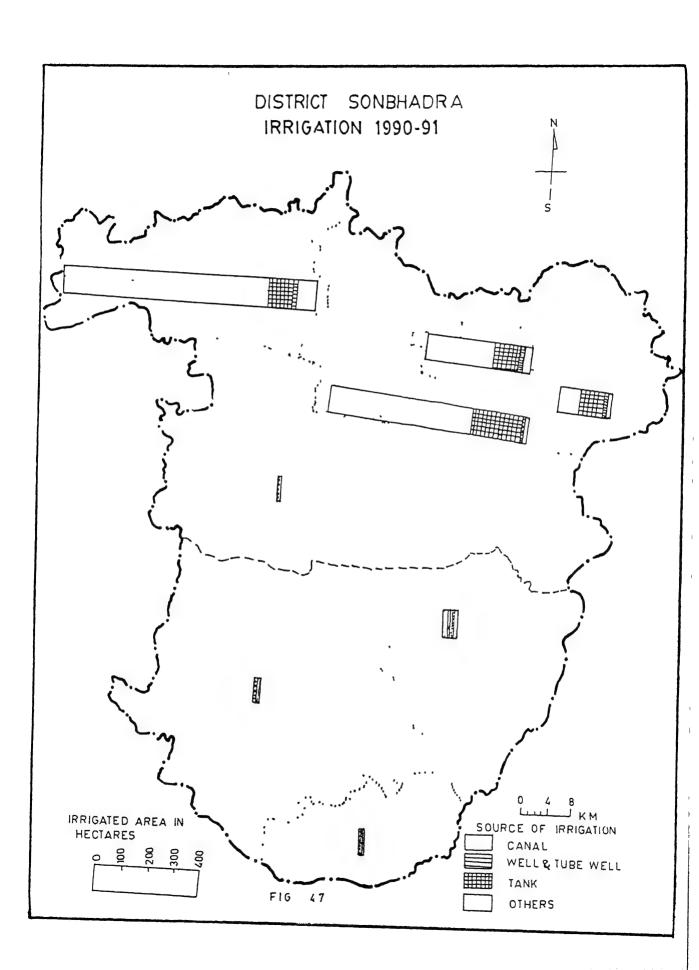
अध्ययन - क्षेत्र में न केवल सिचाई साधनों का वरन सिचाई सोतों का भी अभाव है। शुद्ध बोये गए क्षेत्र का 28 81% भाग ही शुद्ध सिंचित क्षेत्र (तालिका 4-8) है। रिहन्द जलाशय के जल का उपयोग सिचाई के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण जल विद्युत एवं ताप विद्युत गृहों का आधार यहीं जलाशय है। दो प्रमुख बाध कर्मनाशा नदी पर नगवा - सिलहट बाध (जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं) (विकासखण्ड नगवा) तथा घाघर नदी पर धधरौल बाध (विकासखण्ड चतरा) से ही मुख्यत सिचाई होती है। नगवा बाध से सिलहट तथा धंधरौल बाध में भी जल की आपूर्ति की जाती है। नगवा एवं सिलहट बाध का जलगृहण क्षेत्र विस्तृत है तथा ये दोनो बाध सलग्न है। सिलहट तथा धंधरौल बाध का निर्माण 1918 में पूर्ण हुआ जबिक नगवां बाध 1948 में तैयार हुआ। नगवा बाध की ऊँचाई में वृद्धि की जा रहीं है,शीध ही रबी फसल में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि धंधरौल बांध से निकली नहरों द्वारा अधिकाश सिंचित क्षेत्र मीरजापुर तथा वाराणसी जिलों में है।

विकास खण्ड राबर्ट्सगज, चतरा एव नगवा मे उपर्युक्त बाधों के अतिरिक्त अनेक छोटी-छोटी बन्धिया हैं जिनसे 3-4 किलोमीटर नहर निकाल कर या सीधे बाध से खेतों

तालिका 4-8 सिंचाई

क्रमसंख्या	विकसस्वण्ड	॥ गया हेक्टेयर	शुद्ध सिचित क्षेत्रफल प्रतिशत भे	नहर	नलकूप	कृप	तालाब/झील	अन्य
- !	घोरावल	39464	48 39	82	1 6	0 8	9 -	6 4
2	राबर्ट्सगज	28442	54 57	70 9	-	0 6	27 4	0 9
ω	चतरा	15330	53 65	66 5	1 7	1.2	28 8	- 8
4	नगवां	12118	15 60	44 9	ı	2 7	45 5	6.9
CT	चोपन	33885	0 82	23 3	5 4	4 3	43 3	23 7
6	म्योरपुर	19499	0 94	53 6	1	13 1	9 8	23 5
7	दह्डी	16104	7 63	66 1	ı	21 7	•	12 2
- ∞	बभनी	15293	0 44	1 1 1 1 1				100.0
:	ग्रामीण योग	180135	25 81	72 7	- 3	1.6	20 1	4.2
	नगरीय योग	219	23 29			7 8	! ! !	99 2
	जनपद योग	180354	25.81	72.7	1.3	-5	20.1	4.3

म्रोत. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 47-48



तक जल पहुँचाया जाता है। चोपन के पास सोनपम्प नहर से, जो बारह पम्पों की क्षमता वाली है, विकासखण्ड चोपन में खरीफ एवं रबी दोनों फसलों की सिचाई की जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर तालाब एवं पोखरों से सीमित स्तर पर खरीफ फसलों की सिचाई होती है। अध्ययन क्षेत्र के पठारी स्वरूप तथा जल स्तर अत्यधिक निम्न होने के कारण नलकूप एवं कृप से बहुत कम क्षेत्रों पर सिचाई की जाती है। विकासखण्ड राबर्ट्सगज, चतरा तथा घोरावल के बेलन घाटी तथा चोपन के सोनघाटी क्षेत्र में सीमित स्तर पर नलकूप द्वारा सिचाई की सम्भावना है।

अध्ययन क्षेत्र के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के चौथाई भाग पर ही सिचाई होती है। इन सिंचित क्षेत्रों में से 72 72% भाग पर नहरों से, 13% भाग पर नलकूपों से, 15 भाग पर कूपों से, 20 1% भाग पर तालाबों व झीलों से तथा 4 3% भाग पर अन्य साधनों से सिचाई होती है। शुद्ध बोये गए क्षेत्र के विकास खण्ड राबर्ट्सगण में 54 57% भाग पर, चतरा में 53 65% भाग पर, घोरावल में 48 39% भाग पर, नगवा में 15 60% भाग पर दुद्धी में 7 63% भाग पर सिचाई होती है। विकास खण्ड चोपन, म्योरपुर तथा बभनी का सिंचित क्षेत्र एक प्रतिशत से भी कम है (तालिका 48)। विकास खण्ड बभनी में नहरों, नलकूपों, कूपों तथा तालाब आदि से सिचाई नहीं होती है। विकास खण्ड नगवा म्योरपुर तथा दुद्धी में भी एक भी नलकूप नहीं है (तालिका 48)। उल्लेखनीय है कि सिचाई की अधिकाश सुविधाएं खरीफ फसलों को ही उपलब्ध है। बाधों का जल स्रोत वर्षा है इसलिए रबी फसलों के लिए सिचाई उपलब्ध नहीं हो पाती है। सोन पम्प नहर से सीमित स्तर पर ही रबी फसलों की सिचाई होती है। भूमिगत जल स्तर, ग्रीष्म ऋतु में अत्यिधिक नीचे चला जाता है जिस कारण इससे रबी फसलों के सिचाई की सम्भावना समाप्त हो जाती है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि के पिछडेपन का प्रमुख कारण सिंचाई सिवधाओं का अभाव है।

4.8 जोतों का आकार

जोत का आशय उस समग्र भूमि से है जिसके समग्र या आंशिक भाग पर कृषि उत्पादन एक तकनीकी इकाई के तहत केवल एक व्यक्ति या कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ किया जाता है। तकनीकी इकाई से तात्पर्य उत्पादन के अन्य साधन तथा उनके प्रबन्धन

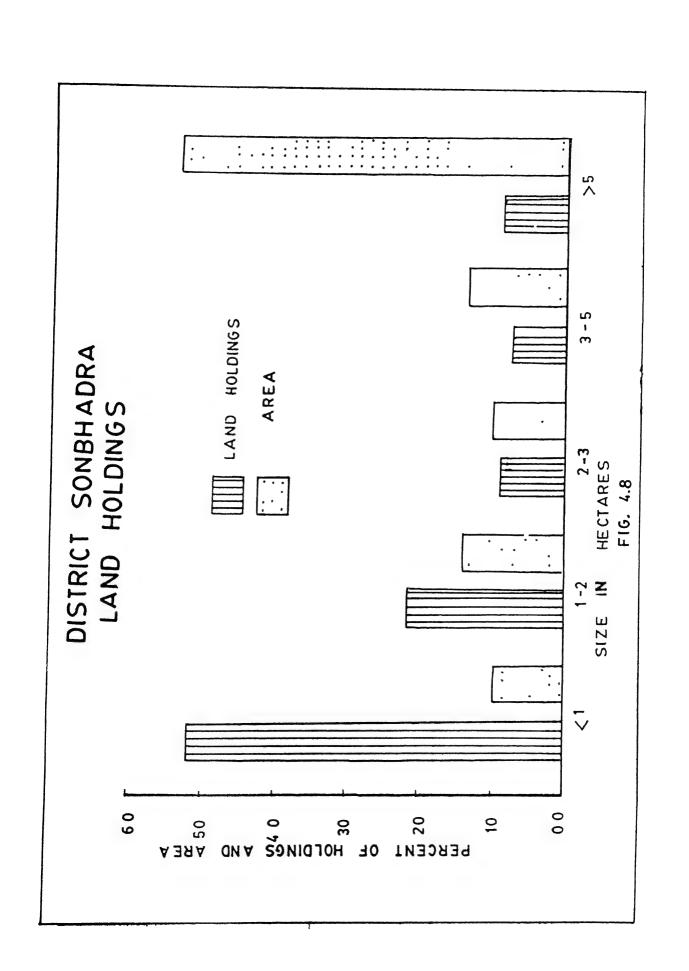
से है। 21 जोतो के आकार से मानव-भूमि सम्बन्ध का ज्ञान होता है।

तालिका 4.9 जनपद सोनभद्र में जोतों की संख्या एवं आकार 1991-92

आ	कार (हेक्टेयर में)	संख्या	प्रतिश्रत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
ı		2	3	4	5
1	सीमान्त(। से कम)	59129	52 19	24802	9 71
2	लघु (। से 2)	24955	22 09	35930	14 07
3.	उपमध्यम्(2 से 3)	9889	8 73	24265	9 50
4	मध्यम् (3 से 5)	9030	7 97	34808	13 63
5	वृहद् (5 से अधिक)	10293	9 08	135515	53 08
 योग 	т т	113296	100.00	255320	120.00

स्रोत: एकीकृत जिला योजना, जनपद सोनभद्र, 1992-93, पृष्ठ 8 एव उससे सगठित ।

तालिका 4 9 से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में कुल जोतों की संख्या 113 296 है जिसके अन्तर्गत 255320 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र में । हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की सीमान्त जोतों की संख्या सर्वीधिक (52 19%) है किन्तु इसके अन्तर्गत 9 71% कृषि क्षेत्र ही सिम्मिलित है। । से 2 हेक्टेयर वाली लघु जोतों के अन्तर्गत 22.09% जोते और 14.07% कृषि क्षेत्र सिम्मिलित है। 2 से 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल की उपमध्यम जोतें तथा 3 से 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की मध्यम जोतें के अन्तर्गत कृमश कुल जोतों का 8 73 व 7 97 प्रतिशत तथा कृषि क्षेत्र का 9 50 व 13 63 प्रतिशत भाग सिम्मिलित है। 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृहद् जोतों की संख्या 9 08 प्रतिशत है किन्तु

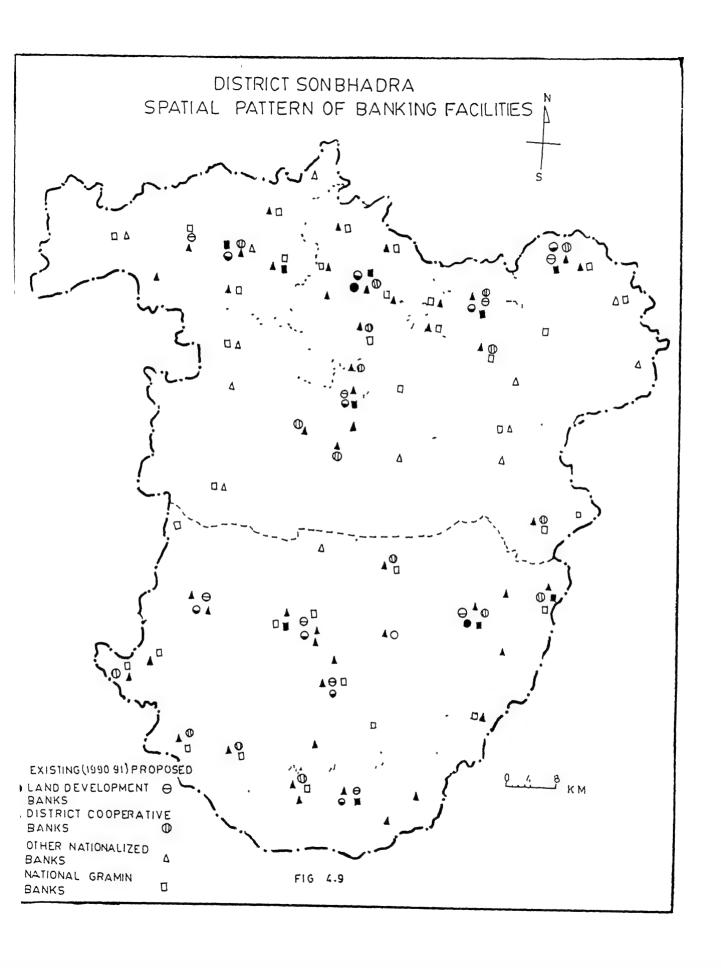


किन्तु इसके अधीन 53 08% कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। स्पष्टत अध्ययन क्षेत्र मे सीमान्त एव लघु जोतो की अधिकता है किन्तु अधिकाश कृषि क्षेत्र वृहद् जोतों के अन्तर्गत है।

4 9 कृषि का यन्त्रीकरण

प्राय अल्पविकसित देशों मे यह समझा जाता है कि आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को एक ही संदर्भ मे विचार करना चाहिए। वस्तुत: कृषि का पिछड़ापन आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की धीमी गति का ही परिणाम है। 22 वास्तव मे अर्थव्यवस्था के अन्य प्रक्षेत्रों के विकास के लिए कृषि-विकास एक आधार है। 23 कृषि विकास के सम्बन्ध मे तैयार एक नीति के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र मे अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उत्पादन, सिचाई सुविधाओं का विकास, विशेषकर भूमिगत जल-स्रोतें का उपयोग, उर्वरकों के पर्याप्त एव सत्तुलित उपयोग, आवश्यकता पर आधारित पौध सरक्षण उपायों को अपनाया जाना और कृषि के काम आने वाली वस्तुओं, जिसमे सस्थागत एव अन्य वित्तीय सगठनों से प्राप्त होने वाला ऋण भी सम्मिलित है, कि सुव्यवस्थित एवं नियमित आपूर्ति आते है। 24 भारतीय कृषि को यन्त्रीकृत करके रूपान्तरित करने का श्रेय हरित क्रान्ति को है। अमरीकी विद्वान विलियम गैड ने सर्वप्रथम हरित क्रान्ति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था। यह जैव प्राविधिकी के विकास का आरम्भिक चरण था। 25

अध्ययन क्षेत्र मे एच0वाई0पी0 (हाई यील्डीग वेरायटीज) किस्म के बीजो के प्रयोग के आकड़े उपलब्ध नहीं है। किन्तु इन बीजो का प्रयोग सीमित स्तर पर सीमित फसलों में ही हो रहा है। क्योंकि इसके लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं का अभाव है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे 1100 ट्रेक्टर कृषि कार्य हेतु है, इनमें से मात्र 37 ट्रैक्टर तहसील दुद्धी में है। लकड़ी के देशी हलों का प्रयोग व्यापक पेमाने पर होता है। सम्प्रति 103588 लकड़ी के देशी हल, 2821 लोहे के हल तथा 4042 उन्नित हैरों तथा कल्टीवेटर का प्रयोग हो रहा है। कुल थ्रेसिंग मशीन की संख्या 1373, स्प्रेयर की संख्या 127 तथा उन्नत बोआई यन्त्र की सख्या 6563 है। 26 तहसील दुद्धी में अभी-भी उन्नत बोवाई यन्त्र, स्प्रेयर तथा हैरों व कल्टीवेटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। उपर्युक्त तथ्यों से कृषि में यन्त्रीकरण के अभाव की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। कृषि को प्रोन्नित करने में विभिन्न प्रकार के बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किन्तु अध्ययन क्षेत्र में बैंकों की नितान्त कमी है(मानचित्र 4.9 व तालिका 3.1)।



अध्ययन क्षेत्र मे 1990-91 मे कुल 5898 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया। इसमे से विकासखण्ड राबर्ट्सगज, घोरावल, चतरा, नगवा, दुद्धी, बभनी, चोपन तथा म्योरपुर मे क्रमश 2580, 2182, 501, 185, 146, 139, 97 तथा 68 टन कुल उर्वरको का वितरण हुआ। 27 उर्वरको के प्रयोग की दृष्टि से विकास खण्ड राबर्ट्सगज व घोरावल की स्थित को ही सतोष जनक कहा जा सकता है। कृषि क्षेत्र के चौथाई भाग पर ही सिचाई होती है इसलिए भी अध्ययन क्षेत्र मे हरित क्रान्ति का सपना साकार नही हुआ है।

4.10 पशुपालन

पशुपालन का विकास विविधीकृत कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिनन अग होता है। पशुधन की सख्या का प्रभाव न केवल कृषि के कुल उत्पादन पर अपितु खेत पर भी पडता है। पशुधन की विभिन्न नस्लों में चौपाए ही अधिक प्रमुख है, केवल इसलिए नहीं कि इनकी संख्या अधिक है, बल्कि इसलिए भी कि ये पशु कृषि कार्यों और किसान की सम्पन्नता में अधिक सहयोग देते हैं। कृषि के लगभग सभी कार्यों के लिए उपलब्ध शिक्त पशु ही है। खेत जोतना, खाद लादना, पानी प्राप्त करना, फसल की दांय (मडाई) देना और यातायात प्रमुख कृषि कार्य है, जो पशु प्रमुख रूप से करते है। मौंस, खाल, ऊन, बाल ओर मुर्गीपालन को छोडकर पशुधन के अन्य सभी कार्मों में चौपायों का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं का गोबर कृषि क्षेत्र की खाद की महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है। ईधन के अन्य साधन उपलब्ध न होने के फलस्वरूप देश में उपलब्ध गोबर का दो - तिहाई भाग ईंधन के रूप में जला दिया जाता है। पशुओं से न केवल कृषि उत्पादन में सहायता मिलती है, बल्कि दूध और दूध से बने पदार्थों की सहायता से शारीरिक जरूरत के अनुरूप गुणकारी पदार्थ भी मिल जाते है।

तालिका 4 10 से स्पष्ट है कि कुत्ते को छोडकर कुल पशुओ की सख्या 740402 है जिसमें से 517318 तहसील राबर्ट्सगज में तथा 223084 दुद्धी में है। पशुओं में सर्वाधिक सख्या गो जातीय पशुओं की है जिसकी कुल सख्या 481363 है, इसमें से तहसील राबर्ट्सगंज में 349825 तथा दुद्धी में 131538 है। महिष जातीय पशुओं की सख्या तहसील दुद्धी में राबर्ट्सगज की अपेक्षा अधिक है। भेडों की अपेक्षा (सख्या 20679) बकरा-बकरियों की संख्या (140150), 6 78 गुना अधिक है। घोडों-टट्टुओं तथा सूअरों की संख्या लगभग

तालिका 4.10 जनपद सोनभद्र में पशुओं की संख्या 1988

पशु		राबर्टसगंज तहसील	दुद्धी तहसील	योग
1		2	3	4
•				
1	कुल गो जातीय पशु	349825	131538	481363
2	कुल महिष जातिय पशु	70105	21166	91271
3	कुल भेंड	18970	1709	20679
4	कुल बकरा एवं बकरिया	74419	65731	140150
5	कुल घोडे एव ट्टटू	2206	1097	3303
6	कुल सुअर	1560	1806	3366
7	कुल पशु कुत्ते			
	को छोडकर	517318	223084	740402
8	कुल कुक्कुट	111516	96145	207661

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 73-78 बराबर है। अध्ययन क्षेत्र मे कुक्कुट पालन भी किया जाता है। कुल कुक्कुटो की सख्या 20766। है, इसमे से 11516 कुक्कुट तहसील राबर्ट्सगज मे तथा 69145 कुक्कुट दुद्धी मे पाये जाते है। अध्ययन क्षेत्र मे मत्स्य पालन नहीं होता है। निदयों, बाधों, तथा बन्धियों मे कुछ मछिलया पकडी जाती है। मत्स्य पालन का अभी व्यावसायीकरण नहीं हुआ है। अध्ययन क्षेत्र मे चराई की सुविधा उपलब्ध है इसिलए पशुपालन की पर्याप्त सभावना है। किन्तु ये अपरदन के सिक्निय कारक है इसिलए चराई की बहुत अधिक छूट नहीं दी जा सकती है।

4.11 कृषि - विकास नियोजन

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की कृषि अत्यन्त पिछडी हुई है। कृषि - विकास मे गित प्राप्त किए बिना समग्र विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृषि के लिए आवश्यक है कि इसके विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न अवयवों को नियोजित ढग से विकसित किया जाय । इस उद्देश्य की प्राप्ति सुसगठित प्रयास से ही सभव है जिसमे प्रशासक और योजना निर्माता, शोध करने वाले वैज्ञानिको, प्रसार कार्यकर्ताओं, वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों, जनसचार माध्यमों तथा कृषकों के सहयोग की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के कृषि की सहनशीलता सबसे उल्लेखनीय तथ्य है । लगातार अववर्षण के बावजूद कृषक दैव-अधीन कृषि कार्यों में लगे हुए है ।

अध्ययन क्षेत्र की समृद्धि बढाने के लिए समन्वित फसल, पशुधन, मत्स्य-पालन तथा बागवानी जैसे उद्यमों के जिरए कृषि में विभिन्नता लाकर कृषि आमदनी को अधिक-से-अधिक बढाना होगा। कृषि के क्षेत्र में सामान्य वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी पर सीधे आकृमण करने की नीति अपनाकर एक सचेष्ट परिवर्तन लाना होगा क्योंकि कृषि विकास के बिना अध्ययन क्षेत्र की गरीबी को दूर करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमें कृषि विकास को केवल और अधिक अनाज उपजाने के साधन' के रूप में ही नहीं लेना है बल्कि गाँव की आमदनी बढाने और रोजगार की और अधिक अक्सर उपलब्ध कराने के माध्यम के रूप में भी लेना है। कृषि विकास नियोजन के लिये भूमि - सुधार, कृषि यंत्रीकरण, पशुधन एव डेयरी विकास, दलहन एव तिलहन विकास, औद्योगिक फसलों का विकास, मिश्रित खेती, शुष्कभूमि कृषि, खरपतवार नियन्त्रण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा कृषि रसायनो एव उर्वरकों के प्रयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने, बचत को बढावा देने तथा महाजनी ऋण जाल से मुक्ति प्रदान करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं मे वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(अ) भूमि सुधार

भूमि ससाधन हमारी पिवत्र ससाधन है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसके केवल अक्षुण्ण रूप में ही नहीं बिल्क सुधरे हुए रूप में आगामी पीढियों के लिए साँप । इसके लिए कृषि विकास की प्रक्रिया में भूमि ससाधन की वहन क्षमता तथा इसके सामर्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के पहलुओं की ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। भूमि तथा जल चक्रों के बीच तालमेल का सम्बन्ध बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने की, उपलब्ध भूमि की उत्पादकता बढाने, उत्पादकता फिर से प्राप्त करने, भूमि का फिर से सुधार करने और कम उपजाऊ भूमि का विकास करने वग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है। भूमि ससाधन के अधिकतम उपयोग तथा सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के सरक्षण आवश्यकताओं को लेकर कृषि तथा इसके अन्य आनुषींगक माध्यमों से अध्ययन क्षेत्र के लोगों के लिए समृद्धि लायी जा सकती है।

अध्ययन क्षेत्र के पहाडी तथा पठारी घरातलीय स्वरूप होने के कारण कृषि-भूमि को बहुत अधिक नहीं बढायी जा सकती है। अत कृषि उत्पादकता को बढाना तथा कृषि योग्य भूमि को कृषिभूमि में बदलना, यही दो विकल्प है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 12.18% (82908 हेक्टेयर) भाग को (बंजर एव परती भूमि) कृषि भूमि मे, आठवी पचवर्षीय योजना तक परिवर्तित करने की आवश्यकता है। 49443 हेक्टेयर परती भूमि को भूमिहीन कृषक मजदूरों मे बाट देने से एक दो वर्ष में ही सम्पूर्ण भूमि उपजाऊ हो जाएगी। 33262 हेक्टेयर ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि मे बदलने के लिए आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि मे परिवर्तित कर देने पर कृषि योग्य भूमि मे 4 88% और वृद्धि हो जाएगी। शुष्कता, बहुत कम तथा अनिश्चित वर्षा, अत्यन्त कम उर्वरा मृदा, भूमि तथा जल पर भारी जैव दबाव तथा अपर्याप्त भूमिगत जल की समस्या को धीरे - धीरे दूर करने का प्रयास प्रारम्भ कर देना चाहिए।

कृषि-उत्पादन के लिए भूमि सुधारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चकबदी, वास्तविक काश्तकारों को भूमि पर कब्जा, भूमि की सीमा निर्धारित करना और सीमा से अधिक भूमि को कमजोर वर्गों में वितरित करना अत्यन्त आवश्यक है। दूसरी तरफ ऐसे नये कानून बनाने चाहिए जिससे भूमि के और टुकडे न हों और कृषि - भूमि को गैर - कृषि प्रयोजनों मे न लगाया जाए। इन भूमि - सुधारों के प्रति किसानों के दृष्टिकोंण की समीक्षा होनी चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनकी सफलता और असफलता के कारण क्या है और असफलताओं के निवारण के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। यह बात ध्यान मे रखी जानी चाहिए अध्ययन क्षेत्र मे भूमि की स्थिति वर्तमान गरीबी और कृषि की प्रगति दोनो दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण है। अत भूमि सुधारो को उच्च प्राथमिकता देने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।

(ब) सिंचाई

अध्ययन क्षेत्र के पहाडी भागों मे अनेक छोटी-छोटी बन्धियों का निर्माण करके सिचाई सुविधाओं मे वृद्धि की पर्याप्त सभावनाएं है। इन सभावनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि अल्प खर्च मे सम्पूर्ण कृषि भूमि मे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। भूमिगत जल तथा नलकूपों से सिचाई की सीमित सम्भावना है, इसलिए तालाबो, बंधियो एव बाधों पर सिचाई को निर्भर करना चाहिए। इनके निर्माण से भूमिगत जल-स्तर भी ऊपर उठेगा। अध्ययन क्षेत्र मे बाधों का निर्माण अत्यन्त आसान है। दो पहाडियों के बीच मे एक और ऊँची दीवाल खड़ी कर देने से बाध का निर्माण हो जाता है। सिलहट तथा नगवा बाध (नगवा विकास खण्ड) उसी तरह बनाए गए है। नहरों के निर्माण के लिए व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन अनेक बाँधयों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

सोन, रिहन्द, कनहर, पांडव तथा कर्मनाशा आदि निदयों से पम्प द्वारा जल उठाकर नहरों के माध्यम से वर्ष भर सिंचाई की जा सकती है। चोपन स्थित सोन पम्प नहर की तरह अन्य स्थानों पर भी पम्प नहर बनाने की आवश्यकता है। इस माध्यम से उंची - नीची भूमि पर भी सिचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। दुद्धी स्थित अमवार कनहर परियोजना, जिसका निर्माणाधीन कार्य 15 वर्ष से ठप पड़ा हुआ है, शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता है। कोन क्षेत्र के मध्य बहने वाली 'पाडव नदी लिफ्ट योजना' तथा कर्मनाशा नदी पर जसौली परियोजना' का निर्माण कार्य शीघ्र प्ररम्भ करने की आवश्यकता है।

गोविन्दपुर स्थित बनवासी सेवा आश्रम द्वारा बधी बनाने की एक नयी तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसे व्यापक स्तर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के दिशाचल में ऊची - नीची एवं असिंचित क्षेत्र है। जहाँ सरकार द्वारा सिचाई उपलब्ध कराये जाने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद सम्पूर्ण क्षेत्र में सिचाई की दस प्रतिशत सुविधा भी उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए छोटे - छोटे नालों पर छोटे - छोटे बिधयों के निर्माण के प्रथम चरण में 17 योजनाए, आश्रम द्वारा ली गयी हैं। इसमें से 5 योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसी बिधयों को 'लूजरॉक फिल डैम' के नाम से जाना जाता है। जो किसी भी नाले पर सामान्य किस्म के पत्थर को एक लोहे की जाली में बधी के रूप में बाध दिया जाता है और नदी या नाले का पानी रूक जाता है। डूब क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता में कायम रहेगा। इन बिधयों के डूब क्षेत्र के दोनों किनारों पर किनों द्वारा पानी खेत में डालकर पर्याप्त खेती की जा रही है।

अध्ययन क्षेत्र जल ससाधनों की दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी सामाजिक - आर्थिक किटनाईयों के कारण सिचाई के क्षेत्र में पिछड़ा है। इस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को, उपयुक्त जल-संसाधन प्रबध-व्यवस्था से बढ़ायी जा सकती है। इसके विकास के लिए जल-निकासी, सिचाई साधनों का इस्तेमाल तथा विद्युत आपूर्ति का सहारा लेना आवश्यक है। बाधों से खेतों तक पानी ले जाने और वितरण के लिए सिचाई इंजीनियरों, कृषि विशेषज्ञों तथा कृषकों से सलाह लेनी चाहिए।

(स) कृषि का वाणिज्यीकरण

फसल प्रतिरूप के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे चावल, गेहू, तथा मक्का की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। शेष फसलो का उत्पादन घरेलू आपूर्ति तक ही सीमित है। गन्ना, तिलहन एव दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। गन्ना की खेती सम्पूर्ण बेलन घाटी मे सिचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराकर की जा सकती है। तिलहन फसलों के लिए आरम्भ की गयी 'टेक्नालाजी मिशन' को प्रसारित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार दलहन फसलों के उत्पादन पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। इससे किसानों की आय बढ़ेगी तथा कृय शक्ति का विकास होगा। अध्यन क्षेत्र की बन्धियों में मत्स्य

पालन किया जा सकता है तथा औद्योगिक केन्द्रों के निकट व्यावसायिक स्तर पर कुक्कुट पालन की पर्याप्त सम्भावना है। यदि अच्छी नश्ल के पशुओं का पालन करके डेयरी विकास किया जाय तो ग्रामीणो के गरीबी का दुश्चक्र शीघ्र समाप्त हो सकता है। चराई की सुविधा के कारण पशुपालन बेहतर ढग से किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि के विविध क्षेत्रों को वाणिज्यीकृत करके विकासकी प्रक्रिया को तेज की जा सकती है।

(द) असिंचित भूमि में कृषि

अध्ययन क्षेत्र का 75% कृषि भूमि असिचित है। सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र मे सिचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन कार्य है। अत जब तक असिंचित कृषि क्षेत्रों का सही उपयोग नहीं होता तब तक कृषि विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। असिंचित क्षेत्रों के रबी मौसम मे नमी की कमी मुख्य समस्या है जिससे रबी फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। अत उक्त ज्वलन्त समस्या के समाधान के लिए खरीफ फसल में जल का उचित सरक्षण तथा उसका रबी के लिए दक्षतापूर्ण उपयोग नितान्त आवश्यक है। जल सरक्षण के लिए निम्न विधिया अपनायी जानी चाहिए -

- । खेतों को समतल करके मेडबन्दी करना चाहिए ।
- 2 ढाल के विपरीत समोच्च रेखा पर कृषि कार्य करना चाहिए ।
- 3 कठोर पर्त को तोडने के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे जल का नीचे प्रवेश हो तथा अपवाह कम हो ।
- 4 जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए जो न केवल पोषक तत्वों के लिए आवश्यक है वरन् जल धारण क्षमता बढाने मे विशेष सहायक होते है।
- 5 फसलों को ढाल के विपरीत मेड़ों पर बोना चाहिए । अतिवृष्टि मे मेडों पर फसलें तथा कूडो मे पानी सुरक्षित रहता है ।
- 6 अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने 'जल शक्ति' नामक रसायन का विकास किया है जो अपने भार से 100 गुनी पानी सोख कर लम्बी अविध तक रोकने की क्षमता रखता है। अत इसका प्रयोग शीष्ट्र प्रारम्भ करना चाहिए ।
- 7 वाष्पोत्सर्जन विरोधी 'पारस' रसायन का प्रयोग करके पंक्तियों से वाष्पोत्सर्जन को कम करना चाहिए । पित्तयों पर 'कैओलीन' तथा पौधों पर 'साइकोसिल' का छिडकान करके

करके ऊपरी बढ़वार को कम करके वाष्पोत्सर्जन को कम करना चाहिए ।

असिचित कृषि क्षेत्रों में गहरी जड़ों वाली फसल या किस्मे विशेष उपयोगी होती है जिससे वे सूखे के समय नीचे की तहों से नमी खीच सके। सूखे की दशा के अनुकूल विभिन्न फसलों की उपयुक्त कुछ प्रमुख प्रजातियों का चयन निम्न प्रकार से करना चाहिए

धान- कावेरी, झोना - 349, साकेत - 4, गोविन्द, नरेन्द्र - ।

गेहूं के - 65, सी - 306, मुक्ता, के - 72, के - 8027

जो- आजाद, रत्ना, लखन, मजूला।

ज्वार - वर्षा, मऊ टा ।, मऊ टा २, सी एस एच - 5

बाजरा- डब्ल्यू सी सी 75, एम पी. - 15, एम पी - 19, बी के 560

मक्का - आजाद उत्तम, कचन, श्वेता, तरूण, नवीन।

अरहर- बहार, टा 7, टा 17, टा 21, यूपी ए एस 120

चना - अवरोधी के 468, के 250, टा.।

अलसी - श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी 27।

असिंचित कृषि क्षेत्रों में सहफसली खेती एक ऐसी पद्धति है जिससे उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। परम्परागत सहफसली (मिश्रित खेती) का मुख्य उद्देश्य उत्पादन की अनिश्चितता को खत्म करना है। इससे उत्पादन के साथ मृदा की उर्वराशिक्त भी बढ़ती है।

(य) जायद कृषि

अध्ययन क्षेत्र में जायद फसलों को विकसित करना चाहिए । जायद कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु उपलब्ध ससाधनों का समुचित एवं सामयिक उपयोग परम् आवश्यक है। आश्वस्त सिंचन सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों मे जायद के खेत मे मूंग, उर्द, सूरजमुखी, मक्का, हरा चारा तथा साग सब्जी की फसलें ली जा सकती हैं, इससे प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक़ उपज मिलने के साथ-साथ सिचाई साधनों का भरपूर उपयोग होता है तथा रोजगार के अवसर

भी बढते है। आवश्वस्त सिचाई सुविधा निजी नलकूप एव राजकीय नलकूप पर ही सभव है, नहरी क्षेत्रों को जायद फसल हेतु चुनना विशेष उपयुक्त नहीं होता है।

अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश कृषक उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा नवीन कृषि यन्त्रों का प्रयोग धनाभाव के कारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि - कृषकों को रियायती दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराए । कृषि - विकास नियोजन के लिए निम्न सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना भी आवश्यक है ।

- । कृषकों मे शिक्षा व कृषि शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए जिससे वे सामाजिक कुरीतियों से मुक्त हों, अन्धविश्वास व भाग्यवाद को त्यार्गे तथा खेती के आधिनक तरीके अपनाएं जिससे आर्थिक प्रगति का वातावरण बन सके ।
- 2 कृषि मे उत्पादन बढाने के लिए नवीन यन्त्रो व तकनीको को ग्रामीणों तक पहुँचाना एव उसके सचालन के लिए समयानुसार सलाहकारी सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहिए ।
- 3 साख सुविधाओं का यथा ग्रामीण बैंकों तथा अन्य बैंको की शाखाओं द्वारा जाल बिछाया जाना चाहिए जिससे कृषकों की फसलें नष्ट न हों तथा गरीब एव मध्यम वर्गीय कृषकों के लिए पर्याप्त साख की व्यवस्था उपलब्ध हो सके ।
- 4. प्राकृतिक तत्वों यथा सूखा, ओलावृष्टि एवं अन्य कारणों से फसल नष्ट हो जाने पर उसकी क्षति पूर्ति के लिए फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया जाना चाहिए ।
- 5 सरकार को कृषि विकास के लिए जिला स्तर पर जिला कृषि केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए । औद्योगिक सुविधाओं की तरह कृषि सुविधाओं को भी उपलब्ध कराना चाहिए ।
- 6. कृषि आदाय तत्वों (बीज, खाद, नवीन यन्त्र, कीटनाशक दवाए) को सीमान्त तथा मध्यम वर्गीय कृषकों तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

7 कृषको को अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रेरणा देने हेतु 'गारण्टी न्यूनतम कीमतों' के रूप मे उचित आय का आश्वासन दिया जाय ।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र को वाछित प्रगति के स्तर पर लाने के लिए समुचित वैज्ञानिक तथा तकनीकी सेवाओं, सरकारी नीतियो एव शासन तन्त्र को एक साथ मितव्यियता के साथ समायोजित करने की सख्त जरूरत है। जब सम्पूर्ण जनपद मे कृषि, ग्रामीण – उद्योग तथा ग्रामीणों की त्रिवेणी का समन्वित विकास किया जायेगा तो निर्माण एव विकास क्रिया का ऐसा महास्रोत उत्पन्न होगा जिससे प्रगति, स्वावलम्बन, पूर्ण रोजगार तथा समृद्धि की धाराए स्वत निकल पडेगी। अत कृषि भूमि की उत्पादकता बढाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी की नवीन व्यूह रचना के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। क्योंकि भूमि सीमित है। इसी के द्वारा अध्ययन क्षेत्र की भूख, अभाव, बेरोजगारी तथा पिछडापन जैसी भयकर समस्याओं से लोगों का उद्वार किया जा सकता है।

सन्दर्भ

- हुसैन, माजिद 'मानव एवं आर्थिक भूगोल', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
 और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली,1986, प्रष्ठ 61.
- 2 Buchanan, R.O.. Some Reflections of Agriculture Geography, Geog. 44, 1959, pp.1-13.
- 3 Mc Carty, H.H. and Lindberg, J.B. A Preface to Economic Geography: Englewood Cliff, N.J.: Prentice Hall, 1966.
- 4 Zimmerman, E.W.: World Resources and Industries, New York, Harper and Brothers, 1951.
- 5 Singh, Jasbir: Agricultural Atlas of India, Kurukshetra, Vishal Publication, 1974.
- 6. कुरैशी, एम0एच0 भूगोल के सिद्धान्त, भाग ।।, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ 50

- 7. Mc Master, D.N.: 'A Subsistance crop Geography of Uganda', The World Land use Survey Occasional Papers No.2, Geographical Publication, 1962. p.IX.
- 8. Fox, K. and Tanber, R: Spatial Equilibrium Models of the Livestock Feed Economy, American Economic Review, as, 1955, pp. 801-802.
- 9. Chauhan, D.S.: Studies in Utilization of Agricultural Land, 1966, p.171.
- 10. Vanzetti, C.: Landuse and Natural Vegetation in International Geography, edited by W.Peter Adams and Frederick, M.Helleiener, Toronto University, 1972, pp.1105-1106.
- 11. Wood, H.A.: A Classification of Agricultural Landuse for Development Planning, International Geogr. (22, I.G.U., Canada), Univ. of toronto Press, 1972, p.1106.
- 12. सिंह, ब्रजभूषण कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, 1988, पृष्ठ 165
- 13. Weaver, J.C.: 'Crop Combination Regions in the Middle West'. Geographical Review, 44, 1954, p.175.
- 14. कुमार, पी0तथा शर्मा, एस के. 'कृषि भूगोल,' मध्य प्रदेश हिन्दी गुन्थ अकादमी, भोपाल, 1985, पृष्ठ 408
- 15. Johnson, B.L.C.: 'Crop Combination Regions in East Pakistan', Geography, 43, 1958, pp. 86-103.
- 16. Thomas, D.: 'Agriculture in Wales during the Neopleanic War', Cradiff, 1963, pp. 80-81.

- 17. पूर्वोक्त संदर्भ संख्या ।5.
- 18. Ayyar, N.P.: 'Crop Regions of Madhya Pradesh- A Study in Methodology', Geographical Review of India, 31.1, 1969, pp. 1-19.
- 19. Doi, K.: 'The Industrial Structure of Japanese Prefecture', Proceedings of I.G.U. Regional Conference in Japan, 1957-59, pp. 310-316.
- 20. Nelson, H.J.: 'A Service Classification of American Cities', Economic Geography, 31, 1955, pp. 189-200.
- 21. दत्त, आर० एव सुन्दरम, के०पी०एम० भारतीय अर्थव्यवस्था, एस०चन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ 587
- 22. सिंह इकबाल 'भारत में ग्रामीण विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रिशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 32
- 23. कुरैशी, एम०एच० 'भारत, ससाधन और आर्थिक विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 1990, पृष्ठ 49
- 24. 'भारत', वार्षिक सदर्भ गृन्थ 1986, स्चना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 378-79.
- 25. Ramachandran, R. The Hindu Survey of Indian Agriculture, Madras, 1988.
 - 26. साख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 6827. वही, पृष्ठ 69.

अध्याय 5

औद्योगिक पृष्ठभूमि एवं विकास-नियोजन

सभ्यता के प्रारम्भ से ही उद्योग मानव का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। प्रगति के अनेक सोपानो का निर्माण करते हुए इसने मानव को आदिम गुफाओ की स्थिति से चन्द्रमा तक पहुँचाया। उद्योग मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मानव प्रयासों के जिन-जिन क्षेत्रों की ओर हम द्रष्टिपात करते हैं, हमें औद्योगिक गति विधियो की अमिट छाप देखने को मिलती गत चार दशकों मे हुई औद्योगिक प्रगति भारतीय आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण घटना इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन मे गुणात्मक, परिमाणात्मक व विविधता की दृष्टि से द्भुत गति से विकास हुआ है तथा औद्योगिक आधार में काफी विविधाताए आयी हैं। साधारणत आर्थिक भूगोल में 'उद्योग' शब्द का व्यवहार वस्तु निर्माण के लिए किया जाता है। अर्थ में 'उद्योग' किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य को कहते है। 2 कच्ची सामग्री को सशोधित और परिवर्तित करके परिष्कृत सामग्री तैयार करना निर्माण उद्योग कहलाता है। 3 प्रक्रिया के अन्तर्गत वे सभी कार्य आते हैं जिनके द्वारा मानव कच्चे माल का स्वरूप परिवर्तित करके उसकों अधिक उपयोगी बनाता है। ऐसे परिवर्तन कार्य कारखानों में होते है, जहां अनेक स्थानों से कच्चा माल लाकर एकत्र किया जाता है। 4 मिलर 5 तथा एलेक्जेंडर 6 ने वस्तुओं को अधिक मूल्यवान स्वरूप परिवर्तन को ही विनिर्माण उद्यो**ग** बताया है। एच0आर0 जैरेट⁷ ने उद्योगों को ही विनिर्माण उद्योग कहा है। उनके अनुसार विर्निमाण उद्योग का तात्पर्य उन विभिन्न प्रक्रियाओं से है जिनकी सहायता से व्यापार में बिकने वाली दस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

5.। औद्योगिक स्वरूप

अज के युग में किसी भी समाज की औद्योगीकरण की स्थित का सीधा सम्बन्ध उसकी अर्थव्यवस्था से है। वास्तव में औद्योगीकरण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है। यहीं नहीं, औद्योगीकरण से कृषि के क्षेत्र में भी अभिवृद्धि हुई है। अत यह अत्यन्त आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए और विकास स्तर को बढ़ाने के लिए औद्योगिकीकरण की ओर सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने के साथ-साथ प्राथमिकता भी दी जाये। अधीयोगिकरण के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं किन्तु इसके स्वरूप के बारे में एक मत नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से औद्योगिक स्वरूप तीन अवस्थाओं से गुजरा है। प्रथम अवस्था का सम्बन्ध प्राथमिक वस्तुओं से माल तैयार करना है। द्वितीय अवस्था का सम्बन्ध कच्चे माल के रूप परिवर्तन से है तथा ततीय में उन मशीनों तथा पूँजी यन्त्रों का निर्माण होता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी क्रिकालिक

आवश्यकताओं की सतुष्टि नहीं करती वरन् भावी उत्पादन क्रिया को सुविधाजनक बनाती है।

औद्योगिक विकास के रूसी सरचना मे सीधे प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था मे प्रवेश किया गया किन्तु ब्रिटिश ढाँचे में धीरे - धीरे विकास किया गया। इसी प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार औद्योगीकरण के विभिन्न स्वरूप विकसित किए जा सकते है। पिछड़े क्षेत्रों एवं देशों के औद्योगीकरण के स्वरूप में पूँजी अभाव को सर्वीच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रम की अधिकता को देखते हुए श्रम प्रधान औद्योगिक स्वरूप अधिक उपयुक्त होता है। अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से चयनित उद्योग ही लगाना चाहिए जिससे वास्तविक रूप मे क्षेत्र विकास हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर आयात - प्रतिस्थापक एव निर्यात संवर्धन उद्योग में संतुलन स्थापित करना चाहिए। वास्तव मे किसी भी देश या क्षेत्र का औद्योगिक स्वरूप नियोजकों के नियोजन व प्राथमिकता तथा ससाधनो पर आश्रित है।

अध्ययन क्षेत्र का औद्योगिक स्वरूप पूर्णतया असंतुलित है। जनपद सोनभद्र में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक एव निजी दोनों ही क्षेत्रों में किया गया है। किन्तु लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि एक जनपद के विकास के लिए एक वृहद्ग उद्योग आवश्यक एवं पर्याप्त है। किन्तु जनपद सोनभद्र में अनेक भारी उद्योगों की उपस्थिति भी पिछड़ेपन को खत्म नहीं कर पा रही है। इसका प्रमुख कारण वृहद्ग एवं लघु औद्योगिक स्वरूप में सहसम्बन्ध न होना तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों के औद्योगिक स्वरूप एवं विविधता में कोई संवृद्धि न होना है।

5.2 ऐतिहासिक पर्यवेक्षण

पश्चिमी एशिया के इतिहास में 1000 - 3000 ई0पू0 में बीच की अवधि में पहली औद्योगिक क्रान्ति घटित हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने कृषि का, बुनाई का और पशुओं को पालतू बनाना आदि कलाओं का अविष्कार किया। ⁹ भारत में उद्योगों की परम्परा सिंघु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। यहाँ उस समय सूती वस्त्र, मिट्टी के बरतन तथा कासे की वस्तुएं आदि बनायी जाती थीं। देश धातु विज्ञान में उन्नत था। अठारहवीं शताब्दी तक भारत जलयान निर्माण में भी आगे था। उत्तम प्रकार के वस्त्र, धातु के बर्तन मसाले तथा

अन्य वस्तुएँ बहुत प्रसिद्ध थी । 10 आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के पूर्व, भारतीय निर्मित वस्तुओं का बाजार विश्ववयापी था । 19वीं शताब्दी से पहले औद्योगिक दृष्टि से एक वृहद उत्पादक देश था । भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते थे अपितु औद्योगिक उत्पादो का निर्यात भी किया जाता था । भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुओं में सूती, रेशमी, सिल्क, ऊनी कपड़ा, चीनी, नमक, तलवारे, तोपे आदि सिम्मिलित थे । ब्रिटेन द्वारा भारत को राजनीतिक उपनिवेश बनाने एवं औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् भारतीय हस्तिशिल्प उद्योगों का पतन प्रारम्भ हो गया । भारत में मशीनों से निर्मित वस्तुओं की भरमार हो गयी। भारत में हस्तिशिल्प उद्योगों के पतन से जो स्थान रिक्त हुआ, उसकी पूर्ति भारत में आधुनिक ढग से उद्योग स्थापित करके नहीं की गयी क्योंिक ब्रिटिश सरकार की नीति मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं का भारत में आयात तथा भारतीय कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने की थी।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही राष्ट्रवादियों ने औद्योगीकरण के महत्व एव उसके स्थापना की वकालत की । प्रो0 बिपिन चन्द्र 12 के अनुसार शुरूवाती राष्ट्रवादियों में इस मुद्दे पर पूरी तरह आमराय थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीकी और पूँजीवादी उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना उनकी सभी प्रमुख आर्थिक नीतियों का पहला लक्ष्य है । औद्योगीकरण को उन्होने बहुत महत्वपूर्ण माना । प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को कुछ सीमा तक विकसित होने का अवसर मिला । किन्तु वास्तविक औद्योगिक विकास स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 और 30 अप्रैल 1956 की औद्योगिक नीति की प्रस्ताव से माना जाता है ।

सन् 1948 के नीति प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया गया कि बढ़ते हुए उत्पादन में निरन्तर वृद्धि और समान वितरण के लिए औद्योगीकरण का बहुत महत्व है । साथ ही, राज्यों के कार्यक्रमों में उद्योगों के विकास के लिए उनके सिक्रिय योगदान पर बल दिया गया। अध्ययन क्षेत्र में 1954 में चुर्क सीमेण्ट फैक्ट्री की स्थापना करके, औद्योगिक विकास की नीव रखी गयी । 1956 की औद्योगिक नीति में औद्योगीकरण की गति तेज करने, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने तथा निजी क्षेत्र को भी विकास और विस्तार का संमुचित अक्सर प्रदान

करने पर बल दिया गया । ¹³ 1956 की औद्योगिक नीति में समय की माँग के साथ 1973, 1977 तथा 1980 में आवश्यक संशोधन किया गया । 1973 की औद्योगिक नीति में उन बड़े उद्योगों का वर्णन किया गया जिनमें बड़े औद्योगिक घरानों और विदेशी कम्पनियों के विनियोग को अनुमित दी गयी थी । औद्योगिक नीति 1977 में विकेन्द्रीकरण तथा गृह उद्योगों पर विशेष बल दिया गया जबिक 1980 की औद्योगिक नीति ने घरेलू बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने, तकनीकी विकास तथा आधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया । पुन औद्योगिक विकास के लिए 1985 और 1986 में औद्योगिक नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिससे उद्योगों और उद्यमियों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता और विदेशी पूँजी निवेश एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा सके । विश्व बाजार में निरन्तर हो रहे परिवर्तनों और आर्थिक स्थिति ने इन नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन को अनिवार्य बना दिया था । फलत नवीन औद्योगिक नीति 1991 का उदय हुआ जिसके द्वारा वर्तमान औद्योगिक नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए गए हैं । इस नीति में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा प्रदूषणमुक्त औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया है ।

अध्ययन क्षेत्र में स्वतन्त्रता के पूर्व से विभिन्न परियोजनाएँ शुरू कर दी गयी थी, जिसका विकास स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ द्वतगित से हुआ एवं 1954 में रेलवे लाइन चोपन तक पहुँच गई । राज्य सरकार ने चुर्क सीमेण्ट फेक्ट्री की स्थापना 1965 में की गयी तथा 1972 से उत्पादन प्रारम्भ हो गया । निजी क्षेत्र का अल्यूमिनियम कारखाना 'हिंडालको' की स्थापना 1958 में रेनूकूट में की गयी तथा उत्पादन 1962 में प्रारम्भ हुआ । रिहन्द जलविद्युत गृह से विद्युत उत्पादन भी 1962 में प्रारम्भ हुआ । 'हिंडालको' में विद्युत आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र में 1964 में रेणूसागर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की गयी, उत्पादन 1967 से प्रारम्भ हुआ । ओबरा ताप विद्युत गृह से भी 1967 में उत्पादन प्रारम्भ हुआ । सिंगरौली सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एन.टी पी.सी.) की पहली परियोजना थी जिसे दिसम्बर 1976 में सरकारी अनुमोदन मिला, इस थर्मल पॉवर से उत्पादन 1982 में प्रारम्भ हुआ । अनपरा थर्मल पॉवर की स्थापना 1978 में तथा उत्पादन 1986 में प्रारम्भ हुआ । रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर की स्थापना 1983 में तथा उत्पादन 1991 में प्रारम्भ हुआ । अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक अधिनियम 1984 के अन्तर्गत लगभग 54 उद्योग पंजीकृत हैं । साथ ही लगभग 500 लघु इकाइयाँ भी वर्तमान समय में कार्यरत हैं । चूना उद्योग

कालीन उद्योग, रसायन उद्योग तथा कुटीर उद्योग यत्र - तत्र पाए जाते हैं ।

5.3 उद्योगों का वर्गीकरण

अध्ययन क्षेत्र मे अनेक प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं जिनका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है -

- (अ) आकार के अनुसार वर्गीकरण
 - । वृहद् उद्योग
 - 2. लघु उद्योग
 - 3. कुटीर उद्योग
- (ब) उत्पादों के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण
 - ।. आधारभूत उद्योग
 - 2. उपभोक्ता उद्योग
- (स) कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण
 - ।. कृषि पर आधारित उद्योग
 - 2. वन उत्पाद पर आधारित उद्योग
 - 3. धातु उद्योग -
 - (क) अलौह धातु उद्योग
 - (ख) लौह धातु उद्योग
 - 4. रसायनिक उद्योग
- (द) स्वामित्व एवं प्रबन्ध के आधार पर वर्गीकरण
 - ।. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग
 - 2. साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग
 - 3. मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग
- (य) उत्पाद की किस्म के अनुसार वर्गीकरण
 - प्राथमिक उद्योग
 - 2. गौप उद्योग
 - 3. तृतीयक उद्योग

एल्सवर्थ हिन्दंगटन 14 ने उद्योगों को चार भागों में विभक्त किया है -

- । प्रारम्भिक उद्योग
- 2. साधारण प्रकार का उद्योग
- 3. समुदाय आधारित उद्योग
- 4. अधुनिक प्रकार के जटिल उद्योग

प्रस्तुत अध्ययन मे उद्योगों को निम्न तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है -

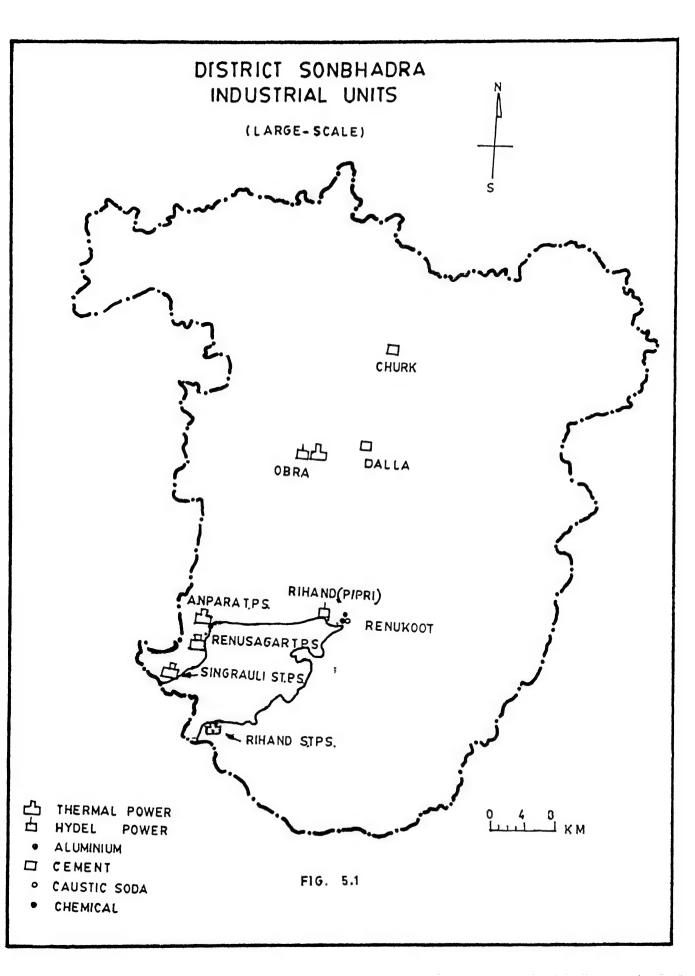
- (अ) बड़े पैमाने के उद्योग
- (ब) लघु पैमाने के उद्योग
- (स) ग्रामीण एव कुटीर उद्योग

(अ) बड़े पैमाने के उद्योग

इस प्रकार के उद्योगों में ऊर्जा चालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है, श्रिमक व पूँजी की अधिक आवश्यकता होती है । अध्ययन क्षेत्र मे बड़े पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत सीमेण्ट, अल्यूनियम, ताप विद्युत, जल विद्युत तथा रसायन उद्योग आते हैं ।

(।) सीमेंट उद्योग

सीमेंट आधुनिक विनिर्माण उद्योग का एक महत्वपूर्ण संघटक है । सीमेट उद्योग, में मूल कच्चे पदार्थों के रूप में चूना पत्थर, मृत्तिका और शेल का उपयोग होता है । इसके अतिरिक्त कोयला और जिप्सम का उपयोग भी सीमेंट विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले अन्य घटकों के साथ किया जाता है । 15 अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन दो सीमेंट कारखानें चुर्क एवं डाला में सीमेंट कारखानों के स्थापना का प्रमुख कारण स्थानीय क्षेत्र गुरमा एवं कजरहट में चूना पत्थर की उपलब्धता है । चूना पत्थर की अधिकता तथा परिवहन लागत में कमी के उद्देश्य से क्षेत्र के सिन्निकट ही सीमेंट उद्योग लगाया जाता है। सीमेंट उत्पादन की दो विधि है - आर्द्र विधि (वेट मेथेड) और शुष्क विधि (इर्ह् मेथेड) । चुर्क सीमेंट कारखाने से केवल आर्द्र विधि से सीमेंट तैयार किया जाता है । इस कारखाने से उत्पादन 1954 - 55 में प्रारम्भ हुआ । डाला सीमेंट कारखाने से आर्द्र एवं शुष्क दोनों विधियों से सीमेंट बनाया जाता है । आर्द्र विधि से सीमेंट उत्पादन 1970-71 मे तथा शुष्क विधि से 1981-82 में प्रारम्भ हुआ । आर्द्र विधि की अपेक्षा शुष्क (इर्ह्) विधि को आधुनिक माना जाता है ।

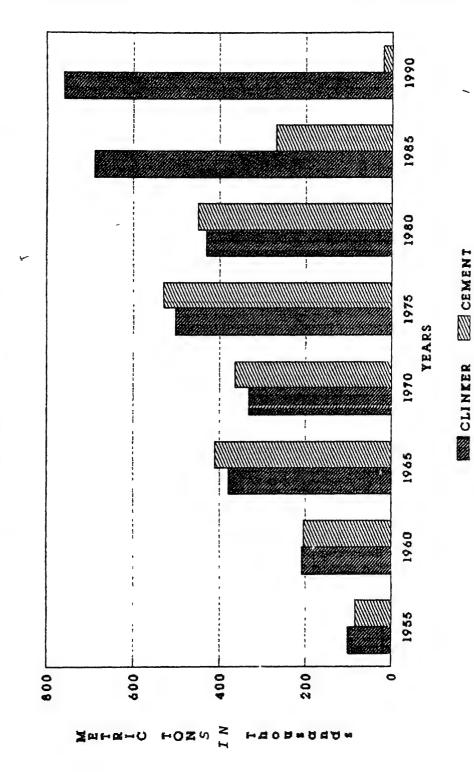


तालिका 5 । विलंकर एवं सीमेंट का उत्पादन

वर्ष	विलकर उत्					उत्पादन	
	चुर्क आर्द्र	डाला आर्द्र	WK-L	योग	चुर्क आर्द्र	डाला आर्द्र एवं शुष्क	योग
	બાદ્ર	આદ્ર 	शुष्क 	વાગ	আছ	आद्र एप शुष्क	पाग
1954-55	101887			101887	84459		84459
1959-60	208659			208659	203891		203891
1964-65	329063			379063	410793		410793
1969-70	331380			331380	364116		364116
1970-71	338292	32238		372530	344246	14100	358346
1971-72	328930	163000		491930	362735	108681	471456
1972-73	374418	242300		616718	438437	273237	711674
1973-74	291064	267200		558264	315327	244830	560157
1974-75	301108	201500		502608	302076	228600	530676
1975-76	315750	300500		616250	384495	315960	600455
1976-77	358491	277000		635491	386154	296700	683854
1977-78	315663	270900		586563	336158	270700	606858
1978-79	317984	238200		556184	336314	247000	583314
1979-80	252313	179300		431613	267462	183768	450230
1980-81	273766	228150		401916	303638	212337	515975
1981-82	32988	277400	44477	654865	287002	120274	512975
1982-83	339759	285400	52204	677363	232880	43000	275880
1983-84	306000	233550	216700	756250	212000	85497	297497
1984-85	277000	188921	222003	687924	186000	81976	267996
1985-86	301776	192476	264120	758369	5084	49773	54857
1986-87	326649	201206	278633	806488	66510	33698	100208
1987-88	217182	238868	438972	895022	97288	28656	125944
1988-89	218512	243352	408197	870061	84199	89098	173297
1989-90	167252	226980	365839	760071	11874	8187	20061
1990-91	109756	226335	220062	536153	67856	52244	120100
1991-92	895221	102740	101855	294121			

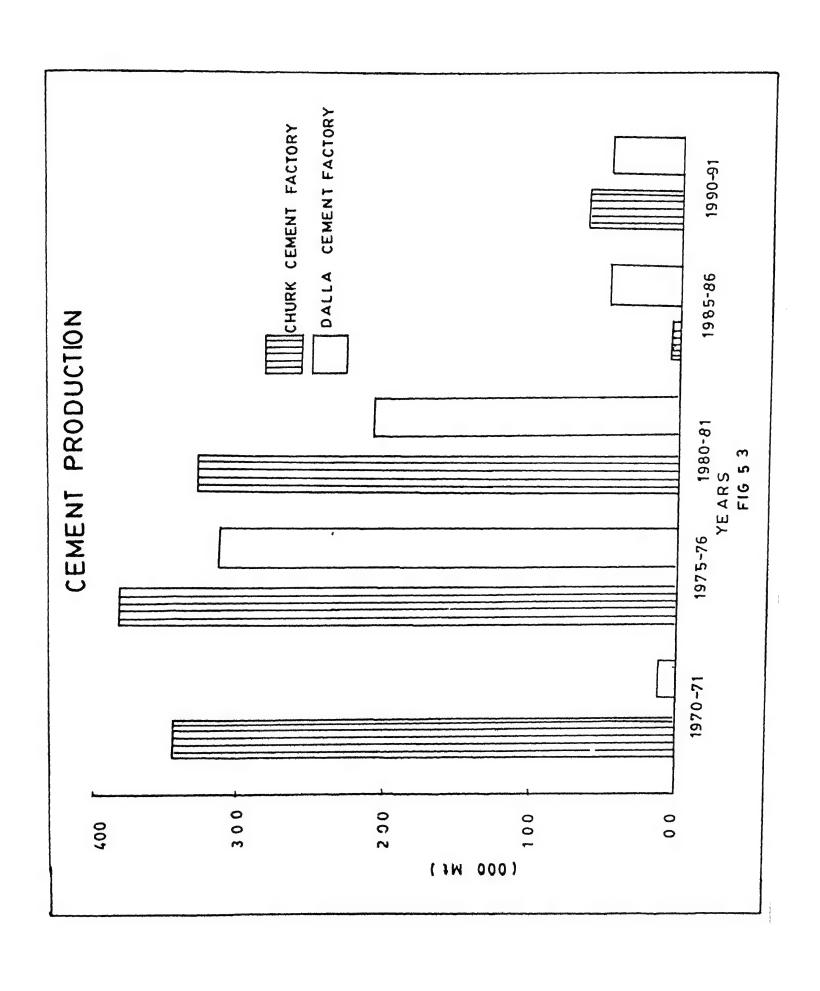
स्रोत: डाला सीमेट कारखाने से सगृहित ।

TOTAL CLINKER AND CEMENT PRODUCTION OF CHURK AND DALLA CEMENT FACTORY



1955 Weans April 1954 to March 1955 & so on

F1g 5.2



निलकर सीमेट उत्पादन के पूर्व की अवस्था है । चुर्क व डाला में क्लिकर का निर्माण न केवल स्वय के कारखाने के लिए बल्कि चुनार स्थित कजरहट सीमेट कारखाने के लिए भी होता है । उल्लेखनीय है कि डाला के समीप स्थित कजरहट चूना पत्थर क्षेत्र के नाम पर ही चुनार स्थित सीमेट कारखाने का नाम कजरहट सीमेट कारखाना है । तालिका 3 । से स्पष्ट है कि 1954 - 55, 1961 - 62, 1971 - 72, 1981 - 82, तथा 1991 - 92, में कुल क्लिकर उत्पादन क्रमश 101887, 218461, 491930, 654865 तथा 294121 मीट्रिक टन हुआ । इसी प्रकार सीमेट उत्पादन वर्ष 1954 - 55, 60 -61, 1970 - 71, 1980 - 81, तथा 1990 - 91 में क्रमश 84459, 244131, 364116, 515975, 120100 मीट्रिक टन हुआ । तालिका 5 । तथा चित्र 5 । से स्पष्ट है कि आर्द्र, शुष्क तथा कुल क्लिकर व सीमेट उत्पादन में उतार चढाव है ।

(2) अल्यूमिनियम उद्योग

धातु उद्योगों मे लौह इस्पात के बाद अल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख स्थान आता है । अध्ययन क्षेत्र मे अल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना, द्वितीय पचवर्षीय योजना मे 1958 मे स्व जी ई बिडला ने 'कैसर अल्यूमिनियम केमिकल कम्पनी' (स्युक्त राज्य अमरीका की कम्पनी) के सहयोग से किया । इस उद्योग की अवस्थिति, जिला मुख्यालय राबर्ट्सगज से लगभग 72 कि0 मी0 दक्षिण, विकासखण्ड म्योरपुर मे रिहन्द जलाशय के तट पर रेनूकूट मे है । इस उद्योग का नाम हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (हिडालको) रखा गया । अल्यूमिनियम का उत्पादन स्थापना के 4 वर्ष बाद, 1962 मे प्रारम्भ हुआ ।

अल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति बाक्साइट अयस्क से होती है । बाक्साइट मुख्यत बिहार से मँगाया जाता है । यद्यपि स्थानीय रूप मे निम्न कोटि का बॉक्साइट उपलब्ध है किन्तु कम्पनी के निजी क्षेत्र मे होने के कारण उत्तम बाक्साइट गढ़वा व पालामऊ से मगाया जाता है । यहाँ के बॉक्साइट में 50 से 60% तक अल्यूमिनियम आक्साइड पाया जाता है । बाक्साइट को शुद्ध करने के लिए कास्टिक सोडा रेनूकूट में स्थित कास्टिक सोडा उद्योग से प्राप्त किया जाता है । अल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए अन्य प्रमुख कारक विद्युत शिक्त की प्राप्ति, बिडला के ही रैणूसागर ताप विद्युत केन्द्र' से की जाती है । उद्योग के लिए आवश्यक

। जल विद्युत - देश मे जल विद्युत के विकास के लिए 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत शिवत निगम (एन एच पी सी) की स्थापना की गयी । वोयला तथा पेट्रोलियम ऊर्जा, अनव्यकरणीय संसाधन है जबिक जल ऊर्जा का नव्यकरणीय संसाधन है । अध्ययन क्षेत्र में जल विद्युत के निम्न दो केन्द्र है -

(क) रिहन्द जल विद्युत गृह पिपरी - रिहन्द जलविद्युत गृह की अवस्थिति रेनूबूट से सलग्न तथा ओबरा से लगभग 45 कि0 मी0 दक्षिण मे है । इस विद्युत गृह वा 300' ऊँचा बाध, रेणू नदी के तट पर कक्रीट ग्रेविटी पद्धित पर निर्मित है । 180 वर्ग मील मे फैला इसका जलाशय (गोविन्द वल्लभ पत सागर) 8 6 मिलियन एकड फीट जल सगृह कर सकता है । इस जलविद्युत गृह की 6 इकाइयों की उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है (तालिका 5 2)।

तालिका 5 2 रिहन्द जलविद्युत गृह पिपरी

इक इयो	उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)	उत्पादन व र्ष	_
I	50	मार्च 1962	
I	50	फरवरी 1962	
II	50	फरवरी 1962	
IV	50	मार्च 1962	
V	50	मार्च 1962	
VI	50	नवम्बर 1966	

50 - 50 मेगावाट की मेसर्स इगिलश इलेक्ट्रिक (यू0के0) की उपर्युक्त 6 इकाइयाँ 45 78 करोड की लागत से, विगत् 31 वर्षों से कार्यरत है । यह विद्युत केन्द्र 'पीकिंग केन्द्र' है, सामान्यत प्रात एव सायकाल जल विद्युत की माँग सर्वाधिक होती है, चलाया जाता है इसके जलाश्रय में अधिकतम 880' तक पानी का स्तर रखा जा सकता है । यह स्तर विगत

वर्षों मे मात्र 4 बार 1964-65, 1971-72, 1987-88 एव 1991-92 मे ही पहुँच पाया है तथा स्पिलिंग किया गया है । इसका न्यूनतम स्तर 830; से नीचे नहीं चलाते है । क्योंकि इस जलाशय के चतुर्दिक शक्तिनगर, रिहन्द नगर, विध्यनगर (मध्य प्रदेश), अनपरा, रेणूसागर आदि थर्मल पाँवर इसी जलाशय से जल लेते है ।

तालिका 5 3 रिहन्द जलविद्युत गृह पिपरी

वर्ष	विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट मे)
1985-86	702
1986-87	957
1987-88	866
1988-89	931
1989-90	867
1990-91	619
1991-92	1265
1992-93	388

तालिका 5 3 से स्पष्ट है कि जलविद्युत उत्पादन मे प्रति वर्ष काफी असमानता है। इसका प्रमुख कारण वर्षा एव जल स्तर है। 1991-92 मे जल स्तर अधिकतम होने के कारण विद्युत उत्पादन भी सबसे अधिक (1265 मि यू) हुआ । 1992-93 मे जल स्तर निम्नतम था इसलिए विद्युत उत्पादन भी निम्नतम (388 मि यू) रहा । रिहन्द जलाशय के चतुर्दिक ताप विद्युत केन्द्रों को जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी, रिहन्द जल विद्युत गृह से सीमित जल विद्युत का ही उत्पादन किया जाता है।

(ख) बोबरा जल विद्युत मृह - ओबरा जलविद्युत गृह रिहन्द बाँध से जल प्रवाह की दिशा में 32 कि0 मी0 की दूरी पर (उत्तर में) सोन एव रिहन्द नदी के सगम स्थान से जल प्रवाह की विपरीत दिशा में (दक्षिण) ।। कि0 मी0 की दूरी पर ओबरा ताप विद्युत गृह के समीप स्थित है । यह भी 'पीकिम' विद्युत गृह है और रिहन्द जलविद्युत से निकले

जल का सदुपयोग करके चलाया जाता है । इसके जलाशय का क्षेत्रफल 18 वर्ग कि0 मी0 है । इस विद्युतगृह मे मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बी एच ई एल) निर्मित 33 मेगावाट की तीन इकाइयाँ, रू० 27 25 करोड़ की लागत से बनायी गई । ओबरा तापविद्युत गृह के परिचालन के दृष्टिकोण से जलाशय के तल को लगभग 192 से 193 मीटर के मध्य रखना अनिवार्य है । ओबरा जलविद्युत गृह की स्थापना 1963 में हुई और उत्पादन मई 1970 में प्रारम्भ हुआ । तीनों इकाइयों की उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन वर्ष तालिका 5 4 में प्रदर्शित है ।

तालिका 5 4 ओबरा जलिन्द्यत गृह

इकाइयाँ	विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट मे)	उत्पादन वर्ष
I	33	मई 1970
II	33	दिसम्बर । १७७०
III	33	अप्रैल 1974

तालिका 5 5 ओबरा जलविद्युत मृह

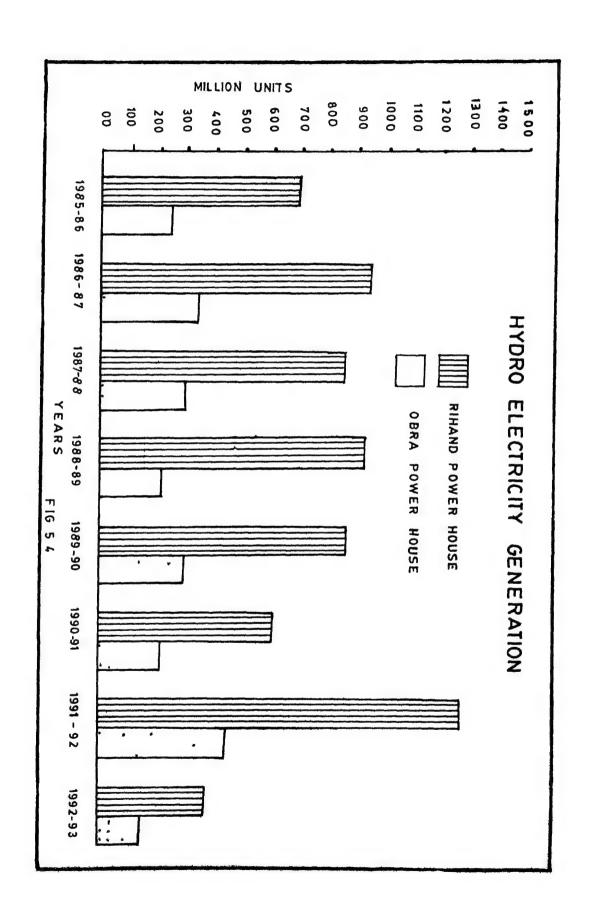
वर्ष	विद्युत उत्पादन
	(मिलियन यूनिट मे)
1974-75	185
1975-76	182
1976-77	448
1977-78	313
1978-79	339
1979-80	323
1980-81	309
1981-82	280

1982-83	243
1983-84	198
1984-85	331
1985-86	250
1986-87	342
1987-88	299
1988-89	216
1989-90	302
1990-91	222
1991-92	454
1992-93	153

म्रोत जल विद्युत गृह से सग्रहित एव सगणित ।

तालिका 5 5 मे विभिन्न वर्षों मे जलिवद्युत उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है । तालिका से स्पष्ट है कि जलिवद्युत उत्पादन मे स्थिरता एव समरूपता का अभाव है । इसका प्रमुख कारण जलाशय का जल स्तर एव ओबरा ताप विद्युत गृह को जल उपलब्धता सुनिश्चित करना है ।

2 ताप विद्युत - कोयला, डीजल तथा जल पर आधारित ताप विद्युत गृहों की स्थापना से देश मे विद्युत उत्पादन मे बहुत वृद्धि हुई है । देश का 60% विद्युत ताप विद्युत गृहों से प्राप्त किया जाता है । कोयला एव डीजल के क्षयशील ससाधन होने के बावजूद ताप विद्युत ही निरन्तर साधन है । जलविद्युत का उत्पादन अनावृष्टिट काल मे अविश्वसनीय है। 'काश्मीर की बेटी' कही जाने वाली धरती का वह भू-भाग जिसे सिगरौली स्टेट के नाम से जाना जाता था,²⁰ के कोयला पर आधारित 6 तापविद्युत गृह ऊर्जा को निरन्तर उत्पादित कर रहे है । इनमे से एक (विध्याचल सुपर धर्मल पाँवर स्टेशन) मध्य प्रदेश मे है तथा शेष पाँच अध्ययन क्षेत्र मे अवस्थित है । दो ताप विद्युत गृहों, रिहन्द सुपर धर्मल पाँवर स्टेशन तथा अनपरा ताप विद्युत गृह का निर्माण अभी भी जारी है , इसे दीर्घ अवधि मे पूरा किया जाना है । शेष तीन ताप विद्युत गृहों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । ओबरा ताप विद्युत गृहों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । ओबरा ताप विद्युत



गृह को छोडकर सभी ताप विद्युत गृह नित् नये कीर्तिमान स्थापित कर रहे है । उल्लेखनीय है कि ओबरा ताप विद्युत गृह सबसे प्राचीन है तथा प्रशिक्षण गृह के रूप मे प्रयुक्त होता रहा है । अपेक्षाकृत नूतन टेक्नालजी का प्रयोग ओबरा ताप विद्युत मे नहीं हो पाया है ।

(क) सिनरोली सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन - एन टी पी सी की यह पहली परियोजना थी जिसे दिसम्बर, 1976 में सरकारी अनुमोदन मिला । आरम्भ में 200 मेगावाट की तीन इकाइयों के लिए (कुल 600 मेगावाट) इसके विस्तार चरण को, जिसमें 200 मेगावाट की दो इकाईयाँ सिम्मलित थी, जुलाई, 1979 में स्वीकृति मिली और इस प्रकार इसकी कुल क्षमता 2000 मेगावाट हो गयी।

देश के विद्युत उत्पादन क्षेत्र मे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले एन टी पी सी के सिगरौली वृहत् ताप विद्युत गृह ने 13 फरवरी, 1992 को अपनी पहली इकाई के उत्कृष्ट उत्पादन का सफलतापूर्वक एक दशक पूरा किया । वर्ष 1982 की इसी तारीख को एन टी पी सी व सिगरौली की पहली इकाई शुरू (सिक्रोनाइज) हुई थी । एन टी पी सी और सिगरौली के इतिहास मे यह तारीख इसलिए भी सर्वाधिक महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन विद्युत उत्पादन की आधारिशला रखी गयी थी । इसके पश्चात् 200 मेगावाट की चार तथा 500 मेगावाट की दो इकाईयों को एक के बाद एक शुरू किया गया ।

शैशवावस्था से ही सिगरौली का उत्पादन स्तर ऊँचा रहा है । इस दशक में इसने एक के बाद एक कई कीर्तिमान स्थापित किये और उल्लेखनीय पुरस्कार अर्जित किये जहाँ तक विद्युत उत्पादन का प्रश्न है, जनवरी 1992 के अन्त तक सिगरौली विद्युत गृह का इन दस वर्षों का औसतन पी एल एफ 73 13% (वाणिज्यिक) रहा है । सिगरौली और भी ज्यादा उत्पादन कर सकता था परन्तु ग्रिंड प्रतिबन्धों के कारण करीब 6 5% पी एल एफ की क्षिति हुई । इसकी सफलता का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि गत् दशक की अविध मे देश के विभिन्न ताप विद्युत गृहों का औसत पी एल एफ 48 6% से लेकर 56 5% के बीच ही रहा । इसकी उपलिब्धियों के क्रम मे 200 मेगावाट की चौथी इकाई द्वारा वर्ष 1986-87 मे 1710 मिलियन यूनिट के उत्पादन का कीर्तिमान अंकित है जो कि 76 6% पी एल एफ के बराबर है ।

तेल खपत की दृष्टि से भी सिगरौली विद्युत गृह का प्रदर्शन सर्वीत्कृष्ट रहा है । जहाँ तक एक दिनी उत्पादन का प्रश्न है इस विद्युत गृह ने 25 अक्टूबर, 91 को 48 91 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पन्न कर अपना अधिकतम उत्पादन का कीर्तिमान बनाया है।

सिगरौली सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन एक नजर में -

- । कुल क्षमता (मेगावाट) -2000
- 2 अनुमोदित क्षमता (मेगावाट) 2000
- 3 ट्रासिमशन प्रणाली 400 के वी सिर्कट किलोमीटर 2337
- 4 कोयला प्राप्ति का स्त्रोत जयन्त /बीना खदान
- 5 कूलिंग वाटर स्त्रोत/प्रणाली रिहन्द जलाशय (200 क्यूसेक पानी की खपत)
- 6 लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एव दिल्ली ।
- 7 अनुमोदित पूँजीनिवेश करोड रूपया 1374 93
- 8 चालू हो चुकी इकाइयाँ 5×200+2×500 मेगावाट
- 9 इकाइयों के चालू होने का कार्यक्रम

विजलीघर	चालू करने की वास्तविक तिथि	ट्रासमिशन
यूनिट । (200 मेगावाट)	फरवरी 1982	सिगरौली - ओबरा
यूनिट 2 (200 मेगावाट)	नवम्बर 1982	सिगरौली - कानपुर I
यूनिट 3 (200 मेगावाट)	मार्च 1983	सिगरौली - लखनऊ
यूनिट 4 (200 मेगावाट)	नवम्बर 1983	लखनज - मुरादाबाद
यूनिट 5 (200 मेगावाट)	फरवरी 1984	मुरादाबाद - मुरादनगर
यूनिट 6 (500 मेगावाट)	दिसम्बर 1986	मुरादनगर - पानीपत
यूनिट ७ (५०० मेगावाट)	नवम्बर 1987	सिगरौली - कानपुर 11

- 10. कोयले की खपत पूर्ण क्षमता के लिए 8 4 मिलियन टन प्रति वर्ष
- 11 कोयले की आपूर्ति 17िक0मी0 लम्बी मेरी-गो-राउण्ड प्रणाली

12 पानी के प्रदूषण का समाशोधन -

वायु एव पानी के प्रदूषण की स्वीकृति प्राप्त 1989 के नवीनीकरण की प्रक्रिया चालू

13 कर्मचारियों की सख्या -

कार्यपालक 582, अकार्यपालक 1964, योग = 2546

14 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता -

600 मेगावाट 150 मिलियन अमरीकी डालर आई डी ए से 171 20 मिलियन डी एम के एफ डब्ल्यू से

1400 मेगावाट 300 मिलियन अमरीकी डालर आइ डी ए से 240 मिलियन डी एम के एफ डब्ल्यू से

(ख) रिहन्द सुपर थर्मल पाँवर स्टेशन - यह विद्युत गृह रिहन्द जलाशय के दक्षिणी - पश्चिमी तट पर बीजपुर में स्थित है । 19 2 ह3 को स्थापित इस विद्युत गृह से 1991 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ । इस ताप विद्युत गृह को, तीन चरणों मे (2×500, 2×500 एव 2×500) विस्तारित करके 3000 मेगावाट विद्युत क्षमता प्रदान करने का उद्देश्य है । प्रथम चरण 2×500 (1000 मेगावाट) का कार्य पूर्ण हो गया है । वर्ष 1991 में 6282 72 मिलियन यूनिट तथा वर्ष 1992 में 6090 29 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ । रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन ने तीसरी बार अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए मार्च 1993 मे 100% से अधिक प्लाण्ट लोड फैक्टर पर विद्युत उत्पादन एव 100% सयन्त्र उपलब्धता प्राप्त करके एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है । यह उत्पादन परियोजना के प्रथम चरण में 500 मेगावाट की दो इकाइयों द्वारा प्राप्त किया गया है जिसने 100 53% प्लाण्ट लोड फैक्टर एव लगभग 100% उपलब्धता पर 7479 लाख विद्युत इकाई का उत्पादन किया है । प्रथम इकाई ने 3772 लाख विद्युत इकाई का उत्पादन 100 32% प्लाण्ट लोड फैक्टर पर तथा द्वितीय इकाई ने 3747 लाख विद्युत इकाई का उत्पादन 100 75% प्लाण्ट लोड फैक्टर पर किया । इसके पूर्व जनवरी 1992 मे 100 84% एव फरवरी 1993 मे 100 22% प्लाण्ट लोड फैक्टर पर विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया जा चुका है । 21 रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा वर्ष 1991 के लिए विशिष्ट उत्पादकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया । सम्भवतं यह

देश का प्रथम विद्युत गृह है, जिसने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश के इस सर्वोच्च पुरस्कार को अपने व्यावसायिक उत्पादन के प्रथम वर्ष में ही प्राप्त किया है । 22

रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन एक नजर मे -

। कुल क्षमता (मेगावाट) 3000

प्रथम चरण 2×500 मेगावाट

द्वितीय चरण 2×500 मेगावाट

त्तीय चरण 2×500 मेगावाट

2 अनुमोदित क्षमता (मेगावाट)

3 ट्रासिमशन प्रणाली 400 के वी 1410/910

सर्किट किलोमीटर 600

4 कोयला प्राप्ति का स्त्रोत सिगरौली कोयला क्षेत्र के अमलोरी खान से

5 जमीन की आवश्यकता 5000 एकड

6 जल स्त्रोत रिहन्द जलाशय

7 लाभान्वित होने वाले राज्य पजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,

जम्मू एव काश्मीर, हिमाचल प्रदेश,

दिल्ली एव चण्डीगढ

8 अनुमोदित पूँजी निवेश (करोड रूपये) 1614 70

9 स्थापित की जाने वाली इकाइयों का अवार 6×500

10 चालू हो चुकी इकाइयाँ 2×500

11 इकाइयों के चालू होने का कार्यक्रम 1988 - 89 में 1×500 मेगावाट

मार्च 1988 मे तथा 1989-90 मे

1×500 मेगावाट जुलाई 1989 मे

12 अन्तर्राष्ट्रीय क्तितीय सहायता ब्रिटेन सरकार से 344 मिलियन डालर

की निर्यात ऋण सुविधा तथा । 17 मिलियन

डालर की वित्तीय सहायता

13 अधिकतम कोयला खपत 31000 मीट्रिक टन / प्रतिदिन

14 कोयला परिवहन का माध्यम मेरी-गो-राउण्ड-सिस्टम

15	अधिकतम पानी की आवश्यकता	4500 क्यूसेक्स
16	खपत की आवश्यकता	300 क्यूसेक्स
17	सीमेट आवश्यकता	280000 मीट्रिक टन
18	स्टील आवश्यकता	61400 मीट्रिक टन
19	चिमनी की ऊँचाई	224 5 मीटर

(ग) ओबरा ताप विद्युत गृह - ओबरा ताप विद्युत परियोजना जनपद मुख्यालय राबर्ट्सगज से लगभग 37 कि0 मी0 दक्षिण मे हैं । यह परियोजना तीन चरणों में प्रस्तावित थी । प्रथम चरण में 5×50 मेगावाट की इकाइयाँ 1967-71 के बीच रूस की सहायता से स्थापित हुई । द्वितीय चरण में 3×100 मेगावाट की इकाइयाँ 1973-76 के बीच बी एच ई एल की सहायता से स्थापित की गयी । तृतीय चरण में 5×200 मेगावाट की इकाइयाँ 1978-82 के बीच बी एच ई एल की सहायता से स्थापित की गई थी । इस प्रकार ओबरा ताप विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 1550 मेगावाट है । 550 मेगावाट (5×50 + 3×100 मेगावाट) की इकाई को ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह तथा 1000 मेगावाट (2×200 मेगावाट) की इकाई को ओबरा 'व' ताप विद्युत गृह कहते है । 100 एव 200 मेगावाट क्षमता की भारत की यह प्रथम इकाई थी । सम्पूर्ण इकाइयों के प्रारम्भ होने का वर्ष तालिका 5 6 में प्रदर्शित है ।

तालिका 5 6 ओबरा ताप विद्युत गृह

इकाई सख्या	स्थापित क्षमता(मेगावाट)	प्रारम्भ होने का दिनाक
1	50	29 6 67
2	50	12 2 68
3	50	25 8 68
4	50	11 6 69
5	50	7 6 71
6	100	18 7 73
7	100	14 12 74
8	100	15 9 75
9	200	13.3 80
10	200	6 3 79
1 t	200	14 3 78
12	200	29 5 81
13	200	29 7 82

इस परियोजना के लिए कोयला सिगरौली कोयला क्षेत्र से तथा पानी रिहन्द जलाशय से प्राप्त किया जाता है । रिहन्द जलाशय का पानी पिपरी स्थित रिहन्द जलविद्युत गृह द्वारा प्रयुक्त रिहन्द नदी के माध्यम से, ओबरा जलविद्युत गृह के जलाशय में आता है । पुन इस जलाशय के पानी का प्रयोग जल विद्युत के साथ - साथ ताप विद्युत गृहों में भी किया जाता है । तालिका 5 7 में 1967-68 से 1992-93 तक के विद्युत उत्पादन का विवरण दिया गया है । 1988-89 में 7894 तथा 1987-88 में 7260 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ । फलत ओबरा ताप विद्युत गृह को 1987 एवं 1988 में 'श्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार से, भारत सरकार द्वारा पुरष्कृत किया गया था ।

तालिका 5 7 ओबरा ताप विद्युत गृह

वर्ष	550 मेगावाट का उत्पादन(मिलियन यूनिट)	।000 मेगावाट का उत्पादन (मिलियन यूनिट)	योग
1	2	3	4
1967-68	153		153
1968-69	695		695
1969-70	846		846
1970-71	1159		1159
1971 - 72	1389		1389
1972-73	1356		1356
1973-74	1468		1368
1974-75	2058		2058
1975-76	2458		2458
1976-77	2780		2780
1977-78	2730()		2730
1978-79	2216		2216
1979-80	2030		2030
1980-81	2046		2046
1981-82	2036		2036
1982-83	2081		2081
1983-84	2190	2663	4853
1984-85	1596	2438	4034
1985-86	1749	3135	4884
1986-87	1471	3657	5128
1987-88	1677	5583	7260
1988-89	2181	5713	7894
1989-90	2295	4710	7005

1990-91	2170	6062	6232
1991-92	1617	4947	6564
1992-93	1624	5440	7064

स्रोत ओबरा ताप विद्युत गृह से सगृहीत ।

(घ) अनपरा ताप विद्युत गृह

अनपरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना 1978 में की गयी। इसकी अवस्थिति रिहन्द जलाशय के उत्तरी किनारे पर रेणूसागर के समीप है। यह परियोजना सिगरौली कोयला क्षेत्र के समीप है। अनपरा 'अ' ताप विद्युत गृह की तीनों इकाह्यों (3×210 मेगावाट) का उत्पादन क्रमश 24 3 86, 28 2 87 तथा 12 3 88 को प्रारम्भ हुआ। अनपरा 'ब' ताप विद्युत गृहकी दो इकाह्यों (2×500 मेगावाट) में से प्रथम इकाई का उद्घाटन 28 7 93 को हुआ। 'ब' तापीय परियोजना का निर्माण भारत एव जापान के सहयोग से किया जा रहा है। इस परियोजना का प्रथम चरण जिसकी उत्पादन क्षमता 3×210 मे0वा0 है, पहले ही पूरा किया जा चुका है। 'अ' परियोजना अपने उत्कृष्ट उत्पादन के लिए लगातार तीन वर्षों से राष्ट्रपति पुरस्कार अर्जित करता चला आ रहा है।

'ब' परियोजना नवम्बर 1993 से व्यावसायिक उत्पादन मे लायी जानी है। दूसरी निर्माणाधीन इकाई सम्भवत मार्च 1994 मे पूर्ण हो जाएगी। जिस प्रकार से वित्तीय सकट आ रहा है, उसे देखते हुए द्वितीय इकाई को समय से पूर्ण होने मे संदेह है। अनपरा 'ब' परियोजना का निर्माण कार्य सितम्बर 1989 मे प्रारम्भ हुआ था। इस परियोजना के पूर्ण होने से लगभग 50000 नलकूपों 10000 गांवों एव 10000 लघु उद्योगों को बिजली दी जा सकेगी, जो राष्ट्रीय विकास की एक मजबूत कड़ी होगी। ²³

अनपरा 'ब' तापीय परियोजना के 2×500 मेगावाट के प्रथम 500 मेगावाट के सभी सयन्त्र एव दोनों इकाइयो के लिए सामान्य उपकरण एव पद्धतियो की आपूर्ति मितसुई एण्ड कम्पनी जापान द्वारा ओ०ई०सी० एफ० के पैक्ट के अन्तर्गत की जा रही है। दूसरी इकाई के सयन्त्रों की आपूर्ति जापान के ही एक्जिम बैंक की सहायता से मितसुई एण्ड कम्पनी द्वारा की जा रही है। विद्युत गृह के लिए कोयला नार्दन कोल फील्ड (एन०सी०एल०) के खडिया बीना एव ककरी खान से प्राप्त की जाती है। खडिया, खान से कोयला लाने के लिए

'मेरी-गो-राउण्ड', का निर्माण भारत सरकार के उपक्रम 'इरफान' द्वारा कराया जा रहा है। इस विद्युत गृह मे 36 लाख टन कोयला प्रतिवर्ष खपता है। इस परियोजना से निकलने वाली राख के विसर्जन हेतु वर्तमान मे परियोजना से 2 किमी0 दूर 10 लाख घन मीटर धारक क्षमता के बाध का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 किमी0 दूर ग्राम वेलवादह के पास भस्म तालाब तक राख निस्तारण का कार्य प्रस्तावित है।

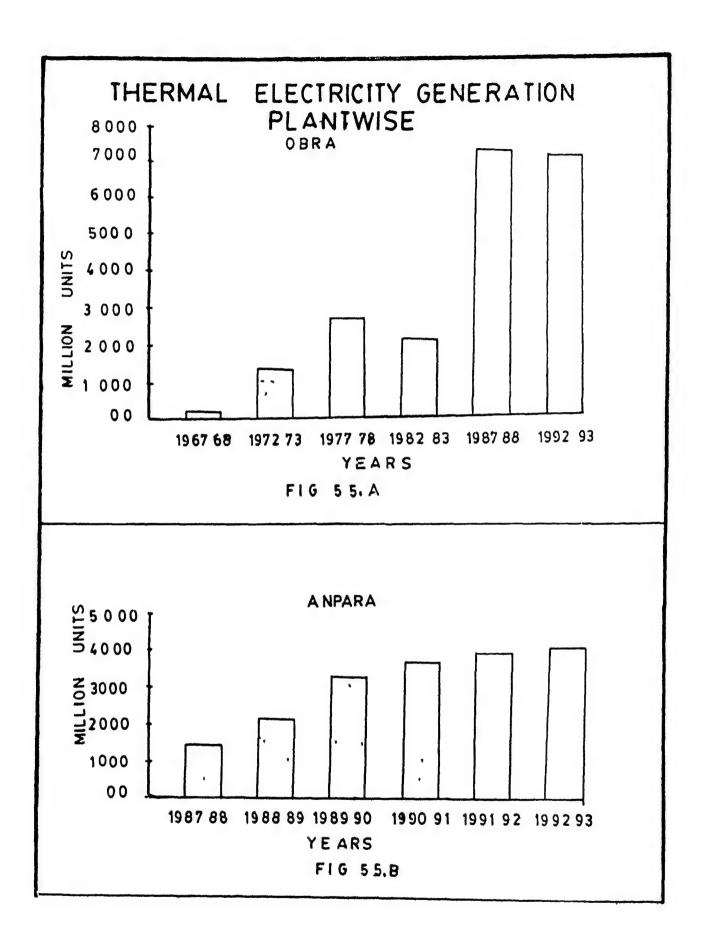
इस परियोजना की अनुमानित लागत 2432 करोड रूपये थी जो अब 3825 करोड हो गयी। परियोजना को ओ०ई०सी०एफ० जापान द्वारा 2020 करोड रूपये, एक्जिम बैंक जापान द्वारा 620 करोड रूपये तथा भारत सरकार एव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1185 करोड रूपये क्तितीय सहायता प्रदान किया गया है। जून 1993 तक परियोजना पर 3100 करोड रूपया व्यय हो चुका है।²⁴

अनपरा तापीय परियोजना की चिमनी की ऊँचाई 275 मीटर है, जो अब तक देश में लगी सभी परियोजनाओं की चिमनिओं से ऊँची है। परियोजना के द्वितीय चरण के पूर्ण होने पर तृतीय चरण (2×500 मेगावाट) की शुरूवात होगी है। सम्पूर्ण इकाइयों की स्थापना के बाद अनपरा ताप विद्युत गृह की संस्थापित क्षमता 2650 मेगावाट हो जाएगी।

तालिका 5 8 अनपरा ताप विद्युत गृह

वर्ष	उत्पादन	मिलियन यूनिट मे
1987-88	1509	
1988-89	2217	
1989-90	3342	
1990-91 1991-92 1992-93	3743 3929 4109	

स्रोत अनपरा ताप विद्युत से गृह से समृहित ।



तालिका 5 8 से स्पष्ट है कि अनपरा ताप विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन लगातार बढ़ रहा है तथा पिछले कीर्तिमानों को भग करता जा रहा है। इन वर्षों में लक्ष्य से अधिक उत्पादन हो रहा है।

(ड) रेणुसागर ताप विद्युत गृह

इस परियोजना की स्थापना 6 मार्च 1964 को हुई। इसकी अवस्थिति रिहन्द जलाश्रय के तट पर अनपरा के समीप है। इस विद्युत गृह से रेनूकूट अल्यूमिनियम कारखाने को बिजली प्रदान की जाती है। कोयले की आपूर्ति रज्जु मार्ग से सिगरौली कोल फील्ड के झिगुरदह खान से तथा जल की आपूर्ति रिहन्द जलाश्रय से होती है। डीजल की आपूर्ति इंडियन आयल के मुगलसराय देन्द्र से होती है। इस विद्युत गृह के पाच इकाइयों एव पाच ब्वायलर के प्रारम्भ होने का समय तालिका 5 9 मे प्रदर्शित है।

तालिका 59 रेणूसागर ताप विद्युत गृह

इकाई		प्रारम्भ होने का दिनाक
I	इकाई	4 10 68
II	इकाई	9 9 67
III	इकाई	2 11 81
IV	इकाई	9 4 83
V	इकाई	31 3 89
I	ब्वायलर	17 6 67
II	ब्वायलर	22 11 67
III	ब्वायलर	8 6 82
IV	ब्वायलर	1 2 83
<i>V</i>	ब्वायलर	18.9 81

रेणूसागर ताप विद्युत गृह से वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 मे क्रमश 2603, 2851 तथा 2740 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ ।

तालिका 5 10 रेणूसागर ताप विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन

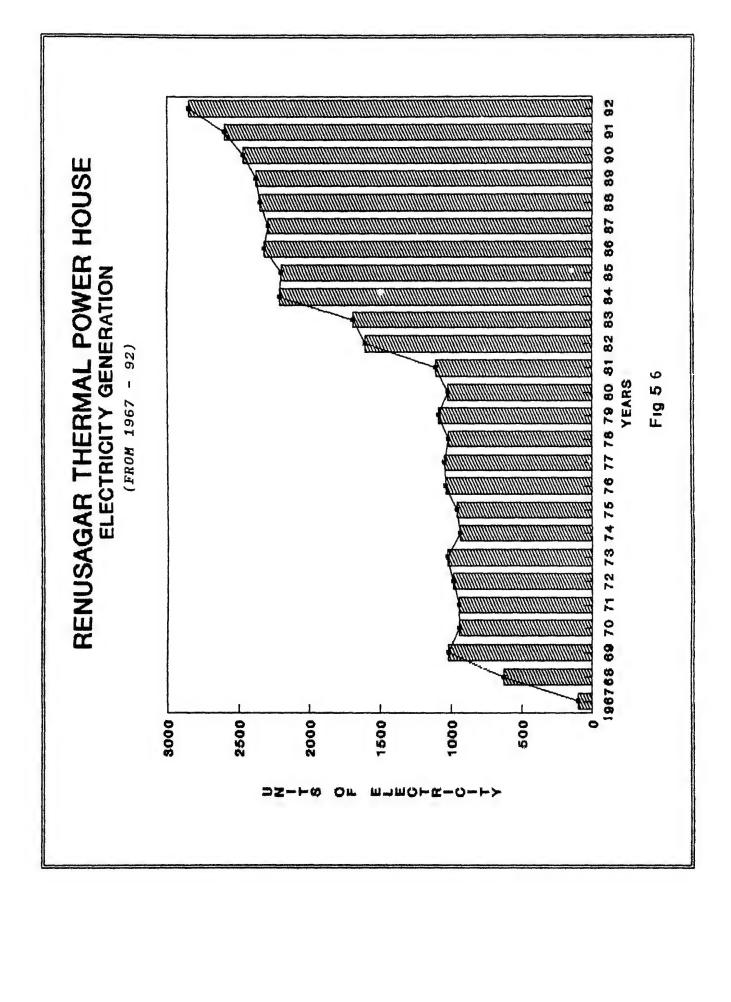
वर्ष	वास्तविक उत्पादन	(एम0डब्ल्यू0एच0 मे)
1967	98341	
1968	630706	
1969	1019093	
1970	944335	
1975	959540	
1980	1023923	
1985	2197784	
1990-91	2602662	
1991-92	2850669	
1992-93	2739672	

स्रोत रेणूसागर ताप विद्युत गृह से सगृहित ।

(ब) लघु पैमाने के उद्योग

लघु पैमाने के उद्योग की परिभाषा विभिन्न औद्योगिक नीति में भिन्न-भिन्न रही है। वर्तमान औद्योगिक नीति में लघु उद्योग में 5 लाख से अधिक तथा 60 लाख से कम निवेश वाले उद्योगों को सिम्मिलित किया गया है। निर्यातोन्मुखी इकाइयों में यह सीमा 75 लाख तक कर दी गयी है। मशीनों का प्रयोग लघु उद्योग को कुटीर उद्योग से अलग कर देती है। अध्ययन क्षेत्र में लघु उद्योग अपेक्षाकृत कम है। प्रमुख, लघु पैमाने के उद्योग निम्न है -

(।) चूना उद्योग- मारकुण्डी से सोननदी के तट तक चूने की अनेक भट्टियां लगी हुई है। सलखन एव पटवध चूना उद्योग के प्रमुख केन्द्र है। चूना पत्थर की स्थानीय उपलब्धता इस उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारण है।



- (2) ऊनी कालीन उद्योग ऊनी कालीन उद्योग मुख्यत भर्दोही एव मिर्जापुर जनपद मे पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे भी ऊनी कालीन उद्योग का विकास हो रहा है। सस्ते श्रम की उपलब्धता तथा बेरोजगारी इस उद्योग के स्थापना के प्रमुख कारण है। इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र उरमौरा, बैराही, गुरमा, घुआस, ककराही, जूडी, पसही, पुरौली, बहुअरा, दुरावल कला, पापी, बसुहा, गुलख, पापीरा, कसया कला, शिवखरी, जमगाव, शिवद्वार, घोरावल, मुडिलाडीह, बकौली, चुर्क, चोपन, ओबरा, शिवतनगर, चपकी, सिद्धिरया, जगदीशपुर आदि है। इस उद्योग ने एक ओर बाल श्रम को बढावा दिया है तो दूसरी ओर रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं।
- (3) बजरी-बालू एव मोरम उद्योग अध्ययन क्षेत्र का यह प्रमुख उद्योग है। बजरी तोडने के लिए चोपन, ओबरा तथा डाला क्षेत्र में हजारों 'क्रैशर उद्योग' लगे हुए है। इन क्षेत्रों की सम्पूर्ण पहाडियों को तोडकर समतल रूप प्रदान किया जा रहा है। यहाँ की बजरी भवनों, परियोजनाओं , औद्योगिक भवनों, पुलों तथा सडकों आदि के निर्माण के लिए दूर दूर तक जाती है। बजरी की दुलाई ट्रकों व ट्रैक्टरों से की जाती है। इससे परिवहन उद्योग में काफी बृद्धि हुई है।

अध्ययन क्षेत्र की सभी निर्दिया (सोन, कर्मनाशा, कनहर, रिहन्द आदि) पहाडी है। इन निर्दियों से निर्मित बालू की मात्रा एव गुण उत्तम प्रकार का है। यहाँ के बालू के कड बड़े तथा चमकीले है, जिसका उपयोग बाधों, भवनों, कारखानों, पुलों आदि मे किया जाता है। यहाँ की बालू अपनी उत्तमता के कारण अन्य प्रदेशों मे भी भेजी जाती है, जो ट्रके अन्य स्थानों से सामान लेकर सोनभद्र आती है उन्हे वापसी कार्य के रूप मे बजरी बालू एव मोरम मिल जाता है। बालू से परिवहन एव निर्माण उद्योग का विकास हो रहा है।

अध्ययन क्षेत्र के सभी विकासखण्डों मे मोरम की खार्ने पायी जाती है। इसका उपयोग रा बनाने, पेट बनाने तथा सड़क निर्माण मे किया जाता है। स्थानीय कच्ची एव खडजा सड़कों पर मोरम बिछाकर सड़कों को आवागमन के अनुकूल बनाया गया है।

(4) फर्नीचर उद्योग — प्रकाष्ठ की मींग बढ़ जाने तथा लकडी चिराई (आरा) मशीनों की स्थापना से सोनभद्र में इस उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। अनेक औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना से इस उद्योग को स्थानीय बाजार भी उपलब्ध है। रेनूकूट के समीप मुर्धवा लकड़ी चिराई एवं फर्नीचर उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र है। इसके अतिरिक्त राबर्ट्सगज, चोपन,

ओबरा, रेनूकूट, अनपरा व शक्तिनगर अन्य प्रमुख केन्द्र है। पर्यावरण सतुलन से साम्य स्थापित करते हुए फर्नीचर उद्योग को और अधिक विकसित किया जा सकता है। वनों से बिना चीरी लकडी (बल्ली, एव गोला) निकाली जाती है। मुर्घवा एव दुन्ही प्रमुख प्रकाष्ठ मण्डियाँ है। साल, असना, सिन्दा, हल्दू, धौ, सर्लाई, सिरिस, साल आदि इस उद्योग मे प्रमुखत प्रयुक्त होती है।

(5) ईंट उद्योग - जनपद के औद्योगिक विकास से इस उद्योग का स्वत विकास हो गया । विकास खण्ड चोपन, म्योरपुर तथा दुद्धी मे अनेक ईंट के भट्ठे चल रहे हैं। कोयले की प्राप्ति सिगरौली कोयला क्षेत्र से हो जाती है तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ते शिमक व स्थानीय बाजार इस उद्योग के विकास के प्रमुख कारण है।

उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त निम्न लघु उद्योग अध्ययन क्षेत्र मे यत्र - तत्र फैले हुए है -

- दाल मिल
- खाद्य तेल मिल
- आटा पीसने का उद्योग
- बेकरी उद्योग
- मोमबत्ती उद्योग
- चमडा उद्योग
- एल्युमिनियम के सामान

(स) ग्रामीण एव कुटीर उद्योग

ग्रामीण एव कुटीर उद्योग को साधारणतया एक समान माना जाता है। यद्यपि काल एव स्थान के अनुसार इनमे सूक्ष्म भेद बताया जाता है। कुटीर उद्योग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक निर्माण उद्योग का आधार है। इसके अन्तर्गत दस्तकार अपनी पैतृक दक्षता के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से घर मे ही वस्तुए बनाता है। इस उद्योग की प्रमुख विशेषता स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग है। इनके उत्पादों की उपादेयता स्थानीय लोगों के लिए अधिक होती है। इन उद्योगों का उत्पादन छोटे स्तर पर होता है तथा बहुत साधारण औजारों

एव उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ²⁵ विस्तृत अर्थों मे ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों मे उन सभी उद्योगों को सिम्मिलित किया जा सकता है। जो ग्रामीणों द्वारा आंशिक या पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप मे किये जाते है। ये उद्योग जातिगत अथवा परम्परागत उद्योग के रूप मे हो सकते है। ²⁶ अध्ययन क्षेत्र मे कृषि एव वनों पर आधारित अनेक लघु उद्योग पाये जाते है, जिनमे प्रमुख निम्न है -

(1) तेंदू पत्ता नेंदू के पत्ते का उपयोग बीडी बनाने में किया जाता है। तेंदू पत्ता व्यापार अधिनियम 1972 के लागू हो जाने के उपरान्त समस्त तेंदू पत्ते का व्यापार शासन ने अपने हाथ में ले लिया है। सन 1983 से यह कार्य उ०प्र० वन निगम द्वारा सम्पन्न हो रहा है। तेंदू पत्ते का संग्रहण स्थानीय श्रमिकों द्वारा किया जाता है और पचास-पचास पत्ते की गड़िडया बनायी जाती है। इस प्रकार बाधी गयी एक हजार गड़िडयों से एक मानक बोरा बनता है। तेंदू पत्ते का निर्गम, मानक बोरों या छोटे-छोटे बोरों जिन्हे 'झाल' कहते है, में किया जाता है। तेंदू पत्ता का सग्रहण वन निगम के निर्धारित डिपो मुर्धवा, दुद्धी, तथा विण्डमगज में किया जाता है।

सोनभद्र के वन प्रभाग के राजस्व का लगभग 3/4 भाग तेंदू पत्ते से प्राप्त होता है। जिस वर्ष गर्मी अधिक पड़ती है तथा 'लू' अधिक चलती है, उस वर्ष तेंदू पत्ता अच्छी तरह पनपता है। पित्तयों को तोडने का कार्य मई से मध्य जून तक होता है। अध्ययन क्षेत्र में तेंदू पत्ते की उपलब्धता को देखते हुए बीडी उद्योग की पर्याप्त सम्भावनाए है।

(2) ईंघन एकत्रीकरण

ईंधन के रूप में लकडियों की स्थानीय माँग पिपरी, रेनूकूट, दुढ़ी, विण्ढमगण शिक्तनगर, अनपरा, रेणूसागर, रिहन्द नगर, ओबरा, डाला, चुर्क तथा राबर्टसगण आदि में बढ़ती जा रही है। मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी इसकी प्रमुख मण्डिया है। ईंधन के रूप में धौ, ककोर, सिद्धा तथा बेर की लकडिया अच्छी समझी जाती है। पर्यावरण सतुलन की समस्या को देखते हुए ईंधन एकत्रीकरण के उद्योग के विकास को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है। पुराने तथा बेकार बुक्षों की लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में अवश्य किया जा सकता है।

(3) मिट्टी के बर्तनों का उद्योग-

अध्ययन क्षेत्र में कुम्हार जाति द्वारा घडा, सुराही, कुल्हड आदि मिट्टी के बर्तन बनाये जाते हैं। दीपावली के अवसर पर दीपक तथा खिलौने बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग बरसात के दिनों में नहीं होता है। कच्चे बर्तनों एव खिलौनों को पकाकर तैयार किया जाता है तथा उन्हें बाजार में विक्रय हेतु लाया जाता है।

- (4) **ग्रामीण चमडा उद्योग** इस उद्योग में मृत जानवरों की खाल निकालना, सफाई करना तथा उससे जूता, चप्पल तथा उपयोगी वस्तुए बनायी जाती है। इस कार्य में अध्ययन क्षेत्र के कुछ विशिष्ट लोग ही लगे हुए है।
- (5) चावल उद्योग अध्ययन क्षेत्र मे विकास खण्ड चतरा, राबर्टसगज व घोरावल की अधिकाश ग्राम सभाओं मे 'हालर' द्वारा धान की कुटाई की जाती है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे एक भी चावल मिल नहीं है।
- (6) बर्गई घास यह एक विशिष्ट प्रकार की घास है, जिसका उपयोग रस्सी बनाने में होता है। जनपद सोनभद्र में बर्गई घास लगभग सभी विकासखण्डों में पायी जाती है। किन्तु विकासखण्ड नगवा चोपन, म्योरपुर, बभनी व दुद्धी में यह अधिक पायी जाती है। बर्गई घास की अधिकता को देखते हुए रस्सी बनाने के कुटीर उद्योग विकासत करने की पर्याप्त सभावना है। यद्यपि स्थानीय निवासियों द्वारा हाथ से बनायी गयी रस्सी, कुछ जरूरतों की पूर्ति करती है। कुछ उपयोग मीरजापुर, अहरौरा, चुनार व राबर्ट्सगज, के क्षेत्रों में किया जाता है। इस हेतु कुछ घासों का निर्यात डेंहरी आनसोन, डालमिया नगर आदि स्थानों को भी होता है। इस तरह सोनभद्र में कागज उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त सभाव्यता है।
- (7) कम्बल उद्योग पठारी क्षेत्र होने के कारण भेडपालन पर्याप्त रूप मे होता है। चरवाहों द्वारा भेडों का उपयोग दूध के अतिरिक्त बालों से कम्बल बनाने व भेडों के मल मूत्र से खाद बनाने के रूप मे किया जाता है। कम्बल, कुछ चरवाहों के परिवार

स्वय बनाते हैं जबिक कुछ चरवाहे बालों को बेचकर धन अर्जित करते हैं। कम्बल बनाने में दक्षता का अभाव होने के कारण उत्तम कोटि का कम्बल तैयार नहीं हो पाता है, जिससे कम्बलों का बाजार स्थानीय हैं । इन कम्बलों का उपयोग यहाँ के मूल निवासियों द्वारा न केवल शीत ऋतु में होता है वरन् ग्रीष्म ऋतु में भी 'लू' से बचने व 'पूजा' आदि में भी किया जाता है । भेड़ों के मलमूत्र से उत्तम कोटि की खाद बनती है। यहाँ भेड़ों के झुण्ड को 'उर्वरक-कारखाना' कहा जाता है। किन्तु रसायनिक उर्वरकों के कारण इन 'प्राकृतिक उर्वरक कारखानों' का महत्व घटता जा रहा है। खाद के रूप में इसे पुन प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक प्रेरणा से ही सम्भव है। अपनी गुणवत्ता की तुलना में भेड़ों की खाद बहुत सस्ती है।

- (8) रस्सी उद्योग (बकेल) पलास के क्षैतिज जड़ों से निर्मित बकेल मजबूत एव टिकाऊ होती है। यद्यपि इसका उपयोग बारीक कामों मे नही होता है फिर भी पशुओं के बाधने की रस्सी (पगहा, पसेल, खोंचा व छान आदि), कुओं से पानी खींचने की रस्सी (लेजूर), चारपाई कसने की रस्सी, कच्चे मकानों के छाजन आदि घरेलू उपयोग मे किया जाता है। बकेल पलास का जड़ होता है, जिसे अप्रैल से जून माह में 2'-3' तक जमीन में खुदाई करके निकाला जाता है, पुन इसके रेशों को अलग कर लिया जाता है। बकेल से रस्सी बनाने का काम स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय उपयोग के लिये किया जाता है। जनपद सोनभद्र में पलास की अधिकता को देखते हुए बकेल से रस्सी बनाने के काम को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- (9) सींक उद्योग स्थानीय रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 'जूर' से उत्पन्न सीक का उपयोग झपोली, कुरूई व झाड़ू बनाने में किया जाता है। सीक से झाड़ू बनाने का कार्य सोनभद्र व उसके समीपवर्ती क्षेत्र को छोड़कर भारत में कहीं नहीं होता है। झपोली, कुर्छ्इ व झाड़ू सोनभद्रवासियों द्वारा अपने अतिथियों को उपहार में दी गयी विशिष्ट वस्तु मानी जाती है। सींक से निर्मित वस्तुओं को कुटीर व हस्तकला उद्योग के रूप में विकसित करने की पर्याप्त सभावनाए है। एक ऐसा उद्योग जिसमें पूँजी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल श्रम की आवश्यकता है। कृषक अनिभन्नता वस 'जूरों' को समाप्त करते जा रहे हैं।

अत इसे रोकने की आवश्यकता है । थोडी सी रूचि व दक्षता के प्रयोग से सीकों से अनेक कलात्मक वस्तुए बनायी जा सकती है , जो नगरों व महानगरों के भवनों मे सजावटी वस्तुओं के रूप मे प्रयुक्त हो सकती है। इससे न केवल आय मे वृद्धि होगी वरन् कला का भी विकास होगा तथा महिलाओं के रोजगार मे विशेष वृद्धि होगी।

- (10) बास- निर्मित वस्तुए बास से घरेलू उपयोग की अनेक वस्तुए यथा डिलया, दौरी, पखा, सूप आदि का निर्माण विशेषत धरकार व डोम जातियों द्वारा किया जाता है। सोनभद्र मे बास पर्याप्त रूप मे पाया जाता है किन्तु इससे निर्मित वस्तुओं का सम्बन्ध विशिष्ट जाति से होने के कारण विकास कम हो पाया है। जरूरत है इसे कुटीर उद्योग के रूप मे विकसित करने की । डोम, धरकार चलते-फिरते निर्माण केन्द्र के रूप मे कार्य करते है।
- (11) **बासुरी व शहनाई का निर्माण -** सीमित पैमाने पर डोम व धरकार जाति द्वारा किया जाता है। उचित प्रोत्साहन देकर कुटीर उद्योग के रूप मे विकसित कर, इसके बाजार क्षेत्र को राज्य व राष्ट्र स्तरीय बनाया जा सकता है।
- (12) **डफला वाद्ययन्त्र -** इसे धरकार लोग सीमित स्तर पर बनाते है। इसे कुटीर उद्योग के मे विकसित कर, आय व रोजगार के अवसर बढाए जा सकते है।
- (13) चरखा उद्योग दुद्धी तहसील मे 'पनिका' जाति के लोग चरखा का निर्माण करते थे तथा स्वय कपास की खेती कर सूत कातने कपडा बुनने का कार्य करते थे। इस तरह कपडा उद्योग मे वे पूर्णतया आत्मिनर्भर थे। किन्तु मशीनीकृत वस्त्रों के भरमार व इस क्षेत्र मे बड़े उद्योगों की स्थापना से पनिका जाति के लोग पुश्तैनी ध्रधे का परित्याग कर अन्य कार्यों मे लग गये है। वर्तमान समय मे 'गोविन्दपुर आश्रम' के स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के फलस्वरूप आश्रम द्वारा स्वय व उसके आसपास के क्षेत्रों मे सीमित स्तर पर चरखे से कपडा बुनाई का काम किया जा रहा है। इस उद्योग मे रोजगार के पर्याप्त अवसर है। अत कपास की खेती को विकसित कर, चरखा बनाने व उससे सूत कातने तथा कपडा बुनने के उद्योग को पुनर्जीवित करना चाहिए।

- (14) गोदना उद्योग विशेषत अनुसूचित जाति एव जनजाति मे प्रचिलत है। गोदना गोदने का काम 'वादी' जाति के लोग करते है। हाथ-पाव मे गोदना से निशान बनाकर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते है। प्रथम गोदना परिचय पत्र का कार्य करता है। अशिक्षित लोगों मे यह विशेष तौर पर कारगर होता है। गोदना अपने प्रिय की याद व पहचान के रूप मे भी कराया जाता है। दितीय गोदना के निशान लोगों के आभूषण की महत्वाकाक्षा की पूर्ति करते है। तृतीय कहा जाता है कि गोदना से अनेक रोग नहीं होते है। अत यह टीकाकरण के उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। चतुर्थ स्वय मे एक कला है। गोदना के साथ साथ कानो व नाकों मे छिद्र करने की भी प्रथा है। कान व नाक मे छिद्र करने की प्रथा न केवल सोनभद्र मे बल्कि नगरों व महानगरों मे भी सामान्य तौर पाया जाता है। शास्त्रों मे तो नाक व कान छेदने को सस्कार के रूप मे वर्णित किया गया है। 'गोदना' चीनी चिकित्सा पद्धति 'एक्यूपचर' विधि से साम्य रखती है। अत ऐसा लगता है कि गोदना उद्योग प्राचीन काल से ही फल-फूल रहा है। गोदना को समाज मे विशेष मान्यता नहीं है, फिर भी इसके कलात्मक रूप आज भी दर्शनीय है व इसे उद्योग के रूप मे प्रसारित किया जा सकता है।
- (15) कत्था उद्योग कत्था मुख्यत दुद्धी तहसील मे पाया जाता है। दुधिया कत्था की वाराणसी तथा मिर्जापुर मे और साधारण कत्थे की कानपुर मुख्य मण्डी है। इस क्षेत्र मे दोनों प्रकार का कत्था बनता है। सोनभद्र मे कत्था निर्माण उद्योग को और विकसित किया जा सकता है।
- (16) गोंद खैर, धौ, कुर्लू तथा पीपल के वृक्षों से निकाला जाता है। इसकी मण्डी अहरौरा, हाथरस तथा दिल्ली मे है।
- (17) कोरेया मण्डी मे कोरेया शब्द का प्रयोग दोनों प्रजातियों होलोराइना तथा राइटिया के लिए होता है। यह खिलौना बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त लकडी है। इसका निर्यात वाराणसी तथा अहरौरा को किया जाता है। लकडी के निर्यात की जगह सोनभूद्र वासियों द्वारा खिलौना बनवा कर निर्यात करना चाहिए। इस कुटीर उद्योग से आय व रोजगार

मे वृद्धि होगी।

- (18) रेश्वम एव टसर उद्योग रेशम के कीट असना (टर्मिनेलिया अलाटा) शहतूत (मोरस इण्डिका) के वृक्षों पर पाले जाते है जिनसे देश का कोआ प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार टसर के कीट अर्जुन या कहवा (टर्मिनेलिया अर्जुना) के वृक्षों पर पाले जाते है। दुद्धी तहसील मे इसके विकास की पर्याप्त सभावनाए है। असना के वृक्ष कोन रेज मे अधिक पाये जाते है जहाँ पर रेशम विकास विभाग की सहायता से रेशम उत्पादन को बढावा दिया जाना चाहिए। अर्जुन के शुद्ध रोपण टसर उत्पादन के उद्देश्य से किये जा रहे है। ऐसे क्षेत्रों मे टसर के उत्पादन को बढावा देने से स्थानीय निवासियों, आदिवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- (19) रेश्नम कीट पालन एव कोया उत्पादन कीटोण्डों से प्रस्फुटित रेशम कीट अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। इसलिए इस अवस्था में इनके पोषण में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। समस्त कोया की बिक्री उचित दरों पर रेशम विभाग द्वारा करायी जाती है। उचित मात्रा में कर्षण कार्य तथा खाद एवं पानी उपलब्ध कराकर प्रति एकड पत्ती उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। फलस्वरूप कोया उत्पादन में भी वृद्धि अवश्यम्भावी है। इसके अतिरिक्त यदि कृषक अपने उत्पादित कोया से चरखा द्वारा धागाकरण प्रारम्भ कर दे तो उनकी आय बढ जायेगी। वयोंकि प्रति 10-12 किलोग्राम कोया से लगभग । किलोग्राम रेशम धागा प्राप्त होता है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 450-550 रू0 प्रति किलोग्राम है।
- (20) मधुमनखी पालन उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रकाशित एव प्रचारित पुस्तक 'मधुमनखी पालन उद्योग' से मौन पालन सम्बन्धी सिक्षप्त रूप रेखा प्रस्तुत है जो कि इस क्षेत्र के आदिवासियों व स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण लघु उद्योग के रूप मे विकसित किया जाता है । इस जनपद मे अनेक उगाई जाने वाली एव जगली वनस्पतिया ऐसी है, जो मधुमिनखयों के लिए उपयोगी है, जिनका विवरण इस प्रकार है जामुन, तुन, रीठा, जकरेन्डा, खेर, दालचीनी, वाटल बुश, आवला, सहजन, नीम, इमली, कचनार साल, अर्जुन, जगली जलेबी, जगली बेर तथा अमरूद आदि ।

5 4 ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों का महत्व

बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का जीवन स्तर ऊपर उठाने, आर्थिक विषमता को कम करने एवं बढ़ती शहरी करण की समस्या के समाधान का एकमात्र विकल्प हैं - ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का विकास । तेजी से बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या को कृषि-क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर को देखते हुए सबको काम नहीं दिया जा सकता । इन उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यहीं है कि प्राकृतिक रूप से श्रमिकों को अपने अनुकूल वातावरण में कार्य मिल जाता है। जिससे आन्तरिक सुख प्राप्त होता है। उनके सामर्थ्य, इच्छा, और रूचि के अनुरूप तथा व्यक्तिगत योग्यता एवं प्रवृत्ति के अनुसार व्यवसाय चलाने की सम्भावना भी बन जाती है। अध्ययन क्षेत्र में कच्चा माल, स्थानीय योग्यता और स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र में श्रम के बाहुल्य तथा पूंजी के अभाव को देखते हुए कुटीर उद्योगों का बहुत अधिक महत्व है। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का महत्व किन्न तथ्यों के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है।

- । गाँव के कच्चे माल पर आधारित ग्रामीण एव कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त है।
- 2 ग्रामीण क्षेत्रों महन उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर अर्द्ध बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- 3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आय स्तर को सुधारने हेतु क्षेत्रीय प्राकृतिक और मानवीय संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है।
- 4 इन उद्योगों की स्थापना से बहुसख्यक ग्रामीणों की क्रय शक्ति में सुधार होगा, फलस्वरूप उद्योगों पर आधारित वस्तुओं की माँग में वृद्धि होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा ।

- 5 ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों की स्थापना करके गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोका जा सकता है।
- 6 इन उद्योगों से कृषि एव उद्योगों के सहयोग से सतुलित विकास की प्राप्ति हो सकेगी ।
- 7 ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों की स्थापना से कुछ सीमा तक उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है ।
 - 8 धन एव आय की असमानता को समाप्त किया जा सकता है।
- 9 ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों से शिष्ट्रातिशीघ्र उत्पादन किया जा सकता है क्योंिक इसमे तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता होती है और इन्हे यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जा सकता है।

5 5 औद्योगिक समस्याएँ

अध्ययन क्षेत्र मे बड़े उद्योगों मे जहाँ प्रबन्धन की प्रमुख समस्या है वहीं लघु एव कुटीर उद्योगों मे ससाधनों तथा कित्तीय अनुपलब्धता की समस्या है। जब तक सभी उद्योगों के समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक समन्वित औद्योगिक विकास नहीं किया जा सकता। चुर्क एव डाला मे स्थित सीमेट कारखाने की समस्या उसके निजी क्षेत्र मे हस्तान्तरण के प्रस्ताव से उत्पन्न हुयी थी। श्रमिकों एव कर्मचारियों के हडताल से कई वर्ष उत्पादन शिथिल रहा। सरकार द्वारा इसे निजी क्षेत्र मे हस्तान्तरण का प्रमुख कारण 'घाटा' बताया गया था। किन्तु उचित प्रबन्धन तथा ससाधनों की समुचित आपूर्ति से इस घाटे की समस्या को समाप्त किया जा सकता है।

चूँकि सभी कोयला क्षेत्र केन्द्र सरकार के अधीन है, इसलिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) के अन्तर्गत आने वाले ताप विद्युत गृहों (रिहन्द नगर तथा सिगरौली

सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन) को उत्तम कोटि का बिट्यूमिनस कोयला प्रदान किया जाता है, जबिक राज्य सरकार के अधीन अनपरा एव ओबरा ताप विद्युत गृह को सब-बिट्यूमिनस कोयले की आपूर्ति की जाती है । राष्ट्रीय हित में इस तरह की समस्याओं को कम किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के रेणूसागर ताप विद्युत गृह को भी उच्च मूल्य पर बिट्यूमिनस कोयले की आपूर्ति की जाती है । ओबरा ताप विद्युत गृह में कोयले की उचित मात्रा सही समय पर न पहुँचने से प्राय बहुत कम विद्युत उत्पादन होता है । अध्ययन क्षेत्र में उर्जा के वृहद् स्रोत होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहुत कम होती है, जिससे लघु उद्योग सबसे अधिक प्रभावी होता है। कुटीर व ग्रामीण उद्योग भी बिजली की अनुपलब्धता से सौर्य प्रकाश पर ही निर्भर करते है। इससे दस्तकारों व श्रमिकों का समय नष्ट होता ही है, समुचित उत्पादन भी नहीं हो पाता है।

परिवहन के साधनों का अभाव लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास में सबसे बडी बाधा है। इसके अभाव में इन उद्योगों का बाजार से सम्पर्क नहीं हो पाता है जिससे उचित मूल्य मिलने में एवं औद्योगिक उत्पादों के प्रसार में बाधा पहुँचती है। नयी टेक्नालॉजी का अभाव व पूँजी का अभाव अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक गित को अवरूद्ध कर रहे हैं। पूँजी के अभाव में अनेक बेरोजगार युवक कुटीर एवं लघु उद्योग नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। इसके अभाव में अध्ययन क्षेत्र के संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। फलत इस क्षेत्र के संसाधनों से अन्यत्र औद्योगिक विकास हो रहा है। उदाहरणार्थ तेंदू पत्ते की प्रचुरता के बावजूद बीडी उद्योग का विकास नहीं हो पाया है। धान की प्रचुरता के बावजूद चावल मिल की स्थापना नहीं हो पायी है।

उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र में जो भी उद्योग है, वे सार्वजनिक क्षेत्र तथा बाहर के बड़े-बड़े पूँजीपितयों के हाथ में है। इस क्षेत्र के लोगों के पास श्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अत यदि इस समस्या पर समय से ध्यान नहीं दिया गया तो स्थानीय लोगों का असन्तोष विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित होगा। उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी न होना विपणन के लिए सड़कों एवं बाजार का अभाव तथा कुछ सरकारी नीतिया अनेक रूपों में औद्योगिक समस्याए उत्पन्न कर रहीं है।

इसके अतिरिक्त वृहद् उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण स्थानीय लोगों की प्रमुख समस्या है। डाला मे यह लोकोक्ति प्रचलित है कि 'सीमेट के लिए कारखाने मे मत जाओ बिल्क किसी पेड को हिला दो पर्याप्त सीमेट मिल जायेगा।' इसी प्रकार सोनपार के क्षेत्रों मे यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 'सरकार सबसे अधिक धूमपान की सुविधा दी है जिसका पैसा भी नहीं लेती हैं'। इन लोकोक्तियों से अध्ययन क्षेत्र मे उद्योगजनित समस्याओं का चित्र उभडता है। वास्तव मे हमारी सम्पूर्ण विकास नीति द्वद मे फस गयी है। उद्योगों की स्थापना एव विकास की समस्या को दूर करने के लिए जहाँ अनेक योजनाए व नीतिया है, वहीं उद्योग जनित समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी नीतियों का सर्वथा अभाव है।

5 6 औद्योगिक समाव्यता एव विकास नियोजन

अध्ययन क्षेत्र मे खिनज ससाधन तथा वन ससाधन की प्रचुरता को देखते हुए अनेक नये उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। कृषि उपजो को संशोधित करने हेतु अनेक उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है। वनस्पितयों तथा जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धित को सुद्धढ बनाया जा सकता है। अनेक प्रकार के पत्थरों, क्रिस्टलों तथा ककड़ों से उपयोगी वस्तुए बनायी जा सकती है। वर्तमान मे बड़े उद्योगों पर आधारित उनके सह - उत्पाद से कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। अध्ययन क्षेत्र मे कुछ ऐसे औद्योगिक उत्पादों की आवश्यकता है जिसे स्थापित करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के वर्तमान औद्योगिक स्वरूप के वर्णन से स्पष्ट है कि बड़े उद्योगों का पर्याप्त विकास हो चुका है। किन्तु लघु एव कुटीर उद्योगों की स्थापना की पर्याप्त आवश्यकता है जिससे कुटीर, लघु व बड़े उद्योगों तथा कृषि एव उद्योगों मे सह-सम्बन्ध स्थापित हो सके। अध्ययन क्षेत्र मे पर्यटन उद्योग के विकास की पर्याप्त सभाव्यता है। क्योंकि यहाँ प्राचीन किलों, मन्दिरों, जल प्रपातों, नदी-नालों, पर्वतो की सुरम्य घाटियों, बड़े बड़े झीलों जलाशयों तथा उद्योगों की अधिकता है।

(अ) पर्यटन उद्योग

अध्ययन क्षेत्र में सडकों की सुदृढ व्यवस्था, होटलों का निर्माण व पर्यटक स्थलों का पुनरूद्वार करके पर्यटन उद्योग को उच्च स्तर पर विकसित किया जा सकता है। मारकुण्डी मोड की घुमावदार सडकों से सलग्न पहाडिया तथा घाटिया, गोविन्द वल्लभ पन्त सागर की प्राकृतिक छटा तथा घघरोल, नगवा व सिलहट बाध किसी भी पर्यटक को आकृष्ट्

करने में सक्षम है। इन जलाशयों में नौकायन की व्यवस्था करके पर्यटकों को लुभाया जा सकता है। सभी ताप विद्युत, जल विद्युत, सीमेट उद्योग तथा अल्यूमिनियम उद्योग को सीमित पैमाने पर पर्यटकों को देखने के लिए छूट देने पर पर्यटन उद्योग को और विस्तृत किया जा सकता है। पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए प्राकृतिक स्थलों के अतिरिक्त ऐतिहासिक स्थल महत्वपूर्ण स्थान रखते है। अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों, गढ, किला, मन्दिरों आदि दा विवरण निम्न प्रकार है।

(।) विजयगढ़ किला

राबर्टसगज से 15 किमी0 दक्षिण पूर्व मे है। यह किला काशी नरेश राजा चेत सिंह के अधिपत्य में अग्रेजों के आने के समय तक रहा है । यह किला चारो ओर से दीवारों से घिरा है, जिस पर तोपची निशाना लगाए बैठे रहते होंगे। किले के मुख्यद्वार को सीढियों से जोडा गया था जो अब टूट चुकी है। कहते है कि यह तिलस्मी किला है तथा इसके नीचे भी एक किला छिपा है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है।

मुख्य द्वार से आगे बढ़ने पर रानी का महल है। रानी के महल में पत्थर की कलात्मक कलाकारी की गयी है। मजार के चारों ओर अब दीवार बनायी जा रही है जिसमें चुने दो पत्थरों को देखने से पता चलता है कि वहाँ एक शिला पर कुछ लिखा है जो हिन्दू परम्परा तथा धर्म से सम्बन्धित है। इस मकबरे के पास एक बड़ा तालाब है जिसका पानी साफ है। आगे चलकर राम सागर तालाब है। इसके साथ ही राजा का महल है। खिड़की का दरवाजा बन्द कर दिया गया था जिसे फिर खोलकर उधर से चढ़ने उतरने का रास्ता बनाया गया है। रास्ते में एक गणेश की प्रतिमा है। वर्तमान में गर्मी के दिन में यहाँ पर मेला लगता है। किले की मरम्मत करके तथा वहाँ तक पक्का मार्ग बनाकर विदेशी पर्यटकों को भी आकृष्ट किया जा सकता है। इसके पास ही में 'केमूर वन्यजीव विहार' भी है।

(2) अगोरी गढ़

राबर्टसगज से 25 किमी0 दक्षिण, चोपन से 7 किमी0 पश्चिम, अगोरीगढ़ का भग्नावशेषरेड, विजुल एव सोन नदी से पिरा है। इस किले में कहावत के अनुसार बहुत सम्पदा है एव यह भी तिलस्मी किला है । मोलागत राजा से लोरिक का युद्ध यहीं पर हुआ था। इस किले मे देवी दुर्गा की कलात्मक मूर्ति आगन के द्वार पर है। कोठिया एव छत गिरते जा रहे है । यहाँ एक कुओं है जो बहुत गहरा है तथा सोन नदी से इसका सम्बन्ध बताया जाता है । यहाँ भी दुर्गा जी की एक कलात्मक मूर्ति स्थापित है । यहाँ पर देवी की पूजा करने लोग दूर-दूर से आते है । दुर्ग को चारों ओर से नालों तथा खाई से सुरक्षित किया गया है दुर्ग से निकलने पर एक गेरूआ पहाड दिखता है, लोग कहते है इस पहाड पर लाखों वीरों की तलवार की धार उतारी गयी थी । सोननदी की धारा मे एक हाथी की शक्ल का पत्थर है इसे लोग मोलागत राजा का कमिनल हाथी बताते है जो लोरिक द्वारा मारा गया था।

- (3) सोढ़री गढ़ घोरावल से आठ कि0 मी0 उत्तर पश्चिम मे शिवद्वार मन्दिर के पहले यह दुर्ग भग्नावशेष के रूप मे मौजूद है । इसके चारो ओर गहरी खाई है । इसकी खुदाई मे बहुत सी मूर्तियाँ मिली है जिनमे से कुछ खिण्डत है जो शायद मुगल काल मे तोड दी गयी होगी । यहाँ गहडवाल राजाओं का कभी राज्य था ।
- (4) शिवद्वार राबर्ट्सगज से 30 कि0 मी0 घोरावल से 8 कि0 मी0 पश्चिम उत्तर मे शिवद्वार गाँव से 1 5 कि0 मी0 पहले ही शिवद्वार का शिव मन्दिर है । इस मन्दिर मे शिव पार्वती की सृजन की एक काले पत्थर की करीब तीन फीट की प्रतिमा है । इसका मूल्य आजकल करोड़ों में आका जाता है । इसी के समीप भग्न अन्य मूर्तियाँ भी है । कलात्मकता की दृष्टिट से ये मूर्तियाँ महत्वपूर्ण है ।
- (5) गौरी श्वकर राबर्ट्सगज से करीब 7 कि0 मी0 उत्तर यह मूर्ति घोरावल रोड पर एक खुले मन्दिर में स्थित है । पचमुखी, गौरीशकर, कन्डाकोट तथा रौप के मन्दिर के शिविलग' चारों दिशाओं में स्थित तथा एक ही काल के राजा के एक ही कारीगर द्वारा बनाये गये है।
- (6) दिधया नाला एक प्राचीन मन्दिर मऊ गाँव के आगे धधरौल बाध से करीब 4 कि0 मी0 पर स्थित है । इसकी शिवलिंग करीब । 5' से 2' व्यास का 3' ऊँचा है । इसी मन्दिर के साथ खुले मे दो और शिवलिंग है जो एक ही मोटाई तथा ऊँचाई के है एक पर सहस्रनाग

की प्रतिमाए बनी है । सहस्रनाग शिवलिंग का भग्नावशेष शिवद्वार में भी देखा गया है परन्तु वह करीब एक फीट का ही है । यहाँ पर काले पत्थर की एक अष्टभुजी की प्रतिमा है।

- (7) कण्डाकोट राबर्ट्सगज से दक्षिण पश्चिम कोण पर लगभग 12 कि0 मी0 की दूरी पर यह दुर्ग स्थित है । इसके प्राचीर ध्वसावशेष है । यहाँ पर कण्डेश्वर महादेव का मन्दिर तथा कई गुफाए है, जहाँ पर शैलाश्रित गुहा चित्र देखे जा सकते है । दुर्ग के चारों ओर खाई तथा हरे जगल है । शिवरात्रि एव बसत पर यहाँ मेला लगता है । यहाँ से दो कि0 मी0 पर कुड़ारी देवी का मन्दिर एव गुफाएँ है ।
- (8) द्वार षाटी श्रिवमुफा डाला से ओबरा जाने वाली सडक पर रेलवे फाटक से एक कि0 मी0 बींये, पहाडी पर स्थित यह गुफा हाल ही मे ज्ञात हुई है । कहते है कि स्टोन क्रशर को लगाते समय , इस गुफा का उद्भव हुआ । करीब 15 मीटर लम्बी इस गुफा के साथ अन्य गुफाए भी जुडी मालूम पडती है । जिसके अन्तिम छोर पर एक नन्दी-नुमा तथा दो पत्थर लम्बे आकार के गोल पत्थर, इन्हे शिव तथा पार्वती का रूप माना जाता है, विद्यमान है । विशेष बात यह है कि यहाँ पर बहुत सी चट्टाने लटकी पडी है, परन्तु किसी से धात्विक ध्विन नहीं आती है । केवल एक ही ऐसा पत्थर है जिसे हाथ से ठोकने पर उमडम की धात्विक ध्विन आती है । इसी से प्रतीत होता है कि आदिकाल मे शिव की आराधना यहाँ के लोग करते रहे होंगे और उसी के लिए इस प्रकार के स्थान का चुनाव करके शिव प्रतिमा, नन्दी आदि स्थापित किये होंगे । यहाँ के पत्थर पानी गिरने से अनोखे प्राकृतिक रूप धारण कर लेते है जो पर्यटक का मन मोह लेते है । सरकार द्वारा यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है जबिक इस प्रकार का स्थान कदाचित ही मिलता है ।
- (9) बरकन्हरा शिवद्वार मार्ग से 5 कि0 मी0 तथा घोरावल से 13 कि0 मी0 पर बरकन्हरा गाँव स्थित है । यहाँ पर एक पाकड के पेड के नीचे छोटे मन्दिर मे माँ अष्टभुजी की काले पत्थर की करीब 3 फीट ऊँची प्रतिमा है जो ऐसा लगता है कि उसी काल की बनी है जब शिवद्वार की शिव पार्वती की प्रतिमा बनायी गयी होगी । भगवान विष्णु की सफेद पत्थर की । 5 फीट की बहुत सुन्दर प्रतिमा भी मिली है । इसे वही स्थापित करने हेतु मन्दिर का निर्माण हुआ है । उसकी कीमत लगभग डेढ़ से दो करोड़ तक आकी गयी है ।

(10) ज्वाला देवी - सुदूर दक्षिणाचल में राबर्ट्सगज से करीब 140 कि0 मी0 पर यह स्थान है । यहाँ पर ज्वाला देवी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है । यहाँ बस द्वारा जाया जा सकता है । मन्दिर के पास ही । कि0 मी0 पहाडी पर गुफा है, जिसमें प्राचीन कलाकृतिया बनी है । मदिर के द्वार पर अष्टभुजी की काले पत्थर की सुन्दर प्रतिमा दर्शनीय है ।

इसके अतिरिक्त मुखादरी, किडिया ताल - अगोरी किले की देवी, अमिला भवानी, मच्छरमारा भवानी एव औढी महाबीर आदि की प्रतिमाए प्राचीन एव दर्शनीय है । साथ ही रेनूकूट मे बिडला द्वारा नया स्थापित रेणुकेश्वर महादेव का मिन्दर, देवी सम्पदा मडल का राधा - कृष्ण मिन्दर एव ओबरा का गीता मिन्दर आदि अत्यन्त सुन्दर है जो पर्यटको का मन मोह लेते है । अध्ययन क्षेत्र मे अनेक मुफाए व प्रपात है । इनका अति सिक्षिप्त विवरण निम्न है -

- (11) ओबरा गुफा- ओबरा मे पानी हेतु टकी तथा पाइप लाइन बिछाने का कार्य चलते समय ये गुफाए मिली । वैसे तीन गुफाये स्पष्ट दिखाई देती है । प्रमुख गुफा गरीब 20' गहरी 10' ऊँची तथा 20' चौडी है जिसको देखने से यह प्रतीत होता है कि जब भौगर्भिव हलचल या भूकम्प आया होगा तो कठोर चट्टानो के चटकने से इनका निर्माण हुआ होगा ।
- (12) मुखादरी जल प्रपात जनपद में सबसे सुन्दर जल प्रपात मुखादरी है जो शिवद्वार से करीब 8 कि0 मी0 पिश्चम में बेलन नदी पर स्थित है । बीच रास्ते में कडिया ताल है जिसे विकसित कर झील का रूप दिया जा सकता है, जहाँ नौका बिहार एव होटल, पर्यटक दृष्टि से प्राभावी होगा । मुखा-दरी की गुफाओं में बहुत से शैलाश्रित गुहा चित्र है जो प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण है । यहीं देवी की प्रतिमा तथा मन्दिर है ।
- (13) हाथीनाला जल प्रपात -यह राबर्ट्सगज से करीब 60 कि0 मी0 दक्षिण- पूर्व मे दुद्धी मार्ग पर अग्रेजों द्वारा निर्मित कृत्रिम प्रपात है । यहाँ पर ठहरने के लिए 'हट' भी निर्मित है जिसका उपयोग पर्यटकों के लिए किया जाता है । इससे करीब 35 कि 0 मी0 पर म्योरपुर के पास नदी मे भी एक प्रपात दर्शनीय है ।
- (14) पेड के कटे तने पत्थर हो गए राबर्ट्सगज पिपरी मार्ग पर सलखन नामक स्थान पर मुख्य मार्ग से । कि0 मी0 पश्चिम गरगजवा पहाड़ी है । यहाँ पर पेड के कटे तनों की आकृति

की चट्टाने अभी हाल ही मे पायी गयी है । इसके विषय मे कहा जाता है कि इस पेड के कटे तने लगभग डेढ अरब वर्ष पुराने है जो कालान्तर परत-दर-परत चढने पर पत्थर की आकृति मे परिवर्तित हो गए ।

(ब) चिकित्सा उद्योग

अध्ययन क्षेत्र मे चिकित्सा उद्योग विशेषत अपूर्वेदिक चिकित्सा के विकास की पर्याप्त सभाव्यता है । सोनभद्र मे ऐसे अनेक पेड-पौधे तथा जडी-बूटियाँ है जिनका प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है । इस क्षेत्र के वनस्पतियों, जडी-बूटियों, वैद्यों के अनुभव तथा कुछ आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धित मे साम्य बैठाया जाय तो अनेक असाध्य रोगों की भी दवा की जा सकती है । वास्तव मे उत्तम स्वास्थ्य विवास का एक प्रमुख लक्षण है। कुछ प्रमुख जडी-बूटियों तथा वनस्पतियों के औषधीय गुण निम्न है, जिनहे पहचानने, प्रयोग करने एव प्रसारित करने की महती आवश्यकता है ।

- । कुचिला अगोरी के पास गोठानी क्षेत्र में पर्याप्त रूप में मिलता है। इससे निर्मित दवा वायुविकार में प्रयोग की जा सकती है।
 - 2. गुरूचि यह एक प्रकार की लता है जो बुखार में प्रयुक्त होती है।
 - 3. पथर चट्टी धातु सम्बन्धी समस्त रोगों मे गुणकारी होती है ।
 - 4. गदह पुरना पीलिया रोग की अमोघ दवा है ।
 - 5. हड़-जोड़ टूटी हुई हड्डी को जोडने के काम में आता है।
- 6. धतूर की पत्ती इसे गर्म सरसों के तेल मे डालकर, बरसात के मौसम मे सडी र्रेगुलियों मे लगाया जाता है । इसका दूध दर्द-निवारक है ।
 - 7. नीम का तेल चर्मरोगों मे प्रयुक्त होता है।
- 8. महुआ का तेल अध्ययन क्षेत्र में इसे डोरी का तेल भी कहते है । इसका प्रयोग शुष्क अगों को मुलायम बनाने तथा सदी-जुकाम मे होता है । महुआ का वृक्ष सर्वत्र विद्यमान है ।
- 9. कूटज इसका वृक्ष कर्मनाशा नदी के किनारे बडी सख्या मे पाया जाता है। यह पेचिस के रोग में उपयोगी होता है।

- 10. कहवा (अर्जुन) इसकी छाल को दूध में पकाकर सेवन करने से हृदय रोग कभी भी नहीं हो सकता । यह सोनभद्र के सभी विकास खण्डों में पाया जाता है । इसके वृक्ष म्योरपुर, बभनी, नगवा व चोपन में अधिक सख्या में पाये जाते हैं ।
- आँवला ऑवला मे अनेक औषधीय गुण होते हैं । इससे च्यवनप्राश,
 त्रिफला का चूर्ण आदि बनाया जाता है । ऑवला आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धित का आधार है।
- 12. हर्र (हरण) इसके बारे में कहा जाता है कि माता कुपित हो सकती है किन्तु हर्र का सेवन मिथ्या नहीं हो सकता । हर्र का चूर्ण पाचक होता है तथा खासी की उपयुक्त दवा है।
- 13. **बहेरा -** यह त्रिफला का घटक है तथा कफ निस्सारक है । हर्र व बहेरा के वृक्ष पर्याप्त पाए जाते है ।
- 14 कचनार गलगड रोग मे प्रयुक्त होता है । फरवरी मार्च मे इसका फूल देखने योग्य होता है । इन फूलों का प्रयोग सब्जी के रूप मे भी होता है ।
- 15 चिरौंजी पियार' का फल खाने में स्वादिष्ट होता है तथा इसकी गुठली से चिरौंजी निकाली जाती है । चिरौंजी पीस कर बच्चों को लगाने से, चर्मरोग नाशक तथा हड्डी को मजबूत करने वाला होता है ।
- 16 मिलावा इसका प्रयोग रासायनिक दग्ध (केमिकल काटराइज) के रूप में किया जाता है । इन क्षेत्रों में लोग इससे त्वचा को दागकर (जलाकर) रोगों को दूर करते है ।
- 17 करवन इसका न केवल फल खाया जाता वरन् इसके जड को पीसकर, ज्वर मे पीने से ज्वर समाप्त हो जाता है।
- 18 खादिर (खैर) इससे कत्था बनाया जाता है । खादिर रक्तशोधन, कुष्टरोग तथा खासी मे प्रयुक्त होता है ।
- 19 पलास के बीज का प्रयोग मनुष्य एव जानवरों के उदर में कृमि नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- 20 सतावरी दूध व शक्ति बढाने के लिए विशेषत जानवरों को पीस कर पिलाया जाता है।
- 21. लिसोड़ा इसके पत्ते का काढ़ा बनाकर पीने से खासी जुकाम समाप्त हो जाता है।

- 22 शिवनाक दस्तावर के रूप मे प्रयोग किया जाता है।
- 23 जगली जानवरों के हड्डी, चमडा, सींग तथा अनेक जडी बूटियों व पत्थरों का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है ।

(स) प्रस्तर उद्योग

अध्ययन क्षेत्र मे विभिन्न प्रकार के प्रस्तर (पत्थर) पाए जाते हैं । इन पत्थरों से पेन्ट, भवन निर्माण सामग्री तथा मूर्तियों का निर्माण, ग्रामीण एव कुटीर उद्योग के रूप में किया जा सकता है । इन पत्थरों का उपयोग करने के लिए सरकार को छूट या लाइसेंस देने की आवश्यकता है । इस क्षेत्र के पत्थरों से कुटीर उद्योग के रूप में निम्न वस्तुए बनायी जा सकती है ।

- हरे रग का पत्थर इसे पीस कर हरा रग तैयार किया जा सकता है।
- 2. रॉक एव केल्श्रियम क्रिस्टल यह पहाडियों मे बहुतायत रूप मे है । इससे 'नग' एव अन्य आभूषण बनाया जा सकता है । इससे न केवल धनार्जन होगा वरन् एक विशिष्ट कला का भी विकास होगा ।
- 3. रेड ऑक्साइड (गेरू) पेन्ट के रूप में इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जा रहा है । प्रागैतिहासिक कालीन चित्र इसी से पेन्ट किए गए थे जो आज तक अपनी अमिट छाप छोड़ रहे है । गेरू की रगाई से जग नहीं लगता है । अत गेरू से रग एवं पेन्ट बनाने का काम लघु एवं कुटीर उद्योग में विकसित किया जा सकता है । शहरों में गमलों एवं गाँवों में दीवालों की रगाई (पुताई) गेरू से ही किया जाता है । उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र में गेरू बहुतायत में उपलब्ध है ।
- 4. चाइना क्ले (चीनी मिट्टी) यह दुद्धी क्षेत्र में प्रचुर रूप में उपलब्ध है चुनार की तरह यहाँ भी चीनी मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने का लघु एवं कुटीर उद्योग प्रारम्भ किया जा सकता है । इस उद्योग को विकिसत करने की प्रमुख समस्या दक्ष कारीगरों को आकृष्ट करने की है।
- 5 मोरन इसका वितरण सर्वत्र है । इसका उपयोग रग व पेन्ट बनाने में किया जा सकता है ।
- 6. सबमरमर यह दुन्ही व शिक्तनगर क्षेत्र मे पाया जाता है । यहाँ का सगमरमर उत्तम कोटि का नहीं है, फिर भी फर्स बनाने व मुजैक के रूप मे प्रयोग किया जा

सकता है । इन्हे श्रमिकों व कारीगरों द्वारा उपयुक्त आकार देने की आवश्यकता है ।

7 चूना पत्थर - कैमूर पहाडी के दक्षिणी भाग मे, बसुहारी क्षेत्र मे चूना पत्थर के विशाल भण्डार है । यहाँ सीमेण्ट उद्योग के रूप मे एक बडा उद्योग तथा चूना उद्योग के रूप मे लघु उद्योग स्थापित किया जा सकता है । इससे उद्योगविहीन एव पिछडे विकासखण्ड नगवा मे विकास की लहर दौड जाएगी है ।

- 8 अध्ययन क्षेत्र के लाल एव बलुआ पत्थर से 'पटिया' बनाने की पर्याप्त सभावना है । उचित प्रोत्साहन देने पर चुनार की तरह 'घटिया' निर्माण का केन्द्र हो सकता है ।
- 9 पहाडी निदयों मे बिखरे पत्थरों को कुटीर उद्योगों मे तराशकर मूर्तियाँ, अलकारिक वस्तुए, 'पेपर वेट' व अन्य उपयोगी वस्तुए बनायी जा सकती है ।

(द) हस्तकला उद्योग

इस प्रकार के उद्योगों में ऊनी दरी, चादी के आभूषण, पत्थर के आभूषण, म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेट्स, बेंत, बास व लकडी के खिलौने, फैन्सी आइटम, जरी, पीतल के बर्तन तथा अन्य उत्कृष्ट उत्पादों के विकास की पर्याप्त सभावनाए है।

(य) खादी तथा हैण्डल्म उद्योग

सूती तथा ऊनी कपड़े, पाली खादी, बनारसी साडी, सिल्क साडी तथा खादी ग्रामोद्योग द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तन, काष्ठ कला, लौंह कला तथा चर्मशोधन के इकाईयो को स्थापित करने की आवश्यकता है।

(र) कृषि आधारित उद्योग

खाद्य तेल मिल, दाल मिल, चावल मिल, आटा मिल, गन्ना मिल, फल सरक्षण, पोल्ट्री फार्म, डेयरी उद्योग, मकई एव रागी का प्रशोधन आदि के लिए उद्योगों को स्थापित करने तथा औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि की आवश्यकता है ।

(ल) वन आधारित उद्योग

बीड़ी उद्योग, माचिस उद्योग, फर्नीचर, अगरबत्ती, कत्था निर्माण, गोंद और रेजिन निर्माण, लाख निर्माण, कागज के प्याले, पित्तियों के प्याले व तश्तरी, खस की टट्टी, झाड़ू निर्माण, वनोत्पाद का सग्रह, प्रशोधन और पैकिंग आदि उद्योगों का विकास किया जा सकता है।

(व) फाइवर आधारित उद्योग

इस प्रकार के उद्योगों में हथकरघा उद्योग को छोडकर होजरी, नायलान के मोजे, इम्ब्रायडरी जूट के उत्पाद आदि सम्मिलित है । इन उद्योगों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाए है ।

(श) रासायनिक तत्वों पर आधारित उद्योग

डिटर्जेन्ट सोप, चमडे के सामान, रबर एव रैक्सीन के सामान, पी0वी0सी0 पाइप, कैन्डिल, मोम पर आधारित उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन, हेयर आयल, ग्लास केयर आदि उद्योगों के विकास की पर्याप्त सम्भावना तथा आवश्यकता है।

(ष) खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग

पाटरी, स्टोन क्रेशर, सीमेट जाली, सीमेट पाइप, पत्थरों पर नक्कासी, प्लास्टर आफ पेरिस की मूर्तियाँ, वाशिंग पाउडर, डिस्टेम्पर, इस्टेन्सिल केमिकल, टाइल्स, स्लेट, पेन्ट, रजक आदि उद्योगों के विकास की आवश्यकता है।

(ह) सामान्य इंजिनियरिंग उद्योग

इस प्रकार के उद्योगों मे विद्युत सामान, स्टील ट्रक, अल्यूमिनियम ईगाट, कांटेदार तार, आटो रिपेयरिंग, डिजल इजन रिपेयरिंग आदि उद्योग आते हैं, जिनके विकास की आवश्यकता है।

औद्योगिक नियोजन में केवल उद्योगों के स्थापना पर ही विशेष बल देना उपयुक्त नहीं है । उद्योगों की स्थापना के साथ - साथ पर्यावरण सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्कयता है । मनुष्य एव पर्यावरण के बीच सतुलन वृहद् उद्योगों के कार्यसूची का प्रमुख विषय होना चाहिए । सभी उद्योगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए । उच्च क्षमता वाले 'इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर', चिमनी से निकलने वाले धुए

मे व्याप्त कणों की रोकथाम के लिए लगाया जाना चाहिए । चिमनी की ऊँचाई अधिकतम होनी चाहिए । जिससे प्रदूषण का प्रभाव कम हो । विभिन्न परियोजनाओ को स्वय वृक्षारोपण कराना चाहिए । यद्यपि ओबरा, अनपरा, रेणूसागर, शक्तिनगर एव रिहन्द नगर मे व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है ।

सयन्त्र से निष्कासित रॉख को सावधानी पूर्वक 'एश बैंक' मे जमा करना चाहिए। इन रॉखों से ईंट निर्माण उद्योग की स्थापना की जा सकती है । इन रॉख क्षेत्रों को अवाछनीय क्षेत्र समझा जाता है, इसलिए इसे हरित क्षेत्र मे परिवर्तित करने के लिए शोध की आवश्यकता है । यद्यपि रामागुडम सुपर थर्मल पॉवर परियोजना के राख क्षेत्रों मे यूकेलिप्ट्स ग्लोब्युलस, अकेसिया औरीक्यूलीफोरिमस, इपोमिया कारनोसा और न्यूसीना ग्लोका आदि प्रजातियो का सीमित स्तर पर रोपण किया जा रहा है ।

उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा सभी औद्योगिक आवश्यकताओं को एक ही छत के नीचे पूर्ति के लिए सरकार ने 1977 में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम की शुरूवात की थी। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय पर 'विकासखण्ड उद्योग केन्द्र' के स्थापना की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक सभाव्यता बहुत अधिक है जिसे एक केन्द्र (राबर्ट्सगज) से पूरा करना असम्भव है। अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास के अवरूद्धता का प्रमुख कारण वित्तीय एव तकनीकी अनुपलब्धता है। अत इसे सरकारी प्रोत्साहन, ऋण तथा छूट आदि से समाप्त करने की आवश्यकता है। कुशल कारीगरों तथा दस्तकारों को आकृष्ट करके लघु एव कुटीर उद्योग में परिमाणात्मक एव गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

5 7 प्रस्तावित उद्योग

अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक सभाव्यता वे वर्णन से स्पष्ट है कि कुछ उद्योगों को सस्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है । प्रत्येक विकासखण्ड मे निम्न प्रस्तावित उद्योग है ।

राबर्ट्सगज - चावल मिल, फर्निचर, स्टोन ग्रिट्स, चर्मशोधन, चूना, जनरल इंजिनियरिग टायर रिट्रेडिग, आटो मोबाइल सर्विसिग, साबुन, फिनायल, वगगज/दफ्ती आदि के कारखाने स्थापित करने की आवश्कता है।

घोरावल - आरामशीन से लकडी की चीराई, फर्निचर, बास की टोकरी, बीडी उद्योग, चर्मकला, बेकरी, तेल मिल, ईंट भट्टा तथा जनरल इंजिनियरिंग आदि ।

चोपन - स्टोन ग्रिट्स, चूना, मुजैक टाइल्स, आर० सी० सी० पाइप, सेनेटरी फिटिग्स, बीडी, साबुन, फिनायल, चर्मकला तथा जनरल इंजिनियरिंग आदि ।

नगवा - सीमेट उद्योग, चूना, बीडी, दाल मिल, तेल मिल, चावल मिल, दियासलाई साबुन, क्राफ्ट पेपर तथा स्ट्रावोर्ड आदि ।

चतरा - चावल मिल, ईंट, स्टोन ग्रिट्स, हथकरघा, आइसकै ण्डी, बेकरी, साबुन तथा फिनायल आदि ।

दुढ़ी - कत्था उद्योग, रस्सी उद्योग, तेल उद्योग, आरामशीन व लकडी के फर्निचर, बीडी, कागज व स्ट्राबोर्ड, दियासलाई, स्टोनग्रिट्स, कालीन व दरी, कृषि यन्त्र तथा तेल मिल आदि ।

म्योरपुर - कत्था उद्योग, दियासलाई की तिली, स्टोनग्रिट्स, मार्बल चिप्स, कालीन एव दरी, चर्मकला, इण्डस्ट्रियल गैसेज प्लाण्ट, नट वोल्ट, वायरनेल्स, फोरिक एलम, स्टील पाइप, जनरल इंजिनियरिंग वर्कशाप तथा अल्यूमिनियम के बर्तन आदि ।

बभनी - दरी, लाख, चर्मकला, काष्ठकला, बाँस की टोकरी, आरामशीन व लकडी के फर्निचर, जनरल ईजिनियरिंग, आइस फैक्ट्री, अल्यूमिनियम के बर्तन तथा साबुन उद्योग ।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र मे उपर्युक्त लघु एव कुटीर उद्योगों की स्थापना करके औद्योगिक विकास को विस्तृत आधार प्रदान कर, विकास प्रक्रिया की गति को तीव्र की जा सकती है।

संदर्भ

- ।. 'भारत' प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1988-89, पृष्ठ 388
- 2 सिंह, काशीनाथ एव सिंह, जगदीश 'आर्थिक भूगोल के मूलतत्व', वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, 1984, पृष्ठ 296

- 3 कोशिक, एस डी 'आर्थिक भूगोल के सरल सिद्धान्त', रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, 1980-81, पृष्ठ 188
- 4 Richards, T 'The Geography of Economic Activity', Mc Graw Hill Book Co, Inc 1962, p 456
- 5 Miller, E Willard A Geography of Manufacturing, prentice Hall, Inc Englewood Cliffs, N J 1962, p 1
- 6 Alexander, JW 'Economic Geography',
 p 288
- 7 Jarret, HR A Geography of Manufacturing (Second edition), Macdonald and Evans Estover Plymouth, 1977, p VII
- 8 'उत्तर प्रदेश वार्षिकी', सूचना एव जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, 1990-91 व 1991-92, पृष्ठ 109
- 9 शर्मा, आर एस प्राचीन भारत का इतिहास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, पृष्ठ 2।
- 10 दास, शिवतोष 'भारत स्वतन्त्रता दे बाद', प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 115
- ।। माहेश्वरी, श्री कृष्ण 'भारत मे आयोजन और आर्थिक विकास,' हिन्दी माध्यम, कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 1980, पृष्ठ 261
- 12. चन्द्र, बिपिन भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम, कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1990, पृष्ठ 65
 - 13 पूर्वोक्त सदर्भ सख्या -।
- 14 लोढ़ा, राजमल औद्योगिक भूगोल , राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1990
- 15. कुरैशी, एम एच 'भारत, ससाधन और प्रादेशिक विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ 71.

- 16 चौहान, वीरेन्द्र सिंह एव गौतम, अलका 'भारत का भूगोल', रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, 1990-91, पुष्ठ 336
- 17 केशरी, अर्जुनदास लोकनार्थ, पर्यावरण विशेषाक, सेवाश्रम प्रिटिग प्रेस, हरतीरथ, वाराणसी
- 18 भारत, सूचना और प्रसारण मत्रालय, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 457
 - 19 वहीं, पृष्ठ 458
 - 20 दैनिक जागरण, वाराणसी प्रकाशन, 28 जुलाई 1993, पृष्ठ 9
 - 21 वहीं, 5 अप्रैल 1993, पृष्ठ 9
 - **22** वही, 28 अप्रैल 1993, पृष्ठ 9
 - 23 वही, 28 जुलाई, पृष्ठ 9
 - 24 वही
- 25 कुरैशी, एम0एच0 भूगोल के सिद्धान्त, भाग-2, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ 78 एवं 79
- 26 सिंह, इकबाल 'भारत में ग्रामीण विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 75

XXXXXXXXXX

अध्याय 6

परिवहन एव सचार व्यवस्था की पृष्ठभूमि एव नियोजन

परिवहन तन्त्र आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। देश के लगभग 6 लाख गॉवों के लिए एक अच्छी परिवहन प्रणाली का होना आवश्यक है। देश मे कृषीय और औद्योगिक उत्पादन, कार्यक्षम परिवहन व्यवस्था के विकास से सम्बद्ध है। परिवहन स्वय उत्पादन की प्रक्रिया का एक चरण है क्योंकि विभिन्न प्रकार के उत्पादों को देश भर मे फैले हुए उपभोक्ताओं तक पहुँचाना होता है, जो कि परिवहन के साधनों से ही सम्भव है। विकसित परिवहन व्यवस्था से कृषि-विकास और औद्योगीकरण मे भी सहायता मिलती है। परिवहन व्यवस्था का एक अन्य पहलू भी है। प्राय परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास होने पर देश के सामाजिक जीवन मे कुछ ऐसे परिवर्तन होते है, जिनसे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है। 2 किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र के सतुलित विकास के लिए एकीकृत परिवहन तन्त्र की आवश्यकता होती है। परिवहन एव सचार माध्यमों से 'क्षेत्रीय विशिष्टीकरण का लाभ पिछडे क्षेत्रों को भी मिल जाता है। 'इस प्रकार परिवहन जाल, पिछडे क्षेत्रों मे भी ससाधनो के उपयोग को बल देकर वृद्धि एव विकास की स्थिति उत्पन्न करेगा।³ आर्थिक विलगन, राजनैतिक विखण्डन और सामाजिक दूरियों को एकीकृत एव समन्वित परिवहन एव सचार माध्यमों से खत्म किया जा सकता है। उपभोग एव उत्पादन बिन्दुओं में सयोजन, गाँव एव शहर से सम्बन्ध स्थापित करने तथा प्राकृतिक आपदा के समय ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होते है। परिवहन तन्त्र न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है बाजारों को राष्ट्रीय बाजार से और राष्ट्रीय बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जोडता है। विश्व स्तर पर आर्थिक विकास एव परिवहन साधनो के विकास में समानता मिलती है। 5 प्राय सोनभद्र के जिन क्षेत्रों में सडकों का विकास हुआ है, उन भागों का अपेक्षाकृत आर्थिक विकास अधिक हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र जनपद सोनभद्र अत्यन्त पिछडा है किन्तु विकास के लिए उत्तरदायी अधिकाश ससाधनों की बहुलता है। किन्तु ससाधनों का प्रमुख सयोजक तत्व परिवहन एव सचार का अत्यन्त अभाव है। जल परिवहन की सीमित सम्भावना है। वायु परिवहन के माध्यम नही है। रेलमार्गों का अभाव है। रेलमार्ग इकहरा है तथा यात्री रेलगाडियों का अभाव है। अव्यवस्थित तथा अविकसित सडके परिवहन के मुख्य साधन है। जनपद की सचार प्रणाली

भी अविकसित है। अस्तु प्रस्तुत अध्याय मे वर्तमान परिवहन एव सचार माध्यमो का विश्लेषण कर भावी परिवहन एव सचार के विकास के लिए सतुलित नियोजन प्रस्तुत करना है। अध्ययन की स्पष्टता के लिए प्रस्तुत अध्याय दो खण्डों मे विभक्त है। प्रथम भाग मे परिवहन एव द्वितीय भाग मे सचार के वर्तमान स्थिति का विश्लेषण एव भावी सतुलित नियोजन प्रस्तुत किया गया है।

6 । परिवहन माध्यम का प्रतिरूप

'माध्यम' का अर्थ 'मार्ग' जैसे सडक, रेल, समुद्र, नदी, वायुमार्ग माना गया है जबिक 'साधन' का प्रयोग यातायात हेतु प्रयुक्त विविध वाहनों जैसे 'बस', ट्रक, कार, मालगाडी, सवारी-गाडी, नाव, जलयान, टैन्कर आदि के लिए किया जाता है। 'आधुनिक युग मे तीनों मण्डलों (स्थल मण्डल, जल मण्डल व वायु मण्डल) का उपयोग परिवहन के लिए किया जा रहा है। स्थल मण्डल मे रेलमार्ग, सडके, रज्जुमार्ग तथा भूमिगत निलकाए (टनेल पाइप लाइन्स) परिवहन के माध्यम है। जलमण्डल मे समुद्र के साथ नौगम्य निदयों तथा नहरों का प्रयोग परिवहन के माध्यम के रूप मे होता है तो वायुमण्डल मात्र वायुयान परिवहन तक ही सीमित है। स्थानीय यातायात के लिए इन माध्यमों मे रेलमार्गों एव सडकों का विशेष महत्व है जिनके द्वारा क्षेत्र मे सामाजिक सेवाओं के पहुँचाने का कार्य सर्वाधिक किया जाता है। जनपद सोनभद्र मे परिवहन माध्यमों का विवरण इस प्रकार है -

(अ) जल परिवहन

है।

जल परिवहन एक सस्ता परिवहन माध्यम है जो भारी सामान ढोने के लिए अत्यन्त उपयुक्त हैं। 8 सोनभद्र मे जल परिवहन का विकास नगण्य है। पठारी क्षेत्र व ग्रीष्म ऋतु मे जल का अति अभाव, जल परिवहन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। बेलन, कर्मनाशा, कनहर, पाण्डु आदि नदियाँ जल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सोन नदी में जल परिवहन की अल्प सम्भावना है। जल परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रिहन्द जलाशय है। रिहन्द नगर से शक्तिनगर के बीच लगभग 18 किमीं। जलमार्ग की दूरी स्टीमर द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान समय में दिन में एक ही स्टीमर तीन बार शक्तिनगर से रिहन्द नगर तथा तीन बार रिहन्द नगर से शक्तिनगर जाता है। इससे वस्तुओ एव यात्रियों का परिवहन किया जाता

सोन नदी सोनभद्र के मध्य से, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रविहित है। सोन नदी द्वारा विभक्त सोनभद्र के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने के लिए अनेक स्थानों से वर्ष भर नावे चलती है। नाव चलने वाले प्रमुख घाट है - गुरूदह, अगोरी करगरा, ससनई, कोन, चकरिया, हरदी, अमवार, गढ़ाव व बसुहारी आदि। बेलन, कर्मनाशा, पाण्डु व कनहर नदी मे 15 अक्टूबर से 15 जून तक जल प्रवाह की न्यूनता के कारण कुछ खास स्थलों पर लोग पैदल ही इन नदियों को पार कर जाते हैं। इन नदियों का तल पथरीला व कड़ा होने के कारण भारी वाहनों (बसों, ट्रकों आदि) को भी उक्त समय मे पार करने मे कठिनाई नहीं होती है। किन्तु 15 जून से 15 अक्टूबर तक इन नदियों पर पुलो के अभाव के कारण लोग नावो का सहारा लेते है किन्तु वाहनों के आवागमन मे बाधा पहुंचती है। इन नदियों के बरसाती स्वभाव (एकाएक बाढ़ आना) तथा उबड़ खाबड़ तल होने के कारण नौका परिवहन खतरनाक होता है।

(ब) रेल परिवहन

जनपद मे विशाल औद्योगिक केन्द्रों तथा खिनज संसाधनों व औद्योगिक उत्पादों के परिवहन क्षमता को देखते हुए रेलमार्गों का विकास कम हुआ है। कोयला, सीमेट, अल्यूमिनियम, क्लिकर, बजरी आदि के दूरवर्ती क्षेत्रों में ले जाने के लिए रेलमार्गों व रेलों के अभाव के कारण ट्रको पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। अध्ययन क्षेत्र में 'ब्रांड गेज' की 103 6 किमीं लम्बी रेजवे लाइन हैं। सम्पूर्ण रेलवे लाइन 17 स्टेशनों (करमा, पौराही, पसही, राबर्ट्सगज, चुर्क, अगोरी, चोपन, बिल्ली, सलैयाडीह, रेनूबूट, म्योरपुर, झारोखास, दुन्ही, विण्डमगज, अनपरा (औडीमोड), बीना तथा शिक्तनगर से युक्त इकहरी है। जनपद का मुख्यालय राबर्ट्सगज, चुनार (मीरजापुर) व गढ़वा रोड (पलामू, बिहार) नामक दो जक्शन स्टेशन से जुड़ा हुआ है। चुनार से पटना व इलाहाबाद की ओर तथा गढ़वा रोड से पटना व हावड़ा की ओर जाया जा सकता है। बिल्ली स्टेशन से एक रेलवे लाइन कटनी (मध्य प्रदेश) जक्शन में मिलती है। यही रेलवे लाइन करेला रोड (मध्य प्रदेश) से अलग होकर मध्य प्रदेश के सीमा से होती हुई शक्तिनगर को जाती है।

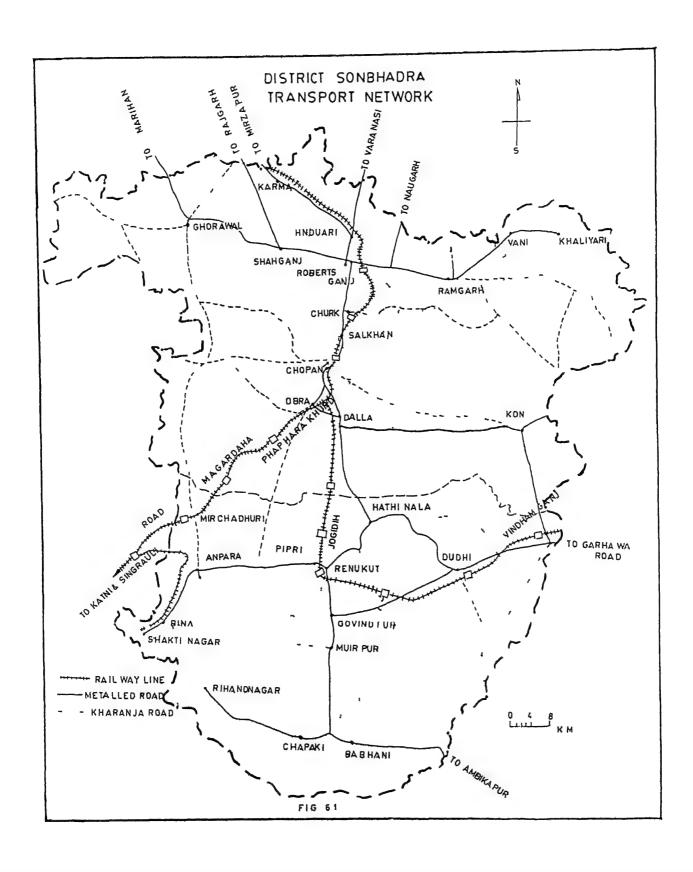
अध्ययन क्षेत्र से होकर 3 एक्सप्रेस रेलगाडी-(1) त्रिवेणी एक्सप्रेस - शिक्तनगर से लखनऊ (2) मूरी एक्सप्रेस - हिट्या से अमृतसर तथा (3) शिक्तपुज - शिक्तनगर से हावडा, अप मे तथा डाउन मे जाती है तथा 4 पैसेंजर रेलगाडी-(1) चोपन से मिर्जापुर (2) चोपन से गढवा रोड (3) चुनार से गढवा रोड तथा (4) चोपन से क्टनी, गुजरती है । अध्ययन क्षेत्र के तीन विकासखण्ड (बभनी, चतरा व नगवा) रेलवे लाइन रिहत है । रेलवे लाइन की सर्वाधिक लम्बाई विकासखण्ड चोपन मे तथा सबसे वम घोरावल मे है । प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र मे रेलमार्गों की लम्बाई अध्ययन क्षेत्र मे जहां । 51 कि0 मी0 है वही उत्तर प्रदेश मे 2 93 कि0 मी0 है । अर्थात प्रदेश के औसत से अध्ययन क्षेत्र मे लगभग 50% कम रेलवे लाइन है । उत्तर प्रदेश मे प्रतिलाख जनसख्या पर 7 78 कि0 मी0 लम्बी रेलवे लाइन का औसत है, जनपद सोनभद्र मे यह औसत 9 6 कि0 मी0 है । स्मरणीय है कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा (476 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0) सोनभद्र मे जनसख्या घनत्व (157 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0) विरल है ।

(स) रज्जु मार्ग (रोप-वे)

अध्ययन क्षेत्र सोनभद्र मे परिवहन का अनोखा माध्यम रोप-वे हैं, जिस पर ट्रालियां चलती है । विद्युत सथलाकृति वाले क्षेत्रों मे यह सबसे उपयुक्त माध्यम है । विद्युत स्तम्भों से सयुक्त मोटे विद्युत तारों से हजारों की सख्या मे लटकते हुए इन ट्रालियों से कोयला, चूना पत्थर व क्लिकर की दुलाई होती है । रोप-वे ट्राली से परिवहन रेणूसागर, डाला व चुर्क मे होता है । सिगरौली कोयला क्षेत्र से कोयले की दुलाई रेणूसागर ताप विद्युत केन्द्र के लिए इसी प्रणाली से होती है । डाला व चुर्क सीमेण्ट फैक्ट्री के लिए क्जरहट व गुरमा क्षेत्र से चूना पत्थर की दुलाई इसी माध्यम से होती है । इसमे मानव शक्ति की कम आवश्यकता पडती है, परिवहन अबाध गित से चलता है तथा प्रदूषण नहीं होता है । इस प्रणाली से विद्युत खर्च होता है किन्तु विषम भ्याकृतिक क्षेत्रों मे जहाँ सडक व रेल लाइन बनाना दुष्कर हो यह परिवहन प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है । जनपद सोनभद्र मे इस प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए अलप विकास हुआ है ।

(द) यातायात की धर्मानियाँ - सड़क परिवहन

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए प्रथमत सडके बनायी जाती है । ये सडके



यातायात की धमनियाँ कहलाती है । सिंधु - घाटी की सभ्यता, जो नगर सभ्यता कहलाती थी, मे लम्बी, चौडी व समकोण पर काटने वाली सडके थी । रामायण व महाभारत काल मे न केवल सडको का उल्लेख है वरन्, सडको के बनाने की विधि का भी उल्लेख है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे तो विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न वर्गों की सडके बनाने का प्रावधान है । 200 बी सी से 200 ए डी तक जो आर्थिक समुन्नत का काल था, विभिन्न व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया है । विभिन्न क्षेत्रों मे पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि प्राचीन काल मे शहरों एव कस्बों मे सडकों के आश्चर्यजनक ढग से योजनाबद्ध सजाल बने हुए थे।

प्राचीन काल से अठारहवीं शताब्दी तक (मौर्यकाल को छोडकर) सम्पूर्ण भारत के एक शासनतन्त्र के नियन्त्रण मे न रहने के प्रमुख कारणों मे से एक था, सडको एव सचार माध्यमों की कमी । शेरशाह सूरी ने कई सडकों और सरायों का निर्माण कराया, जिससे सभी क्षेत्रों का केन्द्र स्थलों से सीधा सम्बन्ध हो गया । उसकी चार सडके अत्यन्त प्रसिद्ध हुई । इनमें सबसे लम्बी सडक थी - पूर्वी बगाल में सोनार गाँव से आगरा दिल्ली और लाहौर होते हुई सिन्धु नदी तक सडक-ए-आजम अर्थात् ग्राड ट्रक सडक । ब्रिटिश शासन काल में भी सडकों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया । भारत सरकार ने 1919 के अधिनयम के अन्तर्गत सडके प्रातों के अधिकार क्षेत्र में आती थी और प्रान्तीय सरकार सडकों के काफी बड़े हिस्से की जिम्मेदारी स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं को सौंप देती थी । देशभर के प्रान्तों और बड़ी रियासतों के मुख्य इजीनियरों का दिसम्बर 1943 में एक सम्मेलन नागपुर में बुलाया और सम्पूर्ण भारत के लिए सडक विकास की एक समग्र योजना निर्धारित की गयी तथा एक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार किया गया । इसी रिपोर्ट को 'नागपुर रिपोर्ट' कहा जाता है, इसमें सडकों की निम्न श्रेणियाँ बनायी गयी -

- । राष्ट्रीय राजमार्ग
- 2 प्रान्तीय राजमार्ग
- 3 जिला सडके
- 4. ग्रामीण सड़के

राजमार्गों के इन्जीनियरों की सस्था 'भारतीय सडक काग्रेस परिषद्' ने 'सडक विकास योजना' तैयार की है जिसमें सन् 2001 तक देश के सभी गांवों तक सडक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है । इससे देश में कुल 27 लाख कि0 मी0 लम्बी सडके हो जाएगी । इस योजना पर लगभग 64250 करोड़ रूपया खर्च होगा । योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यों के राजमार्गों तथा ग्रामीण सडकों सिहत सभी सडकों के सतुलित विकास के साथ - साथ बेहतर सडकों से ईंधन की बचत, सडक सुरक्षा, पर्यावरण सरक्षण, निर्माण प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा अनुसधान गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है ।

6 2 सडक परिवहन का महत्व

अपेक्षाकृत कम लागत के कारण रेल मार्गों की तुलना में सडकों का अधिक विकास हुआ है । सडक परिवहन रेल परिवहन की तुलना में प्राचीन है । सडको पर परिवहन साधनों की विविधता तथा मात्रा के कारण सडकों के स्वरूप में पर्याप्त अन्तर मिलता है । वाराणसी से प्रक्तिनगर तक के सडकों को जहाँ वर्तमान चौडाई से भी तिगुना अधिक करने वा प्रस्ताव है, वही अल्पविकसित क्षेत्रों में सडक के नाम पर मात्र समतल धरातल की सकीर्ण पिट्टयों ही मिलती है । रेल मार्गों की तरह सडकों की कोई मानक चौडाई के अभाव के कारण विभिन्न न्याय पचायतों व ब्लाकों की सडक - दूरी का तुलनात्मक अध्ययन कठिन होता है । लेकिन न्यूनतम स्तर पर यदि मोटरगाडी चलने योग्य मार्ग को सडक मान लिया जाय तब कहीं सभी विकासखण्डों में उपलब्ध मार्ग लम्बाई के ऑक्डों का विश्लेषण किया जा सकता है ।

सड़को का आधुनिक महत्व इसी शताब्दी के आरम्भिक वर्षों से बढ़ा जब मोटरगाडियों के अत्यधिक प्रचलन से द्वृत सड़क परिवहन रेल परिवहन की बराबरी करने में समर्थ हुआ। अब दोनों ही परिवहन माध्यम (सड़क व रेलमार्ग) एक दूसरे के पूरक हो गए हैं । भारी खिनजों एव औद्योगिक पदार्थों का अपेक्षाकृत दूर तक यातायात रेलगाडियों से होता है किन्तु कम मात्रा में तथा स्थानीय माल को गन्तव्य स्थान तक सावधानीपूर्वक पहुँचाने में सड़कों का विशेष महत्व है । अनपरा, शिक्तनगर, रिहन्द नगर आदि ताप विद्युत गृहों में, समीप के सिगरौली क्षेत्र से कोयले की दुलाई सड़कों से ही होती है । सोनभद्र जैसे पहाड़ी व विखरे गाँवों में सड़कों का विशेष महत्व है । प्रत्येक विकास केन्द्र को रेलमार्गों से जोड़ना असम्भव है किन्तु प्रत्येक विकास केन्द्र को सड़कों से जोड़कर अभिगम्यता और बढ़ायी जा सकती है । इसलिए लोच, विश्वसनीयता एव गित को सड़क परिवहन की मुख्य विशेषता बताया गया है ।

है । अत ऐसी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों मे सडके विशेष लाभदायक होती है । भारत मे सडक निर्माण की दिशा मे सर्वप्रथम प्रयास 1943 मे 'नाग्पुर योजना' का आधार यह था कि विकसित कृषि क्षेत्रों मे कोई गाँव किसी भी मुख्य सडक से 5 मील (8 कि0 मी0) से अधिक दूर तथा अन्य प्रकार की सड़कों से 2 मील (3 कि0 मी0) से अधिक दूर न रहे एव प्रमुख सड़क से औसत दूरी 2 मील से कम ही रहे । इसी प्रकार अकृषि क्षेत्रों मे किसी गाँव की दूरी क्रमश 20 मील तथा 5 मील से अधिक न रहे तथा औसत दूरी 6 7 मील रहे । किन्तु रियासतों के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका । इसके बाद 1961 - 81 तक के लिए सडक निर्माण से सम्बन्धित 20 वर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके अनुसार विकसित कृषि क्षेत्र मे कोई गाँव किसी पक्की सडक से 6 5 कि0 मी0 से अधिक दूर न रहे तथा किसी सम्पर्क सडक से 25 कि0 मी0 से अधिक दूर न हो । इसके अनुसार 1981 तक प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र मे 32 कि0 मी0 सडक होनी चाहिए । किन्तु तालिका 6 3 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के 12 67% (170 गाँव) गाँव ही पक्की तडकों पर स्थित है । पक्की सडक से । कि0 मी0 की दूरी तक 9 54% (128 गाँव) तथा । - 3 कि0 मी0 की दूरी तक 15 95% (214 गॉव) गॉव अवस्थित है। पक्की सडक से 3 कि0 गी0 की दूरी तक 38 15% (512 गाँव) गाँव है तथा 3 कि0 मी0 से अधिक दूर स्थित गाँवों का प्रतिशत 61 85% (830 गाँव) है।

तालिका 6 । से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 पक्की व खड़जा सड़कों का घनत्व 12 75 कि0 मी0 है । पक्की सड़कों का घनत्व 7 24 कि0 मी0 प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 है । अत राष्ट्रीय मानक के अनुसार कि प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 मे 32 कि0 मी0 पक्की सड़क होनी चाहिए , के तुलना मे सोनभद्र मे सड़को का घनत्व बहुत कम है ।

अध्ययन क्षेत्र में सड़कों का वितरण असमान है । जनपद में कुल सड़कों की लम्बाई 935 कि0 मी0 है जिसमें से 494 कि0 मी0 (52 83%) पक्की सड़क तथा 441 कि0 मी0 (47 17%) खड़जा सड़क है (तालिका 6 2) । 494 कि0 मी0 पक्की सड़क में 68 कि0 मी0 नगरों में तथा 426 कि0 मी0 ग्रामीणी क्षेत्रों में है । सर्वाधिक 97 कि0 मी0 पक्की

1 -O Ideivilly

		जनपद र	जनपद सोनभद्र में सडक अभिगम्यता एवं घनत्व	भेगम्यता एवं धनत्व		सदक धनन्त्र किंत भीत :	in thin .
विक संखण्ड	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	जनसंख्या 1991	अभिगम्यता क्षेत्रफल %	अगम्य क्षेत्रफल %	सडक लम्बाई कि0 मी0	प्रेडन, सार्च मार्ग नाए ने प्रति 100 वर्गे प्रति 100000 कि0 मी0 जनसङ्या	प्रति ।00000 जनसङ्या
-	2	υ	4	5	6	7	00
। षोरावल	818 73	155963	44 46	55 54	118	14 41	75.66
2 राबर्ट्सगज	442 45	137889	62 83	37 17	86	19 44	62 37
3 चतरा	254 85	67441	40 23	59 77	70	27 47	103 79
4 नगवा	916 20	54518	24 20	75 80	89	9.71	163.25
5 चोपन	1712 97	165693	33 10	66 90	204	11 91	122 38
6 म्योरपुर	1337 89	192719	48 73	51 27	137	10 24	71 09
7 दुब्दी	707 45	96533	70 39	29 61	121	17 10	125.35
8 बभनी	608_26	57618	16 77	83 23	42	6 90	72 89
समस्त विकासखण्ड	6798 80	929374	41 93	58 07	867	12 75	93.29
वन क्ष हा		1584	! ! ! ! ! ! !	; ; ; ; ; ; ;	! ! ! ! ! ! !		1
ग्रमीण योग	6798 80	930958	41 93	58 07	867	12 75	93 29
नगरीय योग	20_48	144083	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	; ; ; ; ; ; ; ; ;	8		47 19
जनपद योग	6819.28		41 03	K9 07	037		13 75 86 87

सडक की लम्बाई विकासखण्ड म्योरपुर मे है, इसके बाद क्रमण विकासखण्ड दुद्धी मे 7। कि0 मी0, राबर्ट्सगज मे 66 कि0 मी0, घोरावल मे 6। कि0 मी0, चोपन मे 54 कि0 मी0, बभनी मे 3। कि0 मी0, नगवा मे 24 कि0 मी0 तथा चतरा मे 22 कि0 मी0 पक्की सडक है। खडजा सडको की सर्वाधिक 150 कि0 मी0 लम्बाई विकास खण्ड चोपन मे तथा सबसे कम 1। कि0 मी0 विकास खण्ड बभनी मे है (तालिका 6 2)। पक्की व खडजा सडकों की सयुक्त सर्वाधिक लम्बाई विकासखण्ड चोपन मे 204 कि0 मी0 है तथा सबसे कम विकासखण्ड बभनी मे 42 कि0 मी0 है (तालिका 6 2)।

तालिका 6 2 जनपद सोनभद्र में सडकों की लम्बाई

क्रम सख्या	विकासखण्ड	कुल पक्की सडक कि0मी।	कुल खडजा) मार्ग कि0मी0	
1	2	3	4	5
ı	घोरावल	61	57	118
2	राबर्ट्सगज	66	20	86
3	चतरा	22	48	70
4	नगवा	24	65	89
5	चोपन	54	150	204
6	म्योरपुर	97	40	137
7	दुव्ही	71	50	121
8	बभनी	31	11	42
	ग्रामीण योग	426	441	867
	नगरीय क्षेत्र	68	-	68
	सम्पूर्ण योग	494	441	935

स्त्रोत मानचित्र संख्या 6 । से परिकलित ।

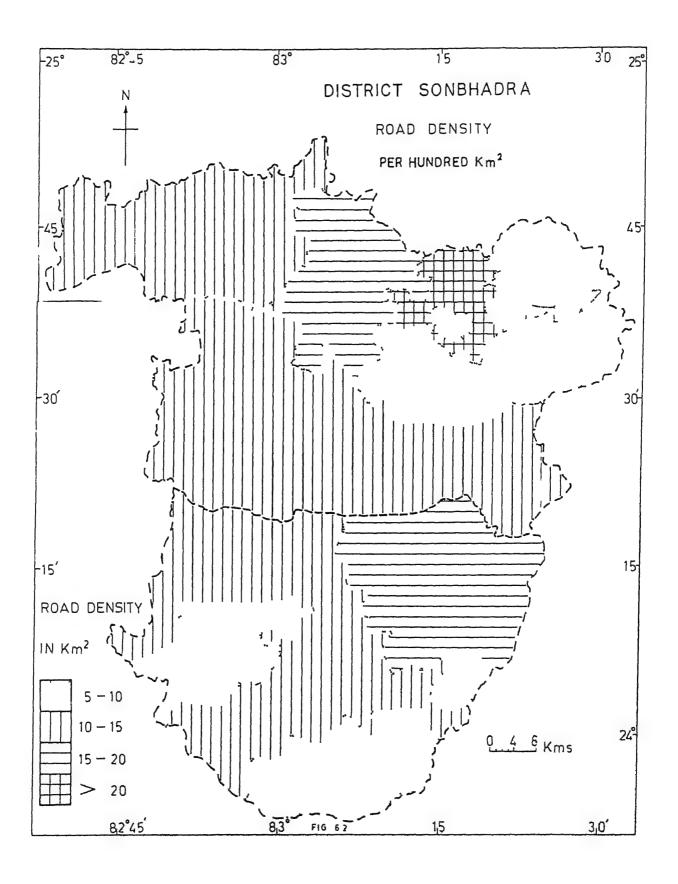
प्रमुख सडक मार्ग करमा से शिक्तनगर दे सडक की लम्बाई 156 कि0 मी0, खिलियारी से घोरावल की लम्बाई 66 कि0 मी0 तथा हाथीनाला से विण्ढनगज की लम्बाई 45 कि0 मी0 है । जनपद मुख्यालय राबर्ट्सगज से प्रमुख सेवा केन्द्रों, बस स्टेशनों एव बस स्टापों की दूरी तालिका 6 6 मे दी गयी है । इस तालिका से विभिन्न सेवा केन्द्रों के बीच स्थित पक्की सडकों की लम्बाई ज्ञात की जा सकती है ।

6 3 सडक घनत्व

सडक परिवहन का अधिकाधिक प्रयोग अपेक्षाकृत कम दूरी के यातायात के लिए किया जाता है । पिछडे क्षेत्र के आर्थिक तन्त्र के प्रादेशिक सन्तुलन के लक्ष्यपूर्ति को रेल की अपेक्षा सडक अधिक उपादेय सिद्ध होती है । किन्तु सडकों के उपादेयता के विश्लेषण मे उनकी लम्बाई की अपेक्षा समनता का प्रयोग अधिक समीचीन प्रतीत होता है । सडकों के घनत्व का आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विस्तार, जनसंख्या तथा आर्थिक कार्यकलापों के वितरण प्रतिरूप एव वैकल्पिक परिवहन साधनों के विकास के जटिल रूप में अन्तर्सम्बन्धित है । अध्ययन क्षेत्र में सडक घनत्व अत्यधिक न्यून है । सांपेक्षिक दृष्टि से सडक घनत्व उन्हीं भागों में अधिक है, जहाँ जनसंख्या एव आर्थिक कार्यकलाप की संघनता है ।

प्रस्तुत अध्ययन में सडक घनत्व की गणना दो प्रकार से की गयी है । प्रथम विकासखण्ड स्तर पर प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्रफल पर तथा द्वितीय 100000 की मानक जनसंख्या पर (विकासखण्ड स्तर पर)। इसका प्रदर्शन क्रमश मानचित्र 6 2 व 6 3 में किया गया है । इन मानचित्रों से सडक घनत्व को आसानी से प्रत्यक्षीकृत किया जा सकता है ।

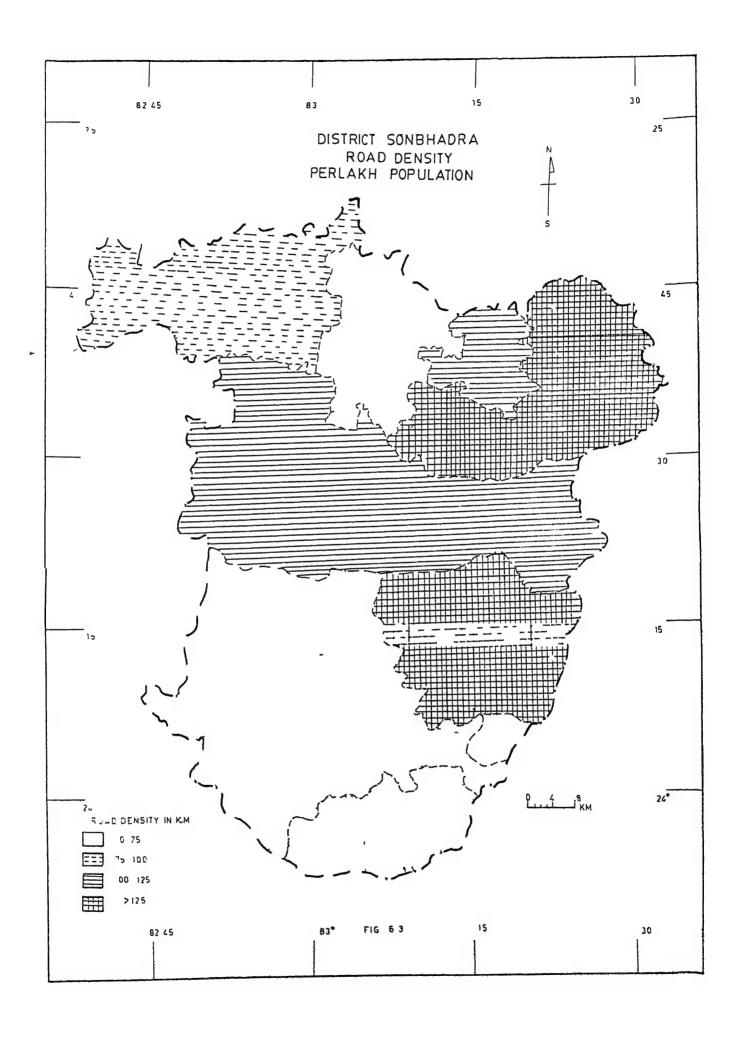
तालिका 6 । से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र में सड़कों (पक्की एवं खड़जा) का घनत्व 12 75 कि0 मी0 है । विकासखण्ड चतरा में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व 27 47 कि0 मी0 प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र में है । पुन अवरोही क्रम में क्रमण्ण विकास खण्ड राबर्ट्सगण (19 44 कि0 मी0), दुद्धी (17 10 कि0 मी0), घोरावल (14 41 कि0 मी0), चोपन (11.91 कि0 मी0), स्योरपुर (10 24 कि0 मी0), नगवा (9 71 कि0 मी0) तथा बभनी (6 90 कि0 मी0) का स्थान आता है (तालिका 6 1)।



तालिका 6 3 सोनभद्र मे पक्की सडक से बस्तियों की दूरी

						1 1 1 1 1 1 1	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
क्र म्स ख्या	विकसस्वण्ड	ग्रम स	।किमी0 से कम	।-3 किमी0	3-5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	योग
1	घोरावल	14	24	30	48	221	337
2	राबर्टसगज	51	56	85	43	94	329
ယ	चतरा	31	33	61	20	23	168
-	नगवा	16	4	7	6	95	128
	चोपन	5	6	9	16	45	91
0.	म्योरपुर	12	1	©	7	93	120
	લુ	19	4	12	4	49	98
00	बभनी	12	_	2		48	71
1	योग	170	128	214	162	668	1342
		(12.00)	1. 2/			•	

म्रोत सांिंध्यकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ156



मानचित्र 6 3 को देखने से भी स्पष्ट होता है कि जनपद के दक्षिणी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मे सडकों का घनत्व सबसे कम है सम्पूर्ण पश्चिमी भाग मे घनत्व अति न्यून से थोड़ा अधिक है।

प्रतिलाख जनसंख्या पर सडकों का औसत घनत्व 86 97 किमी0 है। नगरीय क्षेत्र में सडकों का घनत्व 47 19 किमी0 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 93 29 किमी0 है (तालिका 6 1)। विकास खण्ड स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या पर सडकों का घनत्व अवरोही क्रम में इस प्रकार है - नगवा (163 25 किमी0), दुद्धी (125 35 किमी0), चोपन (122 किमी0), चतरा (103 किमी0), घोरावल (75 66 किमी0), बभनी (72 89 किमी0), म्योरपुर (71 09 किमी0) तथा राबर्टसगज, (62 37 किमी0)। मानचित्र 6 4 से भी स्पष्ट है कि जनपद के दक्षिण-पश्चिम तथा मध्य उत्तर में प्रति लाख जनसंख्या पर सडक घनत्व सबसे कम तथा उत्तर-पूर्व व मध्य पूर्व क्षेत्र में सडक घनत्व सबसे अधिक है। श्रेष भागों में सडक घनत्व अपेक्षाकृत औसत है।

6 4 सडक अभिगम्यता

प्राय मानव लक्ष्य की प्राप्ति मे, कम से - कम समय तथा शिक्त का उपयोग करता है। लेकिन इसकी सम्भाव्यता सडको की अभिगम्यता की तीव्रता पर निर्भर है। सडक अभिगम्यता का तात्पर्य यथा सम्भव कम समय तथा कम शिक्त के व्यय पर निर्वाध गित से सुगमतापूर्वक किसी सडक या सेवा केन्द्र पर पहुँचने से है। सडकों की अभिगम्यता से सडकों की सघनता तथा गमनागमन की सुविधा का ज्ञान होता है। साथ ही इसकी तीव्रता से किसी क्षेत्र के विकास का स्तर एव सडक जाल की प्रभावोत्पादकता का मापन होता है। सामान्यतया मार्ग जाल की गम्यता परिवहन मार्गों से एक विशेष दूरी द्वारा प्रकट की जाती है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक ही दूरी को अभिगम्यता का मानक मापदण्ड नहीं माना जा सकता। अभिगम्यता का मापदण्ड साधारणतया व्यक्तिनिष्ठ होता है। सडक तन्त्र विकसित होने पर अगम्य क्षेत्र लुप्तप्राय हो जाता है। भारत में सडकों की अभिगम्यता मान में 'नागपुर योजना' तथा 'बम्बई योजना' द्वारा निर्धारित मानवण्ड इस प्रकार है -

तालिका 6 4 नागपुर तथा बम्बई योजनाओं द्वारा निर्धारित सडक अभिगम्यता मानदण्ड

क्रमसंख्या	क्षेत्र वि			गाँव की अधिकतम [्] सडक से	- '
1	नागपुर	योजना			
	I P	त्रिष क्षेत्र	3 22	2	8 05
	II वृ	वितर क्षेत्र	8 05	32	2 10
2	बम्बई	योजना			
	I	विकसित कृषि			
		क्षेत्र	4 83	3 12	2 87
	II	अविकसित कृ	षे 8 05	5 19	9 31
		क्षेत्र			
	III	विकसित कृषि	2 41		б 44
		क्षेत्र			

राष्ट्रीय स्तर पर सडक परिवहन के विश्लेषण मे अधिकाशतया उपर्युक्त मानदण्डों को ही अपनाया जाता है किन्तु कृषि प्रधान, पठारी एव कुछ बड़े उद्योगों से युक्त पिछड़े इस जनपद के लिए उक्त मानदण्ड उपयुक्त नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण है। प्रथम, इस मानदण्ड के आर्थिक विकास के स्तर से सम्बन्धित होने के कारण सूक्ष्म स्तरीय क्षेत्रों मे आर्थिक विकास के स्तर के अतिरिक्त भौतिक, सामाजिक एव सास्कृतिक स्तर पर विभिन्नता पायी जाती है। तथा द्वितीय यह मापदण्ड अत्यधिक प्राचीन है। आज के बदले हुए भौगोलिक परिवेश मे सोनभद्र जनपद मे सडकों की अभिगम्यता मापन के लिए उपर्युक्त मापदण्ड उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अत व्यावहारिक अभिगम्यता को देखते हुए इस भाग मे सडक अभिगम्यता के मापन के लिए निन्नलिखित को अभिगम्य माना जा सकता है -

- । मुख्य पक्की सड़कों से 3 किमी0 की दूरी पर स्थित बस्तियाँ,
- 2. अन्य पक्की सड़कों से 2 किमी0 दूरस्थ सभी बस्तियां और

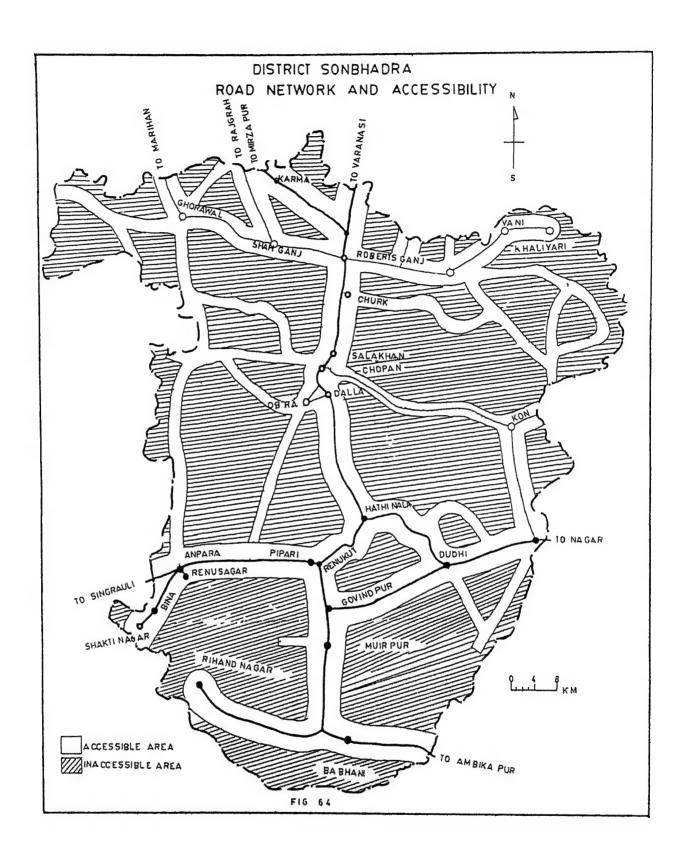
3 किसी भी कच्चे मार्ग या खड़जा मार्ग से । किमी० दूर तक स्थित बस्तियों।

उपर्युक्त मानदण्डो के आधार पर जनपद में वर्षभर परिवहन योग्य सडकों का अभिगम्यता मानचित्र का निर्माण किया गया है (6 4)।

मानिचन्न 6 4 को देखने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की अभिगम्यता अच्छी नहीं है। जनपद के मध्य मे उत्तर से दक्षिण मे जाने वाली गुख्य पक्की सड़क के कारण मध्यवर्ती क्षेत्र मे अभिगम्यता स्रतोष जनक व ही जा सकती है। सोनभद्र मे अनेक ऐसे पठारी तथा जगली क्षेत्र है जहाँ सड़कों से अभिगम्यता स्थापित करना दुष्कर है। पूर्वी घोरावल सम्पूर्ण नगवा, बभनी, म्योरपुर, चोपन व दुद्धी विकास खण्ड मे सड़कों से अभिगम्यता स्थापित करना अत्यन्त खर्चीला है। वर्तमान सड़क तन्त्र के आधार पर (मानचित्र 6 2) तालिका 6 । मे अभिगम्यता परिकलित की गयी है। सोनभद्र का 41 93% भाग अभिगम्य तथा 58 07% भाग अगम्य है। सर्वाधिक अभिगम्यता विकास खण्ड दुद्धी मे (70 39%) है। इसके बाद क्रमश राबर्ट्सगज, म्योरपुर, घोरावल, चतरा, चोपन, नगवा, तथा बभनी मे क्रमश 62 83%, 48 73%, 44 46%, 40 23%, 33 10%, 24 20%, तथा 16 77% है। जनपद के औसत अभिगम्यता से विकास खण्ड दुद्धी, राबर्टसगज, म्योरपुर तथा घोरावल मे अधिक तथा चतरा, चोपन, नगवा व बभनी मे निम्न है (तालिका 6 1)।

6.5 सडक सम्बद्धता

सड़कों की आपस में सम्बद्धता, सड़क परिवहन के विश्लेषण का एक अद्वितीय माध्यम है। परिवहन व्यवस्था की सुगमता, सड़क तन्त्र के विकास का स्तर तथा सघनता का बोध सड़क सम्बद्धता से ही स्पष्ट होता है। जिन क्षेत्रों में सम्बद्धता अधिक होती है, उन क्षेत्रों में सड़कों की सघनता तथा गम्यता अधिक होती है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था के सड़क जाल प्राय सुसम्बद्ध नहीं होते है जबिक विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में सड़क सम्बद्धता अधिक पायी जाती है। जहां सड़कें इस प्रकारिवतिरत हों कि कोई भी सड़क किसी आन्तरिक बिन्दु पर जाकर अकस्मात समाप्त नहीं होती है वरन उसके दोनों छोर अन्य सड़कों से सम्बन्धित हो तो उसे सुसम्बद्ध सड़क जाल कहा गया है। दूसरी ओर, जहां प्रमुख सड़कों से आबद्ध क्षेत्र



के मध्य अन्य सड़के अकस्मात किसी बिन्दु पर समाप्त हो जाती है अर्थात उनके द्वारा हर दिशा मे यात्रा बिना वापस लौटे नहीं की जा सकती तो उसे असम्बद्ध सड़क जाल कहा गया है। इन दोनों के बीच की स्थित को सामान्य सम्बद्धता की दशा मानी गयी है जो सड़क जाल जितना ही सुसम्बद्ध होगा उसमे परिक्रमता उतनी ही कम होगी। 12 सोनभद्र मे यह सम्बद्धता दो माध्यमों से ज्ञात की गयी है एक प्रमुख सेवा केन्द्र के सदर्भ मे तथा दूसरा सड़क जाल सरचना के परिप्रेक्ष्य मे।

(अ) सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता

सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता के द्वारा इस तथ्य को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि जनपद सोनभद्र के प्रमुख सेवा केन्द्र आपस में कितने सेवा केन्द्रों से जुड़े हुए है। इस सडक सम्बद्धता को ज्ञात करने में केवल पक्की सड़कों को ही आधार माना गया है। यद्यपि कच्ची सड़कों द्वारा भी सेवा केन्द्रों में सम्बद्धता पायी जाती है किन्तु जनपद के पठारी क्षेत्र होने के कारण, नालों पर पुल न होने से बरसात के दिनों में सम्बद्धता भग हो जाती है। अस्तु सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता विश्लेषण में समरूपता लाने के लिए कच्ची सड़क एव खड़जा मार्गों को छोड़ दिया गया है।

अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख विकास केन्द्रों की आपस में पक्की सड़क से सम्बद्धता जानने के लिए मानचित्र 6 । के आधार पर 'कनेक्टिविटी मैट्रिक्स बनाया गया है। जिसे तालिका 6 5 के रूप में देखा जा सकता है। जनपद का सबसे सम्बद्ध क्षेत्र राबर्ट्सगज है। यह प्रत्यक्षत चार केन्द्रों (शाहगज, करमा, रामगढ़ व चुर्क) से जुड़ा हुआ है। चोपन, डाला, हाथीनाला, दुद्धी अनपरा, गोविन्दपुर, म्योरपुर, रेनूकूट तीन केन्द्र में सीधे जुड़े है तथा जनपद मुख्यालय के बाद इन केन्द्रों की-सम्बद्धता द्वितीय - स्थान पर है। शाहगज, रामगढ़, बैनी, चुर्क, सलखन, ओबरा, विण्डमगज, पिपरी, बीना, रिहन्द नगर, बभनी दो सेवा केन्द्रों से सीधे जुड़े हुए है जबिक कोन, घोरावल, करमा, खिलयारी, रेणूसागर व शिक्तनगर की सम्बद्धता मात्र एक केन्द्र से हैं।

TABLE 6.5
METALLED ROAD CONNECTIVITY MATRIX

72	BH	RN	d'E	GP	NS	RS	BN	AN	PR	RK	VG	Н	HN	Id	ОВ	CH	SX	CX	KR	Ş	AG.	M	RB	SG	£	35	OT
1	L	-	L	L	L	L	L		L															-		A:D	
N	L	\vdash	_	_	_		L																_		_	38	l
-	-	-	-	-	-	-	_											_			_	_		_		RB	
-14	L	-	-	-	L	-	L																-			KH	
-17	-	-	_	-	_	_	L													~			-			RG	
N	_	-		L	L	_	_												1		-					Ş	
-1	L	L		L	_	_	_													~						XX	
N	_		L	_	_		L										-						-			Q	
N	L	_	_	L	L	L	L									-		-								XS	
w	L														-											£	
N	L				L											1										80	
w	L												_		-	1										DL	
w		L				L				-		1		-												HN	
w	L	L		-							1		_												_	DH	
N												-							-						-	VG	
Cu		L		_					_				-													RK	
N								-		_																PR	
٤u						-	-		-																_	AN	
2					-			-											-			\vdash	Н			BN	
1		Γ						_			Г												Н	Н	_	I RS	
1		Γ					-				Г								-			-	Н			SN	
w		Γ	_			Γ				_		_				-	-		_	-	_	\vdash	Н		_	GP	
ω	-	-		-	\vdash				\vdash						-		-		-		-		Н		-	MP	
N	-		_								_					-					-		Н		_	RN	
N	Γ	-	-												\vdash	-	-		_	-	-	\vdash	H	+	-	V BH	
14								\vdash			-				-		-		-		-	-	H		-	N P	
56	2	~	w	w	1	-	2	3	2	w	2	ω	3	3	12	W	2	2	1	12	2	1	4	2	1	KW T	
6 T Total		BH Babl		MP Mui				BN Bina			PK Pent		J DH Dudhi			OR Ohra										GW Ghos	
ı,		Babhanı	Rihandnagar	Muirour	Govindant	Shaktinagar	Sagar		j +	Pinri	koo+	Vindhamaani	4	Hathinala	b			Salakhan	Churk	lvari	4.	Ramgarh	ia di di	Robertsgani	gan i	Service Centre Ghorawal	

(ब) मार्ग-जाल की सम्बद्धता

मार्ग जालों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए कई मापकों का उपयोग किया जाता है। इस विश्लेषण विधि में किसी भी मार्ग जाल को एक ग्राफ के रूप में माना गया है। जिसमें बिन्दु (वर्टिक्स) तथा बाहु (एजेज) दो मुख्य तत्व होते हैं। किसी भी परिवहन माध्यम के मार्ग जाल में जितने भी उद्गम, सगम तथा अतिम या प्रमुख विकास केन्द्र होते हैं, उन्हें बिन्दु तथा इनको सीधे सम्बन्धित करने वाले मार्गों को बाहु के रूप में माना जाता है। इसमें दो बिन्दुओं के बीच की दूरी अर्थात बाहुओं की लम्बाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में पक्की सडकों के जाल के सदर्भ में प्रमुख बिन्दुओं की सख्या 27 है। इन बिन्दुओं एव बाहुओं के माध्यम से सडक जाल सम्बद्धता को प्रदर्शित करने वाले अल्फा (०८) बीटा (१८) तथा गामा (४०) निर्देशाकों की गणना की गयी है।

'अल्फा निर्देशाक' से मार्ग जाल के सम्बद्धता स्तर का बोध होता है। इस निर्देशाक का मान 0-1 00 के मध्य होता है। पूर्णत असम्बद्ध मार्ग जाल का मान 0 होता है। पूर्णत सुसम्बद्ध मार्ग जाल का निर्देशाक । 00 होता है। इस निर्देशाक की गणना निम्न लिखित सूत्र से की गयी है 13-

$$\propto = \frac{e-v+q}{2v-5}$$

जहाँ

🗴 = अल्फा निर्देशाक

e= बाहुओं की सख्या

v= बिन्दुओं की सख्या तथा

g = असम्बद्ध गाफों की सख्या

अध्ययन क्षेत्र के सड़क जाल का यह निर्देशाक 0 04 है। इससे स्पष्ट होता है कि सड़क जाल न तो पूर्णत सुसम्बद्ध है और न ही पूर्णत असम्बद्ध है। इस निर्देशाक (0 04) मे 100 से गुणा करके सम्बद्धता को प्रतिशत मे भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार जनपद का मार्ग जाल 4 00% सम्बद्ध है। 'बीटा निर्देशाक' से किसी मार्ग - जाल के बाहुओं एव बिन्दुओं के अनुपात का बोध होता है। इस निर्देशाक के अनुसार असमबद्ध मार्ग जालो का मान । 00 से कम होता है। एक ही चक्र मे विभिन्न केन्द्र बिन्दुओं को मिलाने वाले मार्ग जाल का मान । 00 तथा केन्द्र बिन्दुओं के मध्य कई विकल्प वाले मार्ग जाल का मान । 00 से अधिक होता है। इस निर्देशाक की गणना निम्निलिखित सूत्र द्वारा की जाती है -

 $\beta = \frac{e}{v}$

जहाँ

 β = बीटा निर्देशाक,

e = बाहुओ की सख्या तथा

v = बिन्दुओं की सख्या।

अध्ययन क्षेत्र के सडक जाल के इस निर्देशाक का मान । 04 है, जिससे स्पष्ट होता है कि सडक जाल बहुत ही कम सम्बद्ध है।

'गामा निर्देशाक' से किसी मार्ग जाल के बाहुओं और बिन्दुओं के अनुपात का बोध होता है, किन्तु यह बीटा निर्देशाक से भिन्न है। यह निर्देशाक विद्यमान बाहुओं का अधिकतम बाहुओं के गुणाक का द्योतक है। इस निर्देशाक की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है -

जहाँ

\Upsilon = गामा निर्देशाक,

e = बाहुओ की सख्या तथा

v = बिन्दुओं की सख्या।

इस निर्देशाक का मान 0-1 00 के मध्य होता है। पूर्ण सम्बद्ध मार्ग जालों का मान 1 00 तथा अपूर्ण सम्बद्धता वाले मार्ग जालों का मान 1 00 से कम आता है। जनपद मे सड़क जाल का गामा निर्देशाक 0 3733 है। इसमे 100 का गुणा करने पर सम्बद्धता

प्रतिशत मे ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार सडक जाल सम्बद्धता 37 33% है। गामा निर्देशाक तथा अल्फा निर्देशाक के सम्बद्धता प्रतिशत मे अन्तर का कारण है, अल्फा निर्देशाक उन्हीं सडक जालों के लिए उपयुक्त है जिनमे कई असम्बद्ध ग्राफ हों।

6 ६ यातायात प्रवाह

यातायात प्रवाह से न केवल परिवहन की कार्यात्मक विशिष्टताए स्पष्ट होती है अपितु क्षेत्रीय आर्थिक कार्यकलाप, आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध प्रतिरूप एव आर्थिक विकास का स्तर भी ज्ञात होता है। साधारणत यातायात प्रवाह के अन्तर्गत वस्तुओं एव यात्रियों के आवागमन प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण के अन्तर्गत तीन बातो का अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम, वस्तुओं के उद्गम गन्तव्य स्थलों पर आने-जाने से व्यापारिक स्वरूप का बोध होता है, द्वितीय, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रतिमाह परिवहन मार्ग पर कुल यातायात घनत्व का पता चलता है तथा तृतीय, परिवहन के साधनों तथा परिविहत वस्तुओं की सरचना के बारे मे जानकारी मिलती है। परिविहत वस्तुओं के सरचना मे परिवर्तन का प्रभाव परिवहन साधनों पर पडता है।

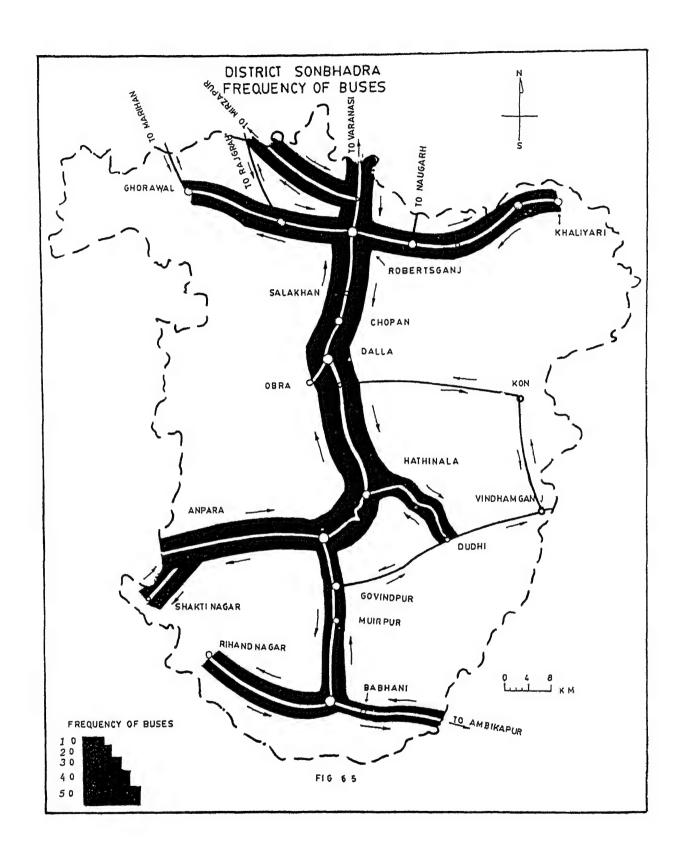
यातायात प्रवाह के उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से इस क्षेत्र के वर्तमान यातायात प्रवाह के स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। किन्तु किसी निर्धारित मापदण्ड के अभाव में यह निश्चित कर पाना कठिन है कि विद्यमान यातायात प्रवाह घनत्व की स्थिति पिछडी अर्थव्यवस्था का द्योतक है या विकसित अर्थव्यवस्था का, दूसरे, संसाधनों की कमी तथा समय के अभाव में इनके प्रवाह के आकडों का सगृहण सभव नहीं हो सका।

चूिक सोनभद्र विविधता युक्त जनपद है तथा इसमे समरूपता का अभाव है। इसलिए यातायात प्रवाह का विशेष महत्व है। अध्ययन क्षेत्र के तीन विकास खण्डों (चतरा, राबर्ट्सगज व घोरावल) मे अच्छी खेती होती है, इसे कृषि प्रधान विकास खण्ड कहा जा सकता है। तीन विकास खण्ड (म्योरपुर, चोपन व राबर्टसगज) बड़े उद्योगों से युक्त है तथा जनपद का अधिकाश हिस्सा जगली तथा पठारी है। म्योरपुर विकासखण्ड मे कोयले की खानें है। औद्योगिक

क्षेत्रों मे खाद्यान्नों, सिब्जियों तथा दुग्ध आदि की आपूर्ति कृषि प्रधान विकास खण्डों से सडक परिवहन से होता है। ताप विद्युत गृहों के लिए कोयले की आपूर्ति, सीमेट उद्योग के लिए चूना पत्थर की आपूर्ति, अल्यूमीनियम उद्योग के लिए बाक्साइट की आपूर्ति तथा विनिर्मित वस्तुओं यथा सीमेट, अल्यूमीनियम, केमिकल्स, सोडा व चूना आदि को दूरवर्ती क्षेत्रों मे भेजने के लिए अधिकाशत ट्रकों का उपयोग किया जाता है। बालू व बजरी का परिवहन न केवल स्थानीय आवश्यकता के लिए किया जाता है वरन् अन्तर्प्रादेशिक क्षेत्रों में भी भेजा जाता है। बड़े उद्योगा की स्थापना से यात्रियों का आवागमन दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है। बाहर से जनपद में आने वाली वस्तुओं तथा जनपद से बाहर जाने वाली वस्तुओं के लिए ट्रकों व रेलगाडियों का उपयोग होता है। बंधियों, सडकों के निर्माण तथा भूमि के समतलीकरण केलिए मिट्टी को ट्रैक्टर व ट्रकों द्वारा दुलाई की जाती है। पहाडी क्षेत्रों में मुख्य सडकों से गोंवीं को जोडने के प्रमुख साधन बैलगाडी है। इक्का, साइकिलों, बैलगाडियों, ट्रेक्टरों, टेक्सी आदि का उपयोग यात्रियों एव वस्तुओं के एकत्रीकरण व विकेन्द्रीकरण के लिए होता है। मौसम के अनुसार यातायात में परिवर्तन दृष्टि गोचर होता है।

किन्तु यातायात प्रवाह के उपर्युक्त आकर्डों का एकत्रीकरण निश्चित समय के अन्दर असम्भव है। दूसरे, यातायात प्रवाह में परिवर्तन बहुत अधिक होता है। वास्तव में यातायात प्रवाह अनेक परिवर्त्यों पर निर्भर करता है। इसिलए यात्रियों के आवागमन के आधार पर यातायात प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। यात्रियों का यह प्रवाह सड़को पर चलने वाले व्यक्तिगत तथा सरकारी बसों के माध्यम से मापने का प्रयास किया गया है। सड़कों पर चलने वाली बसो की गणना व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर की गयी है। बसों की सम्पूर्ण सख्याओं का योग उनके (बसों के) आने व जाने के सदर्भ में किया गया है। सोनभद्र में बसों का प्रवाह मानचित्र 6 5 में प्रदर्शित हैं।

राबर्टसगज से रेनूकूट तक प्रतिदिन लगभग 100 यात्री बसों का आवागमन होता है। मीरजापुर से व वाराणसी से आने वाली बसें हिन्दुआरी तिराहे से होकर राबर्ट्सगज में प्रवेश करती है, इनमें से अधिकाश शक्तिनगर, रिहन्द नगर के लिए जाती है। अध्ययन क्षेत्रं में सर्वाधिक यातायात प्रवाह इसी मार्ग पर सम्पन्न होता है।



रेनूकूट से अनपरा, बीना से होते हुए शक्तिनगर मार्ग पर लगभग 70 बसे प्रतिदिन गुजरती है। खिलयारी से घोरावल मार्ग पर भी लगभग 65-70 बसो का आवागमन होता है। उल्लेखनीय है कि इस मार्ग पर केवल प्राइवेट बसें ही चलती है। जनपद का मुख्यालय दोनो ही सेवा केन्द्रों (खिलयारी व घोरावल) के लगभग मध्य मे पडता है। रेनूकूट से रिहन्द नगर मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 50 बसों का आवागमन होता है। दुढ़ी मार्ग पर लगभग 40 बसो का, शाहगज से राजगढ मार्ग पर 10 बसो का, घोरावल से मिडहान मार्ग पर 16 बसों का, विण्ढमगज से दुद्धी मार्ग पर 25 बसों का, विण्ढमगज से वोन मार्ग पर 20 बसों का तथा बभनी मार्ग पर भी 20 बसों का आवागमन होता है ।

तालिका 6 6 जनपद मुख्यालय राबर्ट्गज से प्रमुख सेवा केन्द्रों व बस स्टेशनों की दूरी

क्रमसंख्या	सेवाकेन्द्र/बस स्टैशन/बस स्टाप	राबर्टसगज से दुरी किमी0 मे	•
l	पसही	8	•
2	ककराही	13	
3	खैराही	16	
4	करमा	23	
5	चुर्क	8	
6	मारकुण्डी	16	
7	सलंखन	21	
8	चोपन	27	
9	डाला	37	
10	ओबरा	39	
11	हाथीनाला	58	
12	रेनूकूट	72	
13	पिपरी	75	
14	अनपरा मोड़	105	
15	बीना	127	
16	शक्तिनगर	142	
17	दुद्धी	79	
18	विण्ढमगज	144	

19	गोविन्दपुर	92	
20	म्योरपुर	104	
21	बभनी	142	
22	रामगढ	18	
23	रिहन्द नगर	172	
24	खलियारी	36	
25	घोरावल	30	

स्रोत राबर्ट्सगज बस स्टिशन की पट्टिका से सगृहित ।

6 7 परिवहन तन्त्र का नियोजन

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे जल परिवहन नगण्य है। वायु परिवहन नही होता है, यद्यपि म्योरपुर के निकट हवाई पट्टी है। साथ ही रेल व सडक परिवहन का भी समुचित विकास नहीं हुआ है। रज्जुमार्ग का प्रयोग सीमित स्तर पर होता है। अध्ययन क्षेत्र मे अनेक ऐसे सेवा-केन्द्र है जो पक्की सड़कों से जुड़े हुए नही है। जनपद के समाकितत विकास के लिए परिवहन सुविधाओं का बढ़ाया जाना आवश्यक है, बड़े औद्योगिक केन्द्रों को अच्छी सड़कों से जोड़ दिया गया है परन्तु जनपद का अधिकाश भाग स्वतन्त्रता के 45 वर्ष बाद भी सड़कों से अभिगम्य नहीं है। परिवहन के विकास के लिए आवश्यक है कि एक समन्वित कार्य योजना तैयार किया जाय। अध्ययन क्षेत्र का 10 वर्षीय परिवहन नियोजन प्रस्तुत है। प्रस्तुत अध्ययन मे ग्रामीण कच्ची तथा खड़जा सड़कों की समस्याओं को देखते हुए उनके विकास के लिए विशेष बल दिया गया है।

(अ) रेल मार्ग

अध्ययन क्षेत्र मे अवस्थित सम्पूर्ण इकहरी रेलवे लाइन को दोहरी (डबल) रेलवे लाइन मे बदलने की आवश्कता है, जिससे यात्री गाडी व माल गाडी परिचालन मे व्यवधान न हो। दिन- प्रतिदिन, चलने वाली मालगाडियों की बढ़ती सख्या को देखते हुए यह और भी आवश्यक हो गया है।

राबर्टसगज से रामगढ पन्नूगज, बैनी, खिलयारी होते हुए सहसाराम (बिहार) तक एक नयी रेलवे लाइन बनाने की जरूरत है। इसके लिए कर्मनाशा नदी (सोनभद्र व भभुआ की सीमा)पर एक पुल बनाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित रेलमार्ग का सम्पूर्ण क्षेत्र समतल तथा कृषि प्रधान क्षेत्र है। अत निर्माण में अधिक आर्थिक विनियोग की भी आवश्यकता नहीं है।

(ब) जल मार्ग

180 वर्ग मील क्षेत्र मे फैले रिहन्द जलाशय के चारों तरफ फैले औद्योगिक नगरों (रिहन्द नगर, अनपरा, रेणूसागर, शिक्तनगर, पिपरी, रेनूकूट व मध्य प्रदेश स्थित विध्यनगर) के बीच जल परिवहन की पर्याप्त सम्भावनाए है। इससे न केवल यात्रियों बिल्क वस्तुओं का भी परिवहन किया जा सकता है। वर्तमान समय मे मात्र रिहन्द नगर से शिक्तनगर के बीच जल परिवहन की सुविधा है। रिहन्द जलाशय मे जल परिवहन की सुविधा बढने से समय तथा दूरी दोनो की बचत होगी। इसके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र मे जल परिवहन के नाम पर, पुलों के अभाव मे निदयों को पार करना मात्र है। पुलों का निर्माण करके नावों का चलाना बन्द करना आवश्यक है। क्योंकि निदयों के पहाडी व बरसाती स्वभाव मे वारण बहुधा दुर्घटनाए होती रहती है।

(स) वायु मार्ग

म्योरपुर के निकट स्थित हवाई पट्टी को आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करके साप्ताहिक वायु परिवहन शुरू करना चाहिए। निकट भविष्य में अध्ययन क्षेत्र वृहद औद्योगिक पेटी के रूप में विकसित होगा इसे देखते हुए वायु परिवहन का विकास करना आवश्यक है।

(द) रज्जु मार्ग

शक्तिनगर, अनपरा, ओबरा में भी रज्जुमार्ग सेकोयले की ढुलाई करना सुविधा जनक होगा। समीप के सिगरौली कोयला क्षेत्र से उपर्युक्त ताप विद्युत गृहों के लिए कोयले की ढुलाई से, सडकों पर न केवल परिवहन साधनों का दबाव कम होगा बल्कि मानव शक्ति की बचत व प्रदुषण से मुक्ति भी मिलेगी।

(य) सडक मार्ग

अध्ययन क्षेत्र मे सडक मार्ग परिवहन तन्त्र का आधार है। सर्वप्रथम वर्तमान पक्की सडकों मे सुधार की आवश्यकता है। करमा- शक्तिनगर मार्ग, रेनूकूट - रिहन्द नगर मार्ग तथा हाथी नाला - विण्डमगज ग्रार्ग को और चौडा करने की जरूरत है क्योंकि इन पर बसों के अतिरिक्त ट्कों का प्रवाह दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है।

घोरावल से खिलयारी सडक मार्ग को चौडा करके दुगुना करने की जरूरत है। इस इकहरे सडक मार्ग पर बसो का प्रवाह, अत्यधिक है। खिलयारी से पूर्व की ओर कर्मनाशा नदी पर पुल बनाकर घोरावल खिलयारी मार्ग को पक्की सडक से बिहार स्थित भभूवा से जोडने की आवश्यकता है। घोरावल से वर्दिया होते हुए कैमूर पहाडियों को पार करके वर्दिया से मध्य प्रदेश स्थित देउरा गॉव तक 9 किमी0 लम्बी सडक बनाने से घोरावल का रीवा से सम्पर्क हो जाएगा । सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे स्थित कुल 44। किमी० खडजा सडकों को पक्की सडकों मे बदलने की आवश्यकता है, क्योंिक बरसात के दिनों मे अपरदन से बस्तियों की सड़कों से अभिगम्यता और कम हो जाती है। विगत दो वर्षों मे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनेक गाँवों को खड़जा मार्ग से पक्की मड़कों से जोड़ा गया। किन्तु मार्गों पर जैविक अपरदन (पशुओं से) व यान्त्रिक अपरदन (ट्रैक्टर व बैलगाडी से) होने से, उद्देश्यो को पूरा करने मे अत इन सभी लघु सम्पर्क मार्गों को पक्की सडक मे बदलने की जरूरत है। दुद्धी के पास कनहर नदी पर खलियारी के पास कर्मनाशा नदी पर कोन के पास पाण्डु नदी पर तथा सोन नदी पर गुरूदह, ससनई, चकरिया, हरदी मे पुल बनाने की आवश्यकता है। चोपन मे सोन नदी पर बने पुल की मरम्मत करने व एक नया पुल बनाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण सडक मार्ग

ग्रामीण सडक ग्रामीण विकास का आधार है। अध्ययन क्षेत्र की 87% ग्रामीण जनसंख्या को नगरों, औद्योगिककेन्द्रों, विकासकेन्द्रों तथा मुख्यसंडकों से जोड़ने के लिए सडकों का जाल होना आवश्यक है। कृषि उपज तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादों की विपणनीय सुविधाए, ग्रामीण सडकों पर बहुत निर्भर करती है। गाँवों को, सडकों द्वारा मण्डियों से जोड़कर गाँवों का बहुमुखी विकास किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र के पिछडेपन को ग्रामीण सडकों के अभाव ने और पिछडा बना दिया है। ग्रामीण सडकों से सम्बन्धित निम्न सुझाव प्रस्तुत है -

- । ग्रामीण यातायात के प्रमुख साधन बैलगाडी मे तकनीकी दृष्टि से सुधार करना चाहिए जिससे ग्रामीण सडकों को क्षति न पहुँचे ।
- 2 गाँवों को मुख्य सडक से जोडने वाली सहायक खडजा सडकों को पक्की सडक में बदला जाय ।
- 3 बैलगाडी के साथ-साथ अब मोटर परिवहन साधन भी गाँवों मे तेजी से पहुँच रहे है। अत सडकों की मरम्मत की व्यवस्था नियमित होनी चाहिए ।
- 4 ग्रामीण क्षेत्रों मे गूँ तो कच्ची सडकों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए किन्तु पक्की सडकों से जुडने वाले सम्पर्क मार्ग को पक्की होनी चाहिए।
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने के लिए ऐच्छिक श्रम अर्थात श्रमदान को प्रोत्साहित करना चाहिए । राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के द्वारा भी ग्रामीण सड़कों का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है ।
- 6 सडक जाल इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी गाँवों का सम्पर्क सेवा केन्द्रों से हो जाय।
- 7 राज्य सरकार को ग्रामीण सडकों के निर्माण मे स्वैच्छिक सस्थाओं से सहयोग लेना चाहिए। सडको के नियमित भाग के रख-रखाव की जिम्मेदारी बाँटी जा सकती है। ग्राम पचायतों एव सहकारी सस्थाओं का इसमे व्यापक सहयोग लिया जा सकता है।

68 सचार व्यवस्था

पिछडे क्षेत्रों के विकास में सचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचार माध्यमों से नवीनताओं का प्रसरण होता है जो पिछड़ेपन को दूर करने में सहायक होता है। विकसित सचार सेवाए आधुनिक समय की अनिवार्य आवश्यकता है। राजनैतिक जीवन, सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यावसायिक प्रबन्ध, कृषि तथा अन्य विस्तार सेवाएँ, उन्नत शैक्षिक प्रविधियाँ, विज्ञापन, उद्योग, मनोरजन क्रियाए, समाचार-पत्र और व्यक्तिगत मामलों का सचालन आदि सभी सचार के अधिक साधनों की माँग करते है। 16

सदेश, विचार एव सूचनाओं इत्यादि के आदान-प्रदान को सचार कहते है। विकास के लिए परिवहन जैसा सचार भी आवश्यक है। सचार माध्यमों को दो वर्गों मे वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रथम - व्यक्तिगत सचार माध्यम तथा द्वितीय जनसचार माध्यम । व्यक्तिगत सचार माध्यम के अन्तर्गत, डाक, तार तथा दूरभाष आदि आते है। ये वैयक्तिक सेवाए प्रदान करने के साथ उद्योगों को बढावा देते है। रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाए तथा सिनेमा आदि जनसचार के माध्यम है जो सूचना, ज्ञान, विचारों, भवनाओं तथा शिल्प आदि का सकेत-चिन्हों, शब्दों, चित्रों तथा आरेखों द्वारा प्रभावशाली प्रसारण करते है। 17

(अ) व्यक्तिगत सचार

सम्प्रति जनपद मे 136 डाकघर, 16 तारघर, 43 पी०सी०ओ० (पिंबलक काल आफिस) तथा 1258 दूरभाष सेवा सम्पर्क है ।

तालिका 6 7 सोनभद्र जनपद में उपलब्ध सचार सेवाए

वर्ष	डाकषर	तारघर	पब्लिक काल आफिस	दूरभाष सेवा
	2	3	4	5
1989-90	133	13	24	1153
1990-91	133	13	24	1175
1991-92	136	16	43	1258

1	2		3	4	5
विव	कास खण्ड 199	01-92			
1	घोरावल	16	-	l	20
2	राबर्ट्सगज	17	ı	4	15
3	चतरा	11	1	2	12
4	नगवा	11	-	l	-
5	चोपन	21	1	8	32
6	म्योरपुर	22	5	8	350
7	दुद्धी	16	-	2	16
8	बभनी	11	-	1	-
योग	ग ग्रामीण	125	8	27	445
योग	ग नगरीय	11	8	16	813
योग	ग जनपद	136	16	43	1258
			_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
स्रोत	त सांख्यिकी	य पत्रिका, ज	नपद सोनभद्र, ।	992, पृष्ठ 108	

(।) डाक सेवा

भारत में आधुनिक डाक प्रणाली सर्वप्रथम 1837 में प्रारम्भ हुई। 1854 में डाक विभाग तथा 1880 में मनीआर्डर प्रणाली प्रारम्भ हुई। रेलवे डाक सेवा 1907 तथा हवाई डाक सेवा 1911 में प्रारम्भ हुई। फलस्वरूप द्वत डाक सेवा, अिकत डाक सेवा (रिकार्डेड डिलीवरी) और द्वतगामी डाक सेवा (स्पीड पोस्ट) जैसे कार्यक्रम शुरू किये गये हैं किन्तु सोनभद्र इससे अभी तक अछूता ही है। जनपद सोनभद्र में कुल डाकघरों की सख्या 1991-92 में 136 थी। भारत में एक डाकघर से औसतन 4731 लोगों को सेवाए उपलब्ध होती है जबिक सोनभद्र जनपद में एक

अध्ययन क्षेत्र मे हवाई मार्ग व हवाई अङ्डा न होने के बारण सीधे हवाई डाक सेवा उपलब्ध नहीं है।

(2) तार सेवा

अध्ययन क्षेत्र मे कुल 16 तारघर है । कुल तारघरों मे से 50% (8) तारघर नगरीय क्षेत्र मे तथा 50% (8) तारघर ग्रामीण क्षेत्रों मे है । तारघरों की अवस्थिति नगरीय क्षेत्रों मे राबर्ट्सगज, घोरावल, दुद्धी, चुर्क, चोपन, ओबरा, रेनूकूट व पिपरी मे है । अन्य तारघरों वी अवस्थिति शक्तिनगर, अनपरा, रिहन्द नगर, रेणू सागर, बीना , डाला, रामगढ व बढौली मे है । जनपद के 89 49% (1201) गाँव तारघरों की सुविधा से 5 कि0 मी0 दूर स्थित है (तालिका 69)। विकासखण्ड नगवा, घोरावल, दुद्धी व बभनी के ग्रामीण क्षेत्र मे एक भी तारघर उपलब्ध नहीं है (तालिका 67) । उपर्युक्त तथ्य से तारसेवा की अभावग्रस्तता एव पिछडेपन का ज्ञान होता है ।

(3) दूरभाष सेवा

वर्तमान समय मे दूरभाष सेवा को आदिवासी क्षेत्र सिंहत ग्रामीण क्षेत्र तक बढाया जा रहा है । सरकार की नीति का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गाँव से 5 कि0 मी0 की दूरी के अन्दर एक दूरभाष सेवा दी जाय । तालिका 6 6 से स्पष्ट है कि जनपद सोनभद्र मे कुल 1258 दूरभाष सेवा सम्पर्क है, इसमे से 445 (35 35%) ग्रामीण क्षेत्र मे तथा 813 (64 65%) नगरीय क्षेत्र मे है । सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के दूरभाष सेवा सम्पर्क का 78 65% (350) विकासखण्ड स्योरपुर मे है, जबिक नगवा व बभनी मे एक भी नही है (तालिका 6 7)। अध्ययन क्षेत्र के 87 48% (1174) गाँव दूरभाष सेवा सम्पर्क से, 5 कि0 मी0 से अधिक दूर स्थित है (तालिका 6 9) । उपर्युक्त तथ्य से जनपद के पिछडेपन का सकेत मिलता है। अध्ययन क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र मे पी.सी ओ (पिब्लिक कॉल आफिस) की कुल सख्या 16 है, जिसमे से राबर्ट्सगज मे 2, चुर्क मे 1, ओबरा मे 2, रेनूकूट मे 4, पिपरी मे 1, शकितनगर मे 2, अनपरा मे 2, चोपन मे 1 तथा रिहन्द नगर मे 1 है । जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास केन्द्रों मे पी सी ओ की सख्या 27 है जिसमे से विकास खण्ड स्योरपुर व चोपन मे आठ - आठ, राबर्ट्सगज मे चार, चतरा व दुखी मे दो - दो, घोरावल, नगवा व बमनी मे एक - एक है।

तालिका 6 8 सोनभद्र जनपद के गाँवों मे उपलब्ध सचार सेवाए 1991-92

क्रमसर	ड्या विकासखण्ड	सुविधाए	गॉंव मे उपलब्ध	।किमी0 से कम दूरी	।-3िकमी0 की दूरी	3-5िकमी0 की दूरी	5िकमी0 से अधिक	योग
1	घोरावल	डाकघर	46	11	33	38	239	337
		तारघर	-	-	-	14	323	337
		दूरभाष	1	22	19	35	260	337
2	राबर्टसगज	डाकघर	17	8	91	85	128	329
		तारघर	1	-	34	34	260	329
		दूरभाष	4	2	12	21	290	329
3	चतरा	डाकघर	11	12	9	45	91	168
		तारघर	1	3	3	8	153	168
		दूरभाष	2	3	3	8	152	168
4	नगवा	डाकघर	11	2	1	15	99	128
		तारघर	-	-	_	-	128	128
		दूरभाष	1	-	-	-	127	128
5	चोपन	डाकघर	21	9	10	11	48	91
		तारघर	1	-	2	1	87	91
		दूरभाष	-	-	-	-	91	91
6	म्योरपुर	डाकघर	22	-	10	14	74	120
		तारघर	5	••	1	8	106	120
		दूरभाष	-	-	-	7	105	120
7	दुद्धी	डाकघर	16	4	21	17	40	98
		तारघर	**	-	13	12	73	98
		दूरभाष	2	-	12	5	79	98
8	बभनी	डाकघर	11	-	2	-	58	71
		तारघर	-	-	-	-	71	71
		दूरभाष	l 	-	_	_	70	71
योग प	न नपद	डाकघर	125	46	177	225	769	1342
		तारघर	8	3	53	77	1201	1342
		दूरमाष	19	27	46	76	1174	1342
				an Ma you have had bee you -				

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पुष्ठ 157, 158 व 159

तालिका 6 9 सोनभद्र जनपद के गाँवों मे उपलब्ध सचार सेवाए 1991-92

							·	
क्रमसर	ड्या विकासखण्ड -	सुविधाए	उपलब्ध सेव					
			गाँव मे	_		0 3-5िकमी0		योग
			उपलब्ध		की दूरी	की दूरी	से अधिक	
				दूरी				
1	घोरावल	डाकघर	4 75	3 26	9 79	11 28	69 92	100
•		तारघर	- 70	-	-	4 15	95 85	100
		दूरभाष	0 30	6 53	5 68	10 39	77 15	100
2	राबर्ट्सगज	डाकघर	4 75	3 26	9 79	11 28	70 92	100
_		तारघर	0 03	-	10 33	10 33	79 03	100
		दूरभाष	1 22	0 61	3 65	6 38	88 15	100
3	चतरा	डाकघर	6 55	7 14	5 36	26 79	54 17	100
Ü	1111	तारघर	0 60	1 79	1 79	4 76	91 07	100
		दूरभाष	1 19	1 79	1 79	4 76	90 48	100
4	नगवा	डाकघर	8 59	1 56	0 78	11 72	77 34	100
4	1 (2)	तारघर	6 39	- 50	0 76	-	100 00	100
		दूरभाष	0 78	-	_	_	99 22	100
5	चोपन	डाकघर	23 08	9 89	10 99	12 09		
3	4141	तारघर	1 10				52 75	100
			1 10	~	2 20	1 10	95 60	100
_		दूरभाष	-	-	0.00		100 00	100
6	म्योरपुर	डाकघर	18 33	-	8 33	11 67	61 67	100
		तारघर	4 17	-	0 83	6 67	88 33	100
_	0	दूरभाष	6 67	•	-	5 83	87 50	100
7	दुर्खी	डाकघर	16 33	4 08	21 42	17 35	40 82	100
		तारघर	-	-	13 27	12 24	74 49	100
		दूरभाष	2 04	•	12 24	5 10	80 61	100
8	बभनी	डाकघर	15 49	***	2 82	-	81 69	100
		तारघर	-	-	•	=	100 00	100
		दूरभाष	1 41	**	=	-	98 59	100
योग स	म्पूर्ण जनपद	डाकघर	9 31	3 42	13 19	16 77	57 30	100
	4	तारघर	0-60	0 22	3 95	5 74	89 49	100
		दूरमाष	1 42	2 01	3 42	5 66	87 48	100
								o one care that one care game shall next new days being who

स्रोत तालिका 68 से सगिपत ।

(ब) जनसचार

इलेक्ट्रानिक तथा मुद्रण जनसचार के प्रमुख माध्यम है । इलेक्ट्रानिक्स के अन्तर्गत रेडियो, दूरदर्शन तथा चलचित्र प्रमुख है । सगीत, मनोरजन, शिक्षा, समाचार, विज्ञापन, सवाद, सूचना आदि के प्रसारण के लिए रेडियो एक सशक्त माध्यम है । खेलों, स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस व अन्य प्रमुख घटनाओं के आँखो देखा हाल का प्रसारण रेडियो को और जीवन्त बना देता है । बम्बई और कलकत्ता के दो निजी स्वामित्व वाले ट्रासमीटरों की सहायता से सर्वप्रथम 1927 मे रेडियो प्रसारण प्रारम्भ हुआ । 1930 मे सरकार ने इसे अपने हाथ मे लेकर 'भारतीय प्रसारण सेवा' प्रारम्भ किया। 1936 मे इसका नाम बदलकर 'आल इण्डिया रेडियो' रखा गया और 1957 के बाद से इसे 'आकाशवाणी' कहा जाता है । सोनभद्र जनपद के सम्पूर्ण भाग पर रेडियो प्रसारण पहुँचता है किन्तु इसका लाभ लगभग 20% परिवार ही ले पाते है गरीबी व अशिक्षा के कारण लोगों को रेडियो सेट उपलब्ध नहीं है ।

दूरदर्शन दृश्य - श्रव्य माध्यम है । दूरदर्शन से उपर्युक्त तथ्यों को न केवल सुना जाता है वरन् देखा भी जाता है । भारत मे दूरदर्शन की शुरूवात सितम्बर 1959 में हुई जब एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र खोला गया । अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत आता है किन्तु आर्थिक विपन्नता व विद्युतीकरण के अभाव के कारण कुछ सम्पन्न वर्ग ही इस सुविधा का उपयोग कर रहे है । ओबरा (विकासखण्ड चोपन) में हाल में ही दूरदर्शन स्टुडियों केन्द्र खोला गया है जिसे शीघ्र ही कार्यरूप (प्रवश्रन) में आने की सम्भावना है ।

चलचित्र भी जनसचार का सशक्त माध्यम है । इससे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व धार्मिक समस्याओं तथा निदान के अभिप्रेरण हेतु उसका चित्रण लोगों तक पहुँचाया जाता है । जनपद मे इस समय 5 चलचित्र घर (सिनेमाघर) चल रहे है । राबर्ट्सगज ओबरा, रेनूकूट, अनपरा तथा रिहन्दनगर मे एक - एक सिनेमाघर है । जनपद के 21 विकास केन्द्रों मे कई विडियो हाल चल रहे है ।

जनसचार का एक प्रमुख माध्यम मुद्रण भी है । जनपद मे दैनिक जागरण, आज, जनमोर्चा, स्वतन्त्र भारत, नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र प्राप्त किए जा सकते है। जनपद मुख्यालय राबर्ट्सगज तथा ओबरा, रेनूकूट, शिक्तिनगर व रिहन्द नगर आदि प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में अग्रेजी में छपने वाले दैनिव अखबार (हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया) भी एक दिन बाद प्राप्त किया जा सकता है । साक्षरता प्रतिशत कम होने के कारण इन अखबारों का उपयोग बहुत कम होता है । जनपद से किसी स्थानीय अखबार या पित्रका का मुद्रण नहीं होता है । दैनिक जागरण में प्रतिदिन सोनभद्र समाचार छपता है ।

69 सचार नियोजन

किसी भी क्षेत्र के विकास में सचार माध्यमों की प्रभावी भूमिका होती है। सर्वप्रथम जनपद में डाक सेवा को कार्यक्षम बनाने के लिए प्रत्येक बस्ती से 5 कि0 मी0 की दूरी के अन्दर डाकघर सेवा उपलब्ध करायी जानी चाहिए । सभी डाकघरों को पक्की सडक से जोडना चाहिए । नदी - नालों पर पुल बनाकर डाक वितरण की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है । पहाडी भागों में डाक वितरण के लिए पोस्टमैन को कुछ अतिरिक्त सुविधा या पैसा प्रदान कराना चाहिए । डाक वितरण प्रतिदिन हो, इसके लिए प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के पास एक उपस्थिति रिजस्टर होना चाहिए, जिस पर पोस्टमैन स्वय आकर हस्ताक्षर करे और पत्र वितरण करे । प्रत्येक गाँव में एक पत्र पेटिका अवश्य लगानी चाहिए। प्रत्येक न्याय प्रचायत में कम - से - कम एक टेलीफोन केन्द्र अवश्य होना चाहिए । जनपद के सभी लोग दूरदर्शन की सुविधा को प्राप्त कर सके, इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक गाँव में विद्युत उपलब्ध करानी चाहिए, तत्पश्चात् सरकार की ओर से प्रत्येक ग्राम सभा में दो टेलीविजन सेट उपलब्ध करानी चाहिए।

समाचार पत्रों के मुद्रण के उद्देश्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अध्ययन क्षेत्र मे पिछले कुछ वर्षों मे औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के बावजूद आज भी वास्तविक सोनभद्र गाँवों मे बसा है । लगभग 87% लोग गांवों मे रहते है तथा ऐसे लोगों का प्रतिशत भी काफी है जो नगरों मे रहते हुए या काम करते हुए भी गाँवों से सम्पर्क बनाए रखते हैं। इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र मे ग्रामीण रिपोर्टिंग का महत्व काफी है । लेकिन अखवारी क्षेत्रों मे ग्रामीण रिपोर्टिंग को खास महत्व नहीं दिया जा रहा है । गाँवों के बारे मे समाचार देने की दिखावटी प्रशसा भले ही की जाती है और कुछ पत्रकार नियमित रूप से समाचार लेने के लिए गाँवों मे जाते भी है किन्तु सामान्य तौर पर पत्रकारिता की प्राथमिकताओं की सूची मे

ग्रामीण रिपोर्टिंग का स्थान बहुत नीचे है । चुनाव, किसान रैलियों तथा अन्य राजनीतिक समाचारों को ही अधिक महत्व मिलता है । इन राजनीतिक समाचारों की भी अच्छी रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों का नियमित रूप से गांवों में जाना अनिवार्य है । पत्रकारों का ग्रामीण रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य गांवों के लोगों, विशेषकर वहाँ के कमजोर वर्गों की वास्तविक सामाजिक आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना तथा उन उपायों का मूल्योंकन करना होना चाहिए जो इन समस्याओं को हल करने और कमजोर वर्गों की सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारने के लिये किये जा रहे है ।

सचार आयोजना के लिए जरूरी हैं कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत, विशिष्टता और प्रभुसत्ता का भान सदैव रहना चाहिए । इसमें आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन को गृहण करने के साथ - साथ परम्परा की निरन्तरता को जीवन्त बनाए रखना चाहिए । प्रेस की वास्तिवक शिक्त जिला या मण्डल स्तर पर उस क्षेत्र की भाषा में प्रकृषित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं के विकास में निहित हैं । रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म के विपरीत प्रेस जैसे माध्यम को स्थापित होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि आधारभूत ढाँचे का विस्तार ही इसके विकास के लिए आवश्यक नहीं हैं । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, प्रकृषित सामग्री को पढ़ने के लिए क्षमता और रूचि का विकास करना । प्रेस के लिए यह आवश्यक है कि हमारी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित विकास हेतु साक्षरता के आधार को व्यापक बनाया जाए । केरल के मलयालम प्रेस से यह साबित होता है कि साक्षरता के कारण ही पत्र - पत्रिकाओं की प्रसार सख्या में बृद्धि होती हैं । जनसम्पर्क माध्यम और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी प्रास्तिक और लचीली, गैर विशिष्ट वर्गीय और सहभागिता के दृष्टिकोण वाली होनी चाहिए । पिछंडे क्षेत्र के लोगों को सहभागी लोकतन्त्र के लिए सक्षम बनाने तथा विकासोन्मुखी समाज की शुद्धात करने के लिए सचार नियोजन और जनसम्पर्क माध्यमों की नीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

सन्दर्भ

- । कुरैशी, एम०एच० भारत का भूगोल, ससाधन तथा प्रादेशिक विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1978, पृ० 100
 - 2 मिश्र, एस०के० व पुरी, वी०के० भारतीय अर्थव्यवस्था, 1991, पुष्ठ 867
- 3 कुरैशी, एम०एच०.भारत ससाधन और प्रादेशिक विकास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण परिषद्, 1990, पृष्ठ 102
 - 4 वही, प्रष्ठ 101
 - 5 सिंह, जगदीश परिवहन तथा व्यापार भूगोल, 1977, पृष्ठ 4
 - 6 वही, प्रष्ठ 38
- 7 Thomas, R L 'Transportation and Development of Malaya', A A A G Vol 65, No 2, P 67
- 8 Qureshi, M H India Resources and Regional Development, N C E R T , New Delhi, 1990, p $\,$ 67
 - 9 Op c1t, fn 3 p 66
- 10. Singh, J Parivahan and Vyapar Bhoogol, Uttar Pradesh Hindi Sansthan, Lucknow, 1977, p 48
- 11. Prasad, U River Transport in UP Unpublished Ph D Thesis, Geography Deptt B H U, Varanasi, 1943, cited in Environmental Planning Resources and Development by R K Pathak, Chugh Publication, Allahabad, 1990, p 181.
 - 12 Op cit, fn 10, 149
- 13. Babu, R Micro-level Planning A case study of Chhibramau Tahsil, Unpublished Ph D Thesis, Geography Deptt, Allahabad University, 1981, p 244
 - 14. Ibid, p 245
 - 15. Ibid p
- 16. गिला के 0 यस । भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुस्रधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली पृष्ठ 204
- 17. Parakh, Bhalchandra Sadashive India Economic Geography, N C E R T., New Delhi, P 151

अध्याय 7

सामाजिक सुविधाओं की पृष्ठभूमि एव विकास - नियोजन

अर्थिक विनियोग के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिससे तत्काल व प्रत्यक्ष लाभ वृद्धियात होता है तथा कुछ क्षेत्रों में विनियोग से अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। यह अप्रत्यक्ष विनियोग विकास का आधार स्तम्भ है तथा विकास की दीर्घकालीन रणनीति इन्हीं विनियोगों पर आश्रित होती है। अप्रत्यक्ष व अनुत्पादक विनियोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरजन जैसे सामाजिक सुविधाए प्रमुख है। किन्तु ये क्षेत्र मनुष्य की कार्यकुशलता की वृद्धि में अभिप्रेरण होने के कारण इस तरह का विनियोग महत्वपूर्ण तथा उत्पादक विनियोग के अन्तर्गत गिना जाने लगा है। इन सामाजिक सुविधाओं को विकास का सूचक माना गया है। इसलिए सामाजिक सुविधाओं के नियोजन को सम्पूर्ण विकास के नियोजन का एक महत्वपूर्ण अग माना जाता है। मानव के सास्कृतिक एव भौतिव विकास प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा एव स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाओं से प्रभावित होता रहता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान निर्माताओं ने शिक्षा एव स्वास्थ्य से सम्बन्धित तथ्यों को मौलिक अधिकारों एव राज्य की नीति निर्दशक तत्यों के अन्तर्गत समाहित किया है। जिसकी प्राप्ति हेतु सरकार ने छठी प्रचवर्षीय योजना में संशोधित न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम को अपनाने पर बल दिया है। 3

'भोजन, कपडा और मकान' के बाद मनुष्य की आवश्यव आवश्यकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रमुख स्थान है। उत्तम स्वास्थ्य व शिक्षा से ससाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, सीमित ससाधनों को विकसित किया जा सकता है तथा नये ससाधनों को खोजा जा सकता है। अत प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं दो तथ्यों (शिक्षा एव स्वास्थ्य) को नियोजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा एव स्वास्थ्य के नियोजन हेतु जनपद में उसके वर्तमान प्रतिरूप का योजना आयोग के लक्ष्यों से सहसम्बन्धित कर विश्लेषित किया गया है।

7। शिक्षा

शिक्षा वह सम्बल है, जिसके सहयोग से मानव विकास प्रक्रिया मे अपनी सही भूमिका का चयन और निर्वहन करता है तथा समाज व राष्ट्र के विकास मे अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर 'सत्यं, शिष और सुन्दरम्' के महान आदर्श की स्थापना मे सहभागी बनता है। शिक्षा को देश की विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग होने के कारण, आयोजन की प्राथमिकताओं

मे उच्च प्राथमिकता दी गयी है। ⁴ अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक नवीन अर्थिक क्रियाओं मे आधुनिक विधियों तथा तकनीकी का प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही सभव है। ⁵ शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जो समाज को बनाए रखने तथा उसके विकास के लिए अति आवश्यक है। देश मे ग्रामीण क्षेत्र की अधिकाश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जिसका प्रमुख कारण अशिक्षा है। ⁶ शिक्षा के नियोजन के लिए कृषि, उद्योग एव अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। किसी क्षेत्र के विकास हेतु नियोजन के लिए, स्थानीय शिक्षा का स्तर एव आवश्यकता, छात्र शिक्षक अनुपात, विभिन्न स्तर के शिक्षण संस्थाओं की स्थिति तथा प्रौढ शिक्षा प्रसार व निरक्षरता उन्मूलन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन में भी इन तथ्यों को लेकर विश्लेषण किया गया है।

7 2 साक्षरता

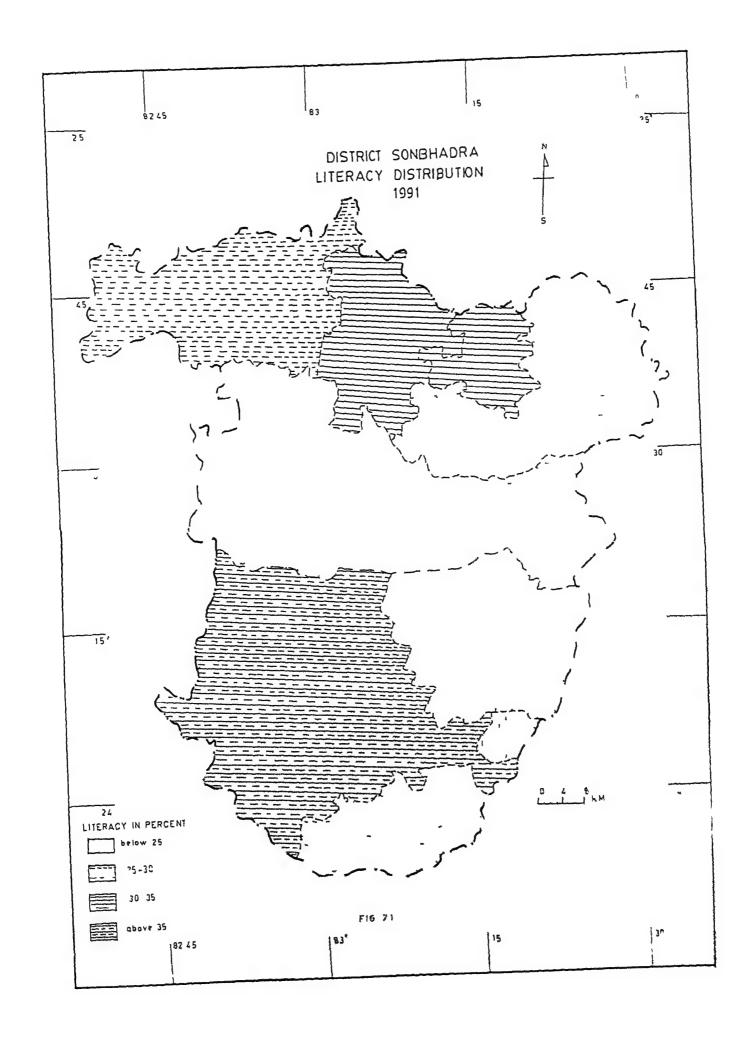
न्यूनतम शैक्षिक निपुणता को साक्षरता कहते है। साक्षरता के आधार एव परिभाषा भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न अपनायों गयी है किन्तु सर्वत्र निम्न दो तथ्यों में से किसी न किसी को अवश्य स्वीकार किया गया है। इनमें से प्रथम हैं - विद्यालयी शिक्षा अविध तथा द्वितीय - किसी भी प्रचिलत भाषा में समझ के साथ पढ़ने व लिखने की योग्यता। 'सपुक्त राष्ट्र सघ जनसख्या आयोग' ने किसी भी भाषा में साधारण संदेश को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता को साक्षरता निर्धारण का आधार माना है। मारतीय जनगणना में लगभग इसी परिभाषा के स्वीकारोक्ति के साथ कहा गया है कि वह व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ लिख और पढ़ सकता है, साक्षर है। वह व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता साक्षर नहीं है। साक्षर होने के लिए आवश्यक नहीं है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त की है या निम्नतम स्तर की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है। 1981 की जनगणना की परिभाषा के अनुसार 0-4 आयु समूह के बच्चों को निरक्षर माना गया था। किन्तु 1991 की जनगणना के अनुसार 0-6 आयु समूह के बच्चों को निरक्षर माना गया है।

सम्पूर्ण सोनभद्र का साक्षरता प्रतिशत 1991 की जनगणना के अनुसार 34 40% है, जिसमे पुरूषों की साक्षरता 47 56% तथा महिलाओं की साक्षरता मात्र 18 65% है। उत्तर

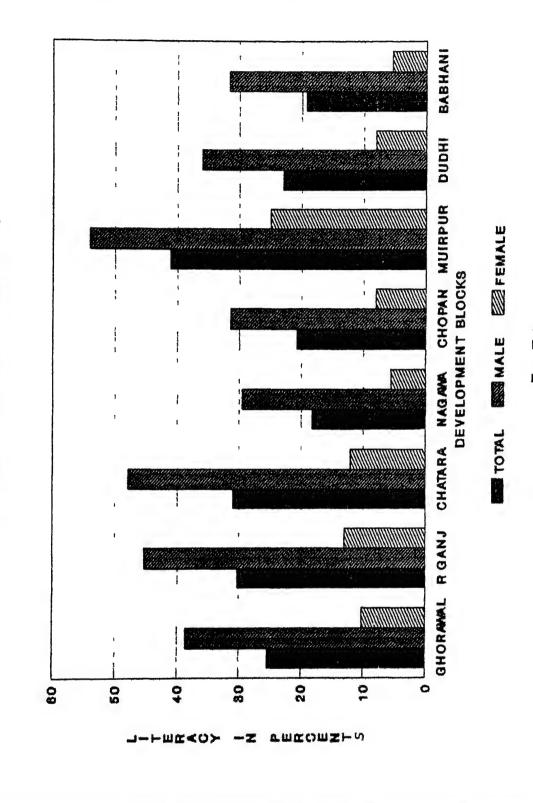
तालिका ७ । जनपद सोनभद्र मे साक्षर व्यक्ति व साक्षरता प्रतिश्रत

वर्ष/जनपद/	साक्षर व्यक्ति	d		साक्षरता प्रतिश्रत	तेसत	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
विकास खण्ड	पुरूष	শ্ব	याम	पुरूष	শ্ব	योग
1971	239734	59104	298838	29 60	8 08	19 39
1981	120919	39534	160453	29 13	10 90	20 62
1991	218171	71458	289629	47 56	18 65	34 40
विकासखण्ड वार 1991						
। घोरावल	25093	5849	30942	38 69	10 28	25 42
2 राबर्ट्सगज	26296	6637	32933	45 40	13 09	30 32
3 चतरा	13602	3062	16664	47 91	12 08	31 04
4 नगवा	6802	1137	7939	29 55	5 56	18 27
5 चोपन	21938	4771	26709	31 47	8 07	20 73
6 म्योरपुर	44697	16232	60929	54 07	25 01	41 29
7 दुब्ही	14256	2789	17045	36 05	8 02	22 94
8 बभनी	7381	1129	8510	31 66	5 42	19 28
वनगाम	308	55	363	46 06	9 68	29 34
ग्रामीण योग	160373	41661	202034	41 12	12 49	27 92
नगरीय योग	57798	29797	87595	84 08	60 20	74 08
सम्पूर्ण जनपद योग	218171	71458	289629	47 56	18 65	34 40
	1 1 1 1 1 1 1				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र 1992, पृष्ठ 41 1971 व 1981 की सूचना पूर्व मीरजापुर जनपद की है ।



DEVELOPMENT BLOCKWISE LITERACY OF DISTRICT SONBHADRA 1991



प्रदेश में 41 71% तथा भारत में 52 11% लोग साक्षर है। दोनों से तुलना करने पर सोनभद्र का साक्षरता प्रतिशत बहुत ही कम है। भारत में पुरूषों की साक्षरता 63 86% तथा महिलाओं की साक्षरता 39 42% है, जबिक उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 26 02% है। इसकी तुलना में सोनभद्र के पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत अल्प है।

अध्ययन क्षेत्र की ग्रामीण साक्षरता 27 92% ही है, इसमे महिलाओं की साक्षरता मात्र 12 49% है। नगरीय साक्षरता 74 08% है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 84 08% तथा स्त्रियों की साक्षरता 60 20% है। सोनभद्र जनपद में सर्वाधिक साक्षरता विकास खण्ड म्योरपुर (41 29%) की है तथा सबसे कम साक्षरता नगवा विकास खण्ड (18 27%) की है। इसके अतिरिक्त बभनी, चोपन, दुद्धी, घोरावल, राबर्ट्सगज व चतरा विकास खण्डों में साक्षरता प्रतिशत क्रमश 19 28, 20 73, 22 94, 25 42, 30 32, तथा 31 04 है(तालिका 7 । व मानचित्र 7 1)।

7 3 औपचारिक शिक्षा का प्रतिरूप

औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत केवल स्कूली शिक्षा वो सिम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा पद्धित नहीं आती है। इसमे प्रौढ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, घरेलू प्रशिक्षण, आश्रम शिक्षा तथा स्वय सेवी सस्थाओं द्वारा दी जाने वाली आदि को समाहित नहीं किया गया है। औपचारिक शिक्षा मे जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, हायर सेकेन्ड्री विद्यालय तथा महाविद्यालय आदि का वर्णन किया गया है।

(अ) जूनियर बेसिक विद्यालय

देश-प्रदेश के जन-मानस में शैक्षिक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा, जगत की मूल श्रृखला एवं आधारिशला है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में इसे सर्वाधिक वरीयता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर में प्रत्याशित अभिवृद्धि सुधार, परिवर्द्धन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विकिध प्रयास किये जा रहे हैं, जिसका एक अश शिक्षा नीति में परिवर्तन भी है। सम्पूर्ण सोनभद्र जनपद में जूनियर बेसिक विद्यालयों की

सख्या 1991-92 मे 715 थी, जिसमे से 658 ग्रामीण क्षेत्रों मे तथा 57 नगरीय क्षेत्रों में है। विकास खण्ड स्तर पर जूनियर बेसिक स्कूलों की सर्वाधिक सख्या चोपन ब्लाक मे 114 (15 95%) है तथा सबसे कम नगवा में 52 (7 27%) है (तालिका 7 2) । आरोही क्रम में जूनियर बेसिक विद्यालयों की सख्या इस प्रकार है - विकास खण्ड नगवा 52 (7 27%), चतरा - 53 (7 41%), बभनी 59 (8 25%), दुद्धी 69 (9 65%), राबर्टसगज 100 (13 98%), घोरावल 102 (14 26%), म्योरपुर 109 (15 24%), तथा चोपन में 114 (15 94%) है (तालिका 7 2)। प्रतिलाख जनसंख्या पर जनपद में जूनियर बेसिक विद्यालयों की औरत संख्या 1991-92 में 70 8 थीं। जनपद के तीन विकास खण्डों में औसत से कम तथा पांच विकास खण्डों (राबर्टसगज, चतरा, नगवा, दुद्धी व बभनी) में औसत से अधिक संख्या है (तालिका 7 2)।

जनपद के सभी जूनियर बेसिक विद्यालयों मे 1991-92 मे 99776 छात्र पजीकृत है इनमे से 84886 ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शेष 14890 नगरीय क्षेत्रों के विद्यालयों मे पजीकृत है। दुल छात्रों मे 57732 बालक तथा 42044 बालिकाए है। इनमे न्युचित जाति एव जनजाति केबालक व बालिकाओं का प्रतिशत क्रमश 34 03 व 19 21 है, जो तालिका 7 2 से स्पष्ट है। छात्रों की सर्वाधिक संख्या विकास खण्ड राबर्टसगज (15225) में है। द्वितीय स्थान घोरावल का है, जबिक सबसे कम नगवा विकास खण्ड मे छात्र है। एव जनजाति के बालक एव बालिकाओं की सबसे अधिक संख्या क्रमश विकास खण्ड म्योर्पुर (17 32%) व चोपन (16 49%) मे है। कुल छात्रों तथा बालक-बालिकाओं की सख्या के साथ अनुसूचित जाति एव जनजाति के बालक व बालिकाओं की अलग्र-अलग सख्या व प्रतिशत को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ इसका विवरण नगरीय व ग्रामीण परिप्रेक्ष्य मे दिया गया है। नगरों मे अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्रों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम है। इससे स्पष्ट है कि विकास के सूचक नगरीय क्षेत्रों में ये बहुत कम उन्मुख हुए हैं। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि बालक व बालिकाओं के ग्रामीण व नगरीय अनुपात मे बहुत कम अन्तर है। ग्रामीण क्षेत्र मे यह अन्तर ! 37% का तथा नगरीय क्षेत्रों मे भी । 37% का अन्तर है। जनपद में छात्र - स्कूल अनुपात जहाँ ।39 5 है वहीं राज्य मे यह अनुपात 167 है। छात्र-विद्यालय अनुपात तालिक 73 मे प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 7 2 जनपद सोनभद्र का शैक्षिक विवरण

विकसखण्ड	जनसङ्या धनत्व प्रति वर्ग किमी0	अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जन0 मे	साक्षर व्यक्तियों का कुल जन0भे	प्रति लाख जन०पर जृ०ने०स्कू० की सख्या	प्रति लाख प्रति लाख जन०पर जन०पर जू०बे०स्कू० सी०बे०स्कू० की साह्या की साह्या	प्रति लाख जू०ने०स्कू० जन०पर की सख्या हा0से०स्कू० ९१-९२ %	जू०ने(रन्तूः) की संख्या 0 91-92		सी0ने०स्कृ० की सख्या 91-92 %		हा0से0 स्कूस की सस्या 1991-92
					1991-92	1991-92	,.				
घोरावल	190	44 0	25 42	65 4	9 0	<u>-</u> ن	102	14 26	4	14 58	N
राबर्ट्सगज	312	31 6	30 32	72 5	6 5	0 7	100	13 98	9	9 37	
चतरा	265	36 5	31 04	78 6	5 9	3 0	53	7 41	4	4 16	2
नगवा	59	53 5	18 27	95 4	9 2	1	52	7 27	Ċτ	5 20	t
चोपन	97	58 0	20 73	68 4	9 6	0 6	14	15 94	6	16 66	-
म्योरपुर	144	43 1	41 29	56 6	∞ 3	0	109	15 24	16	16 66	₽
दुब्दी	136	57 4	22 94	71 5	12 4	0	69	9 65	12	12 50	-
बभनी	95	65 3	19 28	102 4	73 4	1 7	59	8 25	ယ	3 12	-
प्रम्पूर्ण विकास खण्ड	137	47 31	27 92	70 8	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u>-</u>	658	92 02	79	82 29	10
नगरीय	7035	11 93	74 08	39 56	- 8	13 88	57			17 70	
सम्पूर्ण योग-	158	42 5	34 4	66 50	8 92	279	715	100 00 96) 96	100 00	30

ग्रेत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, से संगणित ।

तालिका 7 3 जूनियर बेसिक विद्यालय के छात्रों श्रिक्षकों व विद्या**लयों का अनुपात** वर्ष 1991

विकासखण्ड	सम्पूर्ण छात्रों संख्या	सम्पूर्ण विद्यालयों की सख्या	प्रति विद्यालय छात्रौं का असत	सम्पूर्ण श्रिक्षकों की सख्या	कि ही संख्या
घोरावल	14124	102	138 47	164	86 12
2 राबर्ट्सगज	15225	100	152 25	178	85 53
3 चतरा	7008	53	132 23	76	92 21
4 नगदा	7713	52	148 32	ភូ	140 23
5 चोपन	13761	114	120 71	143	96.23
6 म्योरपुर	11940	109	109 54	93	128 38
दुद्धी	8479	69	122 88	92	92.16
3 बभनी	6646	59	112 64	42	158 23
者 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	84886	658	129 00	843	100 70
नरीय योग	14890	57	261 22	250	59-56
ान्यूर्ण योग	99776	715	139 54	1093	91-28
	1 1 1 1 1 1 1 1 1		*		

सोंिडयकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृ० 90,92 एवं 96 से संगीणत ।

तालिका ७ १ जूनियर बेंसिक विद्यालय से बस्तियों की दूरी वर्ष 1991-92

स्निकस्सल्य प्राप्त प्राप्त से सिक्सी0 1-3 किसी0 3-5 किसी0 5कि प्राप्त से क्सेस 1 प्रोरावल 94 59 145 27 12 2 रावर्ट्सभाज 89 152 76 - 12 3 वतरा 53 73 41 1 1 4 नगवा 51 10 9 20 38 5 वोपन 88 - 2 2 1 2 6 स्वोपपुर 109 - 3 2 6 1 8 बभमी 59 - 30 1 62 73	! !	; ; ; ; ; ;	; ; ; ; ; ; ; ;	t : : : : : : :		: : : : : :			
बल 94 59 145 27 देसाब 89 152 76 - त 53 73 41 1 ह 10 9 20 ह 109 - 2 22 6 ह 59 - 3 5 ह 612 294 30 1 62	विका जनप	. <u> </u>	ग्रम भे	। किमी0 से कम	।-3 किमी0	3-5 किमी0	70		योग का 🗶
हिसगंब 89 152 76 - य 53 73 41 1 10 9 20 न 88 - 2 1 पुर 109 - 3 2 त 69 - 32 6 त 69 - 3 5			94	59	145	27	12	337	25 12
पा 53 73 41 1 श 51 10 9 20 सुर 109 - 2 1 69 - 22 6 भ 59 - 3 5	2	राबर्ट्सगज	89	152	76	1	12	329	24 52
स 51 10 9 20 न 88 - 2 1 पुर 109 - 3 2 69 - 22 6 भ 59 - 3 5	ယ	चतरा	53	73	41	-	t	168	12 52
न 88 - 2 1 पुर 109 - 3 2 1 69 - 22 6 1 59 - 3 5	4	नगवा	57	10	9	20	38	128	9 53
पुर 109 - 3 2 1 69 - 22 6 11 59 - 3 5 612 294 30 1 62	თ	चोपन	88	ı	2	_	1	91	6-78
日 69 - 22 6 計 59 - 3 5 612 294 30 1 62	6	म्योरपुर	109	ľ	ယ	2	6	120	8 94
ी। 59 - 3 5 612 294 30 1 62	7	दुद्धी	69	•	22	6	-	98	7 30
612 294 30 1 62	00	बभनी	59	•	ω	Ch	4	71	5 29
$(A \in COV)$ $(A \cap CV)$ $(A \cap CV)$ $(A \cap CV)$ $(A \cap CV)$	योग	जनपद	612	294	30 1	62	73	1342 100	100

ग्रीत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 146, एवं संगीणत ।

इसके अन्तर्गत प्रति विद्यालय विद्यार्थियों की सख्या वर्णित है। सम्पूर्ण जनपद मे प्रति विद्यालय जूनियर बेसिक विद्यार्थियों की सख्या का औसत 139 54 है। ग्रामीण व नगरीय विद्यालयों में असमानता बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों का औसत जहाँ 129 विद्यार्थियों का है वही नगरीय क्षेत्र का औसत 261 22 विद्यार्थियों का है। जनपद के समस्त विकास खण्डों में प्रति विद्यालय छात्रों की अधिकतम सख्या विकास खण्ड राबर्ट्सगज (152 25) में है। इसके बाद अवरोही कृम में क्रमश नगवा (148 32), घोरावल (138 47), चतरा (132 23), दुद्धी (122 88), चोपन (120 71), तथा बभनी (112 64) का स्थान आता है (तालिका 7 4)।

जूनियर बेसिक विद्यालय मे प्रति शिक्षक छात्रों की सख्या तालिका 7 3 मे प्रदर्शित वित्या गया है। सम्पूर्ण जनपद मे प्रति शिक्षक छात्रों का औसत 91 28 है। ग्रामीण क्षेत्रों मे यह अनुपात 1 100 70 का तथा शहरी क्षेत्रों मे 1 59 56 का है। प्रित शिक्षक विद्यार्थियों की अधिकतम सख्या 158 23 विकास खण्ड बभनी मे है। इसके बाद अवरोही क्रम मे क्रमश नगवा (140 23), म्योरपुर (128 38), चोपन (96 23), चतरा (92 21), दुद्धी (92 16), घोरावल (86 12), तथा राबर्ट्सगज (85 53) का स्थान आता है।

जूनियर बेसिक विद्यालय की दूरी एव गाँवों की सख्या को तालिका 7.4 मे प्रदर्शित किया गया है। विद्यालय से । किमी0 की दूरी तक जनपद के 294 (21 90%) गाँव आते है। जबिक 612 गाँवों मे विद्यालय है अर्थात सम्पूर्ण गाँवों वा 45 60% विद्यालय से युक्त है। 1-3 किमी0 की दूरी पर 301 (22 42%) गाँव आते है, 3-5 किमी0 की दूरी पर 62 (4 61%), गाँव तथा 5 किमी0 से अधिक दूरी पर 73 (5 44%) गाँव है।

(ब) सीनियर बेसिक विद्यालय

सन् 1991-92 में जनपद में कुल 96 सीनियर बेसिक विद्यालय थे (तालिका 7 6)। इन विद्यालयों में कुल पजीकृत विद्यार्थियों की सख्या 22181 थी जिसमें से 19206 (86 59%) ग्रामीण विद्यालयों में व 2975 (13 41%), विद्यार्थी नगरीय विद्यालयों में पजीकृत थे। सम्पूर्ण विद्यार्थियों में बालकों की सख्या 15700 (70 78%) तथा बालिकाओं की सख्या 6481 (29 22%) थी। सम्पूर्ण विद्यार्थियों में अनुसुचित जाति एव जनजाति के कुल विद्यार्थियों

सीनियर बेसिक विद्यालय मे छात्र-छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्र-छात्राओं की सख्या वर्ष (1991-92) तालिका 7 5

			6			
विकास खण्ड		सम्पूर्ण विद्यार्थी	छात्रों की सख्या	छात्राओं की संख्या	अनु0जाति एव जनजाति के छात्रों की सख्या	अनु0जाति एवं भन0 के छात्राक्षी की सख्या
। घोरावल	वल	3193	2295	898	834	130
2 राब	राबर्ट्सगज	3803	2932	871	1366	185
3 चतरा	CI .	1712	1236	476	371	218
4 नगवा	=======================================	1258	878	380	347	74
5 चोपन	ম	3262	2075	1187	1086	183
6 म्योरपुर	पुर	3558	2593	965	1253	186
7 दुद्धी		1456	984	472	593	123
8 बभनी	il and a second	964	682	282	235	53
योग ग्रामीण	1 1 1 1 3 1 1 1	19206	13675	5531	6085	151
		2975	2025	950	614	95
योग जनपद		22181	15700	6481	6699	1246
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

सींख्यकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 93, एवं संगीणत ।

तालिका 7 6 सीनियर बेसिक विद्यालय में छात्रों विद्यालयों तथा श्रिक्षकों का अनुपात वर्ष 1991-92

विकसिखण्ड	कुल छात्र	श्विक्षकों की सख्या	प्रति शिक्षक छात्रौं की सख्या	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय छात्रों की संख्या	प्रति विद्यालय श्रिक्षकों की संख्या
। घोरावल	3193	28	114 04	14	228 07	2 00
2 राबर्टसगज	3803	38	80 001	9	422 56	4.22
3 चतरा	1712	38	45 05	4	428 00	9 50
4 नगदा	1258	14	89 86	Ċī	251 60	2 80
5 चोपन	3262	33	98 85	16	203 88	2 54
6 म्योरपुर	3558	32	111 18	16	222 38	2 00
7 दुन्ही	1456	28	52 00	12	121 33	2 33
8 बभनी	964	σ	160 67	ယ	321 33	2 00
ग्रामीण योग	19206	217	88 51	79	243 11	2 74
नगरीय योग	2975	65	45 76	17	175 00	3 82
सम्पूर्ण जनपद	22181	282	78 66	%	231.05	2.93

त सींख्यकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 90, 93, 96 एवं उससे संगीणत ।

की संख्या 7944 (35 81%) थीं, जिसमें छात्रों की संख्या 6699 तथा छात्राओं की संख्या 1246 थीं (तालिका 7 5) । सम्पूर्ण विद्यार्थियों, छात्र-छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्र छात्राओं की संख्या तालिका 7 5 में दी गयी है ।

जनपद में सीनियर बेसिक विद्यालयों का वितरण असमान है। 73% विद्यालय विकासखण्ड घोरावल, चोपन, म्योरपुर तथा दुद्धी में है, तथा शेष चार विकास खण्डो में मात्र 27% विद्यालय है। जनपद में प्रति विद्यालय विद्यार्थियों की सख्या लगभग 231 है जबिक राज्य में यह अनुपात 166 विद्यार्थियों का है। जनपद में कुल शिक्षकों की सख्या 282 है। जिसमें से 217 शिक्षक ग्रामीण विद्यालयों में तथा 65 नगरीय विद्यालयों में है। जनपद में प्रति शिक्षक छात्रों का औसत लगभग 79 है, जबिक राज्य में यह औसत 31 विद्यार्थियों का है। राज्य की तुलना में जनपद के शिक्षक 255% अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाते है। प्रति शिक्षक छात्रों की सख्या को तालिका 7 6 में दर्शाया गया है। विकास खण्ड बभनी के प्रत्येक शिक्षक को 161 विद्यार्थी तथा चतरा के प्रत्येक शिक्षक को 45 विद्यार्थी को पढ़ाना पड़ता है। अत इस तथ्य से भी क्षेत्रीय विषमता आभाषित होती है। जनपद में प्रति विद्यालय शिक्षकों की सख्या लगभग 3 है जबिक राज्य में यह स्थिति लगभग 6 से भी अधिक है। अत राज्य की तलना में प्रति विद्यालय शिक्षकों की सख्या लगभग 6 से भी अधिक है। अत राज्य की तलना में प्रति विद्यालय शिक्षकों की सख्या लगभग आधी है।

सामान्यत कोई भी सीनियर बेसिक विद्यालय किसी भी गाँव से 5 किमी0 से अधिक दूर नहीं होना चाहिए । जनपद के सन्दर्भ मे अभिगम्यता ठीक नहीं है, 76 75% (1030) बस्तियों 5 किमी0 से अधिक दूरी पर है। 21 24% (285) बस्तियों । से 5 किमी0 की दूरी पर है तथा 27 बस्तियों ही । किमी0 से कम दूरी पर है।

(स) हायर सेकेन्ड्री विद्यालय

हायर सेकेन्ड्री विद्यालय के अन्तर्गत हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट दोनों प्रकार के विद्यालयों को सिम्मिलत किया गया है। 1991-92 में कुल हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों की सख्या 30 थी इसमे से 20 विद्यालय नगरीय क्षेत्रों में तथा 10 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। विकासखण्ड घोरावल में घोरावल, शाह गण, लोहाडी, धनावल व कपुरा में हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों

की सख्या 5 है। राबर्ट्सगज, चुर्क, गुरमा व परासी मे एक एक, चतरा मे रामगढ व सिलथम मे, चोपन मे चोपन, ओबरा, डाला व कोन मे, म्योरपुर मे रेनृकृट, बीजपुर, पीपरी, अनपरा व शिक्तनगर मे, दुद्धी मे दुद्धी व विण्डमगज मे तथा बभनी मे चपकी मे हायर सेकेन्ड्री विद्यालय अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड नगवा मे एक भी हायर सेकेन्ड्री विद्यालय नहीं है। जनपद के अधिकाश हायर सेकेन्ड्री विद्यालय औद्योगिक केन्द्रों पर अवस्थित है। इन विद्यालयों मे पजीकृत विद्यार्थियों की सख्या 26997 है। इनमे से छात्राओं की सख्या 4155 (15 39%) है। सम्पूर्ण विद्यार्थियों मे अनुसूचित जाति एव जनजाति के विद्यार्थियों की सख्या 4644 (17 20%) है। इनमे से बालिकाओं की सख्या 1084 तथा बालकों की सख्या 3560 (तालिका 7 7) है। विकास खण्डवार बालको एव बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के बालकों एव बालिकाओं का विवरण तालिका 7 7 में प्रदर्शित है।

जनपद में सम्पूर्ण शिक्षकों की सख्या 726 है, इनमें से 196 शिक्षक ग्रामीण विद्यालयों में तथा 530 शिक्षक नगरीय विद्यालयों में कार्यरत है। सोनभद्र में प्रति शिक्षक छात्रों की सख्या लगभग 37 है जबिक राज्य का प्रति शिक्षक छात्रों का औसत 35 है। अत राज्य की तुलना में जनपद के शिक्षकों को अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है। विकास खण्डवार यह असमानता और भी अधिक है जिसे 7 8 में देखा जा सकता है। जनपद में सम्पूर्ण विद्यालयों की सख्या 30 है। प्रति विद्यालय छात्रों की सख्या लगभग 900 है, जबिक उत्तर प्रदेश में यह ओसत लगभग 769 विद्यार्थियों का है। अत राज्य की तुलना में जनपद सोनभद्र के विद्यालयों में लगभग 16% अधिक विद्यार्थी है। राबर्ट्सगज, चोपन व दुद्धी के विद्यालय में छात्रों की सख्या और अधिक है।

सोनभद्र मे प्रति विद्यालय शिक्षकों की सख्या लगभग 24 है। उत्तर प्रदेश में प्रति विद्यालय शिक्षकों की सख्या लगभग 22 है। जनपद के औसत से विकास खण्ड चोपन राबर्ट्सगज व नगरीय विद्यालयों में प्रति विद्यालय शिक्षकों की सख्या अपेक्षाकृत अधिक है (तालिका 7 8)। सामान्यत हायर सेकेन्द्री विद्यालय किसी भी बस्ती से 8 किमी0 से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। जनपद के 10 बस्तियों में हायर सेकेन्द्री विद्यालय है। । किमी0 से कम दूरी पर 1 42%, 1-3 किमी0 की दूरी पर 5 07%, 3-5 किमी0 की दूरी पर 5 51%

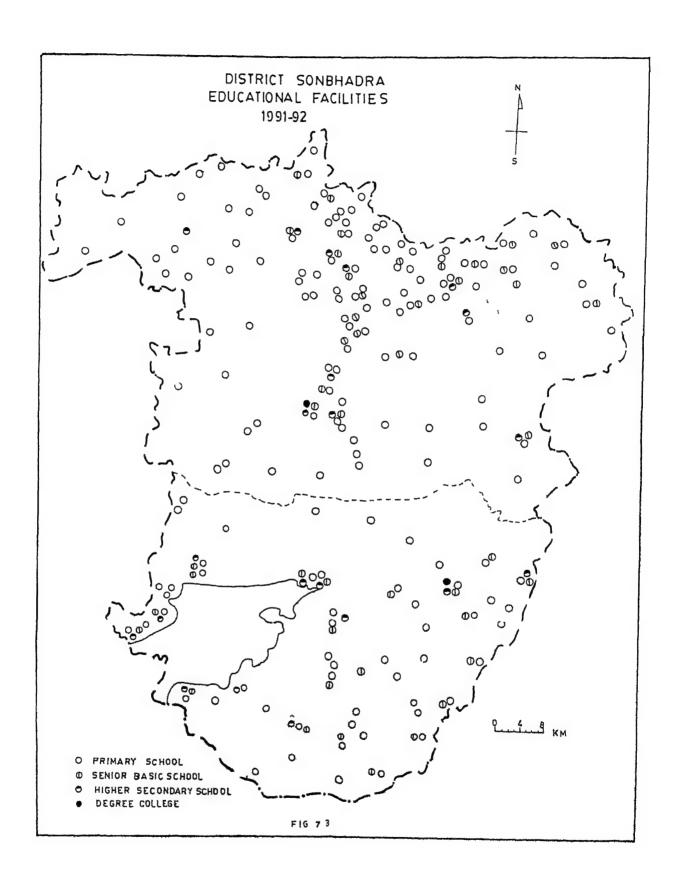
हायर सेकेन्ड्री विद्यालय के छात्र-छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्र-छात्राओं की सख्या- 1991-92 तालिका 7.7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
विकसस्खण्ड	सम्पूर्ण विद्यार्थी	छात्रों की सख्या	छात्राओं की सख्या	अनु ०ना ति एवं जनजाति के छात्रों की सख्या	अनु0जाति एवं जनजाति के छात्राओं की संख्या
। घोरावल	973	895	78	248	35
2 राबर्टसगज	1412	997	415	250	76
3 चतरा	1354	1315	39	110	18
4 नगवा	t	ı	1	1	ı
5 चोपन	2571	2162	409	260	97
6 म्योरपुर	1314	932	382	209	68
7 दुव्ही	1081	735	346	245	56
8 बभनी	546	498	48	95	38
योग ग्रामीण	9251	7534	1717	1417	388
योग नगरीय	17746	15308	2438	2143	696
जनपद योग	26997	22842	4155	3560	1084

म्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 94, एव सगणित ।

तालिका 7 8 हायर सेकेन्ड्री विद्यालय मे छात्रों, विद्यालयों तथा श्रिक्षकों का अनुपात 1991-92

विकसस्बण्ड	सम्पूर्ण छात्रों की संख्या	सम्पूर्ण शिक्षकों की संख्या	प्रतिशिक्षक छात्रौं की संख्या	सम्पूर्ण विद्यालयों की स ख्या	स्त	型 司
घोरावल	973	42	23 17	2	486 5	21
राबर्टसगज	2412	36	39 22	-	1412	36
चतरा	1354	26	52 08	2	677	13
नगवा	1	i	1	1	t	à
चोपन	2571	32	80 34	-	2571	32
म्योरपुर	1314	32	41 06	N	657	16
दुङ्गी	1081	16	67 56	-	1801	16
बभनी	546	12	45 50	-	546	12
योग ग्रामीण	9251	196	47 20	10	925 1	19 6
योग नगरीय	17746	530	33 48	20	887 3	26 5
जनार जोग		726	37 19	30	899.9	24 2



तथा 5 किमी0 से अधिक दूरी पर 87 26% बस्तियाँ है। 87 26% बस्तियों के छात्रों को 5 किमी0 से अधिक दूरी पर ही हायर सेकेन्ड्री विद्यालय उपलब्ध है।

(द) उच्च शिक्षा केन्द्र

उच्च शिक्षा से सम्बन्धित जनपद मे 2 महाविद्यालय ओबरा व दुद्धी मे है। इन दोनो महाविद्यालयों मे स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जनपद मे न तो तकनीकी विद्यालय है न ही प्रशिक्षण सस्थान है। उपर्युक्त दोनों महाविद्यालयों मे 1991-92 मे पजीकृत सम्पर्ण विद्यार्थियों की सख्या 3050 थी, जिसमें से 86 4% (2635) बालक व 13 6%(415) बालिकाये थी। सम्पूर्ण विद्यार्थियों मे अनुसूचित जाति एव जनजाति के विद्यार्थियों की सख्या 24 06% (734) थी। इनमें से बालकों की सख्या 708 तथा बालिकाओं की सख्या 26 थी। दोनों महाविद्यालयों मे कुल शिक्षकों की सख्या 41 है जिनमें से 4 शिक्षिकाये है (सिख्यिकीय पित्रका, जनपद सोनभद्र 1992, पृष्ठ 95) । जनपद मे प्रतिशिक्षक छात्रों की सख्या लगभग 75 है जबिक उत्तर प्रदेश मे यह औसत 25 है। अर्थात तीन गुना अधिक है। सोनभद्र मे प्रति महाविद्यालय छात्रों का औसत 1525 है जबिक उत्तर प्रदेश मे यह 1237 है। उत्तर प्रदेश की तुलना में सोनभद्र के शिक्षकों पर छात्रों की सख्या अधिक है। जनपद मे प्रति महाविद्यालय शिक्षकों का औसत लगभग 21 है। जबिक उत्तर प्रदेश मे यह औसत लगभग 50 है। इस प्रकार प्रति महाविद्यालय शिक्षकों की सख्या जनपद मे बहुत कम है।

7 4 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु छठीं पचवर्षीय योजना में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में वर्ष 1979-80 से अनौपचारिक शिक्षा योजना अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के पूरक के रूप में प्रारम्भ की गयी, इस योजना के अन्तर्गत 9-14 वय वर्ग के ऐसे बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है जो सामाजिक आर्थिक तथा अन्य किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते है अथवा किन्ही परिस्थितियों के कारण प्राइमरी अथवा मिडिल स्तर की शिक्षा पूरी किये बिना ही पढ़ाई छोड़ने के लिए विविश्व हो गए है। ऐसे बालक - बालिका शिक्षा से सदैव विचत न रह जाए इसके लिऐ उन्हें उनके स्थान एवं समय की सुविधानुसार शिक्षा देने की व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत की गयी है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अशकालिक शिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक मापदण्ड निर्धारित है जिसके अन्तर्गत स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अनीपचारिक शिक्षा केन्द्रों मे नामांक्ति छात्रों को नि शुल्क पाठुपुस्तकों अभ्यास पुस्तिकाये, स्लेट-पेन्सिल, आदि प्रदान की जाती है। केन्द्र का सचालन करने के लिए प्रत्येक केन्द्र को टाट-पट्टी, चार कुर्सी, फोल्डिंग एक, उपस्थित र्गजस्टर दो, स्टाक र्गजस्टर दो, शिक्षक डायरी दो, पटरी दो, चाकू दो, डाट पेन दो, ताला एक, मानचित्र (प्राकृतिक एव राजनीतिक) उत्तर प्रदेश, भारत तथा विश्व का एक मानचित्र, चाव का डिब्बा एक तथा इस्टर एक दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा द्वारा राष्ट्र के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय विकास मे समान रूप से सहभागी बनाने के लिए सचालित विया गया है। इसका उद्देश्य साक्षरता दक्षता, तथा सामाजिक चेतना को बढाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुसार और एक्शन प्लान मे बताए गए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने प्रौढ शिक्षा का एक विशव प्रारूप तैयार किया है जिसका नाम है - राष्ट्रीय साक्षरता मिश्नी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। अध्ययन क्षेत्र मे अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है।

7 5 शिक्षा नियोजन की प्रमुख बाधाए

इस अध्ययन क्षेत्र का सबसे पिछडा पक्ष शिक्षा है। जनपद के लघुकृत होने पर भी सुविधाओं को प्रदान करने के नाम पर शिक्षण सस्थाओं में मात्रात्मक व गुणात्मक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जनपद का शैक्षणिक परिवर्तन वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक पहलुओं में परिवर्तन की तुलना में बहुत पीछे रह गया है। इसके कई निम्न कारण है जिन्हें दृढता और सूझ बूझ से दूर किया जाना चाहिए।

। कोई भी शिक्षा प्रणाली केवल वृहद् सामाजिक - आर्थिक वातावरण की सच्चाई को प्रकट करती है। सोनभद्र में नए औद्योगिक सस्थानो की सस्थापना रे न केवल आर्थिक व्यवस्था में असमानता आयी हैवरन फैक्ट्री स्कृल' अग्रेजी माध्यम के व विशेषाधिकार युक्त है। इन विद्यालयों को सभी सोनभद्र वासियों के लिए गुणवत्ता के आधार पर भी उपलब्ध न होना शैक्षिक उन्नयन में सबसे बड़ी बाधा है।

- 2 विभिन्न स्तरों पर शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से सम्बन्धित समस्याएँ और शिक्षा की विषयवस्तु का गुणात्मक सुधार समाज के उद्देश्यो और उनकी प्राप्ति के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। शिक्षा सम्पूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। अत राज्य और केन्द्र सरकारे इसके विकास एव परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकते है। साधनों का बँटवारा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सामाजिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। किन्तु अब तक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता नहीं दी गयी है। इसी प्रकार क्षेत्रों के चयन में भी सोनभद्र हमेशा उपेक्षित रहा।
- 3 एक अन्य बाधा शिक्षा प्रणाली में रूढ सकीर्णवादिता है, जो संस्थाओं और उनके प्रबन्धकों में निहित स्वार्ध और कट्टर मान्यताओं को जन्म देती है। ये गुणात्मक परिवर्तन और सुधार के स्थान पर आदत और परम्परा को अधिक महत्व देते हैं। अब समय आ गया है कि आयोजन की बेहतर व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाए और उनमें सुधार किया जाय। इन सबसे बढ़कर सभी सम्बन्धित पक्षों को सिम्मिलित करके कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढग से तेजी से लागू करने तथा विकेन्द्रीकरण और स्थानीय पहल के माध्यम से सामाजिक ससाधनों का गितशील इस्तेमाल करने की व्यवस्था की जाए।
- 4 शिक्षा की प्रिकृया में शिक्षकों की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सुयोग्य शिक्षक अपरिहार्य है समाज में सार्थक परिवर्तन तब तक सम्भव नहीं है जबतक शिक्षक उनके लिए तैयार न हो। यह तभी सम्भव है जब अध्यापकों को सभी स्तरों पर योजना तैयार करने और निर्णय करने में सम्मिलित किया जाए तथा छात्रों व सरक्षकों से नियमित सम्पर्क एवं सुझाव लिया जाए।
 - 5 सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय का पिरामिड उल्टा हे अर्थात प्राथमिक शिक्षा

पर बहुत कम व्यय किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 60% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों मे पर्याप्त स्थान, अध्ययन कक्ष, पीने के पानी, टाट-पिट्टियों ब्लैक बोर्ड आदि प्राथमिक आवश्यकताओं की भी कमी है। जनपद के केवल 10% विद्यालयों मे ही उपर्युक्त सभी सुविधाये उपलब्ध है और इनमें से 80% विद्यालय नगरीय क्षेत्रों में है।

- 6 छात्र-छात्राओं का अध्ययन के प्रति अभिरूचि में हास नकल समस्या को और विकराल करती जा रही है। जनपद के विस्तृत पहाडी क्षेत्र मे पढाई के दिनों में भी विद्यालय बन्द रहते है तथा विद्यालय में पढाई की समयावधि भी कम रहती है। नदी-नालों पर पुलों के अभाव में नगवा, म्योरपुर, बभनी, दुद्धी व चौपन विकास खण्ड के ग्रामीण जूनियर बेसिक विद्यालयों में से लगभग 50% विद्यालय अधोषित वर्षावकाश में बन्द ही रहते है। क्योंकि इन क्षेत्रों के नालों में थोडी बरसात से भी उफान आ जाता है।
- 7 विद्यार्थियों का हाई स्कूल तक अध्ययन के उपरान्त अध्ययन कार्य छोड़ देने की मजबूरी अब परम्परा बन गई है। जनपद मे कुल 30 हायर सेकेन्ड्री विद्यालय है, जो आवश्यकता से बहुत ही कम है। यह सामान्य अध्ययन का विषय हो सकता है कि विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ नगवा एक ऐसा विकास खण्ड है जहाँ हाई स्कूल स्तर का एक भी विद्यालय नहीं है तथा सीनियर बेसिक विद्यालय मात्र 5 है। ऐसी स्थिति मे छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने की परम्परा को बढावा देने मे छात्रों व अभिभावकों का नही बिलक सरकार का योगदान अवश्य है और यहाँ की गरीबी शिक्षा पर पाबन्दी लगाती है।
- 8 जनपद में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित एक भी विद्यालय नहीं है ।

7 6 विद्यालयों का शैक्षिक स्तर

किसी भी क्षेत्र में छात्र-शिक्षक, छात्र-विद्यालय तथा विद्यालय क्षेत्र अनुपात का विशिष्ट मान्य स्तर क्या हो यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। भारतीय शिक्षाविदों ने भारतीय सदर्भ में शिक्षक छात्र अनुपात, कम से कम । 25 तथा अधिक से अधिक । 50 उचित

बताया है। इसी प्रकार हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात, कम से कम । 20 तथा अधिक से अधिक । 30 उचित बताया है। ¹⁰ इसी प्रकार राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, मिडिल तथा हाई स्कूल क्रमश । 5 किमी0, 5 किमी0 तथा 8 किमी0 से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। ¹

किसी भी क्षेत्र का नियोजन प्रस्तुत करते समय राज्य व राष्ट्रीय मानकों को न तो पूर्णत आधार बनाया जा सकता है और न ही अवहेलना की जा सकती है, क्योंकि यह मानक स्तर उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक, आर्थिक व सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य मे होनी चाहिए। फलत राष्ट्रीय और राज्य के मानको की सीमाओ को ध्यान मे रखते हुए तथा वर्तमान शैक्षिक सुविधाओं के सदर्भ मे तालिका 7 9 मे निधारित शैक्षाणिक मानदण्डों को दिया गया है।

तालिका 7 9 जनपद सोनभद्र के लिए शैक्षिक मानदण्ड

क्र गरा ख्या 	विद्यालयों का स्तर	श्रिक्षक-छात्र अनुपात	स्कूल-छात्र अनुपात
I	जूनियर बेसिक विद्यालय	1 35	1 150
2	सीनियर बेसिक विद्यालय	1 30	1 120
3	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	1 25	I 500

जनपद के शैक्षणिक इकाइयों की अवस्थिति के सदर्भ मे एक उचित मानदण्ड का निर्धारण होना चाहिए। सोनभद्र मे यह अवस्थितिक मानदण्ड भौतिक स्वरूप, परिवहन के साधन व माध्यमों की प्रकृति एवं प्रकार, बस्तियों की सख्या, जनसख्या, शैक्षणिय इकाइयों की कार्यात्मक रिक्तता तथा उसके विशिष्ट जनसख्याधार के सदर्भ मे निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। सीनियर बेसिक विद्यालयों की दूरी किसी भी बस्ती से 3-5 किमी0 के बीच होनी चाहिए तथा हायर सेकेन्द्री के संदर्भ मे यह दूरी 5-8 किमी0 के बीच होनी चाहिए

अध्ययन क्षेत्र मे केमूर की ऊँची पहाडियाँ व नदी-नालो पर पुलों का अभाव विद्यालयों से बस्तियों की न्यून दूरी को भी अभिगम्य बनाने मे बाधा उपस्थित करती है। अत ऐसी स्थिति मे प्राकृतिक अवरोधों को ध्यान मे रखते हुए व्यावहारिक अभिगम्यता पर ध्यान दिया गया है।

7 7 श्रेक्षणिक नियोजन

विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, बल्कि इसके और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे शिक्षा का प्रसार, जिससे जनसंख्या नियन्त्रण के लिए सही दृष्टिकोण विकासत होने में सहायता मिलती है। 12 शिक्षा की समस्या को स्वय एक समस्या के रूप में न देखकर सकल सामाजिक-आर्थिक विकास के एक अभिन्न पहलू के रूप में ही देखा जाना चाहिए। नियोजन का मूल आधार मानव शिक्त नियोजन होना चाहिए। इसमें भी सम्भव हो तो युवा शिक्त नियोजन को अधिक महत्व दी जानी चाहिए। युवको को अपने अस्तित्व व शिक्त की पहचान करानी चाहिए। आधुनिक शिक्षा पद्धित ही बेरोजगारी की समस्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रहा है। शारीरिक श्रम को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षा के लिए नियोजन प्रस्तुत करने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए -

- । शिक्षा व साक्षरता को जनपद स्तर पर देखा जाए ।
- 2 केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को अपना अनिवार्य कर्तव्य मानकर सहायता करनी चाहिए।
 - 3 अशिक्षा व निरक्षरता गरीबी का ही एक अग है।
- 4 अशिक्षा व्यक्तिगत चिता ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक चिता का विषय है।
- 5 सदी के अन्त तक निरक्षरता व अशिक्षा को मिटाने का प्रयास जनपद स्तर पर शुरू होनी चाहिए ।

शैक्षणिक नियोजन के लिए भविष्य में उसकी उपादेयता एवं आवश्यकता तथा वर्तमान का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान स्वरूप का वर्णन गत पृष्ठों में किया गया है तथा बढ़ती हुई आवश्यकता एवं उपादेयता की मणना जनपद के शैक्षिक मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य मे की जा सकती है। अत जनपद की भावी सभाव्य जनसंख्या की गणना करना आवश्यक है जिससे विद्यार्थियों की बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में जनपद की शैक्षिक सुविधाओं का नियोजन प्रस्तुत किया जा सके ।

(अ) जनसंख्या प्रक्षेपण एव छात्रों की सभाव्य संख्या

नियोजन भविष्य के लिए होता है। कोई भी नियोजन भविष्य मे तभी कारगर सिद्ध हो सकता है जब उस क्षेत्र की सभाव्य जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखा जाय। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के सभाव्य भावी जनसंख्या वृद्धि के अनुमान को जनसंख्या प्रक्षेपण कहते हैं। जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न आधारों यथा आयु समूह सरचना, उत्पादकता, गत् जन्मदर एव मृत्युदर आदि का प्रयोग किया गया है। किन्तु जनसंख्या वृद्धि एक गतिशील प्रक्रिया होने के कारण सदैव बदलती रहती है। जनसंख्या आकार में परिवर्तन जन्मदर, मृत्युदर एव प्रवास के कारण होता रहता है। जनपद में जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त निन्न तथ्यों को भी ध्यान में रखा गया है -

। जनसंख्या प्रक्षेपण में जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर को सभी विकास खण्डों के लिए आधार माना गया है ।

2 यह मान लिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान वृद्धि दर के समान रहेगी क्योंकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि समय के साथ लोग परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते रहेगे।

3 जनसंख्या वृद्धि चक्रवृद्धि दर से होगी।

तत्पश्चात सर्वप्रथम जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर की गणना की गयी है। 1961 की जनसंख्या को आधार वर्ष तथा 1991 की जनसंख्या को अंतिम वर्ष की जनसंख्या के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह गणना गिब्स द्वारा प्रस्तुत निम्न सूत्र से की गयी है 13-

$$r = \frac{(p_2 - p_1)/t}{(p_2 + p_1)/2} \times 100$$

जहाँ,

r = वार्षिक औसत वृद्धिदर,

P 1 = प्रारम्भिक जनसंख्या आकार,

P 2= अतिम जनसंख्या आकार, तथा

t = समयावधि

गिब्स के उपर्युक्त सूत्र से गणना करने पर जनपद की ओसत वार्षिक वृद्धि दर 2 85% आती है। पुन सभी विकास खण्डो की सन् 2001 की भावी जनसंख्या का अनुमान निम्न सूत्र से निकाला गया है 14-

$$A = P \left[1 + \frac{r}{100} \right]^t$$

जहाँ,

A = प्रक्षेपित जनसंख्या,

P = वर्तमान जनसंख्या

t = वर्तमान तथा प्रक्षेपित जनसंख्या के बीच की अवधि

r = औसत वृद्धि दर

सन् 2001 तक जनपद की जनसंख्या बढकर 14,23,862 हो जाने की सभावना है।

चूँिक आयु सरचना के अनुरूप छात्रों की सख्या के आकड़े उपलब्ध नहीं है इसलिए विद्यालयों के स्तर के अनुसार सभाव्य भावी छात्रों की सख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। विद्यालयों के स्तर मे मात्र जूनियर बेसिक विद्यालय, सीनियर बेसिक विद्यालय तथा हायर सेकेन्ड्री स्कूल को ही सिम्मिलित किया गया है। छात्रों की वार्षिक वृद्धि दर की गणना 1961 से 1991 के मध्य 30 वर्षों के जनसंख्या छात्र अनुपात के औसत की गणना कर के की गयी है। प्राथमिक विद्यालयों मे छात्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 0 46% है। सीनियर बेसिक विद्यालय तथा हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों मे वृद्धि दर कृमश 0 16 तथा 0 08 प्रतिशत

है। सन् 2001 तक जूनियर बेसिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की सख्या कुल जनसख्या की 9 72% होने का अनुमान है। सीनियर बेसिक विद्यालयों तथा हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में यह अनुमान क्रमश 2 20 व 2 70% होने के लिए लगाया गया है, जो तालिका 7 10 से स्पष्ट है।

तालिका ७ ।० जनपद सोनभद्र में जनसंख्या छात्र अनुपात ^x

क्रमसख्या विद्यालय स्तर	छात्रों की औसत	अनुमानित छात्र	200। मे जनसंख्या
	वार्षिक वृद्धि	जनसंख्या अनुपात	की तुलना मे छात्रों
	प्रतिश्रत मे	200।	का प्रतिशत
 जूनियर बेसिक विद्यालय सीनियर बेसिक विद्यालय हायर सेकेन्ड्री स्कूल 	0 46 0 19 0 08	I 10 29 I 45 92 I 39 82	9 72 2 20 2 70

[×] छात्र जनसंख्या अनुपात एव प्रतिशत की गणना प्रक्षेपित जनसंख्या व छात्रो की संख्या के आधार पर की गयी है।

(ब) विद्यालय स्तर के अनुसार नियोजन

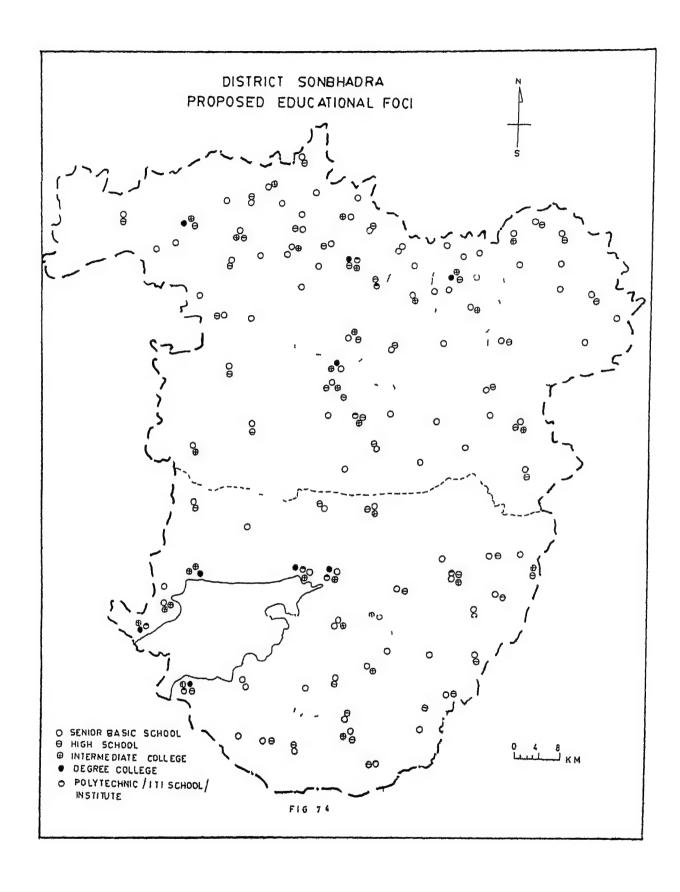
तालिका 7 11 से यह स्पष्ट है कि जूनियर बेसिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की सख्या 2001 से बढ़कर 138356 हो जाने का अनुमान है। बढ़े हुए छात्रों के लिए 207 नये विद्यालयों तथा 2860 नए अध्यापकों की आवश्यकता होगी। सीनियर बेसिक विद्यालयों में 9166 छात्रों के बढ़ने का अनुमान है जिनके लिए 165 नए विद्यालयों तथा 763 नये शिक्षकों की आवश्यकता होगी। हायर सेकेन्ड्री स्कूल में 11462 विद्यार्थी बढ़ेगे जिनके लिए 47 नये विद्यालयों व 812 नये अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

तालिका ७ ।। जनपद सोनभद्र मे आवश्यक श्रेक्षणिक सुविधाए, २००। ई०

क्रम्सख्या विद्यालय का स्तर	छात्र संख्या वर्तमान २०	छात्र सस्या वर्तमान २००। ई० वृद्धि	वृद्धि	विद्यालय सख्या वर्तमान	सस्या 2001 ई0	बुद्धी	क्तिमान	श्रिक्षक सख्या वर्तमान 2001ई0	बुद्ध
। । जूनियर बेसिक विद्यालय	99776	138356	38580	715	922	207		1093 4953	2860
2 सीनियर बेसिक विद्यालय	22181	31347	9166	96	261	165	282	1045	763
3 हायर सेकेन्ड्री स्कूल	26997	38459	11462	30	77	47	726	1538	812

म्रोत तालिका 7 10, तथा 7 9, मे दिए गए मानकों के सदर्भ मे प्रश्लेपित

जनसंख्या से संगीपत ।



(1) जूनियर बेसिक विद्यालय

वर्तमान समय में कुल 715 जूनियर बेसिक विद्यालय है। भावी जनसंख्या में वृद्धि के साथ छात्रों की उचित प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए 2001 तक 207 विद्यालय और खोले जाय। जनसंख्या के अनुपात में लगभग 73 विद्यालय नगरों में तथा 134 विद्यालय गांवां में खोलना चाहिए। गांवों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में विकास खण्ड घोरावल, राबर्टसगज, चतरा व नगवा में सबसे कम विद्यालयों का औसत है। अत इन विकास खण्डों में अधिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। 2001 ई0 तककेवल 792 गांवों में विद्यालय होंगे। 550 गांव उस समय भी जूनियर बेसिक विद्यालय रहित होंगे। विकास खण्ड चतरा, राबर्टसगज व घोरावल के कुछ कृषि प्रधान क्षेत्रों के अतिरिक्त अधिकाश बस्तियाँ बिखरी हुई है। और कुछ गाँवों में अत्यधिक न्यून जनसंख्या पायी जाती है। उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में 1342 गार्मों में से 792 गांमों में विद्यालय होना उपयुक्त होगा।

(2) सीनियर बेसिक विद्यालय

प्रस्तुत अध्ययन मे दिए गए मानदण्डों के सदर्भ मे विद्यार्थियों मे भावी वृद्धि तथा उनकी वर्तमान कमी को देखते हुए सन् 2001 तक 165 नए विद्यालयों की आवश्यकता होगी। नगरों मे भी ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता होगी। नगरों मे ऐसे विद्यालयों की स्थित सतोषजनक है इसलिए नगरों मे ऐसे विद्यालयों के खोलने की आवश्यकता कम है क्योंकि नगरों मे इसकी पूर्ति हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के माध्यम से भी हो जाती है। अतिरिक्त खुलने वाले विद्यालयों की अवस्थितियों का प्रारूप अध्ययन क्षेत्र मे उनकी कार्यात्मक रिक्तता को ध्यान मे रखकर किया गया है। इनकी अवस्थितियां मानचित्र मे देखी जा सकती है।

(3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल

छात्रों की भावी सख्या तथा अध्ययन क्षेत्र मे अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार सन् 2001 तक 47 अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता होगी। इसमे से 30 इण्टरकालेज तथा 27 हाईस्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। इण्टर कालेज की अवस्थित 10 नगरीय क्षेत्रों मे यथा 20 ग्रामीण क्षेत्रों मे होनी चाहिए, मानचित्र मे इनकी अवस्थिति देखी जा सकती है। हाई स्कूल की अवस्थिति का प्रस्ताव कार्यात्मक रिक्तता, प्राकृतिक अवरोधों व अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों

के। ध्यान मे रखकर किया गया है। यह मानचित्र मे प्रदर्शित है।

(4) उच्च शिक्षा केन्द्र

अध्ययन क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नाम पर स्नातक स्तर तक ओबरा व दुद्धी में दो महाविद्यालय है। इसके अतिरिक्त अनपरा में सीमित स्तर पर प्राइवेट डिग्री कॉलेज कार्यरत है। जनपद में मुख्यालय राबर्ट्सगज में एक भी महाविद्यालय नहीं है। जनपद में उच्च शिक्षा के अभाव को देखते हुए 8 नये महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर तक खोलने का प्रस्ताव है। रामगढ, राबर्टसगज, घोरावल, चोपन, रेनूकृट, रिहन्द नगर, शिक्तनगर व अनपरा में एक एक महाविद्यालय 200। ई0 तक खुल जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुद्धी व ओबरा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर तक किया जाना चाहिए।

(5) तकनीकी शिक्षण सस्थान

सम्पूर्ण सोनभद्र जनपद मे एक भी प्रशिक्षण या तकनीकी सस्थान नही है। उल्लेखनीय है कि सोनभद्र मे अनेक औद्योगिक केन्द्र होने के कारण तकनीशियनों की मॉग सदैव बनी रहती है, इसे देखते हुए एक पॉलिटेक्निक व एक आई0टी0आई0 विद्यालय 2001 ई0 तक खोलने की आवश्यकता है। औद्योगिक कर्मियों के प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार औद्योगिक केन्द्रों मे ही औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान खोलने की आवश्यकता है। ओबरा ताप विद्युत गृह मे सीमित स्तर पर प्रशिक्षण सस्थान है। रेनूकूट, अनपरा, शक्तिनगर, रिहन्द नगर, डाला व चुर्क के कारखानों मे प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि तथा लघु एव कृटीर उद्योगों मे कृशलता बरतने हेत राबर्ट्सगज मे एक प्रशिक्षण सस्थान होना चाहिए।

(6) अनौपचारिक शिक्षा

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की 65 60% जनसंख्या निरक्षर है। इसमें पुरूषों की निरक्षरता 52 44% तथा स्त्रियों की निरक्षरता 81 35% है। जनपद में निरक्षरों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अनौपचारिक शिक्षा की महती आवश्यकता है। इसके लिए विश्व स्तर पर 1990 को साक्षरता वर्ष के रूप में अवश्य मनाया गया किन्तु जनपद स्तर पर इसका प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है। अत इसके लिए जनपद व विकासखण्ड स्तर पर साक्षरता वर्ष घोषित करके आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस काम में स्वय

सेवी सस्थाए विशेष योगदान दे सकती है। गोविन्दपुर बनवासी आश्रम द्वारा निरक्षरता समाप्त करने के लिए 'अक्षर सेना' का गठन करके अनूठा कार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि चोपन, म्योरपुर, बभनी, दुद्धी विकास खण्ड मे अकेले इस सस्थान ने अब तक जो कार्य किया है। उसका अन्य स्वयसेवी सस्थाए व सरकार अनुकरण कर सकती है। अनौपचारिक शिक्षा मे प्रौढ शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए तथा उनकी शिक्षा व्यवसायपरक भी होनी चाहिए। प्रौढो को अक्षर ज्ञान के साथ-साथ कृषि मे प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों, कीटनाशक दवाओ, बीजों का प्रयोग तथा लघु एव कुटीर उद्योग आदि से सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए।

निरक्षरता दूर करने के अब तक के हमारे प्रयास अधिक सफल नही हो पाए है। यदि हम सफल रहे होते तो साक्षरता की उम्र बढाने की बावजूद जनपद की लगभग 2/3 जनता आज भी निरक्षर नहीं होती। हमें साक्षरता के प्रसार के लिए भविष्य में और बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे लेकिन समस्या यह है कि हमारे आर्थिक ससाधन सीमित है और निरक्षरों की सख्या मे भी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे निरक्षरों की सख्या भी बढती जा रही है। फिर भी यदि कोशिश की जाए तो अधिकाश को साक्षर बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम एक को पढ़ाने का सकल्प ले और उसे निष्ठापूर्वक पूरा करे। सभी स्नातकों को कम से कम 6 महीने या साल भर निरक्षरता उन्मूलन अभियान मे लगाया जा सकता है। अच्छा तो यह होगा कि स्नातक स्तर पर अतिम वर्ष मे निरक्षरता दूर करने के कार्यक्रम को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। यदि प्रौढ शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप मे लागू नही किया जाता तो नौकरी पाने या स्वरोजगार के लिए ऋण पाने के लिए प्रौढ शिक्षा को अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त साक्षरता अभियान को सफल बनाने का एक माध्यम यह हो सकता है कि निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उनकी आय के अनुपात में एक निश्चित राशि साक्षरता प्रसार के लिए प्राप्त की जाए। इस कार्य को सरल बनाने निजी प्रतिष्ठानों के वाणिज्यिक मडलो की सहायता ली जा सकती है। स्वयसेवी सगठन भी साक्षरता के प्रसार मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है और इस कार्य मे उनका सहयोग लेना बहुत जरूरी है। साक्षरता कक्षाये चलाने मे स्थानीय और सस्ते साधनों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, तभी इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। प्राय ससाधनों की कमी के कारण अभियान

सफल नही हो पा रहा है।

आधुनिक जन सचार माध्यम साक्षरता प्रसार के काम मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। हालांकि कठपुतली, नाटक, लोकगीत, लोककथाए आदि का भी इस क्षेत्र मे उपयोग हो रहा है लेकिन इन सबकी अपनी सीमाए है। दूसरी ओर आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसे माध्यम है, जिनकी पहुँच न केवल जनपद सोनभद्र तक वरन् एक ही बार मे देश के करोडों लोगों तक होता है। इस्रुलिए इन माध्यमों का साक्षरता के प्रसार के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। हमे भूलना नहीं चाहिए कि ये इलेक्ट्रानिक माध्यम केवल मनोरजन के लिए नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से व्यापक सामाजिक परिवर्तन लाये जा सकते है। इसके लिए कठोर सकल्प और इच्छाशिक्त की आवश्यकता है। समन्वित विकास के लिए यह सकल्प लेना ही होगा।

7 8 स्वास्थ्य

ससाधनों का अधिकतम उपयोग स्वस्थ मनुष्य ही कर सवता है । स्वस्थ मनुष्य औषधियों का प्रयोग न वरके, अनेक रूपों मे देश के ससाधनों की बचत वरके उसे अन्य विकास वार्यों में लगाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित वरता है । व्यहा गया है वि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार का निवास होता है । उत्तम स्वास्थ्य सफल एम सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है । विन्त्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय' नागरिकों के जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने के राष्ट्रीय प्रयास को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम विकास की दिशा में हमारे प्रयासों के महत्वपूर्ण अग है । सितम्बर 1978 की 'अलमा आटा' घोषणा वे अनुसार सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने का राष्ट्रीय सकल्प लिया गया है । कि स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने का राष्ट्रीय सकल्प लिया गया है । कि स्वास्थ्य का लक्ष्य को पित में परिकल्पित सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य अब कोई सपना या आदर्श मात्र नहीं रह गया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के चार दशकों में हमारे देश में किए गए निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप अब इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना सभव हो गया है । पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं पर पूरा ध्यान दिया गया है । हमारे देश के सींक्थान के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं पर पूरा ध्यान दिया गया है । हमारे देश के सींक्थान के अनुसार

प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अपने लोगों के पोषाहार के स्तर तथा जीवन - स्तर को ऊँचा उठाए और जन-स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे । इसके अन्तर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और गरीब वर्गों के लिए परिवार कल्याण और पोषाहार के साथ न्यूनतम जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाए प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है । पचवर्षीय योजनाओं मे ग्रामीण, पहाडी और जनजातीय क्षेत्रों मे स्वास्थ्य सेवाए पहुँचाई जा रही है । इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मिकों के शिक्षण और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया है । अधि की भी जनपद के स्वास्थ्य सम्बन्धी नियोजन प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओ एव समस्याओं का निरूपण करना आवश्यक है । अधिकाश बीमारियों की जड पैय जल' की समस्या को जनपद की विशिष्ट समस्या के रूप मे निरूपित किया गया है ।

7.9 स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याए

जनपद में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, जनपदवासी सामान्य बीमारियों के अतिरिक्त विशिष्ट बीमारियों से गस्त है तथा उसका कारण क्या है? द्वितीय, उन बीमारियों को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अस्पताल, शैय्या, डाक्टर है या नहीं। यदि इन सुविधाओं की कमी है या इन सुविधाओं की अवस्थिति सुव्यवस्थित नहीं है या उनमें समुचित कार्यात्मकता का अभाव है तो निश्चय ही ऐसे क्षेत्र को समस्यायुक्त क्षेत्र कहा जा सकता है। ऐसे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार प्राथमिक आवश्यकता बन जाती है। जनपद सोनभद्र में दोनों तरह की समस्याए है।

(अ) रोगों की समस्या

सोनभद्र वासी बहुधा कॉलरा, ग्रैस्ट्रो, तपेदिक, टाइफाइड, मलेरिया, चर्मरोग, कुष्ठरोग, नेत्र रोग,फाइलेरिया, चेचक , कुकुरखाँसी, पोलियो, पेचिस, हड्डी व उदर सम्बन्धी रोग, आन्त्र ज्वर, खाँसी आदि रोगों से पीडित रहते हैं । जनपद के औद्योगिक केन्द्रों (प्रदूषणयुक्त क्षेत्रों) में, धुँआ, धूल के कणों, सीमेण्ट के कणों व पेयजल की समस्या के कारण टाइफाइड, टी वी , खाँसी आदि रोग सामान्य रोगों की श्रेणी में आ गए हैं । अन्य क्षेत्रों में पौष्टिक आहार की कमी तथा पेयजल की समस्या के कारण उपर्युक्त रोगों का वर्चस्व है तथा इससे सम्पूर्ण जनपद समस्याग्रस्त है जिससे विकास कार्यों में बाधा पहुँच रही है ।

राबर्ट्सगज, घोरावल, चतरा, नगवा, विकासखण्डों के कृषि मजदूर कृषि कार्यों से खाली होने पर सोनपार के औद्योगिक क्षेत्रों मे धन कमाने की लालसा से बहुधा जाया करते है और प्रदूषित क्षेत्रों से 'अनाम बीमारियों' को लेकर आते है तथा झोलाछाप डाक्टरों से इलाज कराकर और अधिक 'बेनाम बीमारियों' को पैदाकर, अपनी गाढी कमाई गर्यों कर ऋणगृस्तता के जाल मे फस जाते है । इसके दो प्रभाव दिखाई पडते है -

- (।) नव पर्यावरणवादी जो इन उद्योगों का विरोध करते हैं तथा इनमें काम करने से मना करते हैं, इन बीमारियों ने उनका काम स्वय आसान कर दिया है। बहुत से मजदूर अब सोनपार के क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते किन्तु सोनपार के निवासियों के लिए यह एक जन्मजात समस्या बन गई है।
- (2) अध्ययन क्षेत्र मे रोगों की पर्याप्तता के कारण झोलाछाप डाक्टरों की बहुतायत है । शहर के अच्छे डाकटर तथा सरकारी डाक्टर भी स्वय पैसा कमाने के ध्येय से दूरस्थ क्षेत्रों मे अपना प्रसार शुरू कर दिए है । इससे ग्रामीणों को जहाँ कुछ सुविधा मिली है वहीं अधिक धन सचय (व्यावसायिकता) के कारण अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई है ।

एक विशिष्ट उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये डाक्टर अपनी चिकित्सा के बदले पैसा नहीं लेते वरन् वे दुर्लभ वस्तुए जो पैसा से भी नहीं मिलती जैसे मूल्यवान पत्थर,जगली जानवर,पक्षी, पियार (इससे चिरौजी बनता है), भी, जानवरों की छाल, फर्नीचर के लिए लकडी, हर्र, बहेर, जडी-बूटी, शहद, उनका श्रम, जगीन विदि का शोषण करते है। यह लेन - देन स्वय के उपयोग के लिए नहीं वरन् व्यापार के लिए होता है। ये हिन्दुस्तान के अग्रेज है, इनसे मुक्ति पाने के लिए सामाजिक क्रान्ति आवश्यक है। मेरे 27 वर्ष के अनुभव व व्यक्तिगत सर्वक्षण से ज्ञात होता है कि सोनभद्र वासी अपने समाज से इतर केवल दो सस्थाओं (चिकित्सा व पुलिस विभाग) तथा दो अधिकारियों, डाक्टर व दरोगा को ही जानते है, दूसरे शब्दों में ये दो लोग ही अपनी पहुँच ग्रामीण स्तर पर बनाए है। शायद इसके विश्लेषण की जरूरत नहीं है।

इस तरह स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन से समस्याओं की एक शृखला नजर आती है। इसके मूल मे है - पौष्टिक आहार की कमी, प्रदूषित वातावरण तथा पेयजल की समस्या । पौष्टिकता की कमी गरीबी व अशिक्षा से जुड़ी हुई है । पैसे के लोभ में सोनभद्र के प्रत्येक क्षेत्र में मोटे अनाजों की जगह, बाहर से आए हुए, औद्योगिक केन्द्रों में बसे हुए लोगों के लिए सब्जी उगाने का प्रयास किया जा रहा है । ग्रामीण अचलों से दूध, दही एवं धी सस्ते दामों पर इन 'औद्योगिक केन्द्र स्थलों पर कार्यरत अधिकारियों' के लिए चला जाता है । चराई की सुविधा से युक्त पशुपालन के लाभ से यहाँ के निवासी विचत है । ये तो इसी में खुश है कि अब उन्हें 'खोवा' बनाकर बनारस की मड़ियों में नहीं भेजना पड़ता है ।

चुर्क से शक्तिनगर व रिहन्द तक का सम्पूर्ण क्षेत्र महानगरों की तरह प्रदूषित है। सीमेण्ट कारखानों, चूने की भट्ठियों, क्रेशर उद्योगों, तापविद्युत केन्द्रों आदि से सम्पूर्ण क्षेत्र धूल के कणो व धुआ से भरा हुआ है । इससे नेत्र, चर्म व फेफडे सम्बन्धी अद्यतन बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है । खनन कार्यों में काम करने वालों की अलग समस्या है ।

पेयजल की समस्या जनपद की प्रमुख समस्या है । कहा जाता है कि 50% रोगों का कारण पानी है । अत इस समस्या की विस्तार से विवेचना की गयी है । पेयजल की समस्या न केवल मनुष्यों के लिए है वरन् जानवरों के लिए भी है । पेयजल की समस्या के कई कारण है -

- । जल की कमी बढते जाना,
- 2 भूमिगत जल का लगातार नीचे जाना,
- 3 पेय जल का अन्य कार्यों मे प्रयोग करना,
- 4 पेय जल का प्रदूषित होना,
- 5 पानी को रिफाइन्ड करके दुबारा प्रयोग न करना ।

"हमे सोना नहीं पानी चाहिए" म्यानमार के सूखा पीडित क्षेत्र के एक गाँव मे यह साइन बोर्ड लगा था, इसमे बुनियादी जरूरत और जीवन की कुजी के रूप मे पानी के महत्व का पता लगता है । अनुमानत हर व्यक्ति को हर रोज निजी उपयोग के लिए 20 लीटर पानी चाहिए । यह न्यूनतम मात्रा भी जनपदवासियों को उपलब्ध नहीं होता है । भारत की 1981-91 की दशक की योजना मे पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी । इसमे 30% जनता को नलों के माध्यम से और 70% को मौके पर उपजब्ध साधनों द्वारा पानी की आपूर्ति की व्यवस्था

है । भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ARWSP) के माध्यम से गाँवों मे पीने का पानी उपलब्ध कराने को उच्च प्राथमिकता दी है । राज्य सरकारे अपनी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस काम मे सहयोग कर रही है । सरकार द्वारा पेयजल समस्या से ग्रस्त गाँवों के निम्न मापदण्ड निर्धारित किए गए है -

- । पेय जल स्त्रोत से गाँवों की । 6 कि0 मी0 से अधिक दूरी,
- 2, कूपों की 15 मीटर से अधिक गहराई,
- 3 100 मीटर की ऊँचाई के अन्तर पर,
- सुरक्षित पेयजल रहित गाँव
- जैविक प्रदूषण (गिनीवृमि, हैजा, टायफाइड आदि)
- -रासायनिक प्रदूषण (फ्लोराइड, खारापन, लौह, आर्सेनिक आदि) वाले गाँव ।

सोनभद्र जनपद का प्रत्येक गाँव व नगर किसी - न - किसी रूप में पेयजल की समस्या से ग्रस्त है । चतरा, राबर्ट्सगज व घोरावल के कुछ नहरी सिचाई वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल - स्तर ऊपर आ जाने से जल की गुणवत्ता में झस हुआ है । सिचाई के लिए भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल अदृश्य होता जा रहा है । ग्रीष्म ऋतु में अधिकाश कुए सूख जाते हैं । अन्य ऋतुओं में तालाब - पोखर का पानी मनुष्य व पशु साथ-साथ उपयोग करते हैं, जिससे अनेक रोगों का जनन अपने आप हो जाता है । 180 वर्ग मील में फैले रिहन्द जलाशय से, उसके तटवर्ती औद्योगिक पेटी (रेनुकूट, पिपरी, अनपरा, रेणूसागर, शक्तिनगर, रिहन्द नगर तथा ओबरा) में अधिकाश पेय जल की आपूर्ति होती है । रिफाइन्ड करने के बावजूद इसे प्रदूषण मुक्त करना कठिन है । फलत यहाँ के लोग स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक रोगों से ग्रस्त है । दूर - दराज के पहाड़ी इलाकों (बभनी, नगवा, दुन्दी, म्योरपुर, चोपन) में पेय जल स्त्रोत अल्प है । यूनिसेफ के सहयोग से लगा हैण्डपम्प भी इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ है ।

(ब) स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की समस्या

किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की मात्रा एवं अवस्थिति की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कई प्रश्न हो सकते हैं । जैसे जिस क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या

हो ही नहीं, ऐसे क्षेत्र मे चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की अनुपस्थित को क्या पिछडा क्षेत्र या अभावग्रस्त क्षेत्र कहना उचित है ? यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी कम है तथा उसके अनुरूप चिकित्सकीय सुविधाओं को अल्प सुविधा कहना कहाँ तक उचित है ? यदि किसी क्षेत्र मे विशिष्ट रोग हो तथा उसके अनुरूप वहाँ चिकित्सा सुविधा हो (जैसे तर्राई क्षेत्र मे मस्तिष्क ज्वर का गोरखपुर मे चिकित्सा सुविधा) किन्तु अन्य क्षेत्र मे उस सुविधा का न होना उस विशिष्ट रोग का अभाव हो, तो क्या ऐसे दो क्षेत्रों को दो 'असमान चिकित्सा सुविधायुक्त क्षेत्र' कहना उचित है ? इसी प्रकार गरीबी के कारण आधुनिक मेंहगी चिकित्सा सुविधा का उपयोग न करना क्या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होने की बात कही जा सकती है ? सरल - सादा जीवन व्यतीत करने वाले तथा पर्यावरण से तादात्म्य स्थापित करके जीवन जीने वालों पर प्राकृतिक चिकित्सा रामवाण सिद्ध होती है । जल, हवा सौर प्रकाश, तुलसी की पत्ती आदि अधिकाश रोगों का समाधान कर देती है । ऐसे लोगों को एलोपेथिक चिकित्सा की अल्प आवश्यक्ता को क्या पिछडा कहना उचित है ? उपर्युक्त सभी प्रश्न विवाद एव अतिरिक्त शोध के विषय है, जो साधन व समय की अल्पता के कारण सम्भव नहीं है। प्रस्तुत अध्याय मे सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा सुविधा के मानदण्डों एव जनपद की वर्तमान सुविधा के सदर्भ मे विश्लेषण किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रत्येक 5000 आबादी के पीछे एक उपकेन्द्र तथा एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 30,000 आबादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1 00000 की आबादी के पीछे एक सामुदायिक केन्द्र खोला जाना है 1 किन्तु पहाडी क्षेत्रों रेगिस्तानी व आदिवासी क्षेत्रों मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 20,000 की तथा उपकेन्द्र के लिए 3000 की जनसंख्या होना ही पर्याप्त है 1

जनपद की स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कुछ प्रमुख समस्याए निम्न है -

- । नगरों मे पढे हुए डाक्टरों का, उच्च वेतनमान की प्राप्ति के बावजूद, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर न रहना एक प्रमुख समस्या है । अस्पताल मे समय पर न जाना, भहरों मे रहकर साप्ताहिक निरीक्षण करना डाक्टरों द्वारा प्रमुख समस्या खडी कर दी गयी है ।
- 2 चिकित्सालयों मे दवाओं का अभाव तथा उनके रख-रखाव का उचित प्रबन्ध न होना प्रमुख समस्या है, यह जनपद मे सर्वत्र व्याप्त है ।

- 3 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार की कमी रहती है, इसका कारण गरीबी व अशिक्षा है।
- 4 समस्त ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रसव के लिए नर्सी का अभाव है । अप्रशिक्षित दाइयों से जच्चा - बच्चा विशेष रूप से प्रभावित होते है ।
- 5 ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र मे आवास की समस्या, पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने से मच्छरों द्वारा अनेक बीमारियाँ उत्पन्न कर दी जाती है । इससे जनपद मुख्यालय राबर्ट्सगज सर्वाधिक प्रभावित है ।
- 6 शौचालयों का अभाव एवसफाई व्यवस्था न होने से अनेक रोगों का अपने आप जनन होता है, जिससे सम्पूर्ण स्वास्थ्य च्यवस्था प्रभावित होती है ।
- 7 मद्यपान व नशीले पदार्थी के सेवन से आर्थिक व शारीरिक क्षीणता बढती जा रही

7 10 चिकित्सा सुविधाओं की वर्तमान स्थिति

जनपद में चिकित्सा सुविधाओं की स्थित सतोषजनक नहीं है । रोगियों के अनुसार सुविधाओं का नितान्त अभाव है । जनपद के कुल अस्पतालों की सख्या 83 है, जिसमें से आयुर्वेद के 16 (19 28%) होम्योपेथ के 20 (24 09%) तथा यूनानी चिकित्सा पद्धित का । (1 2%) अस्पताल है । 55 42% अस्पताल एलोपेथ से सम्बन्धित है । 83 अस्पतालों में से 15 अस्पताल नगरीय केन्द्रों में है । अर्थात 13 40% नगरीय जनसंख्या के लिए 18 07% अस्पताल है । उल्लेखनीय है कि नगरों में 'प्राइवेट क्लिनिक' के अतिरिक्त अनेक 'नर्सिंग होम' है । चूँकि व्यक्तिगत क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाए नगरों में अधिक रहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने जनसंख्या के अनुपात में अल्प चिकित्सिकीय सुविधा को प्राप्त किए है । विकास खण्ड घोरावल, राबर्ट्सगज, चतरा, नगवा, चोपन, म्योरपुर, दुद्धी व बभनी के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या क्रमश 9, 8, 4, 7, 11, 16, 6, 7 है । इस प्रकार सम्पूर्ण जनपद में 12798 जनसंख्या पर । अस्पताल का औसत है । प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपेथिक चिकित्सालय /औषधालय एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या 1991-92 में 3 7 था । अध्ययन क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं का विवरण तालिका 7 12,13 में दिया गया है।

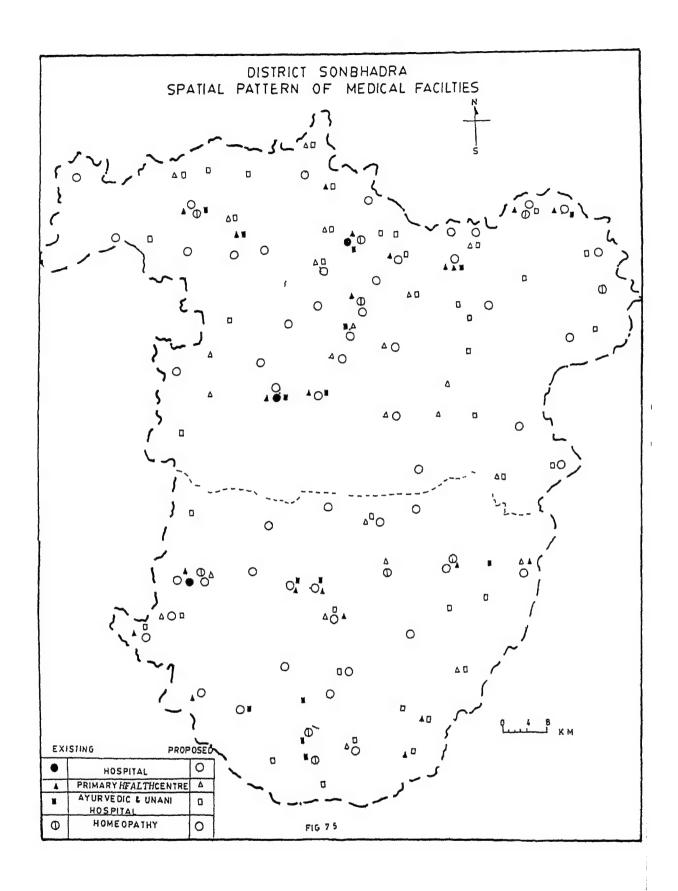
तालिका 7 ।2 जनपद में विक्रास खण्ड वार चिकित्सा सेवा

	_ '	5	1	1		7	1 1 1 1 1 1 1						
वेष/जनपद/ विकासखण्ड	एलापाथक । ज चिकित्सालय/ औष्धालय	चिकत्स स्व / प्रा0स्वा0 उपलब्ध केन्द्र शैय्या	उपलब्ध श्रु <u>य</u> ्या	डाक्टरों की सह्या	अधिवादक औषदा0/ चिकित्सा0	चिकत्स उपलब्ध शैय्या	डाक्टरों की संख्या	औषदा0/ चिकित्सा0	ज्यस्य विश्व अथ्या	ह्मप्रता डावटचे की संख्या	अौषधा०/ चिकित्सा०	चुप्लब्ब अय्या	क् के
-	2	ယ ယ !	4	5	6	7	8	9	10	= :	12	13	4
1989-90	14	22	348	46	9	40	17	- 8	í	15	-	4	-
1990-91	14	22	348	46	16	123	20	20	•	_		4	-
1991-92	17	29	382	4	16	123	20	20	1		-	4	-
1991 - 92 । घोरावल	1	ယ	42	57	ω ; ;	8	2	ယ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
2 राबर्ट्सगज	2	4	48	12	-	5	2	1	1	ı	-	4	
3 चतरा	-	2	0	ယ	_	1	_	t	1	ı	ı	ı	1
4 नगवा		2	74	ယ	8	19	ယ	2	1	ι	1	•	4
5 चोपन	2	4	46	4	-	00	2	4	1	ယ	ı	1	t
6 म्योरपुर	2	6	32	2	4	40	ĆΤ	4		-	ı	ı	1
7 दुद्धी	_	2	26	2		1	-	2	ſ	2	i	ı	1
8 बभनी	ı	8	01	_	_	4	_	4	ı	ပ	ı	,	1
ग्राभीण योग	9	25	228	32	4	94	17	19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	- 1	4 1	- :
नगरीय योग	œ	4	154	9	2	29	ယ	-	t	-	1	,	ı
सम्पूर्ण योग	17	29	382	4	16	123	20	20	: 1 (;		_	14	-
स्रोत सांख्यिकीय पनि	सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 101	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	विश्व ।	1 1	102	120	100		:	1 a 1 a 1		1	:

तालिका ७ । ३ जनपद सोनभद्र मे चिकित्सा सुविधा

1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
विकार	विकासखण्ड	प्रति लाख जन0 पर एलोपेथिक चिकि0/औष0 एव प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या	प्रति लाख जन0 पर एलोपेथिक चिकि0/औष0 एन प्रा0स्चा0के0 मे उपलब्ध सैट्याओं की सख्या	प्रति लाख जन0 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	परिवार एव मातु मानक श्रिश्च कल्याण केन्द्र उपकेन्द्र	मानक समिन्द्र	परिवार एवं मातृ सिश्च कल्याण उपकेन्द्र
	घोरावल	9	26 9	19	-	32	26
2	राबर्ट्सगज	4 3	34 8	2 9	_	34	30
ယ	चतरा	4 5	14 8	3 0	-	13	12
4	नगवा	ъ ъ	25 7	3 7	_	_	10
G	चोपन	3 6	27 6	- 8	-	44	26
6	म्योरपुर	4	16 6	1 6	-	48	22
7	दुद्धी	3 -	26 9	1 0			15
00	बभनी	ယ (π	17 4	17	-	12	-1 4
ग्रामीण योग	योग	3 7	24 5	1 9	ο 1 1	1 	155
गरीय	नगरीय योग				ယ		2
सम्पूर्व	सम्पूर्ण जनपद			1	=	215	157
1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1 1 1 1 1 1	

ग्रीत सांंध्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 21, 22, एव 103



जनपद में कुल चिकित्साधिकारियों की सख्या - 73, अस्पतालों में उपलब्ध समस्त शैय्या की सख्या - 509, मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र की सख्या - 11 तथा उपकेन्द्रों की सख्या 157 है । अस्पताल की सख्या - 83 तथा डाक्टर की सख्या-73 से स्पष्ट है कि कुछ अस्पताल कम्पाउण्डर द्वारा ही चलाए जा रहे हैं ।

7 ।। स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन

स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन, उनकी वर्तमान मात्रा एव अवस्थिति का निश्चित मानदण्डों से तुलना करके भविष्य की आवश्यकताओं तथा वर्तमान समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में किया गया है । नियोजन को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है संसाधनों का अनुमान तथा उसके निवेश के प्राथमिकता का निर्धारण सरकार करती है, इसलिए संसाधनों की उपलब्धता व निवेश प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार पहाडी क्षेत्रों में प्रति 20000 जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए । किन्तु जनपद में 37070 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है अर्थात 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जगह मात्र 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जनपद के प्रदूषण को देखते हुए यह मात्रा और होनी चाहिए । विकासखण्ड चतरा में सिलथम, नगवा में केमूर के दक्षिण व सोननदी के उत्तर में गड़ाव , बभनी में कोरची, दुन्दी में बीडर, बघाड़, चोपन में सेन्दुरिया म्योरपुर में बेलहत्थी, घोरावल में लहास न्यायपचायत केन्द्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने से लोगों के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को सुधारने में महती सहायता मिलेगी । जनपद में सम्पूर्ण अस्पतालों की सख्या 83 है किन्तु चिकित्साधिकारियों की सख्या 73 है । अत किसी भी अस्पताल को कम्पाउष्टर के सरक्षण में छोड़ना लोगों के जीवन से खिलवाड करना है । प्रत्येक अस्पताल पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति एव उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए ।

जनपद वासियों का जड़ी - बूटी पर विश्वास है, अत आयुर्विदिक, यूनानी एव होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की और आवश्यकता है । विकासखण्ड चतरा, रार्बर्ट्सगज, चोपन, दुद्धी व बभनी मे मात्र एक - एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है । इन पार्चो विकासखण्डों मे कम-से- कम चार - चार आयुर्वेदिक चिकित्सालय या यूनानी चिकित्सालय और खोलना चाहिए।

जिला मुख्यालय पर कम-से-कम 200 शैय्या युक्त जिला अस्पताल का होना आवश्यक है । मुख्यालय विवाद के कारण इस कार्य मे और विलम्ब नहीं करना चाहिए । इसके अलावा सभी बड़े औद्योगिक केन्द्रों पर कम-से-कम 100 शैय्या युक्त अस्पताल होना चाहिए । ऐसे अस्पताल ओबरा, डाला, चुर्क, रेनूकूट, पिपरी, रिहन्दनगर, अनपरा, रेणूसागर व शक्तिनगर मे आवश्यक है । इन सभी अस्पतालों को उपर्युक्त उल्लिखित सभी बीमारियों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार पहाडी क्षेत्रों मे 3000 जनसंख्या पर एक चिकित्सा उपकेन्द्र होना चाहिए । सोनभद्र के जनसंख्या के अनुपात मे सभी उपकेन्द्रों की संख्या 358 से कम नहीं होना चाहिए किन्तु वर्तमान उपकेन्द्रों की संख्या मात्र 155 है । अत 203 उपकेन्द्र और खोलने की जरूरत है । जनपद मे कुल 586 ग्राम सभाए है । । 64 ग्राम सभा पर । उपकेन्द्र का औसत है । जनपद मे प्राकृतिक अवरोधों को ध्यान मे रखते हुए, प्रत्येक व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुँचाने के लिए 203 ग्राम सभा केन्द्रों पर उपकेन्द्र खोलने की नितान्त आवश्यकता है ।

सभी स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों एव कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थित तथा चिकित्सा ससाधनो की उपलब्धता की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि मात्र से ही सुन्दर स्वास्थ्य नहीं प्राप्त किया जा सकता । दवा से स्वस्थता का धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है । इसके लिए पौष्टिक आहार, शुद्ध वायु, उचित सफाई व्यवस्था, शुद्ध वातावरण तथा शुद्ध पेय जल की आवश्यकता होती है । इसमे से अधिकाश की प्राप्ति स्वविवेक तथा जागरूकता से की जा सकती है । पौष्टिक आहार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मेवे - मशाले ही खाए जाए बल्कि मोटे अनाजों दूध, सब्जी व स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों से भी प्राप्त किया जा सकता है । सफाई व्यवस्था को दैनिक क्रिया के रूप मे अपना लेने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है जो उत्तम स्वास्थ्य का सूचक है ।

शुद्ध वायु की प्राप्ति जनपद के 5 विकासखण्डों (चोपन, राबर्ट्सगज, म्योरपुर, दुद्धी

व बभनी) के लिए दुर्लभ होती जा रही है । ऐसी स्थित में सम्पूर्ण स्वास्थ्य नियोजन प्रक्रिया खर्चीली होकर अर्थहीन हो जाती है । वास्तव में विकास नीति के द्वन्द्व में फर्स जाने के कारण एक तरफ हम बड़े - बड़े उद्योगों की स्थापना की तरफदारी करते हैं तथा दूसरी तरफ उससे निसृत प्रदूषण की आलोचना करते हैं । पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तेजी से समुद्र मन्थन हुआ तो उसमें से अमृत कलश के साथ विषकुण्ड भी निकला । ठीक इसी प्रकार जब हम तेजी से विकास नीति अपना रहे है तो प्रदूषण रूपी विषकुण्ड का जहर पीना ही पड़ेगा। इसके प्रभाव को प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगाकर तथा चिकित्सा सुविधाए बढ़ाकर कुछ कम किया जा सकता है ।

पेयजल जनपद की प्रमुख समस्या होने के साथ - साथ इसका नियोजन प्रस्तुत करना भी किठन है । जनपद में पेय जल कूपों, नलों, हैण्डपाइप, निदयों व बाधों से प्राप्त किया जाता है । भूमिगत जल ही वह स्त्रोत है जिसका अनेक प्रकार से दोहन करके जल आपूर्ति करते हैं । अत यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम इसका सावधानी से उपयोग करे । हमें वैज्ञानिक आधार पर भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय करने चाहिए । सम्पूर्ण सोनभद्र क्षेत्र भूमिगत जल के रूप में दुर्बल क्षेत्र है । अत भूमिगत जल का उपयोग केवल पेयजल के रूप में ही करना चाहिए । इसका उपयोग सिचाई के लिए तभी करना चाहिए जब छोटे-छोटे तालाबों, पोखरो व बन्धियों का निर्माण करके जलस्तर को बढाने का प्रयास किया जाय । इस तरह का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जा सक्ते हैं ।

पेयजल की सुविधा बढ़ाने से सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को होता है, इसलिए पानी का स्त्रोत चुनते समय उनसे विचार विमर्श अवश्य लिया जाना चाहिए । ऐसा करने पर कभी - भी असुविधाजनक स्थानों पर नल नहीं लग सकते । पानी की समस्या का समाधान सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र मे उपलब्ध विशेष व्यावसायिक और तकनीकी जानकारी को प्राप्त करके कर सकती है । इसके लिए महाराष्ट्र की स्वैच्छिक एजेंसी ' पानी पचायत' से प्रेरणा ली जा सकती है । इसके अलावा निम्न उपबन्धों का सहारा लिया जा सकता है ।

- । लागत की कमी लाने के लिए वैज्ञानिक स्त्रोत का पता लगाना ।
- 2 जल की गुणवत्ता की जाच के लिए आधारभूत सुविधाए उपलब्ध कराकर जल की गुणवत्ता पर बल देना ।
- 3 सुरिक्षित जल की पूर्ति करके गिनीकृमि का उन्मूलन करने, डिफ्लोराइडेशन सयन्त्र लगाकर अतिरिक्त फ्लोराइड को हटाने, लौह तत्वों को हटाने के लिए सयन्त्र स्थापित करके अतिरिक्त लौह तत्वों को दूर करने, सयन्त्र लगाकर क्षारता दूर करने जैसे रासायनिक और जीवाण्विक दूषण समाप्ति के कार्यों को करने के लिए विशेष अभियान चलाना ।
- 4 वर्षा के जल को इकट्ठा करने और पानी एकत्र करने के लिए समुचित ढाँचों के निर्माण को बढावा देने का कार्य करना चाहिए ।
- 5 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से ग्रामीण जल पूर्ति गतिविधियों/आदानो का मानकीकरण करना ।
- 6 पचायतों व जल उपभोक्ता सिमितियों को बडे पैमाने पर सिम्मिलित करके सामुदायिक सहभागिता और गैर सरकारी सगठनो की अधिक सहभागिता को बढावा देना तथा चुने हुए क्षेत्रों में समुदाय आधारित मॉडल पर प्रयोग करना ।
- 7 जलापूर्तिक निवेश को सामुदायिक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य स्तर प्रदान करने वाले माध्यम के रूप मे परिवर्तित करने वाले प्रेरक तत्वों के रूप मे महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देकर जलापूर्ति प्रबन्ध में महिलाओं की भूमिका का विस्तार करने का प्रयास करना।
- 8 जल प्रबन्ध, जल लक्ष्य निर्धारण और जल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भू भौतिकी तकनीकों, विशेषकर कैमूर पर्वत के दक्षिण के कठोर चट्टानो और दुर्गम इलाकों मे स्त्रोत का पता लगाने के लिए विद्युत जाच तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए।
- 9 कड़ी चट्टान वाले क्षेत्रों मे कुओं से अधिक पानी प्राप्त करने के लिए हाइड्रोलिक फ़ेक्चरिंग स्टिमुलेशन तकनीक (बोर वेल) का विकास करना होगा ।

सुरक्षित पेयजल की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जल के शुद्धिकरण और जल सरक्षण की संसाधन प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। यह रिहन्द जलाशय के लिए उपयुक्त होगा। 40 कि0 मी0 प्रति घंटे के वायु वेग को सहन करने के लिए एलकोक्सी इथेनॉल

मिश्रणो का उपयोग करके जल वाष्पीकरण का नियन्त्रण करना । पानी के गदलेपन की जाँच 'टबिडिमीटर' द्वारा करके ही नगरों मे जलापूर्ति करनी चाहिए । गाँवों मे यह विधि सभव नहीं है । रिहन्द जलाशय से पेयजल आपूर्ति के पहले पानी के खारेपन, कठोरता और अपिष्ठिट क्लोरीन का विश्लेषण टाइट्रेशन विधि से करनी चाहिए । फ्लोराइड, लौह तत्वों, सल्फेट, नाइट्रेट आदि का क्लोरीमीट्रिक विधि से पता लगना चाहिए । जनपद के औद्योगिक पेटी वाले क्षेत्र मे पेय जल के गुणवत्ता के मूल्याकन तथा जल के भौतिक - रसायन, जीवाणु और जैविकीय विश्लेषण के लिए चलती - फिरती जाच प्रयोगशाला का विकास करना चाहिए ।

इन सब योजनाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य नियोजन का सबसे नायाब तरीका 'परिवार नियोजन' है, जिसके बिना उत्तम स्वास्थ्य व सतुलित विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । जनपद के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रगति के लिए हमें सर्वाधिक प्रमुखता स्वास्थ्य क्षेत्र को ही देनी होगी क्योंकि केवल स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। 21

सन्दर्भ

- 1. Thapaliyal, B K and Ramanna, D V Planning for Social Facilities 10th Course on DRD, NKD, Hyderabad 1977, Sept - Oct , p 1, (Unpublished paper)
 - 2 वही, पुष्ठ ।
- 3 Draft Five Year Plan, 1978 (1978-83), Planning Commission, Govt of India, New Delhi, p. 106
- 4 'भारत', प्रकाशन विभाग, सूचना एव प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 1988-89, पृष्ठ 62
 - 5 वही
- 6 योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, पिटयाला हाउस, नई दिल्ली, 30 सितम्बर 1991, पृष्ठ 14
- 7 चॉदना, आर सी. जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिसर्स, नयी दिल्ली, 1987, पृष्ठ 179

- 8 वार्षिकी, उत्तर प्रदेश, 1990-91 व 1991-92, पृष्ठ 121
- 9 वहीं, पृष्ठ 123
- 10 Report of Education Commission, 1966, p 234
- 11 Pathak R K Environmental Planning
 Resources and Development, Chugh Publication, Allahabad,
 1990, p 153
- 12 दत्त, भग्तोष योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 26 जनवरी 1990, पृष्ठ 2
- 13 Gibbs, JP (ed) Urban Research Method,
 1966, p 107
 - 14 वही
 - 15 पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 4, पृष्ठ 155
 - 16 पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 8, पृष्ट 330
 - 17 योजना , 15 सितम्बर 1991, पृष्ठ 9
 - 18 पूर्वोक्त सदर्भ संख्या 13, पृष्ठ 161 तथा 331-335
 - 19 योजना, 26 जनवरी 1992, पृष्ठ 5
- 20 दास, शिवतोष भारत स्वतन्त्रता के बाद, प्रकाशन विभाग , सूचना और प्रसारण मत्रालय, 1987 , पृष्ठ 48
 - 21 पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 19, पृष्ठ 4

 \times

अध्याय 8

समन्वित क्षेत्र - विकास

'सर्रान्वत क्षेत्र-विकास' की सकल्पना एक व्यापक सकल्पना है। किसी अर्थव्यवस्था या क्षेत्र के विकास का तात्पर्य केवल कुछ सुविधाओं की वृद्धि करना ही नहीं है वरन् समग्र विकास करना है। पिछले अध्यायों में अध्ययन क्षेत्र के उद्योग, कृषि, परिवहन, सचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रतिरूपों एव समस्याओं को विश्लेषित कर विकास-नियोजन प्रस्तुत किया गया है। किन्तु किसी क्षेत्र के विकास में उक्त मुख्य तथ्यों का ही योगदान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे कारक है यथा - आवास, सफाई, प्रौद्योगिकी विकास, विकसित मानव ससाधन, पर्यावरण सतुलन, मनोरजन के साधन, खेलकूद के साधन, वर्ग-द्वेष का अभाव, सामुदायिक भावना तथा चरित्र निर्माण आदि, जिसके बिना समग्र- विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती। किन्तु एक शोध - प्रबन्ध में समग्र - विकास के लिए आवश्यक सम्पूर्ण भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा राजनीतिक कारको का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके लिए शोध - श्रृखला की आवश्यकता है। एक शोधकर्ता के लिए समय, ससाधनों तथा विशेषज्ञता के अभाव में समग्र अध्ययन करना सभव नहीं है। अत प्रस्तुत अध्याय में क्षेत्र विकास से सम्बन्धित विश्लेषणात्मक वृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

जिस क्षेत्र की (जनपद सोनभद्र) लगभग 86% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण हो, 2/3 अशिक्षित हो, 1/4 भाग पर कृषि कार्य हो तथा 40% बस्तियाँ ही सड़कों से अभिगम्य हो ऐसे क्षेत्र के समग्र-विकास के लिए, विकास के लिए उत्तरदायी सभी कारको को झकृत करने होंगे। वस्तुत क्षेत्र के समग्र - विकास की सकल्पना भी सापेक्षिक होती जा रही है। पिछंडे क्षेत्रों के विकास की योजना, प्राय विकसित देशों के विकसित क्षेत्रों के आधार पर की जाती है। किन्तु अध्ययन क्षेत्र का अपना एव विशिष्ट व्यक्तित्व है, जिसके विकास का नियोजन क्षेत्रीय समस्याओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए। कभी-कभी राष्ट्रीय हित मे क्षेत्रीय हित को गौण बना दिया जाता है। लेकिन समन्वित क्षेत्र-विकास क्षेत्रीय असतुलन उत्पन्न कर प्राप्त नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय - हित को ध्यान मे रखते हुए अध्ययन क्षेत्र के हित एवं विकास को भूला दिया गया है। गोविन्द बल्लभ पन्त सागर, विद्युत परियोजनाओं, सीमेट, अल्यूमिनियम,

रसायन तथा अन्य अनेक उद्योगों की स्थापना सेहजारों लोग बेघर हो गए। बीना, खडिया तथा ककरी कोयला क्षेत्रों के उजडे हुए लोगों से बात करने पर उनके क्षोभ का पता चलता है। एक आदमी ने कहा - 'यदि मुझे ज्ञात हो जाय कि मेरे घर या गांव मे सोने की खान है तो भी मै किसी से नहीं बताऊँगा सरकार से तो कदापि नहीं। क्योंकि हमारा उजाडना तो निश्चित हो जाता है और खुश करने के लिए (मुआवजा के रूप मे) कुछ पैसे मिल जाते हैं'। उजडे हुए लोगों के पुश्तैनी सामाजिक, सास्कृतिक एव प्राकृतिक वातावरण को तो प्रदत्त नहीं किया जा सकता किन्तु पुनर्स्थापना की समुचित व्यवस्था कर उनकी समस्याओ को कुछ हद तक कम अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए पैसा नहीं वरन् उनके अनुरूप वातावरण एव आरक्षण देने की आवश्यकता है। वास्तव मे हजारों सोनभद्रवासियों के त्याग (मन से भले ही न किया गया हो) से देश के विभिन्न क्षेत्रों मे विकास की किरण फैली है।

चुर्क से शक्तिनगर एव रिहन्द नगर तक सम्पूर्ण क्षेत्र पर्यावरण प्रदृषण की समस्या से ग्रस्त होता जा रहा है। हमारी भोगवादी सभ्यता ने 'टेक्नोस्फीयर' मे सास लेने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारी सभ्यता का उदय अरण्यों मे हुआ था किन्तु हम पिश्चम के समुदी सभ्यता (विस्तारवादी एव भौतिकवादी) के अनुकरण मेस्चावलम्बी एव सतुलित विकास का परित्याग करते जा रहे है। आने वाले कुछ दशकों मे जनपद सोनभद्र 'महानगरीय प्रदूषण' जैसी समस्या से ग्रस्त हो जाएगा। 'स्टोन क्रेशर' से पहाडों को तोडने, ताप विद्युत गृहों, सीमेट कारखानों तथा चूना भट्ठियों आदि से निकलने वाले धृम्म एव कणों से न केवल जीव जन्तुओं पर वरन् वनस्पतियों पर भी दुष्प्रभाव पड रहा है। औद्योगिक केन्द्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों मे फसलो एव बागानो पर पडने वाले प्रभाव एव उसे दूर करने के लिए उपाय हेतु शोध की आवश्यकता है।

वनों की कटाई एव उससे जिनत अपरदन की समस्या समिन्वत विकास की प्रिक्रिया को बाधित कर रही है। बाधों, बिन्धयों एव निदयों में लगातार बढ़ते निक्षेप से अनेक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। अत वनोपज की चोरी एव कटाई पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अनियन्त्रित चराई से भी अपक्षय एव अपरदन में वृद्धि हो रही है। विकासखण्ड चतरा एवं घोरावल के कृषि प्रधान बेलन - घाटी से, वर्षा के दिनों में, पालतू पशु जमलों में चराई

वे लिए भेज दिये जाते है । अत ऐसी समस्याओं वे समाधान वी आवश्यवता है ।

लगभग 40 वर्ष की छोटी सी अवधि मे जनपद सोनभद्र के पर्यावरण वी समस्याओं के लिए तीन कारणों को बताया जाता है। वे है गरीबी, कम विकास और विकास वार्यक्रमों का गलत आयोजन तथा गलत कार्यान्वयन । किन्तु गरीबी या गरीबी मे जीवन बसर वरने वाले लोगों ने नहीं बिल्क धनी किसानों, जो बड़े बाधों और अधिक रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशव दवाओं के उपयोग पर जोर देते है । बड़े और मझोले उद्योगपतियों ने जो हमारे वनो की कटाई के लिए जिम्मेदार है और जो प्रदूषण नियत्रण उपकरण के बगैर अपने वल - वारखाने चला रहे है, पर्यावरण को नुवसान पहुँचा रहे है । अल्प विकास से नहीं बिल्क इसके विपरीत तेज और जल्दबाजी के विवास से पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है । विवास कर्यव्रम के खराब आयोजन और क्रियान्वयन से भी पर्यावरण को नुक्सान नहीं पहुँचा है बिल्क इसलिए कि हम विवास की परिकल्पना शुद्ध रूप मे बृद्धि के रूप मे करके मात्रात्मक आकार देते हैं । जबिक हमें गुणात्मकता पर ध्यान देना चाहिए ।

अनपरा ताप विद्युत गृह, रिहन्द नगर तथा सिगरौली सुपरथर्मल पॉवर हर वर्ष उत्पादन के कीर्तिमान बना रहे हैं । इसे हम प्राय विकास का सूचक मानते हैं । वास्तव में इनके द्वारा उत्पादित उत्पादों के मूल्य को, उनके द्वारा जिनत पर्यावरण प्रदूषण के पुनरूद्धार के मूल्य में से घटा दर ही वास्तविक लाभ ज्ञात करना चाहिए । समन्वित क्षेत्र - विकास के लिए यहीं सबसे उपयुक्त मापदण्ड है । अब ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे पता चल सके कि मनुष्य और पर्यावरण के साथ आज और भविष्य में क्या हो रहा है ।

अध्ययन क्षेत्र वे समन्वित विकास के लिए यह आवश्यक है कि 'वृद्धि रोग' से बचा जाय । इसके जगह 'निर्वाह योग्य विकास' की नयी सक्लपना स्थापित करनी होगी।' निर्वाह योग्य विकास वह विकास है जो सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, खासकर बहुसख्यक गरीबो की रोजगार, भोजन, ऊर्जा, पानी और आवास की जरूरतें पूरी करने के लिए, कृषि, निर्माण, ऊर्जा और सेवाओं की प्रगति सुनिश्चित करता है । इसमे पर्यावरण एव अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का विलय होता है ।

अधिकतर गाँवों की सबसे बडी समस्या पेय जल की है । मानसून की वर्षा न होने से और भूमिगत जल के स्तर मे कमी से अध्ययन क्षेत्र मे भयानक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । भूमिगत जल का पता लगाने के लिए उपगृहों द्वारा भेजे गए दूर - संवदन आकडों का व्यापक इस्तेमाल करना चाहिए ।

पशुओं की पर्याप्त सख्या देखते हुए उनके समुचित विकास की आवश्यकता है। ये पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अग है । इन पशुओं की उत्पादकता काफी कम है। नस्ल सुधार के लिए अब तक जो कार्य हुआ है वह विदेशी जाति के पशुओं से सकर-नस्ल के पशु पैदा करने तक सीमित है । भेड़ - बकरियों के पालन की सुविधाए एव उनके उत्पादों को सही मूल्य दिलाने की कोशिश करनी चाहिए । भेडों के ऊनों से कम्बल बनाने के कार्य को प्रोत्साहन एव दक्षता प्रदान करने की आवश्यकता है । मुक्त बधुआ मजदूरों को 'जर्सी गाय' देने की बजाय, भेंड, बकरी या देशी गाय आदि देनी चाहिए, जो उनके वातावरण के अनुकूल हों।

उद्योगों मे श्रीमकों की भागीदारी कैसी हो ? इसे तर्क से नहीं बिलक व्यवहारिक रूप से सोचना होगा । कृषकों एव कृषि - मजदूरों के सम्बन्ध एक परिवार की तरह होते थे । कृषि - मजदूरों को किस - किस वस्तुओं की आवश्यकता है तथा कृषक मजदूरी के रूप मे क्या दे सकता है, के सतुलन एव सामजस्य पर कृषि मजदूरों की मजदूरी एव सम्बन्ध स्थापित थे । किन्तु सरकार औद्योगिक श्रीमकों की तरह कृषि श्रीमकों को भी पैसा दिलाने की नीति अपना रही है जिससे कृषि श्रीमकों की दुर्दशा बढती जा रही है । अत इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है ।

अध्ययन क्षेत्र की अधिकाश ग्रामीण बस्तियाँ कच्चे एव झोपडी के रूप मे हैं । इन्दिरा आवास योजना के तहत इनके लिए पक्का मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है । सरकार को इनके पुराने मकान की मरम्मत एवं सुधरा स्वरूप प्रदान करना चाहिए । इससे उनके पुश्तैनी मकान का मोह भग भी नहीं होता है तथा नया (सुधरा मकान) मकान किसी के भी द्वारा अधिगृहित नहीं किया जा सकता है । कच्चे मकानों व झोपडियों मे रहने वाले लोगों के लिए 'हवाई पैखाना' बनाने की जगह प्रत्येक गाँव मे नाली की सुविधा, गिलयों मे खडजा तथा प्रत्येक गाँव मे एक सफाई कर्मी नियुक्त किया जाना चाहिए । सामुदायिक - भावना मे वृद्धि करके भी सफाई, नाली तथा सडक अव्यवस्था से मुक्ति पायी जा सकती है । गोबर के खाद के गड्ढे को गाँव से बाहर बनाना चाहिए, पशुओं को निवास स्थान से दूर तथा खेतों के पास गोशाला मे बाधना चाहिए । ग्रामीणों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए गांधी जी के विचारों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । अधिकाश ग्रामीण समस्या नगरों की नकल करने से उत्पन्न हो रही है ।

अध्ययन क्षेत्र के विकास को नगरीकरण से नहीं मापना चाहिए । क्योंकि नगरीकरण स्वय एक समस्या है । वह दिन दूर नही जब नगरों से गाँवो की ओर पलायन होगा । नगरों की झोपड-पट्टियों व गदी गलियों मे रहने वाले लोगों से सोनभद्र का आदिवासी अधिक सुखी है । वर्तमान मे सुख की अनुभूति एव विकास कार्यक्रमों से खुशहाली मे लगातार वृद्धि होना ही समन्वित विकास है ।

जनपद सोनभद्र में खेलकूद के एवं मनोरजन के साधनों की कमी है । खेलकूद को प्रोत्साहन देकर, प्राचीन किलों मन्दिरों तथा प्राकृतिक स्थलों को सड़कों से जोड़कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है । विकासखण्ड स्तर पर खेलों की प्रतियोगिताए होनी चाहिए । इससे चारित्रिक विकास एवं मनोरजन के उद्देश्य की पूर्ति होगी । भारतीय संस्कृति में भौतिक सुविधाओं में बृद्धि से ही समन्वित विकास की परिकल्पना नहीं की गयी है । वस्तुत सामुदायिक भावना, उच्च चरित्र के लोग तथा वर्ग - द्वेष की भावना का अभाव भी समन्वित क्षेत्र - विकास की संकल्पना को पूर्ण करते हैं ।

अध्ययन क्षेत्र मे विकास की ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिससे आत्म निर्भरता समाप्त होती जा रही है तथा निर्भरता बढ़ती जा रही है । इसे समुचित विकास नहीं कहा जा सकता है । हमारी क्षमता विकसित देशों की तरह विकल्प पैदा करने की नहीं है । हमे तो अपने विकल्पों से ही विकास करना है । तभी समुचित एव आत्मीनिर्भर विकास किया जा सकता है । यहां के अरण्यों मे रहने वाले सत बिना किसी भौतिक सुविधा के सम्पूर्ण विश्व की स्विदना रखते थे । क्या आज का भौतिक गुग तथा तथाकथित विकसित विश्व उन्हें पिछड़ा कह सकता है? समन्वत - क्षेत्र - विकास की एक नयी परिकल्पना दी जा सकती है । जो क्षेत्र जितना अधिक अन्तर्विरोधों की पचा (समाहित) सकता है उसे उतना ही विकसित कहा जा सकता है । यदि अध्ययन क्षेत्र में बड़े उद्योगों से प्रदूषण न होता, वनों की कटाई से अपरदन न होता तथा जलाशयों के निर्माण से बस्तियों का विस्थापन न हुआ होता तो इसे उच्च स्तर का विकसित क्षेत्र कहा जा सकता था । एक ओर हम तेजी से विकास कर रहे है तो दूसरी ओर उसके दुष्परिणाम दिखायी दे रहे है । विकास प्रक्रिया से यदि दुष्परिणाम न हो तो समन्वित विकास कहा जा सकता है किन्तु सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र इससे प्रभावित है । यह तथ्य स्वय एक शोध का विषय है ।

अध्ययन क्षेत्र का समन्वित विकास, उस क्षेत्र मे उपलब्ध साधनों, वहाँ के निवासियों की आवश्यकताओं, महत्वाकाक्षाओं और उनके तकनीकी कौशल पर निर्भर है । यहाँ के प्राकृतिक उपहारों का साधन के रूप मे मूल्य तभी बढेगा, जब लोगों को उनके उपथो दा ज्ञान हो जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण है, जहाँ सभाव्य साधन विशाल मात्रा मे उपलब्ध है, किन्तु उपयोगिता के ज्ञान के अभाव तथा आर्थिक कारणों से उनका विकास नहीं हो पाया है । पूँजी, सडकों, रेलों, तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव मे विकास मे कठिनाई आ रही है।

जनपद के सभी विकासखण्डों मे ससाधनों का वितरण असमान है । विकासखण्ड नगवा, बभनी, चतरा एव घोरावल मे अभी तक विकास प्रक्रिया आरम्भ नहीं हो सकी है । इससे पिछडे जनपद मे भी क्षेत्रीय असमानता दृष्टिगोचर हो रही है । उपर्युक्त विकासखण्डों मे उनके ससाधानों के अनुरूप विकास प्रक्रिया शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता है । इससे क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है ।

समिन्वत क्षेत्र - विकास एक अविछिन्न प्रिक्रिया है, जिसे अल्प अविध में प्राप्त नहीं किया जा सकता है । इस विकास को पूर्ण तभी कहा जा सकता है जब अध्ययन - क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने (सोनभद्र के) ही ससाधनों द्वारा विकास किया जाय । राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह सकल्पना विवादास्पद हो सकती, किन्तु क्षेत्रीय दिदास के लिए यह अनिवार्य भर्त है। किसी क्षेत्र में (जैसे सोनभद्र) अनेक उद्योग स्थापित कर देने से ही क्षेत्र का विकास नहीं होता है। हाँ, वहाँ के ससाधनों (जिस पर उद्योग आधारित) का विकास तथा उपयोग अवश्य हो जाता है। इस प्रक्रिया मे जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग (जिससे रोजगार मिले) प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक समन्वित क्षेत्र - विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यावहारिक शोध की आवश्यकता है।

वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार जनपद सोनभद्र में 425% लोग अनुसूचित जाति एव जनजाति के हैं। स्वतन्त्रता के पूर्व इन्हें केवल पिछड़ा कहा जा सकता था। किन्तु बड़े उद्योगों की स्थापना, खनन व निर्माण कार्य तथा अन्य कार्यों के प्रारम्भ होने के पश्चात इनका शोषण प्रारम्भ हो गया। इन पिछड़े व शोषित लोगों के कल्याण के लिए विशेष नीति तैयार करने की आवश्यकता है। विकास प्रक्रिया एव विकास-लाभ में इन्हें सम्मिलित किए बिना समन्वित क्षेत्र - विकास की परिकल्पना अधूरी रह जाएगी। इसके लिए आवश्यक है जगली क्षेत्रों में भी छोटे-छोटे विकास केन्द्रों की स्थापना की जाय। यहाँ के लोगों के रूढिवादिता को तोडने व नवीनताओं के प्रसरण के लिए व्यावहारिक नीति अपनाने की आवश्यकता है।

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के विकास की व्यूह रचना इस प्रकार करनी होगी जिससे न केवल सभी विकास खण्ड एक दूसरे के पूरक हो जाय बल्कि प्रत्येक गाँव एक दूसरे का पूरक हो जाय। 'आत्म निर्भर विकास' ऐसा हो कि सम्पूर्ण गाँव, न्यायपचायत एव विकास खण्ड एक दूसरे से विलग न हो बल्कि माला की तरह एक दूसरे से गुथ जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत् प्रयास एव व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके अभाव मे ही जिला मुख्यालय विवाद तथा 'सोनपार क्षेत्र' को अलग जिला बनाने की माँग हो रही है।

किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उसका सभाव्य संसाधन माना जाता है। इसमे उनकी सख्या और गुणवत्ता दोनो ही सिम्मिलत है। लोगों की गुणवत्ता में उनकी कार्य क्षमता या उत्पादकता, उनका वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास, उनके सांस्कृतिक मूल्य और उनके सामाजिक एव राजनीतिक सगठन सिम्मिलत है। अत अध्ययन क्षेत्र के मानव और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक साथ अनेक दिशाओं में लगातार एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में परिवार, समाज तथा विद्यालय जैसी

सामाजिक सस्थाए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके प्रभावी भूमिका पर शोध करने के लिए विस्तृत क्षेत्र खुला है। सोनभद्रके मानव ससाधन को अधिक से अधिक अच्छे ढग से विकसित, शिक्षित एव प्रशिक्षित करना आवश्यक है क्योंकि इनके विकास पर ही इस जनपद के प्राकृतिक ससाधनों का विकास निर्भर है। इसके अभाव में ही अन्य क्षेत्रों के लोग यहाँ (सोनभद्र) के कार्यों को हथिया लिए है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य-कुशलताओं का विकास, कार्य के प्रति लगन, चरित्र निर्माण तथा सामाजिक भावना जैसे गुण और अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे है। उपयुक्त तथ्यों का विकास कैसे किया जाय, गहन शोध की आवश्यकता है।

समन्वित क्षेत्र - विकास लिए कुछ लक्ष्य ऐसे है, जिन्हे प्राप्त करना अनिवार्य है। लक्ष्य तो स्पष्ट है, लेकिन उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय तथा किस प्रकार उपयोग किया जाय, शोध का विषय है। ये लक्ष्य है - सबको साक्षर बनाना, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाए जुटाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिकता में प्रवीणता । इनके अतिरिक्त कर्तव्यपरायणता तथा कार्य के प्रति निष्ठा पैदा करना, स्त्रियो को बराबरी का दर्जा देकर उनकी क्षमताओं का विकास करना, श्रमिकों की उत्पादकता बढाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा उर्जा का उपयोग करना, कुछ अन्य प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है।

अनेक ऐसे कारक, जो समन्वित क्षेत्र - विकास के लिए आवश्यक है, किन्तु अनेक कारणों से प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की विषय वस्तु मे सिम्मिलित नहीं िक्या गया है। अत अध्ययन क्षेत्र (जनपद सोनभद्र) के समन्वित विकास के लिए व्यापक शोध की आवश्यकता है जिसमे अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों से सहयोग लेना आवश्यक है।

परिशिष्ट । शब्दावली

आदान Inputs

आर्थिक समृद्धि Economic Growth
आधारभूत उद्योग Basic Industry
आधारभूत कार्य Basic function
उपभोक्ता उद्योग Consumer Industry
औद्योगिक कृन्ति Industrial Revolution

कार्यात्मक आकार Functional Size
कार्यात्मक अक Functional Score
कार्यात्मक सूचकाक Functional Index
कार्याधार जनसंख्या Threshold Population
कुटीर उद्योग Cottage Industry
केन्द्र स्थल Central Place

केन्द्रीयता अक Centrality Score केन्द्रीयता अक Centrality Index केन्द्रीय कार्य Central Function कृषि योग्य भूमि Culturable Land

कृषित Cropped

कृषि सम्पदा Agricultural Resources

खनन Mining

खनिज अयस्क Mineral Ore

खरीफ Kharif खुली खदान Open Mine

गहन कृषि Intensive Agriculture

गैर आबाद Uninhabited

गृह उद्योग House hold Industry

चकबन्दी Consolidation of Holding

जलगृहण क्षेत्र Catchment Area जल विद्युत Hydroelectricity

जल स्तर Water Table

जोत Holding

डेयरी उद्योग Dairy Industry

ढलान Gradient

तालाब Tank

ताप विद्युत Thermal Electricity

तिलहन 011seeds

तृतीयक उद्योग Tertiory Industry द्वितीयक उद्योग Secondary Industry

नलकूप Tube Well
नौ परिवहन Navigation
पठार Tableland
पदानुक्रम Hierarchy
पर्यटन Tourism

प्रवेशी जनसंख्या Threshold Population

फसल कोटि Crop-rank

फसल संयोजन Crop-Combination/association

बस्ती अन्तरालन Settlement Spacing

बेसाल्ट Basalt

बृहद् उद्योग Large-scale Industry

बृहत स्तरीय Macro-level भौम जल Ground water मध्यम स्तरीय Meso-level मुख्य कर्मी Main worker

लघु उद्योग Small Scale Industry

विकास भूव Growth Centre Growth Pole

विदेशज Exotic

विनिर्माण Manufacturing

सतुप्त/सपुक्त जनसंख्या Saturation point Population

शस्य गहनता Crop-Intensity

शुद्ध बोया गया Net Swon

सडक जाल Road Network

संडक सम्बद्धता Road Connectivity

समन्वित Integrated

सर्वगत/सर्वत्रिक Ubiquitous Compact Index

सहत Compact स्चकाक Index

सूक्ष्म स्तरीय Micro-level सेवा केन्द्र Service Centre सेवित जनसङ्या Served Population

शुष्क कृषि Dry Farming हृदय क्षेत्र Heart-Land

परिशिष्ट 2

FURTHER READINGS

BOOKS AND ARTICLES

- Abder, R. et al 'Spatial Organisation' Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1967
- Agarwal, S N 'Indian Population Problems, Tata McGraw Hill, Bombay 1972
- Ahmed, E 'Geomorphic Regions of Peninsular India', Journal of Ranchi University, 1/9, 1962, pp 1-29
- Alagh, Y. (1972) Regional Aspects of Indian Industrialization, University of Bombay, Economic Series No 21
- Arora, R.C 'Development of Agriculture and Allied Sectors-An Integrated Area Approach', New Delhi, 1976, pp.1-9
- Atkinson, B W Precipitation in Man and Environmental Process edited by K J Gregory and D E Walling, Butercuorths, pp 23, 37
- Bannet, H H 'Adjustment of Agriculture to its Environment', AAAG, Vol 33, No 4, Dec 1943, pp 169-198
- Berry, L and Perov, G. 'Economic Planning in the Soviet
 Union in Planning of Manpower in the Soviet Union
 Translated by Shcherbovich, S.B., Progress
 Publisher, Moscow, 1975, pp. 24-36
- Bhalla, C.S. Changing Agrarian Structure in India, A Study of the Impact of Green Revolution in Haryana, Meenakshi Prakashan, Meerut (1972).
- Bhatt, L S. 'Regional Planning in India', Statistical Publishing Society, Calcutta, 1972.
- Bhatnagar, L.P. Transport in Modern India, 5th ed Kishore Publication House, Kanpur (1970).
- Bracey, H.E. 'Towns As Rural Service Centres An Index of
 Centrality with Special Reference to Somerset',
 Transaction of papers, Institute of British
 Geographers, No. 19, (1953), pp. 85-105

- Champion, H G A, Preliminary Survey of Forest Types of India and Burma, Indian Forest Record, New Series, Silviculture, vol 1, Delhi, 1936
- Cartor, H. 'Urban Grades and Sphere of Influence in South West Wales', Scotish Geographical Magazine, Vol 71 (1955), pp 43-58
- Chauhan, D S. Studies in the Utilisation of Agricultural Land, Shiv Lal and Co , Agra, (1966)
- Chandna, R.C and S Manjit Introduction to Population Geography, Concept Publishing Company, New Delhi, (1980)
- Chaudhury, M.R. Indian Industries Development and Location, Oxford, Calcutta, 1970
- Dubey, B and M Singh Integrated Rural Development, Jeevan
 Dhara Publication, Varanasi, (1985)
- Dutta, A K Two Decades of Planning-India An Anotomy of Approach', National Geographical Journal of India, Vol XVIII (3-4), (1972),pp 187-205
- Friedman, J 'Cities in Social Transformation', Reprinted in J Friedman, et al (ed) 1964, Regional Development Planning-A Reader (1961), pp 343-60
- Gadgil, D R 'District Development Planning', Gokhale
 Institute of Politics and Economics, Poona, 1967,
 pp.1-38
- Glasson, J. 'An Introduction of Regional Planning Concept,
 Theory and Practice', London, 1978, pp.24-31
- Gould, P.R. 'The Development of the Transportation Pattern in Ghana', Illionis, 1960, p 132
- Government of India, National Atlas of India, New Delhi, Ministry of Education, 1957
- Government of India Irrigation and Power Projects, Ministry of Irrigation and Power, New Delhi, 1970
- Grossman, L. Man-Environment Relationship in Anthropology and Geography, Annals of the Assoc Amer, Geographers, Vol. 67, pp 126-44.
- Haggerstrand, T. Innovation Deffusion as a Spatial Process, Chicago (1970)

- Haggett, P. Location Analysis in Human Geography, Arnold, London (1967)
- Hansen, N M. (ed) The Regional Economic Development, The Press, New York (1972)
- Harvey, D. Social Justice and the City, Edward Arnold, London(1973)
- Indian Council of Agriculture Research Handbook of Agriculture, New Delhi, 1970
- ICSSR 'A Survey of Research in Geography', Popular Prakashan, Bombay, 1972, pp 122
- Jana, M.M. 'Hierarchy of Market Centres in Lower Silabati Basin', Geographical Review of India, Vol 40, No 2 June 1978, pp 164-176
- Kar, N.R. 'Urban Hierarchy and Central Functions Around Calcutta and their Significance', Land Studies in Geography, Series B, Human Geography, No 24, 1962, pp 253-274
- Kayastha, S.L et al. 'Geographical Environmental Approach for Integrated Rural Development', Proceedings of 65th Session of ISCA (Geology & Geography Section), 1978, p 3
- Kulkınskı, A K. 'Some Basic Issues in Regional Planning', in Regional Planning and National Development by Mishra, R P et al (Eds.), VP, New Delhi, 1978, pp 3-21
- Kuznetsov, V.I. 'Economic Integration Two Approaches', Progress Publishers, Moscow, 1975, pp 13-25
- Khan, W.and R.N. Tripathi Plan for Integrated Rural Development in Paurigarhwal, NICD, Hyderabad (1976).
- Law, B.C. (ed.) Mountain and Rivers of India, Calcutta, National Committee for Geography, Calcutta, 1968
- Mishra, B N.. Spatial Pattern of Service Centres in Mirzapur Disti, U P., Unpublished Thesis, in Geography, 1980.
- Mishra, H.N. 'The Concept of Umland A Review', National Geographer, Vol 6, 1971, pp 57-63
- Majid Hasan, Crop Combination in India, Concept Publishing Company, New Delhi, 1982

- Misra, R.P Diffusion of Agricultural Innovation, University of Mysore, 1968
 - District Planning Development Studies No 6, Institute of Development Studies, University of Mysore 1972
 - Regional Planning and National Development, Vikas Publishing House, New Delhi, 1976
- Nicholson, M The Environmental Revolution, Penguin, Harmondsworth, 1972.
- NSSO 'Report on the Status of Estimation of Agricultural Production in India (1974-75)8, Govt of India, New Delhi, 1977, pp.191-198
- Preogrzhenzky, V.S 'Integrated Research on the Natural Environment and Resources'in Man Society and the Environment, by Gerasimov, I.P et al (Eds), Progress Publishers, Moscow, 1975, pp 60-70.
- Ramanna, D.V. and Thapliyal, B.K. 'Planning for Agricultural Infrastructures', 10th Course on IRD, Hyderabad, Sept -Oct 1977, pp.1-2, (Cyclostyled Paper)
- Rao, V.L S P. Regional Planning, Indian Finance, Calcutta,
 1949
 Regional Planning, Asia Publishing House, Bombay,
 1963.
- Regier, H A.and Cowell, E B. Application of ecosystem theory, succession, diversity, stability, stress and conservation, Biological Conservation, Vol. 4, 1972, pp 83-88
- Singh, B. 'Land Use-its Efficiency, Stages and Optimum Use',
 National Geographical Journal of India, Vol 23,
 Nos 1-2, March-June 1977, pp 61-72
- Singh, H.P 'Development Pole Theory-Review and Appraisal',
 National Geographer, Vol 13, No 2, Dec 1978,
 pp. 155-162
- Singh, J'Transport Geography in South Bihar', NGSI, Varanasi, 1964
- Singh, L.R., Savindra, Tiwari, R.C and Srivastava, R.P.:

 Environmental Management (ed), Allahabad

- Geographical Society, Geog Deptt Allahabad University, 1983
- Singh, R L.(ed.) 'India-A Regional Geography', NGSI,

 Varanasi, 1971, pp 189-196
- Singh, R.N.. and Sahab Deen 'Occupational Structure of
 Urban Centres of Eastern U P A Case Study of
 Trade and Commerce', Indian Geographical Journal,
 Vol 56 No p 81, pp 55-62
- Smith, D.D. and Wischmeier, W H Rainfall erosion,
 Advances in Agronomy, Vol 14, 1962, 109-48
- Spate, O.H K. and Lear Month, A.T A Indian and Pakistan A
 General and Regional Geography, 3rd ed Methuen,
 London, 1967
- Stamp, L.D. 'The Determination of Planning Regions',
 National Geographer, Vol 5, 1962, pp 1-6
- Sundram, K.V. 'Regional Planning in India', in Symposium on Regional Planning (21st I G C), Calcutta, 1971, pp 109-123
- Thapliyal, B.K. and Ramanna, D.V. 'Planning for Social Facilities', 10th Course on IRD, NICD, Hyderabad, Sept -Oct 1977, pp 1-3 (Unpublished Paper)
- Verma, L.N. 'Spatial Arrangement on Central Places on the Rewa Plateau' in Essay in Applied Geography by Mishra, V.C et al (Eds), University of Saugar, 1976, pg 251-258.
- Wadia, D.N.: Geology of India (Economic Minerals) 5th ed., MacMillan, London, 1965.
- Wadia, M D.N. 'Minerals of India, N.B T , India, New Delhi, 1966
- Wanmali, S 'Central Places and their Tributary Populationsome observations', Behavioural Sciences and Community Development, Vol.6, No 1, March 1972, pp 11-39
- William, R.C. and Morill, R.L. 'Diffusion Theory and Planning', Economic Geography, Vol 51, No 3, July 1975, pp 290